Motion of Thanks on the President`s Address (Contd.)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रख रहा हूं ।

महोदय, 31 जनवरी, 2024 को नए संसद भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण हुआ और इस अभिभाषण के माध्यम से देश में राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन मिला । जब नये संसद भवन में संसद का पहला सत्र शुरू हुआ, उसमें देश की महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बनाया और लोक सभा तथा देश की विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर एक नए युग का आरंभ किया गया । इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

महोदय, 16वीं और 17वीं लोक सभा में जब से देश में माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है, देश हर कदम प्रगति की ओर बढ़ा है । इस सरकार के द्वारा देशहित में किए गए निर्णय से देश के जन-जन तक इसका लाभ पहुंचा है । नरेन्द्र मोदी जी ने 26 मई, 2014 को पहली बार प्रधान मंत्री पद की शपथ ली और उसी दिन से मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार के 10 साल आम जनता को समर्पित रहे । इन 10 सालों में केंद्र सरकार कई जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर आई । जन-धन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और उज्ज्वला योजना से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिला और देश के एक बड़े वर्ग को इन योजनाओं का लाभ मिला है ।

महोदय, यह वर्ष हमारे संविधान के लागू होने का 75वां वर्ष है । अभी हम आजादी का 75वां वर्ष मानकर अमृत महोत्सव मना रहे हैं । इस 75 वर्षों

में देश ने कई उतार-चढ़ाव देखे । आज हम विश्व की पांचवीं आर्थिक शक्ति हैं और जल्दी ही हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे । ?(व्यवधान)

माननीय सभापति : अध्यक्ष पीठ की तरफ पीठ मत कीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, व्यवस्था बनाए रखें ।

? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): कोई मिनिस्टर यहां नहीं हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए । मिनिस्टर हैं, आप विराजिए ।

? (व्यवधान)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : इसके साथ ही साथ, पिछले 10 वर्षों में हमारे देश का निर्यात 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हुआ है । इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और उनके कुशल नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

महोदय, इस सरकार से देश के नागरिकों को बहुत आशाएं हैं । सरकार जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरी उतरी है । आज देश में हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है । हर गांव, देहात में इंटरनेट और मोबाइल सुविधा का विकास हुआ है । जन-जन तक सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचा है ।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य सभी को घर उपलब्ध कराना है । इसी के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना को लांच किया गया है

और देश में बेघर लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गांवों में घर प्रदान कराए गए हैं । सरकार के पिछले 10 वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों के रहे हैं । बड़े पैमाने पर मिशन मोड पर नौकरियां सरकार द्वारा दी गई हैं ।

महोदय, देश में नए संसद भवन के निर्माण के साथ ही साथ, भारत मंडपम और यशो भूमि का निर्माण कर देश को नया आयाम और ऊर्जा प्राप्त हुई है । देश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है ।

महोदय, देश ने 9-10 सितम्बर को जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की । जी-20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए । इस सम्मेलन की कामयाबी का श्रेय मोदी सरकार को जाता है । जी-20 सम्मेलन के बाद हमारे देश भारत की छवि दुनिया भर में और मजबूत हुई है ।

भगवान राम हम सबके दिलों में बसते हैं । एक लंबे समय से देशवासियों की मांग थी कि भगवान राम का मंदिर बने । आज वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है । 22 जनवरी से रामलला अपने भवन में विराजे हैं ।

सरकार ने तीन तलाक की कुरीति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया । इस मकसद के लिए 26 जुलाई, 2019 को तीन तलाक बिल लोक सभा में पास किया और यह बिल 30 जुलाई, 2019 को राज्य सभा में भी पास हो गया । इस बिल के पास होने और प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की जीत हुई और महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा ।

23 अगस्त, 2023 को जब मिशन चन्द्रयान-3 चन्द्रमा के साउथ पोल पर उतरा तो हमारा देश चन्द्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश

बन गया । इस मिशन की सफलता का श्रेय भारत के सभी वैज्ञानिकों के साथ ही साथ मोदी सरकार को भी जाता है ।

देश में वन रैंक वन पेंशन की मांग लंबे समय से चली आ रही थी । लेकिन पुरानी सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया । वन रैंक वन पेंशन को लागू किया और लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा किया ।

नरेन्द्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा कर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया । कश्मीर को दो भागों में बांटकर इसे केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया । विपक्ष के विरोध के बाद भी यह फैसला ऐतिहासिक बन गया और इससे सरकार के कठोर निर्णय लिए जाने की क्षमता का पता चलता है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है । इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है । योजना के तहत ऐसे किसान परिवारों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जा रहे हैं । ये रुपये चार-चार महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपये की किस्त के रूप में किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं । इस योजना का लाभ लाखों गरीब किसानों को मिला है ।

आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए जीवनदान साबित हो रही है । इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष फ्री बीमा की सुविधा दी जा रही है । इसे सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माना जा रहा है । इस योजना को 2018 में लांच किया गया था । इस योजना के कारण करोड़ों लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं । सरकार की इस योजना की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी तारीफ की है । इस योजना के जरिए लाखों गरीब लोगों का बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुलवाया गया है । जन धन

योजना के तहत खोले गए खाते पर बैंक किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं लगती है । इन खातों को खुलवाने का लाभ यह भी हुआ कि अब सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ सीधे जन धन खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है ।

इसी के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): माननीय सभापति जी, मुझे समय और सहृदय अनुमति देने के लिए मैं आपको और अपनी पार्टी के वरिष्ठ लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्मान में, उनके समर्थन में अपना वक्तव्य आरंभ करता हूं ।

सभापति जी, महान् भारत का यह महान् सदन, ?एक भारत, श्रेष्ठ भारत? का प्रतीक है । यह सदन आजाद भारत का सदन है । हम सभी सांसदों को गौरवांवित करने वाला और गौरव प्रदान करने वाला यह सदन 31 जनवरी, बुधवार के दिन और गौरवांवित हो उठा जब भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पहली बार पदार्पण हुआ । उनका आगमन जिस पवित्र ?धर्म दंड? के साथ, पवित्र सेंगोल के साथ हुआ, यह एक बहुत बड़ा संदेश था ।

माननीय सभापति जी, आज आपके इस पवित्र आसन के ऊपर ?धर्म चक्र? विराजमान है । महामहिम राष्ट्रपति जी का ?धर्म दंड? के साथ इस ?धर्म चक्र? के नीचे केवल विराजमान होना ही, बिना किसी अभिभाषण के ही बहुत बड़ा संदेश था । 31 जनवरी का दिन एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया । हमारी अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करने का इससे बड़ा कोई दूसरा जीवंत उदाहरण नहीं हो सकता है ।

महोदय, जैसे मैंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने संदेश दिया। मुझे याद आता है कि महाभारत काल में महारानी द्रौपदी ने महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में संदेश दिया था। उस दरबार के अंदर बड़े महारथी, आचार्य और गुरु बैठे हुए थे, लेकिन सब चुप थे और सबने चुप्पी साधी हुई थी। महारानी द्रौपदी ने कहा था ?

"न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्।

धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तद् यच्छलमभ्युपैति॥"

अर्थात "वह सभा नहीं जहां वरिष्ठ, अनुभव और ज्ञानी पुरुष न हों, महिलाएं न हों। वे वृद्ध नहीं, वे ज्ञानी नहीं अगर वे धर्म की बात नहीं करते हों। वह धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो, सच्चाई न हो, और वह सच्चाई नहीं जहां छल छुपा हुआ हो।? यह संदेश हम सब लोगों के लिए है। महर्षि व्यास ने एक बात कही थी ? ?धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः? अर्थात् जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है और जो धर्म को मारता है, धर्म उनको खत्म करके मार देता है। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही पाप इस देश के अंदर किए। सबसे पहले क्या पाप किए? उन्होंने धर्म के नाम पर सबसे पहले इस देश को बांट दिया। उन्होंने इस देश को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष तो बना दिया, लेकिन धर्म का बिस्तर यहां से बांध कर गोल कर दिया। कांग्रेस की दूसरी गलती थी, उन्होंने भाषा के नाम पर राज्यों का बंटवारा कर दिया और उन्होंने सनातन संस्कृति का मज़ाक उड़ाया। संविधान के अनुच्छेद इस प्रकार से गड़े गए, आर्टिकल्स इस प्रकार से गड़े गए, अनुच्छेद 26 से लेकर 31 तक इस प्रकार के अनुच्छेद, इस प्रकार के आर्टिकल्स भारतीय संविधान के अंदर रखे गए कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार दिए गए थे और बहुसंख्यकों के अधिकार कम हो गए। बहुसंख्यकों को धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया गया कि आप सहनशील रहो, धैर्य रखो। दुनिया के अंदर इस देश में अल्पसंख्यकों के जितने अधिकार हैं, उतने किसी और देश में नहीं हैं।

कांग्रेस पार्टी ने पाप किया, जब देश में ?राम सेतु? प्रोजेक्ट आया, ?राम सेतु? प्रोजेक्ट के समय कांग्रेस की सरकार ने देश के सुप्रीम कोर्ट में एक वसीयतनामा दिया, एक शपथ पत्र दिया । उस शपथ-पत्र में कहा गया कि इस देश के अंदर भगवान राम पैदा ही नहीं हुए । भगवान राम तो काल्पनिक व्यक्ति हैं । न केवल भगवान राम, बल्कि भगवान कृष्ण भी काल्पनिक हैं । इसीलिए हमारे स्कूलों व कॉलेजों में हमारे बच्चों को कभी भी भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ाया गया । जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस ने एक और गलती की । जातियों के नाम पर समाज का बंटवारा कर दिया गया । बांटो और राज करो । अंग्रेजों की नीति को कांग्रेस ने अपनाया और अलग-अलग नामों पर जैसा कि मैंने कहा- बहुसंख्यकों व अल्पसंख्यकों के खेमे में बांट दिया गया । अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से अधिकार दिए गए, ये उन लोगों को एक प्रकार से एक इंसेंटिव था कि अल्पसंख्यक बनो और अधिकारों को इंजॉय करो । हमारे हिंदू समाज के अंदर कभी बौद्ध व जैन अलग हो गए, तो कभी सिख पंथ वालों ने कहा कि हमको भी अलग करो । यहां तक हुआ कि हिंदूवादी संगठन राम-कृष्ण मठ जैसे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि हमको भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए । मुझे लगता है कि इससे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता है । धर्म तो जोड़ने की बात करता है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने धर्म को बांटने का काम किया । ?धर्मो धार्यते प्रजा? ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि समाज को जोड़ने का जो काम करता है, उसका नाम धर्म है, लेकिन उसको हमने पूरी तरह से इस देश से निकालने का काम किया ।

?अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ।?

ऐसा भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं । जो बंटे हुए में भी एक रूप देखता है, उसे हम सात्विक व उत्तम ज्ञान कहते हैं । वर्ष 1976 में हमारे देश के संविधान के प्रिएंबल यानी प्रस्तावना में सेकुलरिज्म नामक नया शब्द जोड़ा गया । उसका परिणाम हमारे सामने है । कांग्रेस ने जिस प्रकार से धर्म को

मारा, धर्म और संस्कृति का जिस प्रकार से उपहास व मजाक उड़ाया, जिस प्रकार से भगवान राम और भगवान कृष्ण जी को काल्पनिक कहा, इसी वजह से कांग्रेस की पुण्य तिथि भी नजदीक आती जा रही है । वह समय अब दूर नहीं है, जब हम कांग्रेस की पुण्य तिथि मनाएंगे ।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुन: धर्म की स्थापना की । धर्मदंड के साथ इस धर्म चक्र के नीचे महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस देश के अंदर, सदन के अंदर धर्म की पुन: स्थापना की । महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश में मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं, उनका एक बहुत बड़ा दिग्दर्शन है तथा भविष्य के लिए एक ऊर्जादायी प्रेरणा भी है । देश की आजादी के 75वें वर्ष को हमने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया । ?मेरी माटी, मेरा देश? का अभियान चला । ?हर-घर तिरंगा? अभियान चला और देश भर के हर गांव से मुट्ठी भर मिट्टी लेकर, हर घर से मुट्ठी भर चावल लेकर अमृत कलश दिल्ली के अंदर लाए गए । वीरों के नाम पर लाखों शिलापट लिखे गए । अमृत सरोवर तथा अमृत वाटिकाएं बनाई गईं । दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई । अंडमान में रॉस आईलैंड का नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर रखा गया । अंडमान के 21 द्वीपों का नाम इस देश के परम् वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया । गुरु गोविंद जी के शहजादों के नाम पर वीर बाल दिवस की घोषणा की गई । देश के लिए शहीद हुए उन हजारों बलिदानी, गुमनाम वीरों को याद किया गया । उन शहीदों को याद किया गया, जो यह गुनगुनाते रहते थे-

?इस भारतवर्ष में सौ बार मेरा जन्म हो ।

कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो॥?

इसके बावजूद ऐसे शहीदों के साथ क्या हुआ? मोदी जी के आने से पहले इस देश में इन शहीदों की किस प्रकार से उपेक्षा की गई थी, इनके

परिवारों की किस प्रकार से उपेक्षा की गई थी । किसी ने बहुत अच्छा लिखा है ?

?वीराने थीं कब्रें उनकी, जिनके खून से जलते थे चिराग-ए-वतन ।

जगमगाते थे मकबरे उनके, जो बेचते थे शहीदों के कफन॥?

यह सब इस देश में हो रहा था । मोदी जी के आने से पहले इन वीरों को, इनके बलिदानों को, इन शहीदों को कोई याद नहीं करता था ।

सभापति महोदय, यह श्रेय भी देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है कि 70-75 वर्षों के बाद पुलिस में शहीद होने वालों के नाम पर एक राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाये गए और फौज में शहीद होने वालों के नाम पर राष्ट्रीय समर स्मारक बना ।

सभापति महोदय, इसी अमृत महोत्सव के कालखंड में यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 2023 को इस देश के 140 करोड़ नागरिकों को पंच प्रण की एक शपथ दिलवाई थी । उस पंच प्रण में उन्होंने कहा था कि हम इस देश को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और पूर्ण रूप से विकसित बनाएंगे । हम लोग दासता के सारे चिह्न खत्म करेंगे । तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्रण की शपथ ली थी । मोदी सरकार ने लगभग सवा सौ-डेढ़ सौ वर्षों के बाद पुराने औपनिवेशिक अपराधिक कानून, जिसको हम पुलिस कानून कहते हैं, उनको खत्म करके जिस प्रकार से वहां पर जो उनकी दंड के पहले दंड की प्राथमिकता थी, न्याय की प्राथमिकता देते हुए इस देश से दासता के एक बहुत बड़े चिह्न को उन्होंने खत्म कर दिया ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर भारतीय ज्ञान परम्परा को हमारे सिलेबस में, करिकुलम में देने के लिए प्राथमिकता दी गई । हम अपनी संस्कृति के महानायकों को, भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण, भगवान शिव, जो करोड़ों लोगों के आस्था

के प्रतीक हैं, इस देश के अंदर मूर्त रूप दिया गया । भगवान राम का मंदिर बना और रामलला अयोध्या के अंदर विराजमान हो गए ।

सभापति महोदय, अब समय आ गया है कि दासता के सभी चिह्नों को इस देश से खत्म किया जाए ।

माननीय सभापति : समय सीमित है ।

डॉ. सत्यपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं सीमित ही कर रहा हूं ।

माननीय सभापति : आप कृपया ध्यान रखिएगा कि समय सीमित है ।

डॉ. सत्यपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, मैं इस सम्माननीय सदन से भी निवेदन करना चाहता हूं और भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारे कानून मंत्री भी यहां पर बैठे हैं, पुराने वाले और वर्तमान के कानून भी यहां पर बैठे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक दासता का चिह्न भारतीय संविधान में है । भारतीय संविधान का पहला ही आर्टिकल यह कहता है - ?India, that is Bharat?, यह इंडिया भी खत्म होना चाहिए । इस देश का नाम भारत है । भारत का नाम है, जिसमें ज्ञान व्याप्त है । यह महान नाम है, इसलिए इसको भी बदलने की जरूरत है । ऐसा देश, दुनिया में कहते हैं कि विश्व भर में अगर सबसे अच्छा कोई देश है तो वह भारत है । इसलिए तो कहते थे-
?गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।?

देवता लोग भी लालायित हैं कि इस भारत भूमि में हमारा जन्म हो, इसलिए हमें इसका नाम इंडिया से हटाकर पुन: भारत कर देना चाहिए ।

सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मोदी जी की गारंटी की गारंटी है । जो माननीय मोदी जी की गारंटी है, उसकी गारंटी की गारंटी महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है । हम सब लोग मिलकर सबका साथ लेकर, सबके प्रयास के साथ और सबका विश्वास लेकर देश की

गरीबी खत्म करेंगे, देश की गंदगी खत्म करेंगे, देश से आतंक और आतंकवाद खत्म करेंगे, देश से सम्प्रदायवाद और जातिवाद खत्म करेंगे । वर्ष 2047 तक, जैसा आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हम इस देश को आत्मनिर्भर, पूर्ण रूप से विकसित और विश्व मित्र बनाते हुए इसका जो पुराना गौरव है, भारत विश्व गुरु था, हम पुन: इसको विश्व गुरु बनाएंगे । लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद अयोध्या के अंदर भव्य राम मन्दिर बन गया । यह राम मन्दिर केवल पत्थरों और कंक्रीट का नहीं है, यह इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है । यह इस देश के करोड़ों लोगों की, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, उनकी आस्था का यह साकार रूप है और यह उनकी ऊर्जा का भी साकार रूप है । इसीलिए, यह मन्दिर हमें सतत प्रेरणा देता रहेगा और हमें तब तक आराम से नहीं बैठने देगा, जब तक हम इस देश के अंदर, इस भारत भूमि के अंदर पुन: राम राज्य की स्थापना नहीं कर लेते । आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी कहते थे कि राम राज्य की स्थापना करेंगे । हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी भी महर्षि दयानन्द जी के आदर्शों को लेकर, महात्मा गांधी जी के आदर्शों को लेकर और पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों को लेकर इस देश के अंदर पुन: राम राज्य की स्थापना के लिए सतत संघर्षशील और संकल्पित हैं । जिस प्रकार से मैंने कहा था एक ऐस राम राज्य, हमें मालूम होना चाहिए, मैं यह बात सम्माननीय सदस्यों के सामने भी रखना चाहता हूं, ऐसा राम राज्य जिसके अंदर महागोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था?

दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज नहिं काहुहि ब्यापा ।

उस राम राज्य के अंदर किसी भी प्रकार के दु:ख नहीं थे, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी, कोई दैवीय प्रकोप नहीं थे ।

?*सब* जन करही *परस्पर प्रीति?*

सब लोग आपस में प्रेम और प्रीति से रहते थे

?चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती?

वेदों के बताए हुए रास्ते पर चलते थे । श्रुति की रीति पर चलते थे । पुनः हम लोगों के सामने ये एक बहुत बड़ा संकल्प है । जैसे राम राज्य में होता था -

?यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यन्चौ चरतः सह, तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना ।?

जिस देश और जिस समाज के अंदर छात्र और ज्ञान शक्ति दोनों एक साथ चलती हैं, वह देश स्वर्ग समान बनता है । हम सभी लोग ऐसे देश बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से अपने वक्तव्य को विराम देने से पहले, अपने संसदीय क्षेत्र बागपत का उदाहरण जरूर देना चाहता हूं । मेरा बागपत इस दिल्ली एनसीआर का भाग होते हुए भी, 15 किलोमीटर दूर होते हुए भी विकास से 1,500 किलोमीटर दूर था । वह दशकों तक पिछड़ापन झेल रहा था ।?(व्यवधान)

माननीय अटल जी एक बार हमारे बागपत गए थे । वहां पर उन्होंने विशिष्ट अंदाज में कहा था कि मैंने देश कि विभिन्न भागों में सड़कों में गड्ढे तो देखे हैं, लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देख रहा हूं । हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक वीडियो है, मुझे उस वीडियो को देखने का मौका मिला है । उन्होंने कहा था कि मैं सड़क के रास्ते दिल्ली से सहारनपुर जा रहा था । मुझे कार में नींद आ गई । जब मेरे पेट में धक्के लगने लगे और मेरी कमर में दर्द होना शुरू हुआ, तब मेरी नींद खुली, तो मैंने पूछा कि क्या बागपत आ गया है? बागपत ऐसा था ।

उस बागपत में 29 मार्च, 2014 को आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी आए थे । तब उन्होंने लोगों से यह अपील की थी कि यहां पर कमल का फूल खिलाओ

और मैं आपको विकास और समृद्धि का रास्ता दूंगा । पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके आशीर्वाद से मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है । पहले जब हम कहते थे कि गड्ढों में सड़क हैं, आज वहां 5-5 नेशनल हाइवेज़ हैं । वहां मेडिकल कॉलेजेज़ हैं, सेन्ट्रल स्कूल्स हैं, सीजीएचएस हॉस्पिटल है । वहां पर न जाने क्या-क्या है ।? (व्यवधान)

सभापति जी, मैं केवल एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा । मेरे पास एक छोटी-सी कविता है । मैं इस सम्मानित सदन के सामने उसको पढ़ना चाहता हूं ।

माननीय सभापति : क्या कविता आपने खुद लिखी है?

डॉ. सत्यपाल सिंह : महोदय, जी हां, मैंने लिखी है । इसीलिए मैं कह रहा हूं ।

बच्चा-बच्चा गुनगुनाता है,

सबको सुनाना चाहता है,

विकसित भारत मोदी की गारंटी है,

सुरक्षित भारत मोदी की गारंटी है,

किसानों का कल्याण मोदी की गारंटी है,

गरीबों का उत्थान मोदी की गारंटी है,

युवाओं को रोजगार मोदी की गारंटी है,

महिलाओं का सम्मान मोदी की गारंटी है ।

जहां मोदी है, वहां ऋद्धि, सिद्धि और वृद्धि है,

चारों ओर खुशहाली, सुख और समृद्धि है ।

मैं फिर वही दोहराता हूं,

बहरों को सुनाना चाहता हूं,

सोतों को जगाना चाहता हूं,

बिछड़ों को मिलाना चाहता हूं,

यही समय है, सही समय है,

भारत का अनमोल समय है,

यह समय है, जुड़ जाने का,

मोदी के साथ चलते जाने का ।

____

-

12.39 hrs

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन जी ।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Thank you, Chairperson, Sir, for giving this opportunity to speak on a very pertinent issue faced by our country currently. The policy address by the hon. President has not mentioned the basic issue faced by India today.

Our country is the biggest democratic and secular country in the world. However, today our Constitutional rights and freedom are being denied. Even in the Parliament, there was a mass suspension of the hon. MPs after which various important Bills were passed. This shows how much the decency of Parliament has degenerated today.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to highlight the fact that if you undertake a critical analysis of the achievements of past ten years as stated by the hon. President of India, you will notice that all of these are a result of the work of previous Governments. From women?s empowerment to revitalizing urban infrastructure and civic amenities, the current Union Government takes credit for everything. In fact, even the Women?s Reservation Bill which the Government continuously boasts about has its roots in the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts enacted by Shri Rajiv Gandhi?s and Shri P.V. Narasimha Rao?s Governments in 1992. Even the Kerala Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2009 and Kerala Municipality (Amendment) Act, 2009 established reserving 50 per cent seats in local bodies and panchayats for women since 2009.

Similarly, the widely publicized Pradhan Mantri Awas Yojana? Urban and the AMRUT Scheme was basically a reframing of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission launched much before in 2005. It is another big lie of the Government.

Hon. Chairperson, Sir, upon our country?s Independence, two words, among others, were enshrined in the Preamble of the Constitution and they are Socialist and Secular. It is my firm opinion that the current Union Government either does not understand the

meaning of these terms or is blatantly ignoring the Constitution of the country. I do not know what is happening.

India is a Socialist Republic, one that should be dedicated to the welfare of the marginalised without only serving the interests of the one per cent. But the Union Government seems to cater to the one per cent that is crony capitalists like *?* and such other people.

माननीय सभापति : नो, नो, नाम मत लीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, let me complete.

माननीय सभापति : कोई नाम मत लीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRI BENNY BEHANAN: The Union Government is also proposing disinvestment in the steel sector PSUs which have existed almost since the Independence of the country and have been foundational to the country. Now, the Cabinet Committee on Economic Affairs has given an in-principal approval for the strategic disinvestment of four CPSEs, Subsidiaries and Units under the Ministry of Steel including that of the Steel Authority of India. In fact, the state of our economy is so disastrous at present that the BJP?s own Party members have identified this.

Dr. Subramanian Swamy has said, ?If you look at the GDP growth rate since 2014, it has been falling consistently. The claims of the Government are nonsense?. These are the words of Dr.

Subramanian Swamy. Starting from 2022 to 2023, for three consecutive years, the Budget allocated for agricultural sector has been decreasing. When compared to 2022-23, there is a difference of Rs. 1 lakh crore in the Budget allocated this year. When considering the actual expenses in all agriculture-related sectors, the difference adds up to 22.3 per cent.

Hon. Chairperson, I hear the Prime Minister consistently speaking about ?Modi ji ki Guarantee?. We can see it on TV and we can listen it on AIR. But where is the guarantee against unemployment? Even among the so-called skilled workers, the Labour Force Participation Rate (LFPR) according to the usual status for the graduates (15 years and above), it is only 64.5 per cent, implying that a vast section of educated youth is still unemployed. Where is the guarantee for that? Where is the Modi ji?s guarantee for the people of Manipur, where a supreme Committee appointed by the hon. Supreme Court reported that among the 175 bodies in the mortuaries killed during the clashes, 88 bodies still remain unclaimed?

As I stated previously, the word ?secular? also seems to be unfamiliar to the Ruling Party. While India?s greatest strength lies in the absence of a singular ethnic or social identity defining the nation, it appears that the current Government is leaning towards portraying the country, which is home to diverse religions, as a ?Hindu Rashtra?, as evidenced by the recent Ram Mandir Ceremony celebrations.

Sir, our country is heading towards becoming a theocracy today and this is a point of no return. This is in stark contrast to the

glorious values of secularism enshrined in our Constitution. Upon the Independence of our country, the one primary divergence that we had from our neighboring country Pakistan was that we did not choose one religion to be the state religion.

Sir, I am very afraid that our country is heading towards a theocracy by interlinking state and religion. Our Prime Minister, who is a State Representative, was recently a part of the 'Pran Pratishta' ceremony of the Ram Mandir in Ayodhya, clearly violating the idea of maintaining a principled distance between State and religion, mandated by secularism.

Unfortunately, the Union Government's actions are currently only geared towards electoral gains by creating a society divided across religious lines. And while this 'drama' is ongoing, important issues like economic turmoil, the Manipur Conflict, poor infrastructure, and unemployment are being put on the back burner, rarely featuring in the discussions of this House.

A Prime Minister is the head of our country. But, unfortunately, in a secular country like India, the Prime Minister also acts as a religious head. Politics and religion should never be intertwined and our Constitution has clearly drawn a line between them.

When the Prime Minister of India simultaneously becomes a *Pujari*, power and religion is becoming one. This is a threat for a country like India, which has secularism and pluralism. The love for our country should not be injected through religion. Mahatma Gandhi has set an example for this. Gandhiji has never used religion as a tool

to inject patriotism in Indians during the freedom fight. Instead, he symbolised Charkha and salt. According to Gandhiji, religion, God and nation are synonyms for values and public services. Never did he pretend to be a saint to please any religion. Nor did he grow his beard or wear a *Kaavi*. He always wore the dress of the poor. Gandhiji symbolises secularism and pluralism and this is what we always kept in our hearts.

Sir, before closing, I leave a thought with my fellow hon. Parliamentarians. India was once the epitome of a democratic country where secular values were respected and people's grievances were taken note of seriously. If issues existed, then people-centric schemes were brought in place to address them. Today our democratic values are being eroded with some even saying that the word 'Secular' will be removed from our Constitution. People's grievances are suppressed by PR stunts, and people-centric schemes are only renamed, thereby never addressing the emerging nature of issues.

So, I urge my fellow Parliamentarians to take actions wisely in order to prevent the further democratic backsliding of our country. I thank the hon. Chairman for this opportunity to present my views.

माननीय सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समय का आवंटन आनुपातिक होता है, कृपया उसका ध्यान रखें और पांच मिनट में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करें ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया । यह परम्परा 31 जनवरी, 1950 से शुरू हुई । इसके तहत पूरा देश सरकार की पहलों, नीतियों एवं योजनाओं से भली-भांति परिचित होता है, जो बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान के आर्टिकल 79 की सफलता है ।

महोदय, सबसे पहले मैं आज अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बिहार एवं बिहार की पूरी जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया ।

महोदय, बिहार राज्य गौतम बुद्ध की धरती है और सम्राट अशोक के नेतृत्व में मगध सम्राज्य ने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया । बिहार हमेशा से राजनीति में अग्रणी रहा है । यदि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार द्वारा बिहार को स्पेशल फाइनैंशियल असिस्टेंस दी जाती है तो बिहार का सर्वांगीण विकास होगा ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी का एक कथन उद्धृत कर रहा हूँ । उन्होंने कहा है कि Bihar has unlimited potentiality. It can invigorate the entire nation. India will be fully developed only when the eastern part of India develops. आज भारत सरकार ने सबके विकास के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं । साथ ही साथ बिहार में हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ, समावेशी विकास के साथ आत्मनिर्भर बिहार विजन पर कार्य कर रहे हैं ।

मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए सरकार से निवेदन करता हूँ कि आउटसोर्सिंग जॉब में भी नियम बनाकर रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि

एससी / एसटी तथा ओबीसी को तेजी से और आगे बढ़ाया जा सके और ये समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें ।

सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के लिए 4 लाख 78 हजार 751 करोड़ रुपये रिकमेंड किए गए हैं । 35 हजार 577 करोड़ रुपये लोकल गवर्नमेंट के लिए रिमेंड किए गए हैं । 7 हजार 824 करोड़ रुपये डिजास्टर के लिए रिकमेंड किए गए हैं । 3 हजार 223 करोड़ रुपये हेल्थ के लिए रिकमेंड किए गए हैं । 1 हजार 694 करोड़ रुपये रोड्स के लिए रिकमेंड किए गए हैं । 960 करोड़ रुपये ज्यूडिशियरी के लिए रिकमेंड किए गए हैं । मेरा आग्रह है कि बाकी अनुदान को भी यथाशीघ्र प्रदान किया जाए, ताकि इससे निश्चित ही देश का सर्वांगीण विकास हो ।

सभापति महोदय, बिहार सब्जियों के उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है और फलों के उत्पादन में आठवें स्थान पर है । बिहार की 74 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है । बिहार में न्याय के साथ विकास के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ?सात निश्चय ? 1? के बाद ? सात निश्चय ? 2? का प्रथम चरण सफलतापूर्वक चला रहे हैं और उन्होंने दूसरे चरण की शुरुआत भी काफी जोश के साथ शुरू कर दी है, ताकि आर्थिक दृष्टि से बिहार की प्रगति हो ।

सभापति महोदय, जी-20 और पी-20 की सफलता हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी भारतीयों की सफलता है, क्योंकि हमने अपने मेहमानों की सेवा ?अतिथि देवो भव:? के भाव से तथा उसकी परंपरा के अनुसार की और हम सब उसमें सफल हुए । आई.एम.एफ. के डेटा के अनुसार भारत का जीडीपी 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और विश्व में पांचवें स्थान पर है । दी सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 43 करोड़ मजदूर हैं और 12 करोड़

दिहाड़ी मजदूर हैं । इनके वेलफेयर के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है ।

सभापति महोदय, यूनाइटेड नेशन्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक एक्स्ट्रीम पावर्टी को दूर करने का लक्ष्य रखा है । साथ ही निश्चित ही यह उम्मीद है कि उसके पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह गोल पूरा कर लिया जाएगा । देश में बॉटम-हाफ पापुलेशन देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । उसके लिए जरूरी है कि वे ज्यादा अर्न करें, काफी ज्यादा खर्च करें और परिणामस्वरूप प्रोडक्शन बढ़े, रोजगार मिले तथा देश की ग्रोथ भी बढ़े । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि बॉटम-हाफ पापुलेशन पर इनवेस्टमेंट किया जाए । मेरा यह सुझाव है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टीसिपेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान में यह कम है । अगर हम महिलाओं को काम में मौका दें तो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अनुसार भारत 1.5 प्रतिशत पॉइंट्स की ग्रोथ कर सकता है ।

सभापति महोदय, यदि हमारी अर्थव्यवस्था डॉलर में वर्ष 2027 तक 8.7 परसेंट की वृद्धि दर बनाकर रखे तो वर्ष 2023 में प्रकाशित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च के अनुसार इंडियन इकोनॉमी विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर सकती है, जिसके लिए सरकार बहुत ही सुन्दर प्रयास भी कर रही है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): सभापति महोदय, परसों जब प्रेसिडेंट अपना स्पीच दे रही थीं कि मेरी गवर्नमेंट ने यह-यह किया और उस पर जितनी तालियां बज रही थीं, उसमें प्रेसिडेंट की बात कम सुनाई दे रही थी

। यह अच्छी बात है, लेकिन प्रेसिडेंट का एड्रेस सिलेबस में था और ताली बजाना भी सिलेबस में था । मैं अभी सिलेबस के बाहर का बोलना चाहती हूँ ।

Hon. President Madam said: ?According to NITI Aayog, in the last one decade of my Government, about 25 crore countrymen have been lifted out of poverty.? This estimation by NITI Aayog, based on NMPI, invites more questions than clarity. NITI Aayog has released NFHS-5 data for 2019 and 2021. It is also important to note that the NFHS Survey was stopped after data collection was stopped in 22 States due to COVID. Since the survey has already been stopped, perhaps, the projection of the data has been taken by using data from non-COVID years and the same non-COVID rates of improvement has been extended to 2022 and 2023. While consumption expenditure surveys were not done for eight years from 2014 to 2022, it raises valid questions on the purpose of making the NMPI as the poverty indicator for India. Thus, the question is whether the assumption of 25 crore is justified and credible or not.

My second point is that Madam President said: ?Today, crores of citizens are working in MSMEs.? What are the ground realities? According to Mint Street Memo 13, August 17, 2018, the study paper from the Reserve Bank of India, the MSME sector has witnessed two major recent shocks, namely, demonetisation and GST. As per the Udyam Registration Portal, the total number of MSMEs shut down between July 1, 2020 and July 18, 2023, stood at 24,839, of which, during the fiscal year 2023, 5152 units shut down their operations.

My third point is that in the last decade 16 AIIMS have been established but none of them is fully functional in the list of the

Government as per the Press release of 19th December, 2023 of the Ministry of Health and Family Welfare. In the past, six AIIMS became functional within a period of nine years in spite of the fact that there were different political parties in Government.

The next point is that the Government ordered Aadhaar-based payment system for MGNREGA holders. The TRAI input indicates that as on October 2021, in rural India where the job card holders of MGNREGA reside, only 29.3 per cent broadband entry was there. In fact, the police and SBI are advising public at such places to lock Aadhaar to prevent hacking from hackers.

13.00 hrs

Sir, what remain absent in Madam President?s Address are as follows. There are issues like unemployment, which is a burning issue, the high inflation, the average commoner compromising with many essential needs, safety and security of girl child, MSP for farmers, and Manipur issue where we saw devastated lives of girl children and commoners. The reality of suffering of ordinary and poor people while traveling by trains across India has been hidden under the hype of flagging Vande Bharat. Madam President said that her Government believes in following pillars towards the journey of development ? youth power, women power, farmers and poor. However, the constructed optics merely establish that the majority of youth, women, farmers, and poor are the confirmed victims in reality.

As far as the Ujjwala Yojana is concerned, out of 95.9 million PMUY beneficiaries, 11.8 million did not get even a single LPG

bottle during the last financial year as has been stated by State Minister of Petroleum and Natural Gas, Shri Rameswar Teli, in a statement given on the Floor of Rajya Sabha in 2023. आप लोग कह रहे थे कि लोगों को चूल्हे से गैस पर लेकर आए । यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह जानना है कि कितने लोगों ने गैस सिलेंडर्स रीफिल किए हैं? क्योंकि आप जितने लोगों को गैस पर लेकर आए थे, आपने उतने ही लोगों को वापस चूल्हे की ओर भेज दिया है । The CAG Audit Report in 2019 revealed the cylinder scam in PMUY. Thereafter, there were no further reports of CAG on PMUY.

मैं कैग रिपोर्ट के बारे में बोलना चाहती हूं । कैग रिपोर्ट के हिसाब से आप पश्चिम बंगाल में सौ दिन का पैसा नहीं दे रहे हैं । अगर आप कैग रिपोर्ट के अनुसार यह नहीं दे रहे हैं तो हम लोगों को यह जानने का हक है कि नेशनल हाइवे की कैग रिपोर्ट क्या है, आयुष्मान भारत की कैग रिपोर्ट क्या है? देश के कौन-कौन से स्टेट में आप कैग रिपोर्ट के हिसाब से पैसा दे रहे हैं और कौन-कौन से स्टेट में नहीं दे रहे हैं? सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं दे रहे हैं या और भी कोई स्टेट है, जिसके साथ आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट एविएशन है । आप लोग बोल रहे हैं कि चप्पल के साथ फ्लाइट में चढ़े । यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन मिनिस्टर या सरकार को यह पता है कि फ्लाइट के फेयर अभी कितने पहुंच गए हैं? डोमेस्टिक फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में मिनिमम 30 हजार रुपये, 29 हजार रुपये में टिकट मिलता है । इस पर भी सरकार चुप है और कुछ नहीं बोल रही है ।

Next, Madam President said:

?The country remembered unsung freedom fighters.?

यह याद तो जरूर रखेंगे । लेकिन इसके साथ यह भी याद रखेंगे कि एक ऐसी सरकार आई है, जो सिर्फ किसी एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर चीज के बारे में बात करती है । पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक

करते हैं और हर स्पीच में वही बोलते हैं । सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि पहले जो सरकार थी, सब गलत है, सब गलत है । इसको मिटाने के लिए आप लोग नाम बदल रहे हैं, स्टेडियम बदल रहे हैं, पार्लियामेंट बदल रहे हैं । दुनिया यह याद तो रखेगी, लेकिन इसके साथ आप भी यह याद रखें कि ऐसा कोई आएगा, जो आपको भी मिटा देगा ।

Then, Madam President talked about ?Nari Shakti?.दो हिस्टोरिक ऑकेजन्स के बारे में हमारी प्रेजीडेंट ने कहा है? एक न्यू पार्लियामेंट और दूसरा राम मंदिर । अनफॉर्च्युनेटली दोनों में ही उनको इनवाइट नहीं किया गया था । यह नारी शक्ति है । इंडिया सेवन प्राउड डॉटर्स ? जो सेक्सुअल हैरासमेंट की कंप्लेंट लेकर गई थी, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद सात दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी । यह नारी शक्ति है । फिर आप लोगों ने उस प्लेयर के साथ, उस स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसा कर किया कि उसकी जिंदगी भर की कमाई, जो मैडल था, उसने उसे वापस दे दिया और स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले ली । यह नारी शक्ति है । As per the NCRB records, in 2013 there were 3,09,546 cases of crimes against women. In 2022, it has reached 4,45,256 cases, which shows an increase of 30.48 per cent. यह नारी शक्ति है । आप बोल रहे हैं कि जहां पर राम मंदिर है, वहां पर आप राम जी, राम जी कर रहे हैं । वह तो बहुत अच्छी बात है । हर जगह पर राम जी हैं । यह अलग बात है कि राम जी के ज्यादा फोटो हैं या मोदी जी के ज्यादा फोटो हैं । लेकिन फिर भी हर जगह पर राम जी सीता माता कहां हैं? यह नारी शक्ति है । कुछ पुरुष शक्ति की बात करें । जैसे बिलकिस बानो ? बिलकिस बानो केस में जो रेपिस्ट थे, वे बाहर आए । उनका दो बार ऑनर किया, एक जेल से बाहर निकालने के बाद माला पहनाई और दूसरा गांव में जाने के टाइम मतलब आप रेपिस्ट को रेस्पेक्ट दे रहे हैं । यह पुरुष शक्ति है ।

हमारी पार्लियामेंट में दो लड़के आ गए थे । जिस एमपी की रिकमंडेशन से वे आए थे, उस एमपी की किसी ने बात नहीं की और न ही आकर वह कुछ बोले तथा न ही उनको कुछ बोलने दिया गया । जब हम उसके बारे में पूछ रहे थे कि क्यों हुआ, क्या हुआ तब हम लोगों को सस्पेंड किया । यह पुरुष शक्ति है ।

साक्षी मलिक ने जिस पुरुष एमपी के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट की कम्पलेंट की थी, साक्षी मलिक का स्पोर्ट्स कैरियर खत्म हुआ, लेकिन उस एमपी की पावर और भी बढ़ गई । यह पुरुष शक्ति है । मैं इस बात पर अपनी बात खत्म करूंगी कि बीजेपी वाले चीख-चीख कर बोल रहे हैं कि मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं । यह बहुत अच्छी बात है । एक इंसान इतना पावरफुल है कि भगवान को ला सकता है । यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन देश यह जानना चाहता है कि जिसकी इतनी पावर है कि वह भगवान को लाया है, तो क्या वह छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकता है? छोटा सा इंसान मेहुल चोकसी को नहीं ला सकता है, छोटा सा इंसान विजय माल्या को नहीं ला सकता है? छोटा सा काम ? जो हमारा कालाधन है, उसे नहीं ला सकते हैं? देशवासियों का यह क्वेश्चन है । थैंक यू ।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पूरे देश के पिछले दस सालों के विकास का ब्यौरा दिया गया है और इससे पूरे देश में एक अलग माहौल बना है । हम देखते हैं कि चार पिल्लर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से प्रदर्शित होते हैं । पहला हमारी युवा शक्ति कैसे मजबूत बने और उसे कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से प्रदर्शित होता है । दूसरा महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण हो और तीसरा किसान तथा चौथा गरीब का विकास है

। यदि हम देखें तो चार ऐसे पिल्लर हैं, जिनके लिए मोदी जी ने पिछले दस सालों में जबरदस्त नींव रखी है जो कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे । प्रधान मंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि, उनका विजन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में साफ-साफ परिलक्षित होता है । जहां तक युवा शक्ति की बात है, युवाओं के लिए नौकरियाँ, उनके लिए रोजगार, चाहे डायरेक्ट वे में हों या इनडायरेक्ट वे में हों, चाहे सरकारी नौकरियां हों, लगातार नौकरियों की संख्या में वृद्धि हुई है । आप युवाओं की खेल में प्रगति भी देख सकते हैं । चाहे ओलम्पिक खेलों में युवाओं के प्रदर्शन को देखें या एशियाई खेलों में देखें, करीब सौ पदक हमारे युवा एशियाई खेलों में लेकर आए हैं क्योंकि मोदी जी हमेशा युवाओं को प्रोत्साहन देते रहते हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद खेल महाकुम्भ का कार्यक्रम अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी के सांसद खेल महाकुम्भ के रूप में अलग-अलग जगहों पर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं । हम अपेक्षा करते हैं कि सभी सांसद ऐसा करें लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने यह किया है ।

सभापति जी, मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे आग्रह पर वे मेरे संसदीय क्षेत्र में आए । जहां युवाओं की बात आती है तो वे हमेशा युवाओं के लिए खड़े रहते हैं और हमेशा युवाओं के साथ जुड़े रहते हैं । वे मेरे आग्रह पर मेरे संसदीय क्षेत्र में हाल ही में तीन फरवरी को जब सांसद खेल महाकुम्भ का आयोजन हुआ, तब प्रधान मंत्री जी आए । लगभग 1100 स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के लड़के-लड़कियों ने उसमें भाग लिया । करीब दो लाख बच्चों को प्रधान मंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ । युवाओं में उत्साहवर्द्धन हुआ । आप सोच सकते हैं कि युवाओं के लिए अपना अमूल्य समय निकाल कर हमेशा प्रधान मंत्री जी उनको प्रोत्साहन देने के लिए खड़े रहते हैं । मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हूं, जहां युवा रोजगार के लिए पीड़ा भुगत रहे थे । राजस्थान में जिस प्रकार से 18 बार पेपर

लीक हुआ और परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई तो मोदी जी के नेतृत्व में आज ही पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, 2024 करीब एक घंटे पहले पार्लियामेंट में ले हुआ । इसके लिए मैं और पूरे देश के युवा प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम जिस प्रकार से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुईं, युवा निराश हुए और उन्हें कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पिछले पांच साल में रोजगार नहीं मिला । ऐसा कानून लाने से पूरे देश के युवाओं को यह विश्वास हो गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार यह बिल लेकर आई है, तो उनका भविष्य, उनके रोजगार का सपना सुरक्षित रहेगा और उनके साथ किसी तरह की बदमाशी और धोखाधड़ी नहीं होगी ।

सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा कि लम्बे समय से हमारे संस्कार में यह घुस गया था और मातृभाषा में पढ़ाई न होने की वजह से खास कर गांव के गरीब लोग चाहे एससी हों या एसटी हों, चाहे ओबीसी हों, ये हमेशा आगे आने से वंचित रह जाते थे । उनको आगे लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चाहे वह कानून की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, आई.आई.टी. की पढ़ाई हो, ये अब उनकी मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी । यह अपने आप में देश के लिए बहुत अच्छा है । हमारे वे गरीब छात्र, जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं, शिक्षा से वंचित रहते हैं, अब उनको इसमें पढ़ने का मौका मिलेगा और वे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करके देश का नाम और परिवार का नाम रोशन करेंगे ।

इतना ही नहीं, युवाओं के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी को इतनी चिंता है कि उन्हें गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले । इसके लिए करीब 14,000 पी.एम. श्री विद्यालय खोले जा रहे हैं । इसलिए आने वाले समय में हमारे दूरदराज के गांवों के जो युवा हैं, जो गरीब परिवारों से हैं, उन्हें भी आगे आने का मौका मिलेगा । हम देखते हैं कि चाहे वह मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे आई.आई.टी. की शिक्षा हो, यहां पर कॉलेजेज और इंस्टीट्यूट्स कम होने की वज़ह से

हमारे विद्यार्थी बाहर जाते थे । मेडिकल कॉलेज, जो पहले 387 थे, लेकिन पिछले दस सालों से प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब देश में मेडिकल कॉलेजेज़ 660 हो गए हैं । यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है । जहां तक आई.आई.टीज़. की बात है तो वर्ष 2014 तक मात्र 6 आई.आई.टीज़. हुआ करती थीं, लेकिन वर्ष 2014 के बाद पिछले दस सालों से माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुल 23 आई.आई.टीज़. हो गए हैं । वर्ष 2014 तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) की संख्या सिर्फ 7 थी, लेकिन पिछले दस सालों में यह बढ़ कर 22 हो गयी । यही नहीं, पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संख्या 13 हुआ करती थी, वह बढ़ कर पिछले दस सालों में करीब 20 हुई है ।

मैं बताना चाहूंगा कि रिसर्च का क्षेत्र एक बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र भी है । हम हर काम दूसरे देशों की रिसर्च के आधार पर करते हैं । अब माननीय मोदी जी ने रिसर्च में जो रिकॉर्ड बजट का एलोकेशन किया है, वह अपने आप में यह प्रदर्शित करता है कि आने वाले समय में भारत का युवा अब दूसरे देशों के रिसर्च को न मानकर, अपने यहां ही रिसर्च करके पूरे विश्व को देगा । इसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो बजट का एलोकेशन किया है, यह उनकी इसके प्रति सेंसिटीविटी को प्रदर्शित करता है । इसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी गठित किया गया है । अगर आप देखें तो यह पाएंगे कि पिछले दस सालों में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और इसे पोषण मिला है । चाहे हमारे एस.सी. हो, एस.टी. हो, चाहे ओबीसी के छात्र हों, इनमें चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, इनके नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है ।

अब युवाओं के लिए एक ?मेरा युवा भारत? नामक संगठन की शुरुआत हुई है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह विकसित भारत की नींव है और उसके लिए यह एक आधारभूत ढाँचे की तरह काम करेगा ।

इसके लिए एक भावना उत्पन्न करना मोदी जी की सोच है । कर्तव्य और सेवा की भावना इस ?मेरा युवा भारत? संगठन में पैदा हो, जिससे देश आगे बढ़े ।

सभापति महोदय, जहां तक महिला सशक्तीकरण की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन पार्लियामेंट की इस नयी बिल्डिंग में संसद सत्र शुरू हुआ, उसके पहले दिन ही नारी वंदन अधिनियम बना, जिसके तहत हमारे पार्लियामेंट में, विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा । यह मोदी जी की दूरदृष्टि है । पिछले 30 सालों से हमारे विपक्ष और कांग्रेस के मित्र महिला सशक्तीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी उसका पालन नहीं किया, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया । अगर किसी ने इसे इम्प्लीमेंट करने का काम किया तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया और इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के खुलते ही यह काम किया ।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि अब रक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में भी हमारी महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है । चाहे वह जल सेना में हो, चाहे थल सेना में हो, चाहे वायु सेना में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, हर जगह महिला सशक्तीकरण को हम देख सकते हैं । अभी हाल ही में मैंने देखा कि जहां ?विकसित भारत? के कैम्प्स लगे, वहां ?मोदी की गारंटी? की गाड़ी गयी । हर ग्राम पंचायत में यह गाड़ी गयी ।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि पूरे देश में इसके आंकड़े 19 करोड़ हैं, और पाली लोक सभा क्षेत्र में मैंने ऐसे 70 कैम्प्स अटेंड किये । वहां लोगों में बहुत जबर्दस्त उत्साह था ।

आम जन का मोदी सरकार की गारंटी पर इतना विश्वास है कि अगर मोदी ने गारंटी दी है, तो वह बात पक्की होगी, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधान मंत्री सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो । इस तरह से भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं की गारंटी मोदी की गारंटी है ।

पहले भारत सरकार की योजनाएं लंबे समय से जिस हिसाब से लागू होनी चाहिए थी, वे नहीं हुईं, इसकी चिंता मोदी जी को थी । क्योंकि अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग राज्य सरकारें हैं । मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा उन गरीबों को पहुंचाना, जो समाज के अंतिम छोर पर हैं, उन योजनाओं का फायदा गरीबों को नहीं पहुंचने की वजह से मोदी जी को गरीबों की चिंता थी । मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी से वर्ष 2024 में हम विकसित भारत बनाएंगे । भारत विकसित तब होगा, सिर्फ आधारभूत ढांचे से नहीं, सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं, विकसित भारत तब होगा, जब सोशल जस्टिस होगा । इसलिए सामाजिक न्याय के लिए मोदी सरकार की गारंटी की गारंटी लोगों तक जा रही है । यह विश्वास आम जन में बढ़ा है । लोगों में मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है । मैं अपने पाली लोक सभा क्षेत्र के बारे में कह सकता हूँ कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मैं जहां भी गया, वहां लोगों में अटूट विश्वास पाया । लोगों से पूछा कि आपको पक्का घर मिला क्या तो वे बोलते हैं कि हाँ साहब, यह मोदी जी द्वारा दिया गया घर है । एक समय था कि हमारी झोंपड़ी की छत टपकती थी, हमारे बिस्तर गीले हो जाते थे, अनाज गीला हो जाता था, बच्चों के पढ़ने की कॉपियां गीली हो जाती थीं । अब वे कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ । उन्होंने कहा कि मोदी जी को पार्लियामेंट से मेरा धन्यवाद कहना । सभापति महोदय, यह सब सुन कर ऐसा लगता है कि वास्तव में अबकी बार जो मोदी सरकार की संकल्प यात्रा, विकसित भारत 2047 के लिए है और वास्तव में वह उन लोगों के लिए थी, जो समाज के अंतिम छोर पर थे । उनके भाव देखने लायक थे ।

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री पी. पी. चौधरी : जी, मैं समाप्त कर रहा हूं । हमारे देश में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं । यह बहुत बड़ी योजना है । इससे बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं । हमने उनके लोकल प्रोडक्ट्स देखे

हैं । वे अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं । चाहे अचार हो, जूती हो या बैग हो । जब उनसे हमने बात की तो वे बोले कि हम घर का काम भी कर लेते हैं और साथ ही पांच से दस हज़ार रुपये महीना इस तरह से कमा भी लेते हैं । इसके लिए मोदी सरकार ने आठ लाख करोड़ रुपये का ऋण और 40,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता इन महिलाओं को दी है । साथ ही, दो लाख लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य है । यह भी एक बहुत बड़ा कदम महिला सशक्तिकरण के लिए है । उसके अलावा मातृ अवकाश, जो पहले 12 सप्ताह का था, अब 26 सप्ताह कर दिया गया है । सेना में स्थायी कमीशन का भी प्रावधान किया गया । लड़ाकू पायलट और नौसेना में महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है । ये सभी चीज़ें महिला सशक्तिकरण को बताती हैं ।

सभापति महोदय, अब मैं संक्षिप्त में किसानों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे थोड़ा समय और देंगे । मैं दो मिनट किसानों के बारे में बता कर अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

किसानों के लिए पीएम किसान निधि लागू की गई । सभापति महोदय, किसान को बीज की जरूरत पड़ती है तो तीन बार उसके खाते में दो-दो हज़ार रुपये जाते हैं, तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर आती है । इसके लिए सरकार ने पिछले दस सालों में 2,80,000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे हैं और जो ऋण आज तक किसानों को दिया है, वह पहले से तीन गुना ज्यादा दिया है । फसल बीमा योजना में 30 करोड़ का प्रीमियम सरकार ने भरा है और उससे किसानों को डेढ़ लाख करोड़ रुपये का क्लेम मिला है । यही नहीं, एमएसपी के लिए, 18 लाख करोड़ रुपये धान और गेहूं के लिए और सवा लाख करोड़ रुपये दलहन और तिलहन के लिए मोदी सरकार ने पिछले दस सालों में दिए हैं । कृषि निर्यात से चार लाख करोड़ रुपये का फायदा हो रहा है । साथ ही, खाद पर 11 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है ।

सर, इसी तरह से सबका साथ सबका विकास हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के हो रहा है । हम पर कोई भी भेदभाव का आरोप नहीं लगा सकता है । ऐसे आरोप कांग्रेस पर लगाए जा सकते हैं । अगर आप बाबा साहब अंबेडकर की बात देखें, उनको सबसे ज्यादा तिरस्कार मिला है तो वह कांग्रेस के द्वारा मिला है ।

माननीय सभापति: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी : सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । अगर किसी ने पंच तीर्थ स्थापित करने का काम किया है तो हमारे मोदी जी ने किया है । कांग्रेस ने हमेशा उनको इग्नोर किया है । ? (व्यवधान) अगर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए किसी ने 10 संग्रहालयों का निर्माण किया है तो मोदी सरकार ने किया है । मोदी जी ने ओबीसी कमीशन भी बनाने का काम किया है । आज तक कांग्रेस और ये लोग इस काम को इग्नोर करते रहे हैं ।

माननीय सभापति :आप अनुरोध किये जाने के बाद अपने विषय को समेटिए ।

श्री पी. पी. चौधरी : महोदय, पाली लोक सभा क्षेत्र के लिए पिछले 10 सालों में 21,723 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में खर्च हुए हैं । इसलिए, मैं पाली लोक सभा क्षेत्र के निवासियों की तरफ से मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

माननीय सभापति : मेरा निवेदन है कि संकेत होने के पश्चात विषय को तुरंत समेटने का प्रयास कीजिए ।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): सर, एक महिला होने के नाते मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज लोक सभा का मेरा तीसरा टर्म है । इन तीन

टर्म्स में से दो टर्म्स में एक महिला राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया । इससे भी बड़ी बात इस बार यह हुई कि उनके बाद एक महिला वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया । इसकी भी खुशी थी कि अभिभाषण के बाद एक महिला संसद सदस्य ने चर्चा की शुरुआत की । इधर आते ही सबसे पहले इस सदन में वूमेन रिजर्वेशन बिल पेश किया गया । मैं उम्मीद करती हूं कि इस नए भारत में जो नए नियम और चीजें शुरू हुई हैं, वे इसी तरह बढ़ती रहें । इसमें कोई शक नहीं कि हरेक महिला जो इस हाऊस में पहुंची है, वह सैकड़ों पुरुषों को हरा कर यहाँ पहुंची है । इस प्रकार मुझे महिला सशक्तिकरण का अच्छा एग्जाम्प्ल देखने को मिलता है ।

सर, महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी उपलब्धियां गिनाईं, यह हमें बहुत अच्छा लगा । कई चीजों में थोड़ी हैरानी भी हुई कि कितने पेड़-पौधे लगाए हैं, कितने लाख लगाए हैं, कितनी सेल्फीज़ अपलोड हुई हैं । मुझे नहीं पता था कि आज देश की अचीवमेंट का यह एक नया स्टैंडर्ड बन जाएगा । मुझे यह भी सुनने को मिला कि कितनी सेल्फीज़ ली गई हैं और कितने लाख पेड़-पौधे लगे हैं ।

सर, एक तरफ देश में चंद्रयान की उपलब्धि हुई, बुलेट ट्रेन आ रही है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, बहुत बढ़िया रोड नेटवर्क बन रहा है । इन सब के बारे में महामहिम जी ने कहा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारे देश के चार स्तंभ युवा, गरीब, किसान और औरत के ऊपर देश के खजाने का फोकस रहा है । सरकार को कहीं न कहीं इसे आंकड़ों के साथ पेश करना चाहिए था कि क्या देश के युवाओं, औरतों, किसानों और गरीबों के लिए पिछले 10 सालों में अच्छे दिन आ गए हैं? उनकी जो मुसीबतें हैं, जैसे देश विकसित हो रहा है, क्या हमारे देशवासी भी वैसे ही विकसित हो रहे हैं? कहीं न कहीं मैं समझती हूं और यहां हम सब का फर्ज़ भी बनता है । ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम पक्ष में हैं तो सिर्फ तारीफ करें और विपक्ष में हैं तो

सिर्फ नुक्स निकालें । कहीं न कहीं हमें हकीकत को आंकड़ों के हिसाब से देखना चाहिए और यह हम सभी का फर्ज़ बनता है ।

Sir, I would like to say that when we talk about the youth, 50 per cent population of India comprises of youths. The data of the World Bank shows that as far as the youths between 15 and 24 years are concerned, the 2022 data says that 23 per cent youths in the country were unemployed. This unemployment percentage is more than in Pakistan, Bangladesh and Bhutan. The Centre for Monitoring of Indian Economy data shows that 45.4 per cent youths between 12 to 24 years were unemployed. It means every second youth in the country today is jobless. This is the fact. Another data shows that 26,000 youths of the country between 2019 and 2021 have committed suicides. 43,000 professionals who were in jobs have also committed suicide as per this data which is shocking.

This is the reason, Sir, why there has been a rise of 68 per cent in students leaving the country and going abroad. This is a 6 year all time high data. Two to three lakh Indians have given up their Indian passports and in Punjab this number has been maximum. Hon?ble President ma?am says that the enrolment of SC students have increased. But, the fact is that 14,000 SC, ST and OBC students have dropped out from pursuing higher studies.

I can tell you the data pertaining to my State. During my student days, lots of SC students pursued higher studies. Now, the numbers of SC students have remained half of that only. Many SC students did not get scholarships because there was corruption that was indulged in by the Minister of Congress party. This corruption

was worth 60,000 crores. Without scholarships, the SC students suffered. So, I urge upon the Government to provide more monetary support to SC students. The 2.5 lakh monthly income ceiling has not been increased for the last 10 years. It should be increased to Rs. 8 lakhs.

There is an increasing menace of drugs problem in the country. When we talked about our demographic dividend 10 years ago, now it is becoming a demographic disaster. Why are we not serious about overcoming the drug menace. Punjab is facing a serious drug menace as Pakistan is sending drugs consignment now via drones. Every nook and corner of Punjab, every family is suffering. Daily, our youths are dying in Punjab due to drug overdose. Why drones from Pakistan are not being stopped from entering India. Why are they not shot down? Why borders are not being sealed and air-security is not being strengthened? This is needed.

Sir, 60 per cent country comprises of farmers. In 2015, a promise was made that the income of farmers will be doubled. NSO data shows that in 2015, the income of a farmer was Rs. 8000/-. By 2018-19, it could increase to only Rs. 10,000/-. We do not have the data of their income after that. From 2015 to 2019, if only Rs. 2000/- increase was there in farmers? income, when did their income double? Why did you not fulfil your promises? Why the income of farmers did not get doubled? NSO data also shows that 50% farmer families are in debt now. In 5 years, this debt has increased 58%.

Centre for Science and Environment data shows that in 2019, 2819 farmers committed suicide. Which means, in our

country, every hour, a farmer is committing suicide. So, there is crisis among farmers.

Punjab is an agricultural State. The farmers in Punjab are under maximum debt. 80 to 85% small and marginal farmers are reeling under debt of Rs. 3 lakhs. Thousands of farmers are committing suicide in Punjab. The Hon. President ma?am has talked about Rs. 18 lakh crore MSP amount, but Sir, 850 farmers got martyred during the farmers? agitation. Promises were made that a mandatory Committee will be constituted for fixing MSP, Swaminathan Commission recommendations of C2 + 60% will be made compulsory. Years have passed, but no such thing has been done.

The fact is that if we take wheat, DAP, urea, fertilizers ? the cost input of crops have increased 80% but the output of MSP is dismal. Farmers are spending money from their own pockets. During Russia?Ukraine war, wheat prices had increased. But, the Government banned the export so that farmers should not get any money.

So, I urge upon the Government that your schemes are good. The 6,000/- rupees scheme is there. Kisan Samman Nidhi is good. But, in 2021, this scheme was given to 2 crore 90 lakh farmers whereas in 2023-24, beneficiary farmers were reduced to 8.5 lakh farmers only. Why this reduction? Income of farmers has not increased.

In Punjab, land is 1.5% of India. 80 crore beneficiaries are there of the ration scheme. The farmers of Punjab contribute the maximum foodgrains. Why did you reduce 26% beneficiaries in Punjab of Kisan Samman Nidhi Scheme? What is our fault? Why is this step-motherly treatment meted out to Punjab?

The farmers of Punjab have lost our river waters. We cultivate land by dint of our sweat and blood. Why this discrimination? The Crop Insurance Scheme is there. No one says that Insurance Companies have gobbled up Rs. 57,000 crore rupees from this scheme. We in Punjab do not get a penny.

Our Chief Minister of AAP says that we will help farmers during a crisis or a calamity. The AAP did not give a penny to farmers. Floods were there. Farmers are committing suicide. But, the Punjab Government has not helped the farmers.

Now, I come to the poor people. The Aayushmaan Bharat Scheme for poor is a very good scheme. You are giving houses and ration to poor which is a good thing. But, the Hon. President says that Government has raised 25 crore people and brought them out of poverty level. 80 crore people are beneficiaries of free ration as they cannot feed themselves. They do not have houses, latrines, food etc. How is India developing then?

Sir, the UN Report State of Food Security in the World says that 74 per cent of Indians are unable to afford healthy food. In Global Hunger Index, we are at 111th spot. 1/3rd girls of our country are anaemic. The fact is that income has not increased. Price-rise has

sky-rocketed. Petrol price has increased by 40 per cent. Diesel price has increased by 60 per cent. Prices of pulses have increased by 70 per cent. Crop prices have increased by 75 per cent. Milk and milk products prices have increased by 77 per cent since 2012. 5 years ago, we spent 55 per cent less money on eating food. Now, it has increased by 55 per cent. Prices have gone through the roof.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, please give me 5 minutes.

HON. CHAIRPERSON: Not 5 minutes. Please conclude within one minute. Please.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: The RBI data shows that income of people had got reduced by 5.1% and their debt has increased by 5.8%.

इसे लोगों के लिए अच्छे दिन तो नहीं कह सकते । आखिर में, मैं औरतों के ऊपर आती हूं, मैं मानती हूं कि औरतों के लिए बहुत अच्छी चीजें हुई हैं । मैं इसकी तारीफ करती हूं कि आपने 70 फीसदी आवास औरतों के नाम पर किया, यह बहुत बढ़िया चीज है, इसके लिए सभी को ताली बजानी चाहिए । आपने यह भी कहा है कि 30 करोड़ औरतों को मुद्रा लोन दिया है, आपने उनके लिए टॉयलेट बनाये, मेटरनिटी लीव को 26 हफ्ते कर दिया ।

एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, वर्ष 2019-22 में क्राइम अगेंस्ट वूमेन में 10 फीसदी इन्क्रीज हुआ है । मणिपुर में क्या हुआ? देश की रेसलर्स महिलाओं ने देश का नाम रौशन किया, वे फुटपाथ पर अपने मेडल छोड़ कर जा रही हैं । बेटी बचाओ नारा के बाद अगर उनका यह हाल होगा तो फिर

उनको पढ़ाने से क्या फायदा है? जेंडर इक्विलिटी इंडेक्स में हम 122वें नम्बर पर हैं । नारी शक्ति, वुमेन रिजर्वेशन बिल आपने पास कर दिया है, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं देते हैं कि यह कब से लागू होगा । आप कहते हैं कि इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 में हो जाएगी, 30 ट्रिलियन 2047 में हो जाएगी । 33 प्रतिशत रिजर्वेशन 2027 में आएगा या 2028 में आएगा, यह भी बता दीजिए ।

आखिर में, हमारी राष्ट्रपति जी कहती हैं कि हम फ्रेजाइल फाइव से टॉप फाइव में हो गए । यह बहुत अच्छी चीज है । यह फ्रेजाइल फाइव से टॉप फाइव में देश के दस फीसदी लोग हैं, जिनके पास देश की 90 फीसदी वेल्थ है, 90 प्रतिशत जो दबे कुचले गरीब लोग हैं, उनके बारे में जरूर सोचने की बात है । इसके बारे में ध्यान देना चाहिए । आईएमएफ का डाटा कहता है कि पर-कैपिटा इनकम जो असली में बताता है, हिन्दुस्तान को छोड़कर पांच देश जो आगे बढ़े हैं, आज हिन्दुस्तान का पर कैपिटा इनकम 2 लाख 14 हजार है, चीन, जिसकी पोपुलेशन हमारे बराबर है, उनका 11 लाख 29 हजार है, दूसरे देश जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील की पर कैपिटा हमसे ज्यादा है । हम इसके पीछे नहीं छूप सकते हैं कि यूपीए ने ये किया, हमने ये किया । यूपीए को लोगों ने भगा दिया ताकि आप उससे बेहतरीन काम करें ।

देश तभी विकसित हो सकता है जब देशवासी आत्मनिर्भर हों । आज 80 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए अनाज सरकार को देना पड़ रहा है । हम कैसे कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और देश विकसित हो रहा है ।

मैं उम्मीद करती हूं कि जो कमियां रह गई हैं, उसकी तरफ सरकार ज्यादा ध्यान देंगी और विकसित देश में लोग आत्मनिर्भर हों, तभी देश का भला हो सकता है ।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, शुक्रिया । सद्र-ए-जमहूरिया के खिताब पर शुक्र की तहरीक पर बोलने का मौका दिया । सद्र-ए-जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर ताइद करने या उसके साथ खुद को वाबस्ता करने से कासिर हूं । पहली बात जम्मू-कश्मीर और उसके बाद मुल्क की करूंगा । 1947 में जम्मू-कश्मीर के पास एक विकल्प था, एक ऑप्शन था । माउंटबेटन प्लॉन के तहत हम एक और मुल्क की तरफ जा सकते थे । हमने फैसला किया कि हम इस मुल्क की तरफ आ जाएं । इस यकीन दहानी पर, इस आश्वासन पर, इस भरोसे पर कि यहां हमारी खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाएगा, हमारी शिनाख्त का एहतराम किया जाएगा और हुकूक, ज़मीन और नौकरी के हवाले से हमारे जो हकूक हैं, तशकुश, आइडेंटी का एहतराम किया जाएगा, इस भरोसे पर हम इस तरफ आए वरना हमारे पास बाकी स्टेट्स के मुकाबले विकल्प था जो उस वक्त के कानून, रहनुमा असूल थे, जो गाइडलाइन्स थीं, उसके तहत थे । बहरहाल हमने फैसला किया कि गांधी जी के हिंदुस्तान की तरफ आ जाएं ।

जनाब, 5 अगस्त, 2019 को उन सारी यकीन दहानियों को दरकिनार करते हुए, उनको रौंदते हुए, उनकी वाएलेशन में हमें हमारी शिनाख्त से महरूम किया गया । हमारी ज़मीन और नौकरियों के हवाले से जो हकूक थे, उनसे महरूम किया गया । हमारे तशकस, हमारी आइडेंटी से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया । हमारी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है दोनों-तीनों खित्तों को इकट्ठा करके । अब मैं इसलिए इस बात पर आ रहा हूं क्योंकि सद्र-ए-जम्हूरियत ने खिताब में इशारा किया है कि अनुच्छेद 370 के बारे में शकूक थे और अब वे शकूक अब दूर हो गए हैं । शकूक दूर नहीं हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीक-ए-करार को गैर-आइनी करार दिया । आर्टिकल 370 के अमेंडमेंट का जो तरीका किया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गैर-आइनी था और उसे स्टैपआउट किया, अल्ट्रा वायर्स करार दिया । एक तो तरीके का सलूक नहीं

किया, दूसरी बात, जो हमें डाउनग्रेड करने की बात थी, विभाजन की बात थी, फ्रेगमेंट करने की बात थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तोसीक नहीं थी ।

जनाब, बरहाल सद्र-ए-जम्हूरियत की जो बात है, उस पर तो बात होती रहेगी और हमारी जद्दोज़हद भी जारी रहेगी । अब सद्र-ए-जम्हूरियत की खिताब में हमारे लिए, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर की डेढ़ करोड़ अवाम के लिए कोई आश्वासन नहीं है, यकीन दहाई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है । दस साल से जम्मू-कश्मीर एक चुनी हुई लेजिस्लेचर के बगैर है । हम गौरव करते हैं, हम फख्र करते हैं कि हमारा मुल्क मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, फिर क्या बात हुई कि इसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में डेढ़ करोड़ लोगों के लिए न पंचायत चुनी गई और न ही अर्बन लोकल बॉडी चुनी गई । सदन को खुद से सवाल पूछना चाहिए क्योंकि यहां असैम्बली कोई नहीं है । हमें और डेढ़ करोड़ लोगों को एक अफसरशाही के हवाले किया गया है । अगर अफसरशाही ही ठीक है तो फिर सारे देश में अफसरशाही क्यों नहीं है? हम क्यों अरबों-करोड़ों रुपये इलैक्शन पर खर्च करते हैं? अभी इलैक्शन आने वाले हैं, इससे पहले भी इलैक्शन हुए हैं । डेढ़ करोड़ लोगों को, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख लोगों को क्यों इससे महरूम किया जाए? यह कहीं न कहीं कोलोनियल माइंडसैट की तरफ इशारा करता है, एक एप्रोच की तरफ इशारा करता है, मुझे लगता है कि यह हमारी जम्हूरियत और मुल्क के लिए ठीक नहीं है ।

जनाब, अफसरशाही की वजह से लोगों को एक्सेस नहीं है । अवाम का कोई नुमाइंदा नहीं है जिसके पास वे जा सकें । इतना ही नहीं कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है । सद्र-ए-जम्हूरिया ने अपने बयान में, खिताब में कहा है कि अब सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक हो गया है, मुस्तहकम हो गया है । अभी हाल ही में पोखरनाथ, पुलवामा, रियाज़ी, राजोरी में 20 अफसरानों का बलिदान हुआ, इनमें कमांडिंग और सीनियर अफसर थे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नॉर्मेलसी का नैरेटिव है? इससे तकज़ीम होती है

कि हालात और वाकयात हैं । खिताब में कहा गया कि वहां पर सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है, वह कहां है? क्या उसकी तकज़ीम होती है?

जनाब, हम दस साल से जम्हूरियत से महरूम हैं बल्कि यह एक बे-चेहरे, फेसलैस ब्यूरोक्रेसी है । इसका न तो पोजीटिव करैक्टर है, न ही चुनी हुई ब्यूरोक्रेसी है और न ही एकाउंटेबल है । सद्र-ए-जम्हूरिया के न ही किसी टाइम फ्रेम का ऐलान किया है कि इन महीनों में या इन हफ्तों में इलैक्शन किया जाएगा । इससे क्या हुआ, जम्मू-कश्मीर में एक बहुत बड़ा गवर्नेंस डेफिसिट हो गया । हमारा हैल्थ केयर सिस्टम 40 फीसदी अफरादी कुव्वत है, उस पर चल रहा है । जो प्रपोजल गए, वे सैक्रेटेरिएट में पड़े हुए हैं । अनंतनाग में मैटरनिटी अस्पताल का प्रपोजल है, ऐसे ही बाकी प्रपोजल्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सैक्रेट्री, ब्यूरोक्रेसी मजबूर हैं कि कैसे नार्मलसी नरेटिव बनाएं, कहीं बाल दिवस, पंचायत का कुछ होता है और इसी में घूमते रहते हैं, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है ।

जनाब, 61 हजार के करीब हमारे डेलीवेजर्स, काँट्रैक्चुअल वर्कर्स और टेम्पोररी वर्कर्स हैं, जो 10 साल से अपनी रिकग्नाइजेशन का इंतजार कर रहे हैं । उनको मिनिमम वेजेज भी नहीं दिए जा रहे हैं । हॉस्पिटल सिस्टम, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वहां केवल 40 प्रतिशत डॉक्टर्स, कन्सल्टेंट्स, पैरा मेडिकल स्टाफ हैं । वहां पर एचडीएफ यानी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से जो मुलाजिम लगाए गए, उनको भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं । एक हजार रुपये, दो हजार रुपये महीने दिया जा रहा है । अत: ये ह्यूमिलिएटिंग वेजेज हैं ।

जनाब, बिजली के बारे में भी आप देख सकते हैं । जम्मू-कश्मीर में जहां 3215 मेगावाट बिजली पैदा होती है, वहां इस वक्त केवल 625 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट डेफिसिट है । आप में से ज्यादातर मेंबरान समर सीजन में आते हैं, लेकिन आज 14 घंटे का वहां शट डाउन है । हमारे जो प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी के पास हैं, उनमें बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के

एग्रीमेंट हमारी सरकार ने उनके साथ किए थे । एनएचपीसी के पास 30 साल से हैं और वे वापस नहीं किए जा रहे हैं । हेल्थ केयर और बाकी के जो मामले हैं, उनके अलावा इसी तरह से पीएम पैकेज के अंतर्गत जो मुलाजिम हैं, उनको तपती गर्मी में जम्मू की सड़कों पर लाया गया और वहां पर इस वक्त जो काम कर रहे हैं, वहां पर जो अरेंजमेंट है, उसमें 70 फीसद रेजिडेंट्स को अभी भी एकोमोडेशन नहीं है । जो सिक्योरिटी सिनारियो के तहत उनके पास जो होना चाहिए था, वे अरेंजमेंट्स नहीं हो रहे हैं ।

जनाब, 10 लाख माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए स्कूल्स हैं । अभी मैं जम्मू-कश्मीर का जिक्र कर रहा हूं, फिर मुल्क पर आ जाऊंगा । जो लाइव स्टॉक के साथ जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जाते हैं, उनके लिए स्कूल्स हैं, एजुकेशन सेंटर्स हैं, लेकिन वहां का जो अमला है, वह गैर-मुस्तकिल 10 साल से है, सिर्फ 6 महीने के लिए रहता है । उससे यह होता है कि उनको वह ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जो ट्रेनिंग एक टीचर की होनी चाहिए । इससे जो प्रभावित होता है, जो मुतासिर होता है, जिसके राइट्स वॉयलेट होते हैं, वे हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन के बच्चे होते हैं । ट्राइबल्स में हमारी गर्ल्स चाइल्ड्स का वहां पर केवल 16 परसेंट लिट्रेसी रेट है । ये सारी परेशानियां वहां हैं । इनकी एक गवर्नमेंट डेफिसिट है, चुनी हुई सरकार नहीं है । हम कैसे अपने-आपको देश का हिस्सा कहेंगे । एक तो हमने हाथ जोड़ा । वहां की तरफ नहीं गए और यहां आ गए । हाथ मिलाने के बाद भी हमें हमारी आइडेंटिटी नहीं मिल रही है ।

जनाब, जहां तक मुल्क की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह कहा गया कि हमने वुमेन इम्पॉवरमेंट की बात की । मुझे बताएं कि क्या इसकी कोई समय सीमा है, कोई टाइम फ्रेम है, कोई टाइम लाइन है? ये अपनी दुकान वह सौदा बेच रहे हैं, जो सौदा इनके पास है ही नहीं । सौदा बेचने के बगैर उसका मोल भी वसूल किया जा रहा है । बार-बार यह कहा जा रहा है कि हमने इम्पॉवर किया । इसकी क्या समय सीमा है, क्या टाइम फ्रेम है? अब

ये कह रहे हैं कि हमने एफडीआई बढ़ाया । एफडीआई वहां का नहीं बढ़ा । वर्ष 2022 के मुकाबले वर्ष 2024 में 10 परसेंट एफडीआई में कमी आ गई । अगर बढ़ा है, तो हमारी वित्त मंत्री जी इसकी तस्दीक करें । हमारे यहां के जो नौजवान हैं, उनमें 40 परसेंट तक बेरोजगारी है । मेरे पास कुछ पुराना रिकॉर्ड मौजूद है ।

जनाब, 40 परसेंट तक बेरोजगारी है, लेकिन कहीं पर इसका जिक्र ही नहीं है । आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? हर साल 1 करोड़ 35 लाख लोग हमारी वर्क फोर्स में ऐड होते हैं । इनमें से केवल .05 परसेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ रुख करता है, बाकी सारा वापस जाता है, क्योंकि वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है । जो बातें कही गई हैं, जो उपलब्धियां गिनाई गई हैं, उनको आप देखिए कि कहां पर क्या हकीकत है, क्या नहीं है? आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, उसका क्या मतलब है?

माननीय सभापति : अब कृपया कनक्लूड करें ।

श्री हसनैन मसूदी : जनाब, उसका मतलब यह है कि 130 ग्राम एक दिन में । यानी हमारी 80 करोड़ आबादी, 60 फीसदी आबादी के पास इतने साधन नहीं हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वह 4 किलो राशन एक महीने में खरीद सके । अत: यह आपकी तरफ से एक एहतराफ है । उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है । आप उनको अभी भी हैंड आउट्स दे रहे हैं । इस 60 फीसदी आबादी के पास ? (व्यवधान) यही सिनारियो हमारी एमएसएमईज का है । जम्मू-कश्मीर में बैंक एक साहूकार बन गया है । वहां पर इंडस्ट्रीज और छोटे-मोटे एमएसएमईज बंद हो रहे हैं । जो छोटे-मोटे एमएसएमईज हैं, वे बंद हो रहे हैं । यह सारा वातावरण जम्मू-कश्मीर से और सारे मुल्क के हवाले से है । आप जो हसुलयाबी गिना रहे हैं, यदि आप उसका क्लोजर रूप देंगे, आप देखेंगे तो उसमें कहीं पर उसकी कोई तस्दीक नहीं होती है । खासकर, मैं जम्मू-कश्मीर की बात करूंगा, मैं यह अपील करूंगा और सरकार से कहूंगा कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं ।

आप देखिए कि आज तक कोई कमांडिंग ऑफिसर सड़क पर नहीं मरा । आजकल रोज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां हो रही हैं । लोगों में एतमाद नहीं है, लोग बेआसरा हैं, लोग बेबस हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है ।? (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने संसद के समक्ष समवेत सदन में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव, जिसको हमारी बहन हिना गावीत ने प्रस्तुत किया और बघेल साहब ने समर्थन किया, उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया है ।

लगातार पहले दिन भी 9 घंटे चर्चा हुई और आज भी कई घंटे से चर्चा हो रही है । उस चर्चा को मैं लगातार बैठकर सुन रहा हूं । मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार के कार्यक्रम होते हैं, सरकार की योजनाओं का उल्लेख होता है, सरकार की उपलब्धियां होती है और एक सरकार की दिशा भी होती है । इस बार जिस तरह से इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने अपनी एक इच्छाशक्ति जताई, एक दृढं संकल्प तरीके से एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, मैं यही कह सकता हूं कि अभी तक इस सदन में कभी भी, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण होते थे तो सरकार की तरफ से वायदे होते थे, सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं होती थीं, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं और मैं अपनी सरकार को और प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बार इस सदन के माध्यम से सरकार ने वायदा नहीं किया है बल्कि सरकार ने एक गारंटी और संकल्प देने का काम किया है कि हम देश को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे ।

इसी सदन में क्या होता था? इस सदन में हमेशा चर्चा होती थी, चाहे वे सत्तापक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, कहते थे कि दो भारत हैं, एक ग्रामीण भारत है और दूसरा शहरी भारत है । गांव के भारत में आज भी लाइट नहीं है, आज भी गांव में बिजली नहीं पहुंची, गांव में पक्के मकान नहीं हैं, गांव में शौचालय नहीं हैं और आज भी गांव सुविधाओं से वंचित है । इस बात पर लगातार इसी सदन में चर्चा होती थी । एक शहरी भारत, जिसमें अट्टालिकाएं हैं, रोशनी से रात में भी दिन लगता है । लेकिन, प्रधान मंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर से इन विषमताओं को, जो सदन में चर्चा होती थी कि भारत दो भारत है, एक गांव का भारत है और दूसरा शहर का भारत है, उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम उस गांव के भारत और शहरी भारत के अंतर को और उस खाई को मिटा देंगे । पहली बार उन्होंने पूरे देश में एक आइडेंटीफिकेशन कराया । देश के 18 हजार गांव विद्युतीकरण से वंचित थे । इस सरकार ने अपनी सबसे पहली प्राथमिकता में संकल्प लिया कि हम देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सारे गांवों को विद्युतीकरण से संतृप्त करने का काम करेंगे और उसको समय से पहले करके दिया । आखिर इस तरीके से जो चर्चा होती थी, आज आप देख रहे हैं कि गांवों में जिस तरह से, आपने उस दिन देखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि गांव में 4 करोड़ पक्के आवास बनाये गए हैं ।

<u>13.48 hrs</u> (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

यह बात सही थी कि गांव में लोगों के पास पहले कच्चे मकान थे । गांव में जिस तरीके से परिस्थितियां थीं कि शौचालय नहीं था, गांव में उज्ज्वला गैस का चूल्हा नहीं था, गांव में बिजली के कनेक्शन्स नहीं थे, आज उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार बढ़ी है । शहरी और गांव के अंतर को मिटाकर, आज जो एक बुनियादी सुविधाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गांव के लोगों की बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? महिलाएं शाम तक का

इंतजार करती थीं । उन्हें बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि घर में शौचालय नहीं होता था । सबसे पहली पीड़ा हमारी सरकार ने उन बहनों और माताओं के लिए लिया । आज आपने सवाल उठाएं हैं । मैं कहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रथम वक्ता थे, गोगोई साहब यहां नहीं हैं, उन्होंने कहा कि अब यह लोकतंत्र का मंदिर ही नहीं रहा । उन्होंने सवाल उठाया कि यह ऐसा लग रहा है जैसे सिंहासन पर प्रधान मंत्री जी बैठे हों ।

उन्होंने चेयर के फैसलों पर सवाल उठाया था । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज यह लोकतंत्र का मंदिर है, अगर आपकी लोकतंत्र में आस्था होती, तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हैं, जनता ने उनको चुनकर इस सत्र के लिए भेजा है, अगर उनको सजा हुई, उनकी सदस्यता गई, कोर्ट ने फिर से फैसला दिया कि आप एक सांसद के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, तो जिस समय भारत की लोक सभा का सत्र चल रहा हो, तो वे सत्र में आने के बजाय सैर करने का काम कर रहे हैं । अगर लोकतंत्र के प्रति ऐसी आस्था है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से जो लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, उनके लिए दुख का विषय है । आज आप इस लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं । अगर लोकतंत्र के इस मंदिर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर 12 घंटे चर्चा करेंगे । आप देखिए कि पहले दिन अर्थात् शुक्रवार को 12 बजे से चर्चा शुरू हुई और रात को 9 बजे तक हम लोग यहां बैठे थे । 9 घंटे चर्चा हुई और आज भी 6 घंटे चर्चा होगी । इस विषय पर सदन 15 घंटे चर्चा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी बेंच खाली पड़ी है । कोई भी नहीं है, सिर्फ एक सदस्य है । उन्होंने अपना हाथ उठाया है । मैं उनको धन्यवाद देता हूं । उनकी लोकतंत्र में ऐसी आस्था है । ये सवाल उठा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं, सरकार की पूरे देश के ढाई लाख गांवों के लिए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो दिशा है, आखिर विकसित भारत कैसे बनेगा? अगर आज भी गांव का कोई पात्र व्यक्ति आवास योजना के लाभ से वंचित रह गया है, अगर गांव के किसी

पात्र व्यक्ति के घर में क्लीन एनर्जी नहीं है, अगर वह उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गया है, चाहे नॉर्थ-ईस्ट का कोई गांव हो, चाहे झारखंड के किसी आदिवासी इलाके का कोई गांव हो, चाहे साउथ के तमिलनाडु या कोचीन का कोई गांव हो, अगर आज भी कहीं पर शौचालय नहीं है, तो वह केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दे, तो शौचालय का पैसा उसके खाते में चला जाएगा ।

महोदय, आज ?विकसित भारत संकल्प यात्रा? की बात हो रही है । यह इसलिए हो रही है, क्योंकि ?विकसित भारत संकल्प यात्रा? पूरे देश के ढाई लाख गांवों के लिए है । वह मोदी जी की गारंटी है, वह मोदी जी की वैन नहीं है, वह गारंटी है । आप शायद उसमें नहीं गए होंगे, मैं भी 64 ?विकसित भारत संकल्प यात्राओं? में गया हूं । ये कह रहे थे कि इन योजनाओं में कमीशन चलता है । आप तो स्वयं महसूस करिए, पहले आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर हम एक रुपया भेजते हैं, तो 15 पैसे पहुंचते हैं । आज हम डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में पैसा भेज रहे हैं, अगर हम एक रुपया भेजते हैं, तो लाभार्थी के खाते में एक रुपया पहुंचाने का काम मोदी सरकार करती है ।

इस सदन में चर्चा होती है कि पूरी दुनिया में दो तरह के देश हैं, एक विकसित देश है और दूसरा विकसशील देश है । विकसित और विकासशील देश की बात हो रही है । यह बिल्कुल सही है । आप इसी देश में देखिए कि जब कोविड की वैश्विक चुनौती आई, तब उस समय ऐसी परिस्थितियां थीं कि हम पीपीई किट नहीं बनाते थे । उस समय वेंटीलेटर नहीं बनता था । एन-95 मास्क चाइना से मंगाते थे । इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा था कि सब स्टैंडर्ड दे रहे हैं । उसी समय प्रधानमंत्री जी के मन में आया कि अब भारत को ?आत्मनिर्भर भारत? बनना पड़ेगा । उन्होंने भारत को ?आत्मनिर्भर भारत? बनाने के लिए न केवल कदम उठाएं, बल्कि पहले हमारी तुलना पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के साथ होती थी, आज

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को ?दावोस शिखर सम्मेलन? के उद्घाटन सत्र में बुलाया जाता है । आज भारत की ये स्थिति है ।

मैं विकसित और विकासशील देशों के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । जो विकसित देश हैं, आखिर विकसित देश क्या होता है? विकसित देश अपनी जरूरत की चीजों और बुनियादी सुविधाओं को पूरा करते हैं और वे दूसरे देशों की भी मदद करते हैं । विकासशील देश वे हैं, जो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर मुनहसिर रहें या निर्भर रहें । पिछले नौ सालों में भारत ने एक यात्रा पूरी की है । यह पूरी दुनिया के लिए ऐसी आश्चर्यचकित यात्रा है, कुछ लोग भारत की सक्सेज स्टोरी (ग्रोथ) पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं । मैं आज पिछले नौ साल की बात करना चाहता हूं । आज पूरी दुनिया में भारत एक चीज में नहीं, बल्कि कई चीजों में नंबर एक पर पहुंच चुका है । मैं उसके लिए अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं । आज दुनिया में सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? वह दूध है । दूध में विटामिन है, उससे एनर्जी मिलती है । मां का दूध पीकर एक बच्चा बड़ा होता है । दूध को पीने से एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है । आज दुनिया में भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हो गया है । हमने अपने देश में नरेन्द्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में 50 प्रतिशत मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया है । पूरी दुनिया का जो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसका 24 प्रतिशत केवल भारत पैदा कर रहा है । यह हमारे लिए संतोष का विषय है । हमारी सरकार इस दिशा में जा रही है । इस समय यूएस हम से पीछे है और सेकंड रैंक पर है । पहले दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, लेकिन आज यूनाइटेड स्टेट नंबर दो पर है और भारत नंबर एक पर है । सभापति जी, आज मोटे अनाज की बात हुई और प्रधान मंत्री जी ने योगा के लिए कहा था । उसे यूएनओ और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है । आज इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जा रहा है । इसी तरीके से उन्होंने पिछले साल कहा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट होना चाहिए । मोटा अनाज, जो किसी के स्वस्थ रहने और जीवन के लिए जरूरी है, उस मोटे अनाज में भी हम दुनिया

में नंबर एक पर हैं । आज इंडिया 170 लाख टन मिलेट दुनिया में पैदा करके नंबर एक पर है । यह भारत के लिए उपलब्धि है और ये भारत की उपलब्धियां हैं । पूरे एशिया का 80 प्रतिशत मिलेट हम अकेले भारत में पैदा कर रहे हैं । पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का 20 परसेंट मिलेट आज भारत पैदा कर रहा है और हम दुनिया को दे रहे हैं । महोदय, इसी तरह से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करना चाहता हूं । मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं, जिनको मेरे साथियों ने कह दिया है । अभी हमारी पंजाब की बहन कृषि की बात कर रही थीं । मैं कह रहा हूं कि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम पूरी दुनिया में नंबर एक पर हैं । मैं पूरे डाटा के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में 3,128 लाख मीट्रिक टन पैदा करके भारत के किसानों ने ऑर्गेनिक खेती में खुद को नंबर एक पर किया है । आज डिमाण्ड बढ़ रही है । आप यूरोप, अमेरिका के मॉल्स या अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर आज देखते हैं तो आज लोगों में क्रेज सा है कि हम ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे । जो हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किया है, उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू 5,525 करोड़ रुपये है । हमारे किसानों ने ऑर्गेनिक खेती से 5,525 करोड़ रुपये कमाए हैं । Thirty per organic producers of the world are in India. आप बताइए कि भारत पिछले नौ सालों में कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मिल्क का क्षेत्र हो, कहां आ गया है । मैं मेडिसिन के क्षेत्र पर भी आ रहा हूं । आज युगाण्डा सेकंड नंबर पर है । इसका मतलब यह है कि आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी नंबर एक पर है । आज फार्मास्युटिकल में देखिए कि जब पहले कोई बीमारी हो जाती थी, जापानी इंसेफेलाइटिस हो जाता था, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम हो जाता था, तो उसके लिए हम जापान से वैक्सीन मंगाने की बात करते थे । हमारे यहां हजारों बच्चे जापानी बुखार से मर जाते थे । कोविड में यह लगता था कि हम दुनिया में किस तरह से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है । मैं धन्यवाद दूंगा कि आज नौ सालों में प्रधान मंत्री जी ने जिस तरीके से वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, प्रयोगशालाओं तक चलकर गए और कोविड की दो वैक्सीन्स को निकालने का काम किया, वह चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो । आज दुनिया में

उन्हीं वैज्ञानिकों, उन्हीं प्रयोगशालाओं ने हमको फार्मास्युटिकल प्रोडक्शन में भी थर्ड रैंक पर ला दिया है । विश्व में हमारे लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती है । महोदय, आज दुनिया का जो करेंट मार्केट साइज है, वह 50 बिलियन यूएस डॉलर है । आज हम केवल यूनाइटेड स्टेट और चाइना से पीछे हैं तथा तीसरे नंबर पर हैं । हम कल तक कहते थे कि फ्रेजाइल फाइव हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी स्पीच कन्क्लूड कीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दीजिए । भारत के बारे में कहा जाता था कि यह ?बनाना रिपब्लिक? है । आज आप देखिए कि हम यूएस और चाइना से आगे जा रहे हैं । इसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में है । आज हम रिन्यूएबल एनर्जी में फोर्थ पर विंड पावर कैपेसिटी में है, फिफ्थ पर सोलर पावर कैपेसिटी में हैं, नॉन फॉसिल में हम वन गीगा वाट से 188 गीगा वाट पर पहुंच गए हैं । आज आप देखिए कि हम सोलर एनर्जी में दुनिया में तीसरे-चौथे नंबर पर हैं । मैं ग्लास्गो और पेरिस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करता हूं । वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए जब डोनाल्ड ट्रम्प अलग हो गए तो उस समय पूरी दुनिया में लोगों को लगा कि क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कौन नेतृत्व करेगा । अगर दुनिया में डोनाल्ड ट्रम्प के अलग होने के बाद किसी ने नेतृत्व किया है तो भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व किया है । उसके बाद पेरिस में फिर से जो बाइडेन को जुड़ना पड़ा । मैं केवल महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं । आज दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हमारी है । आजादी के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि गरीब किस तरीके से अपनी दहलीज पर एड़ियां रगड़-रगड़कर मर जाता था और सोचाता था कि हमारी गरीबी नसीब है तथा दवा नहीं करवा सकता था । वह खेत रेहन रखकर, मंगलसूत्र गिरवी रखकर भी दवा नहीं करवा सकता था ।

<u>14.00 hrs</u>

आज हर व्यक्ति के हाथ में पांच लाख रुपये की दवाई की गारंटी है । वह आयुष्मान कार्ड नहीं है, बल्कि देश के किसी अस्पताल में उसकी जिंदगी की सलामती के लिए कैश है कि पांच लाख रुपये उसके हाथों में है । 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड इतने बड़े देश में दिए गए हैं । ओबामा ने मेडिकेयर दिया था । कहते हैं कि अमेरिका ने अपने लोगों को मेडिकेयर दिया है । आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान गारंटी योजना आयी है । टैक्सटाइल में आप देख लीजिए ।

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मैं वह बातें नहीं दोहरा रहा हूं जो हमारे साथियों ने कही है । आज दुनिया में हम टैक्सटाइल में सेकेण्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं । आप सोचिए कि टैक्सटाइल हो या अन्य कुछ हो । India accounts for 60 per cent of the global vaccine production. दुनिया की 60 परसेंट वैक्सीन भारत बना रहा है, यह भारत के लिए फख्र की बात है । आज जिस तरीके से जेनरिक मेडिसिन है । हमारे यहां आयुष मंत्रालय बना और उस आयुष मंत्रालय के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में सस्ती दवा गरीब को मिले, यह भी प्रधानमंत्री जी की सोच थी । एक गरीब व्यक्ति की, जो देश के जनादेश से प्रधानमंत्री के पद पर आए, उसी के मन में सोच हो सकती है कि हर व्यक्ति सस्ती से सस्ती दवाई खरीद कर अपनी जिंदगी की हिफाजत कर सके । आज उस ग्लोबल मेडिसिन में हमने 20 परसेंट का शेयर ऑक्युपाई कर लिया है ।

मैं जीडीपी की बात करता हूं । हमारी बहन कह रही थी कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के इम्पॉवरमेंट के लिए क्या किया? इनफेंटरी अकेडमी में महिलाओं को दिया, फाइटर पायलट के रूप में दिया, नारी वंदन अधिनियम के रूप में दिया । आज देश और दुनिया के लोग मोदी को केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते हैं, दुनिया के लोग उनको स्टेट्समैन

देख रहे हैं । दो घंटे मैंने स्टूडेंट्स की चर्चा को सुना और मुझे लगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए गाइड हैं, यूथ के लिए मैंटर हैं और महिलाओं के लिए समाज-सुधारक हैं और पूरी दुनिया इनको इस बात के लिए याद करेगी ।

आज जीडीपी के आंकड़े देखिए । ये कहते हैं कि ये आंकड़े हैं । ये हमारे आंकड़े नहीं हैं । नीति आयोग ने कह दिया कि 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकल गए । यह तो आईएमएफ का डाटा है, वर्ल्ड बैंक का डाटा है, स्टेंडर्ड एंड पुअर्स का डेटा है कि आज हमारे पिछले दो क्वार्टर में 7.5 परसेंट हमारी ग्रोथ रेट है । India is becoming one of the fastest growing economies of the world. It is a matter of pleasure and proud for us. इसके लिए भी यह नहीं कह रहे हैं, जबकि यह हमारी इतनी बड़ी उपलब्धि है । आज दुनिया में हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं । यूएस की जीडीपी की ग्रोथ रेट 5.2 परसेंट है, चीन की 5 परसेंट है, रशिया की 5.5 परसेंट है और जो ब्रिक्स देश हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन इत्यादि हैं, उनकी एवरेज 3 परसेंट है ।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं । पूरी दुनिया की संस्थाओं ने कहा था कि भारत की जीडीपी 5.5 परसेंट से ऊपर नहीं जाएगी । दुनिया की एक्सपैक्टेशंस को मोदी सरकार ने आज गलत साबित कर दिया कि जितना दुनिया सोच नहीं सकती उससे ज्यादा भारत आगे चलकर जाएगा और निश्चित तौर से वर्ष 2047 तक विकसित और आत्म निर्भर भारत बनेगा ।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, I made my maiden speech in 2014, when I entered this House, on the Motion of Thanks on President?s Address. Now, since I have declared that I am not going to contest the coming general elections, this would be my final speech in this House for now.

Sir, I come from a family of freedom fighters. My grandfather, Shri Paturi Rajagopala Naidu was a freedom fighter, social worker, reformer, writer and the right-hand of legendary Parliamentarian, Prof. N.G. Ranga. He was also an MLA, MLC and twice, the Member of this very House. My mother was a fourth-term MLA and also a Minister in the Government of Andhra Pradesh. So, I come from a family which has a legacy of fighting for the people.

This is indeed the last Session of the 17^{th} Lok Sabha, and every Member of the House is bidding adieu. The reason that I have decided to not contest the coming general elections is this. It is not easy to sail on two boats in one go, that is, to be in public life and also to continue as an entrepreneur. So, I have decided to give a pause to my political life. Despite stepping aside from electoral politics, my commitment and resolve to serve the nation remain steadfast as I plan to contribute to the country?s development by investing, innovating, creating employment opportunities, and generating revenue and wealth for the nation.

My group of companies is providing jobs to about 17,000 people and undertaking various welfare measures for them and their family members. So, I serve the country in a different form and I am sure this House and people of my State will appreciate my decision.

Before I start my observations on the President's Address, I would like to take the opportunity to first thank our party?s President, Shri N. Chandrababu Naidu *Garu*, who has allowed me to be a part of this House twice. I admit that I have learned a lot from him and he guided me during my tenure and difficult times.

I would also like to thank the Hon. Speaker and all the Chairmen for their help, cooperation, and guidance in this House. I also express my gratitude to the officials of the Lok Sabha Secretariat who are always ready to help the Members. I particularly thank and wish to place on record my admiration for the Reporters sitting at the Table who record and report our speeches verbatim. When I read my speech the next day, I could not stop appreciating the flawless speech that has reached me. So, I also thank them.

And, more than anybody else, I sincerely and wholeheartedly express my deep sense of gratitude to every single team member of my Guntur Parliamentary Constituency, the TDP leaders, and colleagues of Guntur without whose support, cooperation, and blessings I would not have been able to undertake my ten-year successful journey as an MP and would not have done whatever I could for the people of Guntur. So, I once again thank all of them from the bottom of my heart.

Sir, I compliment the hon. Prime Minister, Shri Modiji, for finally consecrating Ram Mandir in Ayodhya, and the entire country is greatly indebted to him. I plan to visit the Temple one day, as it realizes the 500-year-old dream of all Hindus. The world knows that we are one of the oldest civilizations on earth. Here, I only wish to

say that the stones may be old, but they are chiselled afresh. Our civilization may be ancient; but, I feel, it is born again under Modi ji. The last ten years of Modiji's Government may be like any other; but he ensured that it marks a new dawn. The date of 22nd January, in many ways, has redefined and rediscovered our civilization. Not just this, this new Parliament imbued with the fragrance of Ek Bharat, Shreshtha Bharat is one more testimony to our civilization and culture. So, I compliment the hon. Prime Minister for his leadership and vision for the country.

Sir, even though we are not a part of the NDA, I cannot resist my temptation to praise the Government under the stewardship of Shri Modiji over the last ten years, how he has taken this country to new heights and we are on the verge of becoming third largest economy in the world. It is not just governance, but it is the leadership that counts, and, that is, Modiji's leadership.

I just want to mention the top ten achievements of this Government which has really brought me a lot of joy. One, he has made our country the fastest-growing economy among G20 countries. Two, twenty-five crore people have been lifted out of poverty and 80 per cent are being given free food grains till 2028. Three, the credit for rolling out GST goes to Modiji. Forex reserves have registered US $ 615 billion now. Four, with the push to Digital India, about 46 per cent of the world's total real-time digital transactions take place in India; 1200 crore transactions were done through UPI in Dec'23; now, even Eiffel Tower ticket can be purchased through UPI. Five, an amount of Rs.34 lakh crore have been transferred through DBT and

JAM Trinity and has helped to curb corruption. Six, 3.75 lakh kilometers new roads have been constructed in villages; 1.46 lakh kilometers new National Highways and 150 airports have been constructed; Seven, One-Nation-One-Power Grid, One-Nation-One-Gas-Grid, One-Nation-One-Ration-Card, One-Rank-One-Pension have all been welcomed. Eight, successful dealing with the COVID-19 pandemic and free vaccines to more than 150 countries. Nine, 33 per cent reservation for women; women as fighter pilots for the first time; women cadets given admission for the first time in Sainik Schools and the National Defence Academy, and the tenth is the PM-KISAN and PM Fasal Bima Yojana which have been a great boon for the farmers of this country.

Sir, the House is aware that I spoke on various subjects relating to local, State, national, and international issues during my 10-year tenure in this House, and gave valuable suggestions and recommendations, including in the Committees that I participated in. Some of them have been accepted and have been implemented as policy also. I thank Modiji and this Government for the same.

Sir, with your permission I wish to touch upon a few things which I have been able to achieve for the people of Guntur. I fought for the capital Amaravati. I raised it many times in Parliament. I am still supporting the farmers' agitation which is going on for more than 1,500 days for making Amaravati as the sole capital. It is still happening in my constituency.

Sir, I request for just a few more minutes. This is my final speech. Please indulge me and give me a couple of minutes.

I could get Rs. 1,500 crore for the development of Amaravati and Rs. 1,000 crore for my constituency in Guntur for the underground drainage system from the Central Government. Nearly 20,000 houses are sanctioned in the Guntur Lok Sabha constituency area and 50,000 free water connections to the poor have commenced. I have been instrumental in getting chilli and turmeric better remunerative price and also geotagging of chillis for export. I also succeeded in getting exemption of tax on capital gains on the first sale of land for farmers from 29 villages of Amaravati. The Kondaveeti Vagu Lift Irrigation project was completed. Many lift irrigation projects were completed in the constituency. There have been completed AIIMS at Mangalagiri, CHC in Thullur and PHCs at Chebrolu, Duggirala, Vatticherukuru and Madikonduru. I played a crucial role in announcing Amaravati as a Smart City. Development of Guntur road infrastructure, including the Inner Ring Road, and various railway works are under progress. One Kendriya Vidyalaya at Tenali has been established during my tenure. There is also a National Agricultural University for Guntur. Rs. 60 crore worth of development works were undertaken in 10 years with MPLADS & MGNREGS funds. And, the list goes on.

Sir, the hon. President has rightly mentioned about setting up of a Central Tribal University in Telangana. I welcome it. But at the same time, I ask the hon. Prime Minister as to what his Government has done about various institutions mandated to be set up in the State of AP under the AP Reorganisation Act. As per the 13th Schedule of this Act, the Government of India should set up 11 institutions, right from a tribal university to National Institute of Disaster Management.

Sir, the less I talk about Polavaram the better. When the TDP left the Government in 2019, about 75 per cent of the project was completed. But now, even after five years, it appears that the project is exactly where it was five years ago. Since this is my final speech in this House, my appeal to the Hon. Prime Minister is to approve the 2nd revised cost estimate of the project, which comes to Rs. 55,656 crores, and complete the project in a time-bound manner.

Sir, again, I do not want to enter into a debate on special category status to AP. It was Modi ji and former Vice President, Shri Venkaiah Naidu *Garu*, who promised SCS for 10 years to the State. Nothing happened and the Government of India is trying to escape by showing non-existing 14th Finance Commission recommendations. AII I ask the hon. Prime Minister is to either give special category status to AP or extend all facilities, financial and otherwise, that are being extended to the North-Eastern and hilly States, also to AP as a stop-gap arrangement, till SCS is conferred, for a period of 10 years.

Sir, there are other issues also such as setting up of a major port, integrated steel plant, crude oil refinery and petrochemical complex, and establishing a new railway zone in Visakhapatnam, development of a metro rail facility in Visakhapatnam and connecting Vijayawada-Guntur-Tenali among other things. The Railway Minister is on record saying that Government of AP has not given land for a new railway zone, but the Government of AP says that it has given the land. Whom should I believe, Sir? We need a clarification.

Sir, since I am not speaking on the Budget, I wish to touch upon a couple of points on the Indian economy. By moving from the 10^{th} largest economy 10 years ago to the 5^{th} largest, it is an indisputable fact that we are one of the biggest bright spots in the world's economy today. Modi Ji rightly says that we have immense potential backed by impressive performance during the last decade as we could demonstrate and showcase robust and resilient growth driven by perseverance, ingenuity and vision. I wish that Bharat continues this in the coming years and becomes the 3^{rd} largest economy in the next two to three years of time.

Sir, we all should agree that reforms help us to be the fastest growing economy among G20 countries. The growth this fiscal is estimated to be about 7.5 per cent when compared to 9.1 per cent in 2021-22 and 7.2 per cent in 2022-23. Forex reserves are over USD 615 billion; FDI is impressive; foreign trade is going up; 25 crore people came out of poverty; unprecedented creation of infrastructure took place; 23.5 lakh crore tax receipts and 30.3 lakh crore revenue receipts are very healthy; and less anticipation of borrowings is there in the coming fiscal. I am sure that Bharat is poised to achieve the set goals in *Amrit Kaal*, and the list goes on.

But, at the same time, we should admit that we are not able to provide jobs that people are expecting. We are still making the industry run from pillar to post for approvals and permissions, particularly in sectors like EVs and lithium-ion battery manufacturing, among others, and imposing duties on them, despite claiming that Government of India is facilitating ease of doing

business. I appeal to the hon. Prime Minister to focus a little bit more on this. Otherwise, it is not easy to achieve the objectives behind Atmanirbhar Bharat.

There are some challenges that our economy is facing, such as increasing integration of the global economy, and to be in tune with that, we have to push our domestic performance and be also ready to bear the spillover effects of the global economy. The second is Artificial Intelligence and the challenges it poses to Governments, given apprehensions that AI may eat away jobs, particularly in the services sectors. The third is non-availability of talented and skilled workforce in the industry. I am sure, the Government is looking into these and other issues to further propel growth to become the third largest economy.

Sir, we are in the election year and a couple of months from now we are going to have General Elections and also Assembly elections in my State. For free and fair elections, the Election Commission should ensure error-free electoral rolls. But, if you look at Andhra Pradesh, the ground reality is the other way around. The DEOs and EROs are not following the directives of the ECI in preparing error-free electoral rolls due to pulls and pressures from the ruling dispensation.

The delegation of TDP met the full ECI and a letter was also written by former CM, Shri Nara Chandrababu Naidu garu, about the subjugation of the democratic rights of the people of Andhra Pradesh through electoral malpractices and removing names of TDP supporters and sympathizers from the electoral list. So, there is a need

to immediately deploy Electoral Roll Observers in Andhra Pradesh from Government of India to stop these electoral malpractices. The unfortunate part is that the field machinery deployed, instead of correcting mistakes in the electoral rolls which is the crux of the issue, took a casual approach by transferring the responsibility to lower officers and not following strict and meticulous instructions given by the ECI.

As I said, Sir, I am taking a break from politics. The reason is I cannot sail on two boats at the same time due to various limitations. I feel, that businessmen are a very important part of the political process, which is essential in my opinion as they play a pivotal role in driving the economy and its growth. They need to have freedom to express themselves and to take a stand against the Government of the day, when necessary, without fear of reprisals and attacks on their businesses. This institution, the Parliament should ensure law-abiding businesses are not exposed to harassment even if they do not share the same political views. This is extremely important because if we look at the affidavits submitted by all the Members, 20 per cent of the Lok Sabha Members are declared as businessmen. I am sure all of them are having the same problems that I have faced in these last ten years.

In the developed world, business people are encouraged to be a part of the political administration as they can play an important part in helping people take charge of their economic destinies. Unfortunately, in our country, this means constant fear of reprisals and vendettas. To start and run a business, one has to get more than

70 approvals from various agencies at the local, State, and Central level, and each of these agencies can be weaponized by the party in power which is detrimental to the Make in India initiative, Atmanirbhar Abhiyaan and defeats the very objective of Ease of Doing Business.

While I may be stepping away from politics, I will not be sleeping. I will continue to contribute to my State and to the country, as a businessman, by investing, innovating, and creating employment opportunities, revenue, and wealth for the nation. When I can devote my full time to politics and be the type of representative that I want to be and that people deserve, just like Shri Rama?s return after his 14 years of *vanavas*, I will also come back stronger.

With these words, I support the Motion and thank the hon. President for her Address to both the Houses. Thank you, for giving me the time, Sir.

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव जी हमेशा पॉजीटिव पॉलिटिक्स करते हैं । बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जो एप्रिशिएबल हैं । हमारी प्रेजीडेंट साहिबा ने जो कहा, जिसमें हम चंद्रयान की सफलता के ऊपर वैज्ञानिकों को मुबारकवाद देते हैं और दुनिया में पहली बार साउथ पोल के ऊपर हम लोग पहुंचे हैं । जी-20 का सफल आयोजन हमारे देश के लिए गर्व की बात थी । एशियन गेम्स के अंदर हमने जो पदक लिए, वह भी शायद पहली बार इतने पदक लिए हैं ।

सभापति जी, खेलो इंडिया स्कीम एप्रिशिएबल स्कीम है लेकिन हमारे देश में कुछ नेगेटिव चीजें भी हुई हैं । हमने देखा कि लोक सभा में कुछ

कानून ऐसे बने, जिनकी वजह से हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान परेशान हुए और फिकरमंद हुए । सीएए कानून आया । पहली बार आजाद हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कानून बना, जिसमें धर्म के आधार पर डिफरेंशिएट कर दिया गया । अगर श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान की शरण में आना चाहता है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी लेकिन दूसरे देशों के मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी ।

क्या हमारे कानून के दायरे में यह बात सही है? महोदय, इसी तरह से आर्टिकल 370 हटाया गया लेकिन आर्टिकल 371 नहीं हटाया गया । हमसे कहा गया कि आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं क्योंकि मैं अभी कश्मीर होकर आया हूं । कश्मीर के लोगों में जितना डिस्सेटिसफेक्शन है, उसका अंदाजा शायद हमारी पार्लियामेंट को नहीं है । हर दूसरे दिन कोई न कोई आतंकवादी घटना होती है । आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर को क्या मिला? मुसलमानों के शरीयत में दखलंदाजी की गई और तीन तलाक का बिल आया । हिंदुस्तान के लोगों को एक प्रकार से मैसेज दिया गया क्योंकि किसी को हिजाब से परेशानी होने लगी, किसी को नमाज से होने लगी, किसी को अजान से परेशानी होने लगी, किसी को मस्जिद से और किसी को मदरसे से परेशानी होने लगी । क्या यह वही देश है जहां हमने साथ मिलकर, एक साथ अपना खून देकर इस देश को आजाद कराया था । आखिर किस जगह जाकर मसला खत्म होगा । एक मसला बाबरी मस्जिद का हुआ । सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया । वह फैसला था लेकिन वह इंसाफ नहीं था । अब ज्ञानवापी दूसरी मस्जिद का काम शुरू हो गया है । उसमें भी एक जज साहब जो रिटायर होने वाले थे, उन्होंने फैसला दे दिया । इसके बाद मथुरा, मथुरा के बाद ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद और तीन हजार मस्जिदों पर लोग क्लेम करते हैं तो आने वाले समय में देश का क्या हाल होगा, यह सोचने की बात है । पार्लियामेंट को इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम अपनी आने वाली नसलों को क्या देने जा रहे हैं । हम

उन्हें प्यार-मोहब्बत देने जा रहे हैं या नफरत देने जा रहे हैं । यह सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? यह सिलसिला बंद होना चाहिए ।

महोदय, एपिडेमिक की स्थिति आई । मैं अपने साइंटिस्ट्स को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत जल्दी वैक्सीन तैयार की और सस्ती तैयार की । वैक्सीन को हमने दुनिया में सप्लाई किया लेकिन एपिडेमिक के आंकड़े हमने क्यों छिपाए? हमारी सरकार कहती है कि तकरीबन पांच लाख लोग मारे गए, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर पचास लाख लोग कोविड के समय मरे । इन आंकड़ों को छिपाने की क्या जरूरत थी क्योंकि इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है, यह तो एपिडेमिक था । देश के अंदर हमने यह दौर भी देखा था कि जब मरीज अस्पताल जाते थे तो उन्हें आईसीयू नहीं मिलता था, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी । दिल्ली के अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस के अंदर लोगों की मौतें हुईं । मरने के बाद जब शमशान घाट लेकर गए तो जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली । उसे गंगा के किनारे दबा दिया गया और उनकी लाशों को जानवरों ने नोचा । इस बात की किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए । इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यकीनी तौर पर सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं । वे बड़ी-बड़ी बातें करके अपनी पीठ थपथपाते हैं लेकिन यह देखने की बात है कि जमीनी हकीकत क्या है ।

सभापति जी, हमने देखा कि किसानों के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ । हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ और 700 किसान शहीद हो गए । किसानों के लिए ऐसा समझा गया कि किसी दुश्मन मुल्क के लोग यहां आकर बैठ गए हैं । कभी कीलें लगाई गईं, कभी कंक्रीट की दीवारें बनाई गईं । वह बिल वापस लिए गए । जब बिल लाए थे तो कह रहे थे कि किसानों के हित के लिए हैं । जब वे बिल वापस ले लिए तो कह रहे थे कि यह भी किसानों के हित में है । यह क्या था?

खाद की बात कही गई । एक दौर था जब यूरिया का बैग 125 रुपये में मिलता था लेकिन आज वह 330 रुपये में मिलता है । एनपीके का बैग 400

रुपये का था जो आज 1300 रुपये का मिल रहा है । डीजल बहुत महंगा हो गया है । किसान की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसकी आय कम हो गई है । आप कह रहे है कि किसान की आय दोगुनी करेंगे । आप किसान के लिए एमएसपी में क्या कर रहे हैं? यह सोचने की बात है कि आपने कितनी एमएसपी की है ।

सर, हम इस बात को जानते हैं । यूरिया और एनपीके के जो कट्टे थे, उसमें आपने पाँच किलोग्राम कम कर दिया, फिर भी आपने कीमतें बढ़ा दीं ।

दुनिया में एक वैश्विक विवाद हुआ, एक बहुत बड़ा विवाद फिलीस्तीन और इज़रायल के बीच हुआ । हमारी सरकार ने उस घटना के पाँच घंटे के अन्दर ही इज़रायल की हिमायत करने का एलान कर दिया । तमाम दुनिया यह जानती है । कोई आदमी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अगर कोई स्टेट आतंकवादी हो जाए कि वह बच्चों को न देखे, बच्चों को मार दे, महिलाओं को मार दे, बुजुर्गों को मार दे, निर्दोष लोगों को मार दे तो क्या हमारा फर्ज़ नहीं बनता कि उसका भी हम विरोध करें? हमारी सरकार, हमारी पार्लियामेंट से दुनिया के अन्दर कोई मैसेज जाना चाहिए था कि यह जो जुल्म हो रहा है, यह खत्म होना चाहिए । लेकिन, हमने उसके लिए कुछ नहीं कहा ।

सर, सोलर पावर में हमें नम्बर-1 पर होना चाहिए था, किसानों को सोलर पम्प्स मिलने चाहिए थे । सोलर पम्प्स की स्कीम आई है, लेकिन इसके लिए जो वेबसाइट है, वह मुश्किल से बस पाँच मिनट के लिए खुलती है और उसके बाद फौरन बंद हो जाती है । मेरी डिमांड है और मेरा पार्लियामेंट में यह कहना है कि सारे किसानों को सोलर पम्प्स मिले, ताकि उनके डीजल का खर्च बचे । हमारा सपना है कि हर घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगें, ताकि एनर्जी में हम आत्मनिर्भर हो जाएं ।

सर, आप कहते हैं कि धर्म के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं । पर, पिछले दिनों हमने इसे देखा है और हमने पार्लियामेंट में इस बात को कई बार उठाया है कि मदरसों में आधुनिक टीचर्स रखे गए थे, जिन्हें 50 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी । जब हमने उस बात को यहां रखा तो उसका नतीजा यह हुआ कि अब वे आधुनिक टीचर्स भी खत्म कर दिए गए । वे टीचर्स प्राइमरी क्लास के लाखों बच्चों को पढ़ाते थे । हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी बेसिक सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें जितनी बच्चों की तादाद है, उससे ज्यादा बच्चों को वे टीचर्स पढ़ाते थे । पर, उन्हें तनख्वाह देने की बात तो दूर है, उन टीचर्स के पद को ही खत्म कर दिया गया ।

हमने देखा कि मुसलमानों के लिए जो स्कॉलरशिप्स थे, जैसे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप, उसे खत्म कर दिया गया । मेरिट-कम-मीन्स, जो रिसर्च स्कॉलर्स को मिलते थे, उसे खत्म कर दिया गया और आप कहते हैं कि हम डिस्क्रीमिनेट नहीं करते हैं । अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का बजट क्यों कम किया गया?

सर, हम पूरे पार्लियामेंट में आपसे यह बात कहना चाहते हैं कि हम उस वक्त तक विकसित भारत नहीं हो सकते, जब तक देश में हम सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बना लेते । हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी इस वक्त परेशान है और बहुत उलझन में है । वह अपने मुस्तक़बिल और अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है ।

बहुत-बहुत शुक्रिया ।

श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार): आदरणीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने, बहुत से वक्ताओं ने यहां अपने विचार साझा किये और खुशी इस बात की हुई कि सदन की कार्यवाही बहुत समय के बाद बिना किसी व्यवधान के, बिना नारों के, बिना पोस्टरबाजी के, और बिना निरर्थक वॉक-आउट्स के चली है । मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं कि जब अठारहवीं लोक सभा आएगी तो इस परिपाटी को आगे बढ़ाया जाएगा ।

महोदय, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार से, बहुत आंकड़ों का सहारा लेकर अपनी बात कह चुके हैं । ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ नया और कुछ अनकहा जोड़ पाऊं । मैं अपने दिए गए समय में कुछ ही बिन्दुओं पर केन्द्रित रहूंगा ।

सभापति महोदय, सदन के दूसरी ओर से मेरे कई वरिष्ठ साथियों ने एक बात पर बहुत जोर दिया कि this Government is high on symbolism and low on substance. अगर इसका साधारण हिन्दी अनुवाद करूं तो वह कुछ इस तरह से है कि इस सरकार में प्रतीकात्मकता की अधिकता है और सार या तत्व की कमी है । उन्होंने विशेष तौर पर इस संदर्भ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ?मेरी माटी मेरा देश?, ?पंच प्रण?, अमृत वाटिकाओं इत्यादि का वर्णन किया । मैं इनकी बातों से सहमत हूं । मैं इससे सहमत हूं कि ये सब अत्यंत प्रतीकात्मक चीज़ें हैं । मैं इसे और आगे बढ़ाना चाहूंगा और कुछ और प्रतीकात्मक कृत्य आपके ध्यान में लाना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, इनमें पहला है - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी । यह सरदार पटेल की 600 फीट ऊँची भव्य प्रतिमा है । यह किस चीज़ की प्रतीक है? यह इस विराट देश की अखंडता का और उस भारतीय गणतंत्र का प्रतीक है, जिसमें सामंतियों का, राजे-रजवाड़ों का, जात-पात, धर्म के ठेकेदारों का, विभाजनकारी और फिरकापरस्त शक्तियों का कोई स्थान नहीं है । यह प्रतीक है, इसी राष्ट्रीय अखंडता का अंतिम अध्याय लिखने का, जिसमें जम्मू कश्मीर से अंतत: धारा 35ए और 370 को निरस्त कर सही मायने में भारत

को संगठित करने का काम किया गया । मुझे जानकर बड़ा हर्ष हुआ, हालांकि अब तो विपक्ष का सारा स्थान खाली है, लेकिन मुझे बड़ा हर्ष हुआ, जब विपक्ष के लीड स्पीकर ने चाहे-अनचाहे अपने वक्तव्य में जम्मू-कश्मीर के सिर्फ पूर्ण राज्य के दर्जा बहाली तक की सोच रखी । इस संदर्भ मुझे विश्वास है कि सरकार उनकी यह मंशा जल्द ही पूर्ण कर देगी ।

सभापित महोदय, एक और प्रतीकात्मकता का यहां ज़िक्र हुआ ? सैंगोल का । सैंगोल जो कि न्याय और स्वराज का प्रतीक है । दुर्भाग्यवश यह सैंगोल इस बात का भी साक्षी रहा कि जब पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको जब ऑपनिवेशिक मानसिकता, कोलोनियल माइंडसेट से बाहर निकाल कर, नए ज़माने और नए भारत के परिवेश के अनुसार न्याय प्रदान करने के तीन कानून इस सदन में लाए गए तो विपक्ष ने इस पर बहस से पल्ला झाड़ लिया । मैं इनको कहना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ियां आपके इस गैर-ज़िम्मेदाराना किरदार को हमेशा याद रखेंगी और सैंगोल उसकी याद हमेशा दिलाता रहेगा । यह इस सदन का इतिहास है, जो रचा गया है ।

तीसरा प्रतीक जिसका मैं ज़िक्र करूंगा । इंडिया गेट की छत्तरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित करना भी प्रतीक है, उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्हें इतिहास के पन्नों में उचित सम्मान नहीं मिला और इतिहास से उन्हें गायब करने का प्रयास किया गया । कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाए, इतिहास उन्हें भुला देता है । यह प्रतीक है, उस इतिहास को सदा याद रखने का । इसी प्रकार 26 जनवरी की परेड में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देना भी उस नारी शक्ति का प्रतीक है, जिसका सही मायने में उदय होना अब शुरू हुआ है । सेना में महिलाओं को शामिल करना हो या संसद और राज्य की विधान सभाओं में एक तिहाई स्थान देना वाला कानून हो, यह सब मोदी जी की सरकार में ही संभव हुआ है । इसी संदर्भ में ज़िक्र किया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध

अपराध और हिंसा पर अंकुश लगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो । इसके हम सब पक्षधर और प्रयासरत हैं । लेकिन मेरा अपने प्रतिपक्ष के सदस्यों से यह अनुरोध रहेगा कि आंकड़ों की आड़ में छिप कर दलगत राजनीति के आधार पर इन अपराधों की गिनती गिनाना न तो तर्कसंगत है और नहीं शोभनीय है । इससे बचा जाए तो सबके लिए बेहतर है ।

चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचना भी एक प्रतीकात्मक है । यह प्रतीक है हमारे देश के साइंसदानों की कमरतोड़ मेहनत, निष्ठा, कौशल का, भारत को विज्ञान, खास तौर पर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा करने का । इसके लिए मैं सभी सांइसदानों का नमन और धन्यवाद करता हूँ ।

सर, मैं एक और दिलचस्प प्रतीक का उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि वह अभी सामने आना है । 14 फरवरी को प्रधान मंत्रीजी यूएई के आबूधाबी में बने भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे । क्या यह भारत और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच बढ़ती घनिष्ठता का प्रतीक नहीं है? क्या यह उस हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को धता नहीं बताता, जिसे भुनाने में कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल हमारे देश में निरंतर लगे रहते हैं? उन्हें इसके बारे में गहरा विचार करने की आवश्यकता है ।

सर, जी-20 का कामयाब आयोजन हो, क्वाड हो, आई-2 यू-2, या ब्रिक्स हो, सबमें भारत की प्रमुखता है । पर्यावरण में कॉप समिट हो या यूक्रेन-रूस का संघर्ष हो, दुनिया के हर पटल पर आज भारत की ओर आशा की नज़रों से देखा जाता है । यह हमारी विदेश नीति की कामयाबी है । यह हमारे प्रधान मंत्री जी के अथक प्रयासों का परिणाम है । इसके लिए हम सब उनके धन्यवादी हैं ।

सभापति महोदय, एक-दो बातें विपक्ष के साथियों ने कहीं, जो मुझे बड़ी अटपटी सी लगीं, हास्यास्पद भी थीं । एक ने तो कहा कि अंग्रेजों के जाने के

बाद से नई रेलवे लाइनें ही नहीं बिछी हैं, उनका कोई विस्तार ही नहीं हुआ । मुझे यह कथन बड़ा अजीब सा लगा । अगर उन्होंने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ठीक से सुना होता या पढ़ लिया होता तो पता चल जाता कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं और करीब-करीब 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन भारतीय रेलवे का हो चुका है । मैंने दो दिन पहले ही हमारे रेल मंत्री जी का बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत हर वर्ष स्वीट्ज़रलैंड जितनी रेलवे लाइन बिछा रहा है । पूरे स्विट्जरलैंड में रेलवे की जो जाल है, वह करीब 5,200 किलोमीटर का है । पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार निरंतर 5,000 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर की रेलवे लाइन इस देश में बिछा रही है । फिर ये कहते हैं कि वंदे भारत कौन-सी ट्रैक पर चल रही है, यह बड़ा अजीब सा कथन है, पता नहीं कहां से ढूंढ कर लाए हैं?

सभापति महोदय, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि नेशनल हाइवेज़ डेढ़ लाख किलोमीटर लंबे हो गए हैं, 149 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पौने चार लाख किलोमीटर नयी सड़कें बन चुकी हैं । आप सब इसका रोजाना उपयोग कर रहे हैं । प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ।

सभापति महोदय, देश में करीब 31 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं । मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि जब वह अपने क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग इस सुविधा से वंचित हैं । उनका एक दुखड़ा वह रो रहे थे । मैं उनको बताना चाहूंगा कि 80,000 करोड़ रुपये का लाभ करीब 6.25 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हासिल कर चुके हैं ।

महोदय, 140 करोड़ लोगों का यह देश है, इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ समय तो लगेगा । पिछले दो वर्षों में पौने 17 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड

बनाए गए हैं । चालू वर्ष 2023-24 में भी साढ़े सात करोड़ और नए कार्ड बन चुके हैं ।

माननीय सभापति : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री बृजेन्द्र सिंह : सर, अब मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा । कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, यह हमारी सरकार का मूल मंत्र है । अंत्योदय हर कल्याणकारी योजना का उद्देश्य है और यही आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई का भी ध्येय है । फिर चीन के आक्रामक रवैये का जिक्र किया गया ।

सभापति महोदय, चार साल से हमारी सेना बर्फीली पहाड़ियों में डटी-खड़ी है । पूरे एशिया में भारत एकमात्र देश है, जिसने चीन से इस कद्र लोहा लिया है और देश की संप्रभुता की पुरजोर तरीके से रक्षा की है । उस पर सवालिया निशान उठाना शोभा नहीं देता है । मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस प्रकार की बयानबाजी से गुरेज करें । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस प्रदेश से आता हूं, उसकी रीढ़ की हड्डी कृषि और फौज है । उस संदर्भ में मैं दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा । पीएम किसान हो या कृषि बीमा योजना हो या 14 फसलों को एमसीपी पर खरीदना हो, ये सब अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है । इससे कृषक को बहुत राहत मिली है । अब कृषि क्षेत्र को एक नई सोच, नई दिशा और एक नई शुरुआत की दरकरार है, ताकि कृषि में जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ उत्पन्न हुए हैं, उनको भी एड्रेस किया जा सके ।

दूसरा, अग्निवीर का मुद्दा है । मेरा सरकार से विशेष तौर पर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि अग्निवीर का जो रेगुलर कैडर में जाने का अनुपात व प्रतिशत है, कृपया उसके बारे में आप जरूर पुनर्विचार करें । अगर उसको बढ़ाया जाएगा तो पूरा देश इसके लिए आपका आभारी रहेगा ।? (व्यवधान)

सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । मैं अपनी बात सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक का उल्लेख करके खत्म करूंगा । अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को उसका प्राण-प्रतिष्ठा उन करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, सदियों से इतिहास के अंधकार में सिसकियाँ ले रही जन-मानस की उस उम्मीद का, भारत के जीर्णोद्धार का जिसकी कल्पना पीढ़ी-दर-पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने की । उस आत्म-सम्मान और आत्म -विश्वास का जिसने हजारों वर्ष से अपनी संस्कृति और सभ्यता का संजोए रखा । इसे कोई सदस्य अन्यथा ना ले ? राम सभी के है, राम सब में है । आप सबको मेरा राम-राम, जय हिंद ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, those who want to lay their written speeches on the Table can do so. They will be treated as part of the proceedings. Thank you.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय चेयरमैन सर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो अभिनंदन प्रस्ताव रखा गया है, उस पर मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और नीतियों पर सार्थक संवाद होना चाहिए । अब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि नीतियां सही है या नहीं, सार्थक संवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर इसके ऊपर हम आत्म-निरीक्षण करें तो लगेगा कि सभ्यता में आज काफी गिरावट हुई है । कल महाराष्ट्र में एक विधायक ने पुलिस थाने में जाकर अपनी ही पार्टी के दूसरे व्यक्ति पर गोली चला दी ।

यह हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है । संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, तो मणिपुर में जो कुछ हुआ, वह देश के लिए कलंकित करने वाली बात हुई । आज भी मणिपुर शांत नहीं है । इसका उनके वक्तव्य में कहीं परामर्श नहीं हुआ, उसका मैं खेद प्रकट करता हूं ।

उन्होंने कहा कि भारत 5जी की तरफ जा रहा है । मुझे दुःख हो रहा है कि वर्ष 2014 में जब आए, हम तो गठबंधन से आए, उस वक्त 2जी, 3जी स्कैम की बहुत बात होती थी । उसके बाद, जिनके ऊपर इल्जाम लगे, वे सभी चुनकर आए । उसका क्या हुआ? सब भ्रम पैदा किया गया । आज क्या हो रहा है? भारत संचार निगम, महानगर टेलीफोन निगम ध्वस्त हुआ । 10 वर्ष में हमारी सरकार उन कंपनियों को उबारकर आगे लेकर नहीं आई । यह हमारी असफलता है ।

आपने किसानों के बारे में कहा । किसानों के कानून की बात आपको याद होगी । किसानों के कानून आदरणीय प्रधान मंत्री जी को क्षमा मांगकर वापस लेने पड़े । यह न भूलना कि उसमें 700 किसानों की मृत्यु हुई । इसके लिए कौन जिम्मेदार था? यह भी सोचने की बात है । नारी शक्ति वंदन की बात हुई । उन्होंने कहा कि मैं पहली बार संबोधित कर रहा हूं । वहीं नारी शक्ति का वंदन सोच लीजिए कि पहली बार क्यों आना पड़ा, उसके पहले क्यों नहीं आए, किसने रोका था? यह भी सोचना पड़ेगा । खिलाड़ियों के जो अपमान हुए, वह भी नहीं भूलना है और मणिपुर भी भूलना नहीं है । इसके बाद राम मंदिर के निर्माण की बात कही । मैं इससे बहुत खुश हूं । वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा, आग्रह किया । माननीय भारत रत्न आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वर्ष 1990 में रथ यात्रा निकाली थी । इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब वर्ष 1992 में ढांचा गिरा, तब ये जो आज श्रीराम कहते घूम रहे हैं, सब भाग गए थे । उस वक्त एक ही शख्स इस देश में इसके पक्ष में था । ढांचा गिरने के बाद सभी ने कहा कि यह तुम्हारे लोगों ने गिराया, तो वे बोले

कि हमने नहीं गिराया । मेरे पास तो आदरणीय अटल बिहारी जी की क्लिप है । उन्होंने तो उसका दु:ख व्यक्त किया था । अगर ढांचा न गिरता तो राम मंदिर न खड़ा होता । अगर कारसेवकों की कुर्बानी न होती, तो भी राम मंदिर नहीं खड़ा होता । वंदनीय बाला साहब ने कहा कि अगर यह मेरे शिव सैनिकों ने गिराया होगा, तो मुझे इस पर गर्व है । यह कहने वाला एक ही हिंदू हृदय सम्राट था, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे । हमें राम मंदिर के निर्माण में बहुत हर्ष है, बहुत आनंद है । जो होना चाहिए था, वह हो गया । मैं इतना ही कहूंगा,

ऐ मेरे वतन के रामभक्तों, जरा आंख में भर लो पानी,

मंदिर के लिए जो शहीद हुए, उनकी याद करो कुर्बानी ।

वह न भूलना, वह हम लोग भूल गए । किसी एक शख्स ने सपोर्ट किया था । जो कभी वहां गए ही नहीं थे, वे आज बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं । हम उनमें से हैं, जिनके लिए रामलला प्यार हैं, कुछ लोगों के लिए रामलला व्यापार हैं । हम उनमें से हैं, जिनके लिए राम लला प्यार हैं, कुछ लोगों के लिए राम व्यापार हैं । हमारे लिए राम, प्रभु राम नीति हैं, तो कुछ लोगों के लिए राजनीति है । हमारे लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं । कुछ लोगों के लिए राम प्रचार उत्तम हैं । उसके आगे उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, जबकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है । दोनों जो ये विचार हैं, यह देखिए कि यह क्या चीज है? 130 करोड़ की आबादी और हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं । हम उनको गरीबी से ऊपर नहीं ला पाए हैं । 80 और 25 करोड़ पकडूं तो 105 करोड़ हो गए, बाकी क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे यह सवाल है ।

आपने स्टार्ट अप की बात की । पेटीएम का क्या हुआ? रिजर्व बैंक ने उसके पर बंदी लागई है । ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीएसटी में सब कांट्रैक्टर का एक क्लॉज है । मैं कल बोलने वाला था, लेकिन आज बोल देता

हूं कि सब कांट्रैक्टर के क्लॉज पर उसको बहुत तकलीफ हो रही है । उसको जीएसटी भरने के बाद भी जुर्माना भरना पड़ रहा है । एनसीएलटी के कारोबार पर ध्यान देना पड़ेगा ।

महोदय, आज बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है । आपने तो देखा है कि जेट एयरवेज बंद हुआ, किंगफिशर बंद हुआ, गो एयर बंद हुआ । आपको पता है कि एनसीएलटी में लोगों की देय रकम 70 लाख रुपये तक गई । एनसीएलटी कहती है कि 23,500 ले लो और पीछे हट जाओ । हमारी बैंक हां कहती है । हमने लड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक गए । अभी तक उनको पीएफ का पैसा नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया । एक कंपनी, जो घाटे में चली गई । अपने लाडले उद्योगपति के छोटे भाई की कंपनी है, कितना घाटा हुआ, 46 हजार 500 करोड़ रुपये घाटा हुआ । कंपनी लिक्विडेशन के बाद एनसीएलटी में गई, एनसीएलटी ने क्या कहा, यह कंपनी हम 4 हजार 500 करोड़ रुपये में बेच देंगे, 46 हजार 500 करोड़ रुपये कर्ज है, बैंक हाँ कहती है । बड़े भाई इस कंपनी को खरीद लेते हैं, आप सोच लो, कहां जा रहे हैं । दुर्भाग्य की बात है, छोटे बच्चों को नहीं बता सकते, गरीब लोगों को मालूम नहीं है । सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी के बारे में बताया कि यह 7 प्रतिशत से 10.8 प्रतिशत बढ़ी, ग्रामीण बेरोजगारी 6.2 से 10 प्रशित बढ़ी, हम लेबर कानून रोजगार के लिए लाए, उसमें न सामाजिक सुरक्षा है न कानूनी सुरक्षा है ।

आपने बंदरगाह के विकास की बात की । आदरणीय गडकरी साहब ने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, बंदरगाह को विकसित करने के लिए बनाया था । मुंबई बंदरगाह के लिए आपने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया । जितने भी उद्योग आए, ड्रग्स पार्क हो, डिवाइस हो, मेडिकल डिवाइस, सब गुजरात लेकर चले गए, हमें इस बात का दुख नहीं है, गुजरात भी हमारा ही है । आज के दिन तो दे दो ।

माननीय सभापति : लास्ट कमेंट करके आप एक मिनट में खत्म कीजिए । समय नहीं है, बहुत सारे स्पीकर्स बोलने वाले हैं ।

श्री अरविंद सावंत : सभापति महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा कि हम पांच स्थानों को पंच तीर्थ बना रहे हैं । संविधान की सुरक्षा करो, वह ज्यादा अच्छा रहेगा । ज्येष्ठ नागरिकों के लिए आपने सारी फेसिलिटीज बंद कर दी । भारतीय जन औषधि परियोजना, भारतीय बी, जन औषधि का जे, परियोजना का पी, टेबलेट में भी बीजेपी, यह तुम्हारा प्रचार है, इतने नीचे गिर जाओगे, अलग अक्षर, बोल्ड अक्षर और अलग कलर में, इसका आप ध्यान रखना ।

मैंने मंदिर निर्माण के बारे में कहा ही है, उसके लिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा । प्याज का भाव देखो, किसान आज भी परेशान है, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है । उसको भाव नहीं मिल रहा है, एमएसपी की बात मत कीजिए, झूठ हो रहा है । फिर दोबारा रामलला की बात उनके भाषण हुई, एक भजन बताता हूं ।

रामचन्द्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा,

हंस चुनेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा ।

मैं राम मंदिर से यही अपेक्षा करता हूं कि राम राज की कल्पना करो, राम राज आना चाहिए । अगर राम राज आया तो आदरणीय मोदी जी को सभी सर पर चढ़ाएंगे, लेकिन राम राज नहीं चल रहा है, ईडी, सीबीआई चल रहा है, इसके लिए मैं इतना ही कहता हूं ।

देखो ओ दीवानो तुम यह काम न करो

राम का नाम बदनाम न करो ।

जय हिन्द ।

श्री हँसमुखभाई एस. पटेल (अहमदाबाद पूर्व) : मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं । जिस प्रकार भारत की महामहिम राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों और भावी योजनाओ पर विचार प्रस्तुत किया गया है, जिसपर मैं अपने कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं-

आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, यह सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से ही सम्भव हो रहा है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चार साल सात मास पूरे किये है । यह सरकार गरीबो, वंचितों, किसानो, दलितों और वनवासी बंधुओ के लिये कार्य कर रही है ।

लोकतंत्र में लोगो से फिर से मिला जनादेश नये भारत के निर्माण के लिये दिया गया है, एक ऐसा नया भारत जिसमे हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो ओर जो 21वी सदी में विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से एक ऐसा नया भारत जो चौथी औद्योगिक क्रांति मे अग्रणी भूमिका निभाये ओर विश्व मंच पर हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचे ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने संसद के दोनों सदनो की सयुंक्त बेठक को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा एक सशक्त भारत के निर्माण की दिशा के सबंध मे उठाये गये क्रांतिकारी कदम की हमे जानकारी दी जो किसानो, महिलाओ, गरीबो ओर युवाओ सहित आम नागरिकों के लिये उत्साहवर्धक है, अभिभाषण मे देश की गौरवमयी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था की तस्वीरो की झलक थी । आजादी का

अमृतकाल, चन्द्रयान - 3, मेरी माटी मेरा देश अभियान की सराहना की है, और

इस उत्सव के दौरानः

1. मेरी माटी, मेरा देश अभियान के तहत, देश भर के हर गाँव क मिट्टी के साथ अमृत कलश दल लाए गए ।

2. 2 लाख से जादा शिला-फल कम स्थापित किए गए ।

3. 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली ।

4. 70 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बने ।

5. 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ ।

6. 2 करोड़ से ज्यादा पेड़-पौधे लगाए गए ।

7. 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी फोटो अपलोड की ।

अमृत महोत्सव के दौरान ही :

1. कर्तव्य पथ पर नेता जी सुभाष चंद्रबोस की प्रतिमा स्थापित की गई ।

2. राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियो को समर्पित म्यूजियम खोला गया ।

3. शांति निकेतन और होयसला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए ।

4. साहबजादों की याद में वीर बाल दीवस घोषित हुआ ।

5. भगवान बरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया ।
6. विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया गया ।

और उपलब्धियां जो आज दिख रही हैं, वे बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार हैं :

हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे थे । अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे है । नीति आयोग के अनुसार, मेरी सरकार के एक दशक के कार्य काल में, करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं । यह प्रत्येक गरीब में विश्वास जगाने वाली बात है । जब 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है ।

पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है । आज दुनिया भारत को देखना और जानना चाहती है । इसके अलावा, शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है । जगह-जगह एयरपोर्ट बनने से भी बहुत फायदा हो रहा है । नॉथ-ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं । अंडमान निकोबार और लक्षदीप को लेकर उत्साह चरम पर है, सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलोंके विकास पर बल दिया है, जिससे भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है, बीते एक वर्ष में साढ़े आठ करोड़ लोग काशी गए हैं । 5 करोड़ से अधिक लोगों ने श्री महाकाल के दर्शन किये हैं, 19 लाख से अधिक लोगों ने श्री केदार नाथ धाम की यात्रा की है, अयोध्या धाम में ही 1 प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, भारत को मीटीग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती

है, इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, आने वाले समय में टूरिस्म, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा ।

श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एकात्म मानवता के दर्शन माध्यम से अंत्योंदय की कल्पना को साकार करते हुए 'सबका साथ सबका विकास' के मजबूत संकल्प को मूर्तिमंत किया है ।

इस तरह हमारी सरकार सर्वांगीण विकास के लिये हर एक पहलू पर विकास कर रही है 'मेक इन इंडिया', स्कील इंडिया आदि के एकीकृत पहल के माध्यम से रोजगार सर्जन प्रशस्त हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र मे उत्कृष्टता एवम अनुसंधानो को प्रोत्साहन, स्वास्थय, स्वछता, तथा कुपोषण को जड़ से खत्म करने हमारी सरकार कृत संकल्पित है, आइये हम सब मिलकर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधीजी के सपनों के एक समृध्ध भारत के निर्माण दिशा में आगे बढ़े, और हमारी सरकार ने ऐसे अनेक अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करता हूँ ।

सधन्यवाद ।

***m25 श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल):** मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं । जिस प्रकार भारत की महामहिम राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों और भावी योजनाओ पर विचार प्रस्तुत किया गया है, जिसपर मैं अपने कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं-

आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, यह सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से ही सम्भव हो रहा है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चार साल सात

मास पूरे किये है । यह सरकार गरीबो, वंचितों, किसानो, दलितों और वनवासी बंधुओ के लिये कार्य कर रही है,

लोकतंत्र में लोगो से फिर से मिला जनादेश नये भारत के निर्माण के लिये दिया गया है, एक ऐसा नया भारत जिसमे हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो ओर जो 21वी सदी में विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से एक ऐसा नया भारत जो चौथी औद्योगिक क्रांति मे अग्रणी भूमिका निभाये ओर विश्व मंच पर हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचे,

महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने संसद के दोनों सदनो की सयुंक्त बेठक को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा एक सशक्त भारत के निर्माण की दिशा के सबंध मे उठाये गये क्रांतिकारी कदम की हमे जानकारी दी जो किसानो, महिलाओ, गरीबो ओर युवाओ सहित आम नागरिकों के लिये उत्साहवर्धक है, अभिभाषण मे देश की गौरवमयी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था की तस्वीरो की झलक थी । आजादी का अमृतकाल, चन्द्रयान - 3, मेरी माटी मेरा देश अभियान की सराहना की है, और

इस उत्सव के दौरानः

1. मेरी माटी, मेरा देश अभियान के तहत, देश भर के हर गाँव क मिट्टी के साथ अमृत कलश दल लाए गए ।

2. 2 लाख से जादा शिला-फल कम स्थापित किए गए ।

3. 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली ।

4. 70 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बने ।

5. 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ ।

6. 2 करोड़ से ज्यादा पेड़-पौधे लगाए गए ।

7. 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी फोटो अपलोड की ।

अमृत महोत्सव के दौरान ही :

1. कर्तव्य पथ पर नेता जी सुभाष चंद्रबोस की प्रतिमा स्थापित की गई ।

2. राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियो को समर्पित म्यूजियम खोला गया ।

3. शांति निकेतन और होयसला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए ।

4. साहबजादों की याद में वीर बाल दीवस घोषित हुआ ।

5. भगवान बरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया ।

6. विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए, 14 अगत को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया ।

और उपलब्धियां जो आज दिख रही हैं, वे बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार हैं :

हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे थे । अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे है । नीति आयोग के अनुसार, मेरी सरकार के एक दशक के कार्य काल में, करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं । यह प्रत्येक गरीब में विश्वास

जगाने वाली बात है । जब 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है

पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है । आज दुनिया भारत को देखना और जानना चाहती है । इसके अलावा, शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है । जगह-जगह एयरपोर्ट बनने से भी बहुत फायदा हो रहा है । नॉथ-ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं । अंडमान निकोबार और लक्षदीप को लेकर उत्साह चरम पर है, सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है, जिससे भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है, बीते एक वर्ष में साढ़े आठ करोड़ लोग काशी गए हैं । 5 करोड़ से अधिक लोगों ने श्री महाकाल के दर्शन किये हैं, 19 लाख से अधिक लोगों ने श्री केदार नाथ धाम की यात्रा की है, अयोध्या धाम में ही 1 प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, भारत को मीटीग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती है, इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, आने वाले समय में टूरिस्म, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा ।

श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एकात्म मानवता के दर्शन माध्यम से अंत्योंदय की कल्पना को साकार करते हुए 'सबका साथ सबका विकास' के मजबूत संकल्प को मूर्तिमंत किया है । इस तरह हमारी सरकार सर्वागीण विकास के लिये हर एक पहलू पर विकास कर रही है 'मेक इन इंडिया', स्कील इंडिया आदि के एकीकृत पहल के माध्यम से रोजगार सर्जन प्रशस्त हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र मे उत्कृष्टता एवम अनुसंधानो को प्रोत्साहन, स्वास्थय, स्वछता, तथा कुपोषण को जड़ से खत्म करने हमारी सरकार कृत संकल्पित है, आइये हम सब मिलकर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधीजी के सपनों के एक समृद्ध भारत के निर्माण दिशा में आगे बढ़े, और हमारी सरकार ने ऐसे

अनेक अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करता हूँ ।

सधन्यवाद,

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ । माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह परिलक्षित होता है कि केन्द्र सरकार "सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास" के वायदे के अनुरूप देश को तेज गति से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है । देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा सरकार के इस समावेशी आर्थिक विकास के केन्द्र में है । अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा कि इस नए संसद भवन में यह मेरा पहला संबोधन है । आजादी के अमृतकाल की शुरुआत में यह भव्य भवन बना है । यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है । भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है । इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है । साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए, नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है । आजादी के 75वे वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया तथा "मेरी माटी, मेरा देश अभियान" के तहत देश भर के हर गाँव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली में लाए गए । 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पंच प्राण की शपथ दिलायी गयी । देश भर में 70 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बने । 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण किया गया । 2 करोड़ से ज्यादा पेड़-पौधे लगवाए गए । 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की । कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित की गयी । राजधानी स्थित नई दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम को खोला गया है । साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस घोषित हुआ । भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया । विभाजन की

विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया । माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि दुनिया में गंभीर संकटों के बावजूद भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना और लगातार 2 क्वार्टर में भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत से ऊपर रही है । भारत, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना । भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई । ऐतिहासिक जी-20 सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया । पिछले 10 वर्षों में, भारत ने राष्ट्र-हित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था । राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी जो आज यह सच हो चुका है । जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने को लेकर शंकाएं थीं । आज वे इतिहास हो चुकी हैं । इसी संसद ने तीन तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया गया । हमारे पड़ोसी देशों से आए पीडित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून बनाया । वन रैंक वन पेंशन को भी लागू किया, जिसका इंतजार चार दशकों से था । क्च्च लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं । भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है । नीति आयोग के अनुसार, करीब 25 करोड देशवासी गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं । यह प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है । जब 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है ।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो यह विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में है तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है । दिसंबर 2017 में, 98 लाख लोग GST देते थे, आज इनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख है । 2014 से पहले के 10 वर्षों में, लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे । पिछले 10 वर्षों में, देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं । 2014-15 में, लगभग 2 हजार इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे । जबकि 2023-24 में दिसंबर माह

तक ही लगभग 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं । बीते दशक में सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है । इसी का परिणाम है कि हम सभी बडे आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं । कोई भी राष्ट्र, तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह पुरानी चुनौतियों को परास्त करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए । सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है । इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं । मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुके हैं । भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है । पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है । कुछ साल पहले भारत खिलौने आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है । भारत का डिफेंस प्रोडक्शन एक लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है । आज हर भारतीय, देश में बने एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत को देखकर, गर्व से भरा हुआ है । लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं ।

आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेनदेन का 46 प्रतिशत भारत में होता है । इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेनदेन हुआ है । दुनिया के दूसरे देश भी आज UPI से ट्रांजेक्शन की सुविधा दे रहे हैं । डिजिटल इंडिया के कारण बैंकिंग आसान हुई है और लोन देना भी सरल हुआ है । जनधन आधार मोबाइल (JAM) की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिली है । केन्द्र सरकार अब तक 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से ट्रांसफर कर चुकी है । जनधन आधार मोबाइल (JAM) के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं । इससे पौने 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं । डिजिलॉकर की सुविधा भी जीवन को आसान बना रही है । इसमें अभी तक यूजर्स के 6 बिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी हुए हैं । आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है । डिजिटल के

साथ-साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश हुआ है । आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसका सपना हर भारतीय देखता था । पिछले 10 वर्षों के दौरान गांवों में पौने 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनीं हैं । नेशनल हाईवे की लंबाई, 90 हजार किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख 46 हजार किलोमीटर हुई है । फोर-लेन नेशनल हाइवे की लंबाई ढाई गुना बढ़ी है । हाई-स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी, जो आज 4 हजार किलोमीटर है । एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से दो गुना बढ़कर 149 हो चुकी है । देश के बड़े बंदरगाहों पर cargo handling capacity दोगुनी हो गई है । ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है । देश की लगभग 2 लाख गांव पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है । 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स भी खुले हैं जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं । देश में 10 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई है । वन नेशन, वन पावर ग्रिड से, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है । वन नेशन, वन गैस ग्रिड से, गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है । सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है । 25 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए । यह कई विकसित देशों के कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई से ज्यादा है । भारत, रेलवे के शत-प्रतिशत बिजलीकरण के बहुत निकट है । इस दौरान भारत में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरु हुई हैं । आज 39 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं । अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है । केन्द्र सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी । ये स्तंभ हैं - युवाशक्ति, नारीशक्ति, किसान और गरीब । देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं । इसलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है । सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है । 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला । इस पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गए । लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है

। इस पर 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं । हाल में ही 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन पूरे हुए हैं । आज इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस भी दी जा रही है । इस पर भी सरकार द्वारा ढाई लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं । कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है । अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है । अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान है । सरकार का प्रयास है कि हर योजना का तेजी से सैचुरेशन हो । कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे । इसके लिए 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है । अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं ।

माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि बीते वर्षों में विश्व ने दो बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया । ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीय का बोझ नहीं बढ़ने दिया । 2014 से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 8 प्रतिशत से अधिक थी । पिछले दशक में औसत महंगाई दर 5 प्रतिशत रही । सरकार का प्रयास रहा है कि सामान्य देशवासी की जेब में अधिक से अधिक बचत कैसे हो । पहले भारत में 2 लाख रुपए की आय पर टैक्स लग जाता था । आज भारत में 7 लाख रुपए तक की आय पर भी टैक्स नहीं लगता । टैक्स छूट और रिफॉस के कारण भारत के टैक्सपेयर्स को 10 साल में करीब ढाई लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है । आयुष्मान योजना के अलावा भी केंद्र सरकार, विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देती है । इससे देश के नागरिकों के साढे तीन लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं । जन-औषधि केंद्रों की वजह से मरीजों के करीब 28 हजार करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं । कोरोनोरी स्टेंट, घुटने के इंप्लांट तथा कैंसर की दवाओं की कीमत भी कम की गई है । इससे मरीजों को हर वर्ष लगभग 27 हजार करोड़ रुपए की बचत हो रही है । किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस का अभियान भी चला रही है । इसका लाभ प्रतिवर्ष 21 लाख से ज्यादा मरीज उठा रहे हैं । इनके प्रतिवर्ष एक लाख रुपए खर्च होने से बचे हैं । गरीबों को सस्ता राशन

मिलता रहे, इसके लिए मेरी सरकार ने पिछले दशक में करीब 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारतीय रेल में यात्रा के लिए रेलवे, प्रत्येक टिकट पर, करीब 50 प्रतिशत डिस्काउंट देती है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को हर वर्ष 60 हजार करोड़ रुपए की बचत होती है। गरीब और मध्यम वर्ग को कम कीमत पर हवाई टिकट मिल रहे हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्ग को हवाई टिकटों पर 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। LED बल्ब की योजना के कारण, बिजली के बिलों में 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के तहत, गरीबों को 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की क्लेम राशि मिली है। नारीशक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारीशक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। सरकार ने जल, थल, नभ और अंतरिक्ष, हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन और 40 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, समूहों को 15 हजार ड्रोन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से देश की लाखों महिलाओं को बहुत मदद मिली है। सरकार ने महिलाओं को पहली बार सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन दिया है। पहली बार सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स को प्रवेश दिया गया है। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी हैं और नौसेना के जहाज को भी पहली बार कमांड कर रही हैं। मुद्रा योजना के तहत जो 46 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं उनमें करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिले हैं। इस योजना से लाभ लेकर करोड़ों महिलाओं ने स्वरोजगार शुरु किया है। केन्द्र

सरकार किसानों के लिए खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर बल दे रही है । हमारा यह प्रयास है कि खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक हो । पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी है । पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपए, किसानों को मिल चुके हैं । 10 सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30 हजार करोड़ रुपए प्रीमियम भरा । इसके बदले उन्हें डेढ़ लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है । पिछले 10 वर्षों में, लगभग 18 लाख करोड़ रुपए MSP के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं । यह 2014 से पहले के 10 सालों की तुलना में ढाई गुना अधिक है । पहले तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीद नहीं के बराबर थी । पिछले दशक में तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को डैच के रूप में सवा लाख करोड़ रुपए मिले हैं । किसानों को सस्ती खाद मिले, इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं । पौने दो लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं । अभी तक लगभग 8 हजार किसान उत्पादक संघ FPO बनाए जा चुके हैं । सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है । इसलिए, देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है । सहकारी क्षेत्र में, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है । जिन गांवों में सहकारी समितियां नहीं हैं, वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही हैं । मत्स्य पालन क्षेत्र में 38 हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन पिछले दस साल में 95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग दोगुना हो गया है । इनलैंड फिशरीज का उत्पादन 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मीट्रिक टन हो गया । मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30 हजार करोड़ रुपए से बढकर 64 हजार करोड़ रुपए तक, यानी दोगुने से ज्यादा बढ़ा है । देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है । पिछले दशक में, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40 प्रतिशत बढ़ी है । पशुओं को

खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है । अब तक, चार चरणों में, 50 करोड़ से ज्यादा टीके, पशुओं को दिए जा चुके हैं । जनकल्याण की ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सिर्फ सुविधाएं भर नहीं हैं । इनका देश के नागरिकों के पूरे जीवन-चक्र पर सकारात्मक असर पड़ रहा है ।

बीते वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययन में सामने आया है कि 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच बंद होने से, अनेक बीमारियों की रोकथाम हुई है । इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रति वर्ष 60 हजार रुपए तक की बचत हो रही है । पाइप से शुद्ध पेयजल मिलने से भी प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की जान बच रही है । पीएम आवास योजना पर हुए अध्ययन के अनुसार, पक्के घर से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ी है । पक्के घरों में बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है और ड्रॉप आउट की दर में कमी आयी है । प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की वजह से आज देश में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहे हैं । इस वजह से माता मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है । एक और अध्ययन के अनुसार, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों में, गंभीर बीमारी की घटनाओं में कमी आई है । मानव केंद्रित विकास पर बल दे रही है । हमारे लिए हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है । यही सामाजिक न्याय की हमारी अवधारणा है । भारत के संविधान के हर अनुच्छेद का संदेश भी यही है । हमारे यहां लंबे समय तक सिर्फ अधिकारों पर चर्चा होती थी । हमने सरकार के कर्तव्यों पर भी बल दिया । इससे नागरिकों में भी कर्तव्य-भाव जागा । आज अपने-अपने कर्तव्य के पालन से हर अधिकार की गारंटी का भाव जागृत हुआ है । केन्द्र सरकार ने उनकी भी सुध ली है, जो अब तक विकास की धारा से दूर रहे हैं । ऐसे हजारों आदिवासी गांव हैं जहां बीते 10 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची है । लाखों आदिवासी परिवारों को अब जाकर पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ है । विशेष अभियान के तहत मेरी सरकार, हजारों आदिवासी बहुल गांवों में 4 जी इंटरनेट सुविधा भी पहुंचा रही है । वनधन

केंद्रों की स्थापना और 90 से ज्यादा वन-उपज पर MSP दिए जाने से, आदिवासियों को बहुत लाभ हुआ है। पहली बार, जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की सुध ली है। उनके लिए लगभग 24 हजार करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बनाई है। आदिवासी परिवारों की अनेक पीढ़ियां सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित रही हैं। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरु किया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। दिव्यांगजनों के लिए भी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाया है। साथ ही, भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं। ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु भी कानून बनाया गया है। विश्वकर्मा परिवारों के बिना, दैनिक जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी, अपने कौशल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सरकारी मदद के अभाव में, हमारे विश्वकर्मा साथी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। मेरी सरकार ने ऐसे विश्वकर्मा परिवारों की भी सुध ली है। अभी तक पीएम विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। रेहडी-ठेले-फुटपाथ पर काम करने वाले साथी भी दशकों से अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी सरकार ने, पीएम स्वनिधि योजना द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ा। इस योजना के तहत, अब तक 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार ने इन पर भरोसा करते हुए, बिना collateral के ऋण दिया। उस भरोसे को मजबूत करते हुए, अधिकांश लोगों ने ऋण तो वापस किया ही, अगली किश्त का भी लाभ उठाया। इस योजना के अधिकतर लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र पर चल रही मेरी सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर देने में जुटी है।

केन्द्र सरकार, भारत की युवाशक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई

गई और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है । इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में प्रारंभ कर दी गई है । स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मेरी सरकार, 14 हजार से अधिक पीएम श्री विद्यालयों पर काम कर रही है । इनमें से 6 हजार से अधिक विद्यालय शुरु हो चुके हैं । सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है । उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले ज्यादा हो रहे हैं । अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन में लगभग 44 प्रतिशत वृद्धि हुई है । अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 65 प्रतिशत और ओबीसी के विद्यार्थियों की 44 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है । इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10 हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए है । इनमें 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं । साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे । वहीं पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं । 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं । MBBS की सीटों में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है । पर्यटन क्षेत्र, युवाओं के लिए रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है । मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है । भारत में घरेलू टूरिस्ट्स की संख्या के साथ ही, भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है । पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है । आज दुनिया भारत को देखना और जानना चाहती है । इसके अलावा, शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है । जगह-जगह एयरपोर्ट्स बनने से भी बहुत फायदा हो रहा है । नॉर्थ-ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं । अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है । देश भर में तीर्थों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है । इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है । वहीं दुनिया भी, भारत में हैरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हो रही है । बीते एक वर्ष में साढ़े आठ करोड़ लोग काशी गए हैं । 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं । उन्नीस लाख से अधिक

लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है । अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे । पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है ।

अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा अपने अभिभाषक्षण में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने के लिए लायी गई विभिन्न योजनाओं और कार्यकमों का स्वागत और पुरजोर समर्थन करता हूं ।

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा 17 वीं लोकसभा के अखिरी राष्ट्रपति अभिभाषण व नए संसद भवन में प्रथम संबोधन, सविधान लागू होने का 75 वां वर्ष और महामहिम जी के द्वारा लगभग 75 मिनट दिए गए संबोधन का समर्थन करती हुई । में समर्थन करती हूँ महामहिम जी के द्वारा पैरा 7 में कही गई बात का जिसमें उन्होने कहा कि -"कोई भी राष्ट्र, तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह पुरानी चुनौतियों को परास्त करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए ।"

मैं महामहिम जी की सभी बातों का समर्थन करते हुए, विकसित भारत की भव्य इमारत जो 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है मुख्य रूप से उन स्तंभों पर चर्चा करना चाहूगी. वो-चार स्तम्भ जिनके माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंती आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना चाहते है ।

"प्रथम स्तम्भ " - युवा शक्ति

'युवा शक्ति का वंदन अभिनंदन करने में आई हूँ, नई उमंगो को फिर से मैं नभ में उड़ाने आई हूँ? हमारे युवा शक्ति को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से नई राह मिले इसके लिए हमारी सरकार निरंतर नए कदम उठा रही है,

चाहे वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाकर तेजी से लागू करने का कार्य किया हो, या स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 14 हजार से अधिक विद्यालयों में पी एम श्री के माध्यम से कार्य करने काम कर रही हो । या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दे कर - इंजीनियरिंग, मेडिकल, कनून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में प्रारम्भ करने का कार्य कर रही हो । युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, IIT आदि की स्थापना करना व सीटों को दोगुना करने का कार्य कर रही हो ।

युवा शक्ति को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए हम स्पोट्स इकॉनामी को भी मजबूत कर रहे है । ऐसे तमाम योजनाएं जिनसे आने वाले समय में युवा मजबूत हो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा ।

"दूसरा स्तम्भ"- नारी शक्ति

?नारी को अबला समझ, मत कर भारी भूल
नारी इस संसार में, जीवन का है मूल ।'

इन पंक्तियों को ओर मजबूत करने, महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास कराने और उन्हें पंख लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, जब हम महिला के कल्याण और उत्थान की बात करते हैं तो चार सबसे महत्वपूर्ण चीजें जाती है- (i) शिक्षा, (ii) सुरक्षा, (iii) आर्थिक स्वावलंबन, (iv)राजनैतिक सशक्तिकरण जहाँ शिक्षा की बात आती है वहाँ हमारी सरकार 'बेटी पढ़ाओ' का नारा देकर एक अभियान बनाया और हमारे देश की बेटियां सिर्फ पढ़ ही नही रही बल्कि अच्छे नम्बरों के साथ उत्तीर्ण हो कर बड़े-बड़े पदों पर भी अपना स्थान निश्चित करने का काम कर रही है ।

जहाँ बात सुरक्षा की आती है तो हमारी सरकार ने कहा Zero Tolerance against the Women Violence तो सिर्फ कहा नहीं बल्कि हिंसा को बिल्कुल सहन न करने वाली सरकार है ।

आर्थिक स्वावलंबन की बात आती है तो हमारी सरकार ने कहाँ महिला देश के विकास में बराबर की हिस्सेदार है तो सिर्फ कहा नहीं बल्कि राजनैतिक सशक्तिकरण को भी ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत विधेयक पास कर हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे कर भी मजबूत करने का काम कर रही है ।

आज हमारी सरकार महिलाओं को मजबूत करने के लिए हर सम्भव कदम उठाने का काम कर रही है चाहे वह स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जुड़ी महिलाओ को 8 लाख करोड़ रूपए बैंक लोन और 40 हजार करोड रुपए की आर्थिक सहायता के माध्यम से हो, या 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चल कर मजबूत करने का हो या नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से 15 हजार ड्रोन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हो या सैनिक स्कूलो और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैन्डिडेंट्स को प्रवेश के माध्यम से या महिला फाइटर पायलट हो अथवा नौसेना के जहाज को कमांड करना हो हर क्षेत्र में महिला सशक्त और सक्रिय हो रही है ।

'तीसरा स्तम्भ - किसान

आज तक हम सिर्फ गाना सुना करते थे-

?मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती...

लेकिन जिनके मेहनत, परिश्रम और लगन से ये धरती सोना उगलती थी उसकी चिंता किसी को अगर हुई तो वो भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी को हुई, जिन्होनें हमारे अन्नदाता को सम्मान स्वरूप 'किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 2 लाख 80 हजार करोड़ किसान भाईयो को सम्मानित करने का काम किया ।

उनके फसलों की चिंता कर फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षा देने का काम किया तो वहीं सस्ती खाद की भी व्यवस्था की । कृषि यंत्रो पर भी कृषि यंत्र अनुदान योजना के माध्यम से यंत्रो पर सब्सिडी का लाभ भी देने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है ।

चौथा स्तम्भ ? गरीब

हमारी सरकार पूर्व के नेताओ की भांति गरीबी मिटाने का नारा नहीं दिया, बल्कि इस देश से गरीबी को कैसे मिटाया जाए उस पर काम कर रही है चाहे वह गरीब परिवार को छत देकर आज लगभग 4 करोड प्रधानमंत्री आवास बनाने का हो या गरीब परिवार में हर घर में इज्जत घर हो, इसकी चिंता कर बहन-बेटियों को सुरक्षित रखने का काम किया हो आज 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हमारी सरकार ने किया, गरीब परिवारों को 'उज्जवला योजना के तहत लगभग 10 करोड गैस चूल्हा देने का काम हो या लगभग 81 करोड परिवार को मुफ्त राशन देकर उन्हें नई दिशा देने का काम हो या गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसकी चिंता हो, चाहे स्वच्छ जल की चिंता हो हर घर नल से जल पहुँचाने का हो, या गरीब के स्वास्थ की परवाह कर आयुष्मान भारत कार्ड के ताहत लगभग 55 करोड लोगों को 5 लाख रूपए वार्षिक इलाज के लिए देकर उनको सुरक्षित रखने का काम कर रही है ।

आज यदि भारत चौमुखी विकास कर रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी की दूरदर्शिता का नतीजा है । तभी तो कहते है - चार स्तंभों का कल्याण, देश का कल्याण - मोदी से पहले समस्या थी, मोदी के बाद समाधान है । मोदी से पहले विवाद था. मोदी के बाद विश्वास है, मोदी से पहले गरीबी थी, मोदी के बाद समृद्धि है, मोदी से पहले बेरोजगारी थी, मोदी के बाद कौशल विकास है । मोदी हैं तो मुमकिन है ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): I thank you very much for allowing me to express my views on the motion of thanks to the President's Address.

To be very frank, the countrymen expected a lot from the President?s Address as this address is the last one of the incumbent governments, but the people of this country were greatly disappointed as there was no mention of the many challenges the country is facing such as huge unemployment, skyrocketing inflation or price rise, the threat emanating from the tail like neighbouring countries, etc. The Address is like an election speech and presents a progress card of the government, but for the countrymen, it depicts a wasteful 10 years of the country since the year 2014. By portraying a bad into good cannot become good. A decoration without solid support cannot withstand and may fall and this is what is going to happen in the next 2024 elections, the people will expose the government.

It was assured to the youths of the country that the government shall provide two crore jobs every year, and the total number of jobs to be created during these last nearly 10 years amounts to twenty crore, but I am surprised that the government only distributed a few thousands of appointment letters here and there. Even the one lakh fifty thousand youths who were supposed to be inducted into the army were not lucky enough to have it. The unemployment ratio in this country is moving so fast surpassing the speed of a Cheetah The

youths have no direction on what to do and the conditions of our youths are that they are even ready to go into a country where their life can be at risk due to wars or conflicts. We saw thousands of youths lined up for jobs in Israel and the prevailing conditions in Israel are a well-known fact to all of us. This is the pathetic condition of our youths today.

Many promises were made in the past that the government would bring down the prices of all essential commodities The fact is that the benefit of a reduction in the global crude oil price has not been passed on to the people and the people are bound to pay the same price when the global crude oil price was at its peak There is no relief for the women who take care of the kitchen from the escalating price of cooking gas. The prices of all essential commodities have increased manifold and the common man was not able to bear the brunt of escalating price rises on it. On the one hand, people are without jobs or earning avenues, and on the other side, the prices of all essential commodities have become beyond their reach to buy.

The government claims that it lifted twenty-five crore people from poverty, but the fact is that the government itself is bound to provide a free ration of 5 kg food gains to above 80 crore. What does this mean. is it not contradicting what the government claims and the reality prevailing in the country?

Another serious thing that I noticed in the Address is that there has been no mention of the Chinese occupation of our territory since the year 2020. There are reports that more than 4,000 sq.mtrs. of our land has been encroached by China and the people in border areas of

our country were not able to move freely on their land. This is a fact that even the party man of this government is publicly saying about this on various social media.

It was widely publicized the vision of the government which aims the government to make Hawai chappal wala board the flight and quoted many actions in this regard But what we are experiencing is that many State governments have been pleading with the Union government to take action to reduce the airfares as airfares have become not affordable to even affordable segments. So what to talk about Hawai chappal wala boarding the flight. One should preach what he can translate. Many thousands of Keralites who are working abroad and in other parts of the country were not able to visit their hometowns in festive seasons due to exorbitant airfares. Many organizations working for the welfare of Keralites based in many countries were demanding to take steps to reduce the airfares or allow them chartered flights. But nothing is heard and the government is repeating the slogan "My dream was Hawai Jahaz for people with Hawai Chappal" which is in total contradiction to the reality. Even the people were not able to undertake pilgrimage to pilgrim places like performing Haj, etc.

Another cause of concern is increasing road accidents in the country, but in the Address no mention has been made of it. According to the World Health Organisation, road accidents across the globe are fastly declining but in our country, it is steadily increasing. Keeping a check on the increased road accidents in the country is also equally important for laying or constructing more

kilometers of roads. The authorities should take serious note of suggestions they receive from the State governments of any local body institutions from time to time to prevent road accidents by rectifying unscientific methods adopted while laying roads.

In recent times it has been noticed the deviation from the attention of the railways' priority, resulted in many rail accidents in the country, including the infamous Balasore rail accidents which killed hundreds of people. It has been reported widely that one of the reasons for the increased rail accidents is due to the huge shortage of staff consisting of loco pilots, security-related staff, etc. The shortage of staff is piling up and it seems that the government is moving on this at a snail's speed. Another issue which I would like to state here about the increased trade deficit. The trade deficit has reached to unprecedented level, especially with China. The government claims increased exports, but the reality is that we have a huge trade deficit.

The Government has assured the farmers that their income will be doubled by 2022. But the conditions of our annadhataas are that even they were not able to recover the cost they incurred for cultivation. It was assured that the Minimum Support Price on all agricultural produce would be increased, but it is still on paper. Similarly, the rubber growers in the State of Kerala are having a tough time on all accounts and the Rubber Board is not coming to their rescue rather than sending rubber plants to some north-eastern states from Kerala.

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): राष्ट्रपति का अभिभाषण एक संविधानिक जिम्मेदारी है और संविधान ने सरकार को यह दायित्व दिया है की वो हर वर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से पूरे देश के समक्ष अपना Report card रखें । मान्यनीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से विकसित भारत के लिए सरकार का क्या लक्ष्य होंगे उसका आधार रखा है ।

हमारी सरकार ने PM-KISAN के माध्यम से किसानों का मशनिकरण, समग्र शिक्षा अभियान से स्कूल जाने वाले बच्चों का सशक्तिकरण, जन धन योजना से आर्थिक सशक्तिकरण, उज्ज्वला योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण, आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र से स्वास्थ्य सेवाओं का नशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से देश की बेटियों का सशक्तिकरण, उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं का मशक्तिकरण, प्रधान मंत्री आवास योजना से मध्यम वर्ग परिवारों का सशक्तिकरण, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना से स्वरोज़गार को बढ़ावा दिया और खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं और खिलाडियों को प्रोत्साहन दिया ।

यही तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की आधारशिला है । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बताया कि किस प्रकार अमृत काल का यह 25 वर्ष का कालखंड, स्वतंत्रता की स्वर्ण शताब्दी का, और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है । और अब हमारा मिशन अगले 25 वर्षों में भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का होगा और हम सब पर जिम्मेदारी होगी क्योंकि हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है । सरकार ने अपनी सफल नीतियों से इस देश की दशा को बदला है । आज सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई है चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, युवा हो, महिलाओं हो , पिछड़ा समाज हो या छोटे उद्योग हो । यह इसलिए मुमकिन था क्योंकि सरकार ने Ek Roadmap और Plan of Action के माध्यम से विकास करने का लक्ष्य रखा । हमारा देश जो कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की

समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है । हमने कोरोना जैसी महामारी में देश को vaccine के माध्यम से अमृत देने का काम किया । 2014 से सरकार की विचारधारा थी 'सबका साथ, सबका विकास' । समय के साथ इसमें 'सबका विश्वास' और 'सबका प्रयास' भी जुड़ गया । आज भारत में एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है, जिससे विकसित देश भी प्रेरणा ले रहे हैं । आज सिर्फ घोषणा नहीं Implementation भी हो रहा है और हर वर्ग का विकास हो रहा है । मैं एक सांसद होने के साथ एक डॉक्टर भी हूँ और मैंने व्यक्तिगत स्तर पर देखा ही कैसे बीमारी एक परिवार को गरीबी में धकेल देती है । सरकार ने इसका ध्यान रखते हुए आयुष्मान भारत योजना शुरू की । इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई । आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है, उनके 80 हजार करोड़ रुपए खर्च होने से बचाएं हैं । आज देशभर में करीब नौ हजार जनऔषधि केन्द्रों में बहुत कम कीमत में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । इससे बीते वर्षों में गरीबों के करीब 20 हजार करोड़ रुपए बचे हैं । यानि सिर्फ आयुष्मान भारत और जनऔषधि परियोजना से ही देशवासियों को एक लाख करोड़ रुपए की मदद हुई है । बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है । इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए । दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेज़ी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना । लगातार 2 क्वार्टर में भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत से ऊपर रही है । भारत, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना । भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया, धरती में 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई । ऐतिहासिक G-20 सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया । भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते । पैरा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते । भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री-पुल, अटल सेतु मिला । भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली । भारत, दुनिया में सबसे तेज़ी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना । भारतीय

एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की । पिछले साल भी, मेरी सरकार ने, मिशन मोड में, लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है ।

पिछले 10 वर्षों में, भारत ने राष्ट्र हित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था । राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी । आज यह सच हो चुका है । जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने को लेकर शंकाएं थीं । आज वे इतिहास हो चुकी हैं । इसी संसद ने तीन तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया । इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून बनाया ।

सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को भी लागू किया, जिसका इंतजार चार दशकों से था । OROP लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं । भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है ।

देश की जनता के हित में हमारी सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास की विचारधारा का पालन करते हुए देश के समग्र विकास के लिए कार्य किया है । मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): मैं महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर अपने विचार रखता हूँ ।

वास्तव में आजादी के बाद देश के अमृत काल खंड में इस नवीन संसद भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण भारत के एक नए

युग के आरंभ का परिचायक बन गया और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिन्होंने त्याग, बलिदान और अपने सर्वस्व न्योछावर कर प्राणों की आहुति तक देते हुए देश की एकता अखंडता और वैभव को कायम कर आजाद भारत की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति देश के अमृत कालखंड में महामहिम ने आभार प्रकट किया । हम उनके प्रति आभारी है और स्वयं भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धानवत होकर उनके परिजनों के प्रति आभारी हैं । जिन्होंने आज हमें आजाद भारत में गौरव के साथ दुनिया में फिर भारत को सिरमौर बनाए जाने का यह शुभ अवसर प्रदान किया है ।

मैं महामहिम के अभिभाषण पर इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में भगवान बिरसा मुंडा की जनजाति हेतु गौरव दिवस घोषित किए जाने की चर्चा करते हुए, भारत के राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को अविस्मरणीय बनाने के लिए स्थापित की गई प्रतिमा का भी जिक्र किया और भारत की विभाजन के विभीषिका दिवस 14 अगस्त का भी अपने अभिभाषण में उल्लेख किया, जो हमारे लिए अविस्मरणीय और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है ।

इन बिंदुओं पर महामहिम द्वारा हमें स्मृति दिलाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश की एकता, अखंडता, वैभव शांति और उत्थान के लिए हमें पथ प्रदर्शन के रूप में चिरस्मरणीय रखना होगा ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में भारत के गौरव को

स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की, जिसमें उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और आज वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करने के बावजूद भारत लगातार दो तिमाहियों में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना है । भारत की विकास दर 7.5% से अधिक रही है । वहीं उन्होंने भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बनने तथा आदित्य मिशन की सफलता का जो जिक्र किया वह वास्तव में हमारे वैभव, गौरवशाली परंपरा व विश्व के मार्गदर्शन के रूप में स्थापित होने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा ।

इसलिए मैं इस बात के लिए भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । मैं विधायी उपलब्धियों के लिए भी महामहिम द्वारा अपने अभिभाषण में किए गए जिक्र की स्मृति दिलाते हुए अन्य विधायी उपलब्धियो के साथ-साथ तीन दशकों से लंबे इंतजार के बाद पारित हुए नारी शक्ति बंदन अधिनियम के संबंध में हमारी सरकार की उपलब्धियों के लिए भी सरकार और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

मैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भारत के आधारभूत संरचना के संबंध में विस्तार से दिए गए वक्तव्य के संबंध में भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले दशक में भौतिक बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश पर जोर दिया गया जिसके परिणाम स्वरुप प्रत्येक भारतीयों के बुनियादी ढांचे का सपना साकार हुआ और बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियां शामिल हुई आज 3.75 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण गांव में करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर होना, फोरलेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में ढाई गुना वृद्धि होना, हाई स्पीड कॉरिडोर का 500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक विस्तार और हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी 149 होना,

बंदरगाहों की प्रबंधन क्षमता को दोगुना करना, ब्रॉडबैंड उपयोग करने की क्षमता में 14 गुना वृद्धि होना, 2 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, गांव में चार लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना, रोजगार का अहम जरिया बनता जा रहा है । 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाना, वन नेशन वन पावर ग्रिड का कार्यान्वन, देश में विद्युत परीक्षण को बढ़ाना, पांच शहरों से 20 शहरों में मेट्रो सुविधाओं की व्यवस्था करना, 25000 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक बिछाया जाना, जो विकसित देश की ट्रैक की कुल लंबाई से अधिक है, रेलवे में हंड्रेड परसेंट विद्युतीकरण के करीब पहुंचना, भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की शुभारंभ होना, 39 से ज्यादा रूटों पर बंदे भारत ट्रेनों का संचालन, अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का सौंदरीकरण और इन सब के साथ- साथ सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और सबका विश्वास की परिकल्पना को साकार करते हुए सर्वांगीण विकास की धारा में उत्तरोत्तर नित नूतन प्रयोग करते हुए कार्य करना यह भारत के गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित कर हमें विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने की संबंधित आशा का संचार करता है । इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण एवं सरकार के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूं ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हूँ । महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भारत की जनता को अवगत कराया गया । महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि इस वर्ष देश संविधान के लागू होने कि 75 वीं वर्षगाँठ मना रहा हैं । महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस अवधि में आज़ादी के अमृतकाल के अमृत महोत्सव के समापन पर भी प्रकाश डाला ।

उन्होंने कहा कि अमृतकाल का यह 25 वर्ष का कालखंड, स्वतन्त्रता की स्वर्णिम शताब्दी का, और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है । भारत सरकार के द्वारा इस 25 साल के अमृतकाल के दौरान देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और संगठित कर विश्व के सामने एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को पेश करना हैं । मेरी माटी, मेरा देश अभियान के देश भर से मिट्टी अमृत कलश के माध्यम से दिल्ली पहुंचाई गई, जिसके तहत 2 लाख शिला फलक स्थापित किये गए हैं । देश में 70 हजार से अधिक अमृत सरोवर बनाये गए हैं, साथ ही 2 लाख से अधिक अमृत वाटिकाओं का निर्माण करवाया गया हैं । नेताजी सुभाषचंद्र बोश कि प्रतिमा को कर्तव्य पथ पर स्थापित किया गया हैं । साथ ही देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण भी करवाया गया हैं । इसे माध्यम से देश के युवा को आजादी के महत्व को समझने में काफी सहायता मिल रही हैं ।

आज भारत विश्व में एक नई उर्जा का संचार कर रहा हैं । कल तक जो भारत दूसरों पर निर्भर था, आज विश्व कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा आगे रहता हैं । बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल नेटवर्क के दम पर दुनिया के अग्रिणी देशों में अपना स्थान बना चूका हैं । भारत कि अर्थव्यवस्था विश्व कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है, भारत कि विकास दर 7.5% से बह रही हैं । चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत विश्व का पहला देश बना हैं । साथ ही आदित्य मिशन कि सफलता भी अन्तरिक्ष मिशन में भारत का मील का पत्थर साबित हुआ हैं । जी 20 का सफल आयोजन, भारतीय खिलाडियों द्वारा एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक जीतना, अटल सेतु का निर्माण, बंदे भारत व अमृत भारत सरीखी ट्रेन, तेजी से बढ़ता 5G नेटवर्क आदि भारत कि ऐतिहासिक उपलब्धिया रही हैं ।

भारत सरकार के निर्देशन में लगातार भारत एक से एक समस्याओं से निकल कर अपने दृढसंकल्प के कारण आगे वढ़ रहा हैं । भारत कि निडर

सरकार ने दृढसंकल्प करते हुए कई एतिहासिक फैसले लेने का कार्य किया हैं । तीन दशक के इंतज़ार के बाद देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया हैं, जिससे देश में महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में सुनिश्चित हुई हैं । गुलामी के कालखंड के प्रतीक को समाप्त करते हुए भारत सरकार द्वारा नई न्याय संहिता लाने का कार्य किया गया हैं, जोकि अपने आप में एतिहासिक हैं । डिजिटल देता बिल के माध्यम से देश के आम नागरिक कि डिजिटल सुरक्षा का कार्य भारत सरकार के द्वारा किया गया हैं ।

भारत सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में कई ऐसे कार्य किये गए हैं जिसका देश काफी समय से इंतज़ार कर रहा था । देश में भव्य नव्य राम मंदिर कि स्थापना हुई हैं, धारा 370 अब इतिहास कि बात हो चुकी हैं, तीन तलाक को हटा कर महिलाओं को संबल दिया गया हैं । शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून बनाया गया हैं, वन रेंक वन पेंशन को लागू किया गया, देश में सी.डी.एस कि नियुक्ति कि गई हैं । भारत सरकार के द्वारा गरीबी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाते हुए गरीबी को दूर करने का कार्य किया गया हैं । नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकला गया हैं । भारत का निर्यात आज 775 बिलियन डॉलर हो चूका हैं । एफडीआई दोगुना हुआ हैं, आईटीआर भरने वालों कि संख्या 8 करोड़ को पार कर चुकी हैं । वाहनों कि बिक्री में वृद्धि हुई है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों कि बिक्री में भी जबरदस्त उछाल आया हैं । पिछले एक दशक में भारत में मोबाइल फोन उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हो गई हैं । भारत के खिलौना निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई हैं, मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत को मजबूत करने का कार्य किया हैं । डिफेन्स क्षेत्र में अधिकतर उत्पादन भारत में होने लगा हैं । आईएनएस विक्रांत और C295 एयरक्राफ्ट का उत्पादन इस और मिसाल साबित होगा । एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में बेहतरीन कार्य भारत सरकार के द्वारा किया गया हैं ।

भारत सरकार द्वारा देश के आधारभूत संरचना के विस्तार में पिछले 10 साल में बेहतरीन कार्य किया हैं । देश में 3.75 अख किमी कि नई सड़कों का निर्माण किया गया हैं, साथ ही 90 हजार किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य करवाया गया हैं, चार लेन के राजमार्गों में 2.5 गुना कि वृद्धि हुई हैं । सेतु बंधन योजना के माध्यम से रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाये जा रहे हैं । हवाई अड्डे, हाई स्पीड कॉरिडोर, बंदरगाहों पर कार्गो प्रवंचन, आदि में बेहतरीन कार्य सरकार द्वारा किया गया हैं । देश में इन्टरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कार्य करने हेतु 2 लाख गाँवों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य किया हैं, जिसके कारण देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं में 14 गुना कि वृद्धि हुई हैं । गैस पाइपलाइन के माध्यम से देश के हर घर तक कुकिंग गैस पहुंचने हेतु भारत सरकार द्वारा वृद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा हैं । भारत सरकार द्वारा रेलवे के क्षेत्र में भी अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाए जाने का कार्य किया जा रहा हैं । देश के सभी रेल मार्गों को 100% विद्युतिकृत किये जाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा हैं । अमृत भारतस्टेशन योजना के माध्यम से देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन को आधुनिक किया जा रहा हैं ।

भारत सरकार द्वारा देश के गरीब और माध्यम वर्ग को देव मानकर उनके उत्थान के कार्य कर रही हैं । आयुष्मान भारत आज विश्व कि सबसे बड़ी योजना बन चुकी हैं जिसके तहत भारत सरकार द्वारा देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना दी जा रही हैं । पुरे देश में नौ हजार से अधिक जन औषधि केंद्र खोल कर सस्ते दामों पर दवाये उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे देश के आम नागरिकों को 28 हजार करोड़ कि बचत हुई हैं । गरीबों को रियायती राशन उपलब्ध करवाने पर भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ से अधिक का खर्चा किया गया हैं । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से आमजन को काफी लाभ मिल रहा हैं ।

जल जीवन मिशन पूरे देश के लिए आज वरदान साबित हो रहा हैं। आजादी के 75 सालों में जिन घरों तक पानी नहीं पहुंचा था, आज वहां घर में नल से पानी पहुँच रहा हैं। आज देश के 11 करोड़ परिवारों को सीधे उनके घर में नल से पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा हैं।

भारत सरकार द्वारा देश हितकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वन लगातार किया जा रहा हैं। जिसका ही परिणाम हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को खुद का घर उपलब्ध हो सके इसलिए भारत सरकार अपने वादे पर कटिबद्ध हैं और लगातार इस और अपने सार्थक प्रयास कर रही हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को मकान उपलब्ध हो यही भारत सरकार का ध्येय हैं। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे में परिवर्तन कर देश के किसान कि आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और पिछले 10 साल में भारत सरकार द्वारा देश में होने वाले खाद्यानों, दलहनों व तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% से अधिक कि वृद्धि कि जा चुकी हैं, साथ ही सरकार उन्नत बीज व खाद के माध्यम से कृषि कि लागत को भी कम किये जाने का कार्य कर रही हैं। किसानों को संबल दिए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कि जा रही खरीद में वृद्धि करने का कार्य किया हैं। इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के प्रत्येक किसान को 6000 रूपये सालाना सीधे उनके खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से पहुंचा रही हैं, जिसके तहत अभी तक कुल 2.80 लाख करोड़ रूपये किसानों को जारी किये जा चुके हैं। जिससे देश के किसानों को संबल प्रदान किया गया हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी भारत सरकार द्वारा अनेक कार्य किये जा रहे हैं। जिसके तहत 38 हजार करोड़ से अधिक कि योजनाओं का क्रियान्वन किया जा रहा हैं।

मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, भारत सरकार द्वारा देश की प्रगति के लिए लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाएं राष्ट्र को उन्नति की ओर अग्रेषित करेंगी।

***m32 SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI):** I oppose the Address by Hon'ble President of India to the Parliament delivered on 31 January, 2024. I find there is huge gap between the promise made by the Government and the actual performance on the ground.

The inflation is sky rocketing leaving the hapless poor hopeless and cross-fingered. I am shocked to observe the increasing number of suicides by the farmers. Unemployed youth are running from pillar to post in search of jobs making the promise of the Government to generate two crore employment each year, only an election plank.

The policy and programme of Govermment projected for Viksit Bharat' in the 'Amrit Kaal of Independence' remains a mere dream in the absence of efficient and effective execution of development projects. Paradoxically, Government is claiming for alleviating 25 crore people from poverty, however, Government has to give 5 kg free grains to 80 crore people under PMGKY. We know Nari Shakti Vandan Adhiniyam' is a long drown dream. High price of Gas Cylinders is affecting the household management.

I understand that high flown slogans like 'Meri Maati Mera Desh' is bereft of fragrance of the real nationalism. The personality cult in Governance and naked scramble for power has disrupted social fabric, fraternity, harmony, faith in democratic culture and constitutional provisions.

The uneven and imbalanced distribution of sources between Centre and States is causing stress and strains on co-operative federalism. The economic policies of Government emphasizing on privatization all along, including Airports and other PSUs led to

concentration of resources/money in few corporate pockets, thereby the poor becoming poorer, thus highlighting the hollowness of Govemment's claim Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas'.

Therefore, I find failure of Government's policy and programmes/schemes on all fronts.

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): It seems that The President's Address to the Members in Parliament as Political Speech drafted only to Praise the Government. It appears that government tried to hide the truth. The economic and social issues were crushed in the President's Speech President's policy announcement speech has become nothing but a speech filled with empty claims and inflated figures that has no connection with the social reality of the country. The policy announcement was expected to describe where our country is today and how the government should formulate policies for the future. But the President's speech turned out to be one that did not do justice to anything of the sort.

The speech, which cited the Ram temple in Ayodhya as an example of government excellence, raises doubts whether it is a policy statement of a democratic secular country. In the section mentioning the achievements of the government, the President mentioned that the centuries-old wish of the people of Ram temple in Ayodhya has come true today.

This remark is a clear indication of the way the country is moving forward under BJP rule. The President, who listed the achievements of the Modi government including the Citizenship Amendment Act and the removal of Article 370 of the Constitution, which was passed by subverting the parliamentary proceedings, declared loudly that the hallmark of this government is the destruction of democracy.

Any difficulties or hardships experienced by the poor and the people belonging to the minority and backward sections of the country are not part of the policy announcement. It is clear from the President's speech that the problems faced by the poor and the workers are not influencing the policy making of the government. In the thirty-two-page policy announcement speech, there is not a single word of worker.

The fact that many of the projects mentioned in the speech to praise the government's interventions in the field of infrastructural development, poverty alleviation and women empowerment were only announcements that were not useful to the common people in any way is a fact that calls out the hollowness of this policy announcement.

How can the central government, which follows the policy of selling off the public sector industries and the country's wealth, lead the country to progress? The Modi government, which is taking extremely dangerous positions in all sectors, is putting the country and the people in misery again and again. The President's policy

announcement speech, which does not address any of the challenges or major issues facing the country today, is quite disappointing.

The Central Government, which has not planned any plan to solve the sufferings of the common man, is trying to rob the people and fill the pockets of the corporates. Along with this, the severe communalization policy directly carried out by the government is leading the country to a dark age. The biggest irony is that even in this situation, the President was forced to give a speech in praise the government.

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): I would like to put forth my views on the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. Also I congratulate the Hon'ble President to deliver her maiden address in the new Parliament House which has inaugurated/opened recently.

The Hon'ble President has simplly readout the political speech drafted by the Union Government's and tried to hide the truth of economic failture of the government over the past 10 years and to focus on ahead of the coming general elections. This is the speech of election propaganda and speech filled withy empty claims and announcement. It is clear from the speech that the problems being faced by the common man particularly the poor and the workers are not influenng the policy making of the government.

The President's speech has highlighted many achievements in various fields. In facts, many projects mentioned in the speech to praise the Union Government interventions in the field of

infrastructural development, poverty alleviation and women empowernment were only announcements that were not useful to the common people. The Union government, which is taking extremely dangerous positions in all sectors is putting the country and the people in miser of the challengers or major issues facing the country today, is quite disappointing.

The Union Government which has not planned any plan to solve the sufferings of the common man, is trying to rob the people and fill the pockets of the corporate. However, I would like to put forth the following issues, short-comings and demands before the Union Government to take necessary action at the earliest for the interest of the country and welfare of the people:-

The Union Government has built more airports across the country and has doubled from 74 to 149 in the last 10 years even though govt. has no airlines on its own. The Union Government has sold out and privatized govt. owned Indian Airlines. Then for what purpose and is reason behind it to build more airports and spent more money on it? It will benefit to the private corporate and they are earning money at the cost of poor man's GST and income tax.

India is considered one of the leading economies and defense in Asian countries and why the union govt. not taking any stern action against Sri Lankan Government to protect our Indian fishermen from the harassment of its Navy. There are so many incidents of Indian fishermen being captured from our Indian territory by the Sri Lankan Navy and these innocent fishermen are being harassed, tortured and their fishing boats captured and damaged by them. Our many

fishermen are being jailed and still in Sri Lanka's jail. Necessary action is being taken to release them and bring them back to India.

Recently, Chennai, Tuticorin and Nagapattinam districts in Tamil Nadu has been severely affected by heavy incessant rain and flood. Most of the houses and vehicles perished and plunged into the water due to heavy rain and flood, all the roads have been severely damaged. The union government has not allocated any funds from NDMF to the Government of Tamil Nadu to take necessary relief measures from this unpreceded nature's disorders.

Although, the Union Government has passed the Women's Reservation Bill during the last session in a hurried manner, but it will take another 10 years to implement it. Then what is use of passing the Bill at this juncture? It seems that to get the vote they foolish the women. I request the Union Government to take early necessary action to protect the innocent women. An early action being taken to implement it at the earliest to ensure fair justice and empowerment of women both in Parliament as well as in all State Assemblies and Local bodies.

The Union Government must take necessary action to increase the MPLADS fund for each Lok Sabha constituency from the existing 5 crores to 25 crores for equal distribution to all Assembly constituencies comes under one Lok Sabha constituency jurisdiction to undertake various development activities for the benefit of the constituency people.

A Supreme Court branch to be set up in Chennai for the benefit of all southern states to save money, time, and waiting period for disposal of the important judicial cases.

Necessary action be taken to resolve Cauvery Water Dispute and linking of rivers for the benefits of farmers and in interest of our country to attain self- sufficiency in the agricultural production.

Necessary action being taken to provide employment to all educated youths otherwise give monthly stipend to all educated umemployed youths across the country and also to abolish unemployment and poverty in the country.

Necessary action to bring down inflation due to the increase in prices of all essential items across the country.

There is a lot of demand from the people of the state to get admission of their children in Kendriya Vidyalaya. So necessary steps being taken to setting up of more Kendriya Vidyalaya in Tamil Nadu particularly one Kendriya Vidyalaya in each Taluk with Tamil as one of the subject.

Efforts being taken to supply all kind of seeds, pesticides, fertilizers and manures etc. to farmers at concessional rates under PM-Samman Nidhi scheme on the line of Jan Aushadhi Kendra. Necessary steps are being taken for easy coverage and easy procedure to claim insurance to all agricultural crops for loss arising due to natural disasters like floods, cyclones and droughts etc.

Most importantly, necessary action being taken by the Union Government to produce oil in the name of Bharat Coconut Oil like Bharat Atta, Bharat Dal, Bharat Onion which is beneficial to farmers and the public so as to coconut copra procured by NAFED from Tamilnadu..

Finally, one cold storage may be set up in all taluk across the country for the benefit of the farmers to stock their agricultural

yields/products/goods to protect from spoiling, insects bites, rats and any natural disasters like rain, cyclone and heat etc.

With this, I conclude my speech. Thank you.

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): I thank Hon?ble President Draupadi Murmu ji for her Address to the Parliament.

Her speech lays down the achievements of our Govt and the direction of our nation.

I thank the Government led by Hon?ble Prime Minister Sh. Narendra Modi in taking this historic step towards empowering all sections of the society - economically and socially marginalised, women, SC, ST, OBC, EBC, Minorities and other groups.

Under the visionary leadership of PM Modi ji, our nation has made great strides in assuring:

Antodaya - Reaching the last mile person

Transparent Governance - Access to Governance for all through digitization

Inclusive Development - Sabka Saath, Sabka Vikash - Provisioning equal opportunities for all citizens irrespective of their ethnicity, religion, culture, language, region

- It is heartening to know that the use of JAM trinity ? Jan-Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) - has helped curb corruption, weeding

out fake beneficiaries

- Our Government has saved Rs 2.75 lakh crore of public money from going Into the wrong hands
- This is truly remarkable

Modi Govt Performances

- 80 Cr citizens getting free Ration
- 53 Cr got Health Cover
- 50 Cr Jan Dhan ACs opened
- 40 (Cr Mudra Loans given
- 25 Cr People moved out of Poverty in 09 Years ? NITI Aayog
- 12 Cr Toilets constructed
- 12 Cr homes got tap water
- 10 Cr LPG Connections given
- 11 Cr PM Kisan Beneficiaries
- 4 Cr PM Awas Beneficiaries
- 3 Cr Households electrified
- 75 New Airports constructed
- 15 New AlIMS established
- 390 New Universities established
- 9 New IITs established
- 16 IITs established
- 9 New IIMs established
- 70 Medical Colleges established
- 35 Lakhs Vendors got Svanidhi Loans
- 3.75 Lakh Km Rural Roads

- 50,000 Km New National Highway
- 10000 KM Gas Pipeline
- 18 Vande Bharat Express trains
- 1300 World Class Railway Stations
- 115 Unicorn, 1 Lac Startups
- 1000 Khelo India Centres
- 9304 Jan Aushadhi Kendras
- 4 Lakh common service centres
- Digital India Reforms
- Metro 5 to 20 cities
- Car Sold-21Cr v/s 13Cr.
- Tax payers ?
    - 2013-14: 3.79 Cr
    - 2023-24: 6.77 Cr
- **NE-Budget**
    - 2014-15: Rs 24800 crore
    - 2023-24: Rs 95000 crore
- Total: Rs 3.85 Lakh crore in 10-yrs

- **Export**
    - 2013-14: $310 billion
    - 2022-23: $800 billion
- **Forex Reserve**
    - 2013-14: $304 billion
    - 2022-23: $620 billion
- **Defence Export**
    - 2022-23: Rs 16000 crore

- **On 26 May 2014 when Modi took over:**
    - Sensex was at 24715
    - Sensex today at 71842
- **The cumulative market capitalisation of BSE-listed firms**
    - 2014: Rs 85 lakh cr
    - 2023: Rs. 320 lakh cr
- Morgan Stanley says, India?s GDP could more than double from $3.5 trillion today to surpass $7.5 trillion by 2031
- 220 Cr Vaccine Doses administered
- Article-371
- Triple Talaq
- IPC, CRPC & Evidence Act
- Ram Mandir
- New Parliament Building
- Nari Shakti Vandan Adhiniyam
- Economy 10th to 05th
- GST-one tax.
- Corruption-free Government

Darjeeling hills, Terai and Dooars - Administrative History

- I represent Darjeeling Lok Sabha constituency
- I want to take this opportunity to highlight the issues we have faced
- Administratively, Darjeeling hills, Terai and Dooars were always governed as a tribal region
- Prior to 1861 - Non-Regulated Area
- 1861-70 - Regulated Area

- 1870-74 - Non-Regulated Area
- 1874-1919 - Scheduled District
- 1919-1935 - Backward Tract
- 1935-47 - Partially Excluded Area

Darjeeling Prior to Independence

- Darjeeling hills, Terai and Dooars has always been a frontier region
- As a mountain region, Darjeeling has been a pioneer in many aspects
- 1st Municipality in Mountain Region of India ? 1850
- 1st mountain region to have industry
  - Tea Industry 1841-75, Cinchona 1865
- 1st mountain region to be connected with railways - 1871
- 1st city in entire Asia to get electricity connection - 1897
- 1st English school in mountain region 1823 Darjeeling
- Darjeeling hills, Terai and Dooars had many firsts to its name

After Independence

- 1954 - Merged into West Bengal through the Absorbed Areas (Laws) Act, 1954
- Till 1954, Darjeeling was the most prosperous region in entire Eastern and North Eastern India
- However, when our region was merged with West Bengal in 1954, it was done without any consultation with the local populace, and because of this our deprivation began

Deprivation

- Under the succeeding West Bengal Governments, Darjeeling hills, Terai and Dooars has suffered
- 1988-2010 - Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC)
- 2011 - Gorkhaland Territorial Administration (GTA)
- Both supposed to be autonomous - but has been made to fail by West Bengal Government
- Because of this, there has been massive deprivation
- Zero investment was made towards augmenting infrastructure in the region
- Internet, Mobile, Communication and Transport Connectivity was severely lacking
- Schools and Colleges infrastructure crumbling - Lack of qualified teachers
- We don?t have proper medical facilities - AIIMS North Bengal was taken to South Bengal by TMC Government
- We don't have technical colleges ~ No IITs, NITs, IIMS in the entire North Bengal region
- Existing State Universities not able to cater to the needs of modern education

Potential of my region

- Resource rich region
- Leaders of Tourism in the world
- Hub of best tea in the world - Darjeeling tea
- Immense potential for cross border trade and commerce
- Produces millions of rupees? worth of hydroelectricity

- Famous for its oranges, cardamom, floriculture, fruits and vegetables
- Revenue over 25000-30000 crores are drained out of our Darjeeling hills, Terai, Dooars region every year by West Bengal Government
- Only a fraction of this is returned as investment for development
- Most of the money is used to pay interest on the Debt accrued by TMC Government - around 6 Lakh crores

Highlight of Work Done by Central Government in our Region

The West Bengal Government had kept our region so deprived that majority of our villages did not have access roads

People had to walk for hours to access schooling, health care, colleges

There was no provision for drinking water

No efforts at improving the life and living standards of the people

However, I say this with pride, in the past 5-years the Central Government is helping transform our region

Road and Highways

- 1100 mtrs long Atal Setu connecting Darjeeling to Sikkim at Rs 133.49 crores complete
- Kalimpong to Damdim Alternative Highway at Rs 350 crores complete

- Rapid progress on the National Highway 717A project at Rs 2408 crores underway
- NH10 getting refurbished and upgradation work at Rs 800 crores underway
- Balason, Sevoke Elevated Highway Corridor project worth Rs 1000 crores underway
- Rs 3500 crores worth of Siliguri Ring Road project approved
- Alternative to Coronation Bridge Rs 1100 crores approved
- Four-laning of Siliguri to Fulbari Highway at Rs 750 crores approved
- Land acquisition for the 520km long Expressway connecting Darjeeling-Siliguri region to Gorakhpur to be built at an estimated cost of Rs 32000 crores has been initiated.
- 30km - BRO Road connecting Bindu to Khunia More (National Highway 17)

Railways

- Sevoke-Rangpo Rail Line at Rs 12000 crores underway
- Historic Tindharey Railway Workshop being upgraded
- 2 Vande Bharat train connecting Siliguri to Howrah & Siliguri to Guwahati introduced
- NJP Railway Station Modernization project at Rs 350 crore underway
- Upgraded Darjeeling Himalayan Railway station
- Darjeeling Himalayan Railway Special Train with vista-dome coaches introduced
- Heritage Park Renovation at DHR Ghoom Railway Station

- Foot Overbridged and AC Executive Lounge at Siliguri Railway Junction inaugurated

Har Ghar Jal

- 714 projects worth around Rs 2450.34 crores for ?Har Ghar Jal? schemes
- 284 projects worth Rs 1070.77 crores for Darjeeling District
- 146 projects worth Rs 518.64 crores for Kalimpong District, and
- 284 projects worth Rs 860.93 crore for the district of North Dinajpur

AMRUT

- Rs 204 crore for Darjeeling Municipality
- 17 other projects worth Rs 2.5 crores

AMRUT 2.0

- Rs 785.27 crores for Siliguri Municpal Corporation
- Rs 200 crore for Mirik Municipality
- Rs 193 crores for Kalimpong Municipality.

Information and Broadcasting

- Upgradation of All India Radio Kurseong Station to Hub of Nepali Language Programs in India

Airport Development

- Bagdogra Airport the only functional civilian airport in North Bengal, is getting upgraded with new terminals and modern amenities worth Rs 3000 crores.

Health Care

- Central Government has allocated around Rs 211 crores for augmenting health care facilities
  - o Upgradation of Block Health Centre, Primary Health Centre across Darjeeling, Kalimpong, Siliguri region
- Rs 150 crore for the development of Critical Care Unit at NBMCH

PMGSY Roads since 2019

- Total Road Sanctioned: 6972 kms
- Total funds allocated: Rs 4053 crores

Sanctioned Road Length (km) and Total Expenditure (Rs Cr.) PMGSY Darjeeling LS				
Sr	District	Financial Year	Sanctioned Road Length (KM)	Total Expenditure (Rs Cr.)
1	Darjeeling	2019-2020	1349.35	768.87
		2020-2021	1349.35	891.92
		2021-2022	1349.35	941.37
		2022-2023	859.34	602.64
			4907km	**3205cr**
2	Kalimpong	2022-2023	498.31 km	370.31
3	Siliguri (M.P.)	2019-2020	389.19	105.02
		2020-2021	389.19	118.81
		2021-2022	389.19	124.59
		2022-2023	398.8	129.4

		Total	**1566 kms**	**478 Cr**

Please Note: Under PMGSY - Kalimpong started to be counted as separate district only since 2022

PMAY-G

- 4195 houses sanctioned for Darjeeling District
- 2157 houses sanctioned for Kalimpong district
- 77856 houses sanctioned for North Dinajpur district

PMAY-U

- 10408 houses allocated to Darjeeling district
- 2277 houses allocated to Kalimpong district
- 13807 houses allocated to North Dinajpur district
- 16749 houses grounded for construction
- 7578 houses completed
- Rs 314.93 crore approved

Internet and Connectivity

- Central Government is undertaking work to provide 4G to four remote border villages, that were hitherto uncovered
- Optical Fiber Cable being laid from Kaliyhora to Teesta to Kalimpong
- Survey of 41 villages undertaken by BSNL to determine connectivity issues - 8 Villages have been identified as ? uncovered,? which will be connected under USOF Schemes.

- BSNG Connectivity reached to Today Tangta Gram Panchayat

Panchayat - Only Two Tier

- Darjeeling is perhaps the only place in India, where three Panchayat elections haven't been conducted since 1988
- Recently only elections to two tier were held.
- We don?t have grass roots governance system
- Our constitutional rights are not recognized
- We are kept deprived and subjugated

Injustice

- The Gorkha contribution to nation building is immense
- Freedom Fighters Helen Lepcha, Dal Bahadur Giri, Sahid Durga Malla, INA Capt Ram Singh Thakuri, Dalbir Singh Lohar, Bhakta Bahadur Pradhan, and hundreds of others
- But we are labelled as Foreigners
- Recently even a Supreme Court judge called Gorkhas ?foreign origin?
- We did not immigrate - our borders changed
- We were part of Sikkim, then Bhutan, then Nepal, then British, then India
- People remained, borders changed
- How can we be considered foreigners in our own country?
- We are indigenous to these land

- But every time we ask for our constitutional rights we are labelled as ?foreigners?
- It is this ?crisis of identity? which needs to be addressed

Demand for Constitutional Solution

- Darjeeling - the constituency, I represent is part of West Bengal State
- Sadly, West Bengal once great state is today known for corruption, cut-money culture, nepotism and large-scale violence
- Due to the lack of good governance, West Bengal is suffering - economically and socially as well
- There is mass influx of illegal Rohingys and Bangladeshi immigrants
- Majority of our border districts are seeing massive demographic changes
- This is causing the indigenous people - Gorkha, Rajbangshi, Adivasi, Bengali, Hindi Bhasi and others to become marginalised in our land
- This is the reason why, people in Darjeeling hills, Terai and Dooars have been demanding a separate administrative unit.
- This demand has previously manifested as the demand for Gorkhaland state, leading to Andolan of 1986-88 which resulted in the formation of Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC)
- Once again, the demand for separate state was raised in an andolan between 20072011 leading to the formation of Gorkhaland Territorial Administration (GTA)

- Both GTA and DGHC were supposed to be autonomous governing bodies
- However, these bodies were made dysfunctional due to the lack of support and regular interference by the West Bengal Government.
- This again led to Gorkhaland andolan of 2013 and 2017
- GTA has completely failed to fulfil the aspirations of the people from our region
- Therefore, people have been demanding a Constitutional Solution
- Our Government has assured the people, a Permanent Political Solution will be arrived at
- But people are awaiting and their patience is running thin

11 Left-out Gorkha Sub-tribes

- Darjeeling hills, Terai, and Dooars people eagerly await justice for the 11 left out Gorkha sub-tribes
- These sub-tribes are - Bhujel, Gurung, Mangar, Newar, Jogi, Khas, Rai, Sunwar, Thami, Yakha (Dewan) and Dhimal.
- Until 1947, these communities were considered Hull Tribes, as per the census of 1931 and 1941.
- The region was governed as a Scheduled District and Excluded Area, a form of governance applied only to Tribal regions.
- However, after Independence, their Scheduled Tribe (ST) status was revoked without consultation, depriving them of their tribal heritage.
- Due to the Indo-Nepal Friendship Treaty of 1950, we are today labelled as ?Nepalese citizens?, causing harassment and

branding as "foreigners" in our own country.

- The Registrar General of India (RGI) cites absurd concerns for denying ST status, influx issues.
- That?s an administrative issue, Gorkhas demanding constitutional rights.
- I want to ask the Parliament, have the Gorkhas not sacrificed enough for our nation?
- The indigenous Gorkhas are suffering, compromising their language, culture, and traditions.
- Protection of the Gorkha community is vital for national security, achievable by promptly reinstating ST status for the 11 sub-tribes.

Hope of Justice

- It is because of this systematic deprivation and ?crisis of identity?
- The people from our region have struggled for a state of our own called Gorkhaland
- They believe in the leadership of Hon?ble PM Modi ji
- Our party has committed to Permanent Political Solution for the Darjeeling hills, Terai and Dooars region
- Our constitution guarantees equality for all and justice for all
- But people from Darjeeling hills, Terai and Dooars are waiting for justice for the past 77 years since Independence.
- Hence, I request the Union Government to fulfil these commitments
- Gorkhas are awaiting justice ? time has come to fulfil ? Gorkhaon ka Sapna?

- I, therefore, request the Government for re-inclusion of 11 left-out Gorkha sub-tribes as ST, and
- Constitutional Solution for Darjeeling Hills, Terai and Dooars

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं । महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में अमृत काल के 25 वर्षों के कालखंड में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का खाका पेश किया है, जो केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण आकांक्षा को दर्शाता है ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह परिलक्षित होता है कि केन्द्र सरकार "सबका साथ सबका विकास" के अपने वायदे के अनुरूप देश को तेजी से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है। देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा सरकार के इस समावेशी आर्थिक विकास के केन्द्र में है ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में केन्द्र सरकार के विजन और देश में बीते 10 साल की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया है उन्होंने अपने अभिभाषण में यह भी बताया कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी जो अब पूरी हुई है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने, औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों के स्थान पर नए कानून बनाए जाने, नारी वंदन अधिनियम और सरकार के कई अन्य कदमों का भी उल्लेख किया है । उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और लगातार पिछली दो तिमाही में देश की विकास दर साढ़े सात प्रतिशत रही।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डाला है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाता है ।

- भारत में जी-20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन ।
- राम मंदिर के निर्माण का सदियों पूरा सपना सच हुआ ।
- देश के करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर निकले ।
- खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने पर जोर ।
- पहली बार कृषि निर्यात की नीति बनाई गई
- देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है । स्थानीय सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी ।
- सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की गई ।
- ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा साल 2023
- नई संसद भवन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक
- चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत
- मिशन मोड में सरकारी नौकरियां देना बड़ी उपलब्धि ।
- नारी शक्ति वंदन कानून से महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई ।
- 22 जनवरी को लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए ।
- हमारी विरासत ऐसी हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें ।
- नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को ऊर्जा देता रहेगा । यहां नई और स्वस्थ परंपराओं की शुरुआत का भरोसा ।
- सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए कटिबद्ध ।
- भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ।
- देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर एक लाख के आंकड़े से भी आगे निकली ।

- देश में मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में पांच गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई ।
- डिजिटल इंडिया से बड़ा बदलाव, यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लेन-देन ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में यह भी उल्लेख किया है कि वन एवं पर्यावरण मंजूरी में 75 दिन से भी कम समय लगता है, जबकि पहले 600 दिन लगते थे तथा उद्यम और उद्यम सहायता पोर्टल पर लगभग 3.5 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं । करीब पांच लाख करोड़ रुपये के एमएसएमई लोन पर सरकारी गारंटी दी गई है । यह 2014 से पहले प्रदान की गई राशि से छह गुना अधिक है एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएं शुरू की गई हैं । यह भी सरकार की उपलब्धि को दर्शाता है ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि स्टार्टअप आज कुछ सौ से बढ़कर चार लाख से भी अधिक हो गए हैं औरा भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है । इसने पहले की तरह खिलौनों का आयात करने के बजाय उनका निर्यात करना भी शुरू कर दिया है तथा व्यापार करने में आसानी के लिए 40,000 से अधिक अनुपालन हटा दिए गए हैं या सरल बना दिए गए हैं ।

राष्ट्रपति महोदया ने यह भी जिक्र किया है कि पिछले दशक में लगभग 21 करोड़ वाहन बेचे गए हैं, जबकि इससे पहले के दशक में यह आंकड़ा 13 करोड़ था और जीएसटी भरने और आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा दिवाला और दिवालियापन संहिता अधिनियमित की गई एवं बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां पहले दोहरे अंक में रहने के बाद घटकर लगभग 4 प्रतिशत पर आ गई हैं । यह सरकार की उलब्धियों का दर्शाता है, जो प्रशंसनीय है ।

राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में इन महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा इस बात का भी उल्लेख किया है कि भारत ने बीते एक दशक के दौरान वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौर में भी, अपने हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है । उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ को देखने के लिए अनेक साथी इस सदन में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसी होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद करे ।

अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इस प्रकार से जहां विगत वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा देश के सर्वांगीण विकास हेतु किए गए कार्यों को उद्धरित किया है, वहीं सरकार के दूसरे कार्यकाल में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का भी उल्लेख किया है, जिसमें हमारी लोकप्रिय सरकार की आत्म छवि का एक अंदाजा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ।

मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

सधन्यवाद ।

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद): मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक बार फिर इनता उत्तम अभिभाषण किया । नए सदन में, महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यकाल का ये दूसरा अभिभाषण पुरे देश में सकारात्मक संदेश लेकर के आया है, आशा की किरण लेकर आया है, उमंग का आगाज लेकर के आया है ।

इस आग्रिम बजट सत्र 2024 का प्रारंभ में महामहिम राष्ट्रपति जी का दूसरा अभिभाषण फिर से भारत के संविधान और दूर-सुदूर के महान आदिवासीयों का साथ साथ पूरे देश का सम्मान का भी अवसर है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सभी देश के नागरिको के किये विकास कार्यों की एक झलक दिखी है मैं समझता हूँ की पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी ऋणी है कि इतने कम समय में इनता विकास, जो पिछले कई दशकों में नहीं हो पाया । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के विजन और देश में बीते 10 साल की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया ।

महामहिम ने अपने अभिभाषण में देश की रक्षा, विदेश और आर्थिक नीतियों का जिक्र किया । उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा, सरकार विधायिका में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया ।

उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा, 22 जनवरी को लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए । हमारी विरासत ऐसी हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें । राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी जो अब पूरी हुई है । बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह गत 22 जनवरी को हुआ । पीएम मोदी ने राम लला की उत्सव मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की । इस मौके पर देश-विदेश के लगभग आठ हजार मेहमान विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है । राष्ट्रपति जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का जो मूल मंत्र है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास' को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के द्वारा विभिन्न बुनियादी योजनाओं, सुविधाओं को गरीबो किसानो और मजदूर तक की पहुंच में लाने के लिए एक ही मोटो, एक ही लक्ष्य और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी जो एक ही विचार है 'India First Citizen First' सबसे पहले देश, सबसे

पहले देशवासी पर अपने अभिभाषण के दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया की ऐसे क्षेत्र की भी पहली बार विकास से जोड़ा हैजो दशकों तक दशकों तक उपेक्षित रहे हैं । हमारी सीमाओं से सटे गांव को अंतिम गांव कहा जाता था । मेरी सरकार ने उन्हें देश का पहला गांव बनाया है । इन गांव के विकास के लिए काफी काम किया है ।

अपने भाषण के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का भी किया जिक्र । उन्होंने कहा कि ये द्वीप विकास से वंचित थे । हमारी सरकार ने इन द्वीपों में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया है । वहां सड़क, हवाई यातायात और तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई है ।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और लगातार पिछली दो तिमाही में देश की विकास दर साढ़े सात प्रतिशत रही ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया और पहली बार आरक्षण की सुविधा दी गई है । मोदी जी की सरकार ने बाबा साहेब आंबडेकर से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी कहा कि हमारे यहां विश्वकर्मा परिवारों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना मुश्किल है । सरकार ने ऐसी विश्वकर्मा परिवारों की भी सुध ली है । पीएम विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं ।

आदिवासियों के लिए, मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि कि मेरी सरकार ने उनकी भी सुध ली है जो अब तक विकास की धारा से दूर रहे हैं । ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां पिछले 10 सालों में बिजली पहुंची हैं । उनको पाइप से पानी मिलना शुरू हुआ है । हजारों आदिवासी बहुल गांव में 4 जी नेट सुविधा पहुंचा रही है । जनजातियों में सबसे

पिछड़े जनजातियों की सुध ली है । उनके लिए 26 हजार करोड़ रुपये की पीएम जनमन योजना बनाई है ।

अपने भाषण में किसानों का भी जिक्र उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक है । मेरी सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक किसानों को देश की कृषि योजना में प्रमुखता दी है । पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये किसानों को मिल चुके हैं । दो सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में तीन गुना वृद्धि की गई है । पिछले 10 लाख वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं । किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपये खर्च किए गए ।

देश में 15 नवंबर से विकसित भारत संपर्क यात्रा चल रही है अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुकी है । पिछले दो वर्षों में विश्व ने दो युद्ध देखे और कोरोना जैसी महामारी देखी । इसके बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा और सामान्य भारतीयों का बोझ नहीं बढ़ने दिया । 2014 से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 8 फीसदी से अधिक थी । पिछले दशकों में औसत महंगाई 5 प्रतिशत रही । मेरी सरकार का प्रयास रहा है कि सामान्य देशवासी की जेब में अधिक से अधिक बचत कैसे हो । पहले देशवासियों को 2 लाख रुपये की आय पर टैक्स लग जाता था । आज भारत में 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता ।

साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' की घोषणा एवं 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' इसी सोच का परिचायक है । सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि स्वरूप, उनके जन्म-दिवस 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि आज देश के चार बेहद अहम स्तंभ हैं । उन्होंने कहा कि युवाशक्ति, नारीशक्ति, किसान और गरीब से ये देश खड़ा है । देश के हर समाज में इनकी स्थिति ऐसी ही है । इसलिए इन चार स्तंभों को ठीक करने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है । 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का घर मिला है ।

नल से जल योजना के तहत अभी तक 11 करोड़ ग्रामीणों को पाइप से पानी पहुंचा है । कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है । अब इसे आनेवाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है । इस पर 11 लाख करोड़ रुपये और खर्च होने का अनुमान है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने डिजिटल इंडिया का किया जिक्र किया, भारत में बिजनेस करना आसान हो इसके लिए मेरी सरकार काम कर रही है । इज ऑफ डूइंग आसान हो रहा है । मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्मडिजिटल इंडिया का निर्माण है । डिजिटल इंडिया ने भारत में बिजनेस को आसान बना दिया गया है

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम जो पहले पूरी तरह ले चरमरा गई थी वो आज दुनिया में सबसे मजबूत बना है । एनपीए जो पहले डबल डिजिट में होता था वो अब 4 फीसदी ही रह गया । कुछ साल पहले भारत खिलौना आयात करता था आज मेड इन इंडिया खिलौना निर्यात कर रहा है । भारत का डिफेंस प्रोजेक्ट एक लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है । लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहा है ।

औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों के स्थान पर नए कानून बनाए जाने, नारी वंदन अधिनियम और सरकार के कई अन्य कदमों का उल्लेख किया । उन्होंने तीन दशक बाद नारी शक्ति वंदन विधेयक पास करने के लिए मैं सबकी सराहना की और कहा, "मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए सदस्यों का अभिवादन करती हूं । यह मेरी सरकार के महिला

नीत विकास के संकल्प को मजबूत करता है । इससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है । इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था । 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य-शौर्य को अनुभव किया ।

आईपीसी अब इतिहास हो गया है । अब दंड को नहीं बल्कि न्याय को प्राथमिकता है । देश को न्याय संहिता मिली है । अब दंड को नहीं न्याय की प्राथमिकता, न्याय संहिता देश को मिली है बीते 12 महीनों में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आई । ये विधेयक, आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं । ये ऐसे कानून हैं जो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मजबूत आधार हैं । 3 दशक बाद, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूं । इससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है । यह वीमेन लेड डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है । रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है । गुलामी के कालखंड से प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है । अब दंड को नहीं, अपितु न्याय को प्राथमिकता है । 'न्याय सर्वोपरि' के सिद्धांत पर नई न्याय संहिता देश को मिली है । डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है । अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा । जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से, वहां भी जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा । इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया । इससे तेलंगाना में समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइचल यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता सुगम हुआ । पिछले वर्ष 76 अन्य पुराने कानूनों को भी हटाया गया है । मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से

अवगत है । इसलिए ऐसे गलत तरीकों पर सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया कि बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है । इस दौरान देशवासियों के गौरव बढ़ानेवाले अनेक पल आए । दुनिया में भारत सबसे अधिक तेजी से विकसित होनेवाली अर्थव्यवस्था बना है । ऐतिहासिक जी-20 सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा । मिशन आदित्य को लॉन्च किया । भारत को सबसे बड़ा अपना समुद्री पुल अटल सेतु मिला ।

केंद्र की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति बोलीं कि 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' को सरकार ने लगातार जारी रखा है । उन्होंने इस दौरान महिला आरक्षण कानून पारित होने का उल्लेख भी किया और कहा, "मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए सदस्यों का अभिवादन करती हूं. यह मेरी सरकार के महिला नीत विकास के संकल्प को मजबूत करता है."

ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा साल 2023, नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को ऊर्जा देता रहेगा, यहां नई और स्वस्थ परंपराओं की शुरुआत का भरोसा । नई संसद भवन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत, मिशन मोड में सरकारी नौकरियां देना बड़ी उपलब्धि भारत में जी-20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजना देश के करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर निकले । भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम तीसरी पायदान पर आने वाले है देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर एक लाख के आंकड़े से भी आगे निकली देश में मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में पांच गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई । डिजिटल इंडिया से बड़ा बदलाव, यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लेन-देन । खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने पर जोर । पहली बार कृषि निर्यात

की नीति बनाई गई, देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। स्थानीय सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी। सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की गई। सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए कटिबद्ध।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय नीतियां जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लाई गई है, गरीबों के लिए सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है उन पर भी प्रकाश डाला है। यह हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्ष है। इसी कालखंड में आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव, अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतन्त्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल देश भर में एक उत्सव की तरह मनाया गया| हाल में हुए अमृत महोत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयसला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए। साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया मेरी माटी, मेरा देश अभियान के तहत, देश भर के हर गाँव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाए गए। 2 लाख से ज्यादा शिला-फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली। 70 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़-पौधे लगाए गए। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की।

राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत ने बीते एक दशक के दौरान वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौर में भी, अपने हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है । उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ को देखने के लिए अनेक साथी इस सदन में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसी होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद करे ।

अमृतकाल के आगामी 25 वर्ष का कालखंड, स्वतन्त्रता की स्वर्णिम शताब्दी का, और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड के रूप में प्रकाश डाला है जिसमे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्यों की पराकाष्ठा करके दिखाने और एक नव युग निर्माण के अवसर को देखा जाएगा जिससे 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा होगा और आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय होगा । प्रधानमंत्री जी द्वारा एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश की जा रही है, जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भी समर्थ होगा, ऐसा भारत- जिसमें गरीबी न हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त होगा, ऐसा भारत- जिसकी युवाशक्ति और नारीशक्ति, समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो, जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलेंगे, ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्ज्वल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल होगी ।

अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है । जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था । अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही हैं, अब ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पा रहे हैं । अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर आंबेडकर उत्सव घाम, अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । आदिवासी गौरव के लिए तो सरकार ने अभूतपूर्व फैसले किए हैं । पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरु किया । हाल में ही मानगढ़

धाम में सरकार ने आदिवासी क्रांतिवीरों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि दी । आज 36 हज़ार से अधिक आदिवासी बाहुल्य वाले गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जा रहा है । आज देश में 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खुल चुके हैं । देशभर में तीन हज़ार से अधिक वनधन विकास केंद्र आजीविका के नए साधन बने हैं । सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर O.B.C. के welfare के लिए प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है । बंजारा, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए भी पहली बार Welfare and Development Board का गठन किया गया है ।

देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण पूरे कर अमृतकाल में प्रवेश किया । अमृत काल के 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी और विकसित भारत के निर्माण का वक्त है । अमृत महोत्सव में तमाम महापुरुष जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन लगा दिया ऐसे महापुरुषों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कामना की है कि देश का हर नागरिक मानवीय दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हो, गरीबी न हो, मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो । युवा समय से दो कदम आगे चलते हों, भारत ऐसा हो कि जिसकी विविधता और उज्ज्वल और एकता और ज्यादा अटल हो। जनकल्याण की ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सिर्फ सुविधाएं भर नहीं हैं । इनका देश के नागरिकों के पूरे जीवन-चक्र पर सकारात्मक असर पड़ रहा है । विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा, मेरी सरकार की योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है । इनके परिणाम बहुत ही प्रभावकारी हैं और गरीबी से लड़ रहे दुनिया के हर देश को प्रेरित करने वाले हैं । बीते वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययन में सामने आया है कि 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच बंद होने से, अनेक बीमारियों की

रोकथाम हुई है । इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रति वर्ष 60 हजार रुपए तक की बचत हो रही है । प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की वजह से आज देश में शत- प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहे हैं । इस वजह से माता मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है । एक और अध्ययन के अनुसार, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों में, गंभीर बीमारी की घटनाओं में कमी आई है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की तारीफ कि कहा कि कोरोनाकाल में सरकार ने भारत के नागरिको को गरीबी रेखा के नीचे जाने से बचाने में सफल हुई है । और शॉर्टकट की राजनीति से बचने और एक स्थायी समाधान पेश करने कि सलाह दी जिससे सामान्य जनों की समस्याओं का हल है । मोदी जी की सरकार में गरीबी हटाओ अब केवल नारा नहीं रह गया है बल्कि सरकार हर किसी को सशक्त बनाने का काम कर रही है । महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि कोरोनाकाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की तारीफ कि कि सरकार ने देशहित को सर्वोपरि रखा है। नीति और फैसलों में इच्छाशक्ति दिखाई है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जवाबी कार्रवाई तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक सरकार ने हर तरफ काम किया है । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 370 से लेकर तीन तलाक तक हर तरफ काम किया है । आज दुनिया के कई देश संकट से घिरे हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार ने जो भी निर्णय लिए, उनकी वजह से भारत की स्थिति उन देशों से अलग है । माननीय मोदी जी नेत्रत्व वाली सरकार देश में ईमानदारी का पालन करने वाली सरकार है और देश में गरीबी के स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है ये सरकार जनकल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है. देश में प्रगति के साथ ही प्रकृति को संभालते हुए विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास को प्राथमिकता देने की राह चुनी है । एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है । केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक का निर्माण किया तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं ।

तीर्थों का विकास कर रहे हैं तो भारत दुनिया की बड़ी स्पेस पावर भी बन रहा है । भारत ने पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च किया है । एक तरफ आदि शंकराचार्य, बसवेश्वर जैसे संतों के दिखाए रास्ते पर बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत हाईटेक नॉलेज का हब बन रहा है ।

भारत प्राकृतिक खेती की मिलेट्स की परंपरागत फसलों को बढ़ा रहा है । नैनो यूरिया जैसी टेक्नोलॉजी का विकास भी किया । खेती के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर पावर से किसान को ताकत दे रहे हैं । गांव के घरों की ड्रोन से मैपिंग की जा रही है । सैकड़ों आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की जा रही हैं । नदी-जलमार्ग और बंदरगाहों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है ।

मैं पुनः एक बार महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हुए, उनके अभिभाषण का समर्थन करता हूं और साथ ही मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार ।

SHRI RAJESH NARANBHAI CHUDASAMA (JUNAGADH): The Motion of Thanks on the President's Address. The Motion of Thanks on the President's Address is a momentous occasion that allows us to reflect on the remarkable strides our nation has made under the visionary

leadership of our esteemed leaders. As we express our gratitude to the Hon'ble President for addressing both Houses of Parliament and shedding light on the transformative initiatives undertaken by this government, it becomes evident that we stand at the threshold of a new era of progress and prosperity.

The inauguration of the new Parliament Building during the 'Azadi ka Amrit Kaal' serves as a testament to the grandeur of our democracy and embodies the spirit of 'Ek Bharat Shreshtha Bharat'. It encapsulates the essence of our rich civilization and culture, symbolizing our collective aspirations for a brighter future. Under the dynamic leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modiji, the past year has been marked by unparalleled achievements and significant milestones as part of the Amrit Mahotsav.

Our nation, guided by the steadfast leadership of this government, has demonstrated remarkable economic resilience, emerging as the fastest growing major economy with a sustained growth rate of over 7.5 percent for two consecutive quarters amidst challenging global conditions. This commendable feat not only strengthens our economic standing but also reflects the government's adept handling of complex financial landscapes.

In the realms of space exploration, sports, and diplomacy, India has truly excelled. From planting our flag on the southern pole of the Moon to the essful launch of the Aditya Mission, India has solidified its position as a formidable player in the global arena. The success of the historic G-20 Summit underscores India's influential role in shaping international dialogues and policies. Moreover, India's stellar

performance in sports, with over 100 medals in both the Asian Games and Para Asian Games, reflects our unwavering commitment to sporting excellence.

These achievements, coupled with monumental infrastructural developments like the completion of the largest sea-bridge Atal Setu, the introduction of Namo Bharat and Amrit Bharat trains, and India's fastest 5G rollout, collectively represent a transformative year under the government's visionary guidance, shaping the development of 'Viksit Bharat'.

The delineation of the 'Idea of Nation First' encapsulates the government's focus on poverty alleviation and economic prosperity. Over the last decade, India has witnessed a transformative journey, with approximately 25 crore citizens ascending from poverty, marking a significant milestone that is a testament to the success of targeted interventions, economic reforms, and initiatives aimed at enhancing education and healthcare accessibility.

In the pursuit of inclusive growth, initiatives like the PM Vishwakarma Yojana, impacting over 84 lakh people, and the PM SVANidhi Yojana, addressing the challenges faced by street vendors, have found widespread support. The government's commitment to providing fair opportunities to every section of society is evident in measures like extending reservation benefits and fostering the development of places associated with Dr. Babasaheb Ambedkar and museums dedicated to tribal freedom fighters.

Moreover, development has been extended to long-neglected areas through initiatives like the Vibrant Village Programme and the Aspirational Districts Programme, bringing progress to blocks that have historically lagged behind. The Ayushman Bharat Scheme, coupled with the provision of free treatment in hospitals, has resulted in substantial savings for citizens, demonstrating the government's commitment to healthcare accessibility.

Significant strides have also been made in enhancing energy infrastructure and ensuring broader access to energy resources. From 2014 to 2023, key areas in various constituencies have witnessed impressive growth, reflecting the government's dedication to advancing energy infrastructure and alternative fuel options.

The Government's steadfast commitment to empowering MSMES and small entrepreneurs is evident through a comprehensive set of measures. Notably, the definition of MSMEs has been broadened, facilitating a more inclusive and accessible environment for businesses. The implementation of the Credit Guarantee Scheme for MSMEs has been instrumental in fortifying the foundation for a thriving and resilient MSME sector.

As we conclude, I extend heartfelt congratulations to the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modiji, for his unwavering commitment and guidance that has propelled our nation to unprecedented heights. His steadfast leadership, marked by economic reforms and the pursuit of global excellence, has played a pivotal role in our collective journey toward becoming a global powerhouse. Let us rally behind the initiatives set forth by the government to shape

India into a developed nation-a nation that seamlessly blends a forward-looking vision with deep roots firmly anchored in its glorious past. I extend my full support to the Motion of Thanks on the President's Address.

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन मे अपने विचार रखती हूँ ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया की इस संसद भवन मे जहां "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की महक है, वहाँ भारत की सभ्यता और चेतना, लोकतान्त्रिक और संसदीय परम्पराओ का सम्मान, 21वी सदी के नए भारत के लिए नयी परम्पराओ का निर्माण का संकल्प है ।

महामहिम राष्ट्रपतिजी ने यह उम्मीद भी जताई है की नए भवन में नीतियो पर सार्थक संवाद होगा और एसी नीतीया जो आजादी के अमृत काल मे विकसित भारत का निर्माण करेगी ।

यह साल हमारे संविधान लागू करने का 75वा वर्ष मनाने जा रहे है और पिछले साल हमने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव भी मनाया ।

इसी के अंतर्गत कई उत्सव मनाए गए जैसे स्वातंत्रय सेनानियो को याद करना, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश भर के हर गाँव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाये गए, हमारे गुजरात के 182 विधानसभा से भी मेरी माती मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश दिल्ली लाये गए ।

2 लाख से ज्यादा शीला फलकम स्थापित किए गए, 3 करोड़ से ज्यादा लोगो ने पाँच प्राण की शपथ ली, 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओ का

निर्माण हुआ, और 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधो को लगाने के साथ यह सभी कार्यक्रम सम्पन्न किए गए ।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे आज भारत देश एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, आज पूरा विश्व कोई भी समस्या का समाधान के लिए भारत की सहायता चाहता है ।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थ व्यवस्था मे सकारात्मक बदलाव हुए है, आज हर भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है ।

देश के हर एक वर्ग के हर एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हुआ है, ग्रामीण विकास योजनाए के लागू होने मे तेजी आई है एवं सरकार की हर जन सुखाकरी योजनाए जनता के अंतिम तबक्के के व्यक्ति तक पहुंची है ।

आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे देश मे परिवारवाद नाबूद हुआ है ।

पिछले 5 वर्ष मे आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर एक चुनोतियों का साहसिकता के साथ मुक़ाबला किया है, आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगो को मुफ्त राशन दिया गया ।

पिछले 5 वर्षों के दौरान एतिहासिक कदम भी उठाए गए, जिसमे जम्मू कश्मीर मे लागू आर्टिकल 370 आज इतिहास बन कर रह गया है ।

पिछले साल भारत में अदरणीय प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे हुए G 20 के सफल आयोजन से पूरे विश्व ने भारत का सामर्थ्य पहेचाना है ।

पापुआ न्यू गिनी देश के राष्ट्र प्रमुख द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री के पैर छूना और औस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री नरेंद्र मोदी जी को "मोदी इज द बॉस" का कहना एवं अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख के द्वारा भारत को एक अहम मित्र के तौर पर बताना आज के भारत की बढ़ती हुई ताकत को दर्शाता है ।

पिछले साल भारत के वैज्ञानिको द्वारा एतिहासिक सिद्धि हांसील हुई है, भारत देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाला पहला देश बना, तब पूरा देश गौरव और आनंद की अनुभूति के साथ खुशी से झूम उठा ।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की युवा पीढ़ी को "अमृत पीढ़ी" को तौर पर संबोधित किया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवा विकास के द्वारा "सशक्त युवा सशक्त भारत" का निर्माण कर रही है ।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मे हमारी सरकार का लक्ष्य महिला विकास का ज़ोर दिया गया है, नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर स्तर पर कार्यरत है, पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा इसी संसद भवन के प्रथम सत्र के दौरान 3 दशक बाद महिलाओ को 33% आरक्षण प्रदान कर महिलाओ की लोकसभा और विधानसभा में भागीदारी सुनिश्चित की गयी । आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे हमारी केन्द्र सरकार गरीब, महिला, अन्नदाता और युवाओ के विकास के लिए प्रतिबद्धह है आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री के नेतृत्व मे हमारी केंद्र सरकार ट्रान्स्फ़ोर्म, रिफॉर्म और परफ़ोर्म के द्वारा हर स्तर के विकास को साधने हेतु प्रतिबद्ध है ।

मैं आज यह बताते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के करकमलों द्वारा अयोध्या मे भव्य

राम मंदिर का लोकार्पण हुआ और श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गयी, जिससे 500 वर्षों की प्रतीक्षा और संघर्ष की समाप्ती हुई, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी जी के करकमलों से भारत देश की समग्र जनता की सदियो पुरानी आकांक्षा की पूर्ति हुई । आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री के करकमलों से भव्य राम मंदिर लोकार्पण के साथ ही राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र नवनिर्माण की नींव रखी गयी ।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की साथ आगे बढ़ रही है । आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे हमारी केंद्र सरकार का लक्ष्य अमृत भारत की अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करना है । उक्त सभी कार्य निश्चित समय से होने के कारण मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं और साथ ही महमहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का दिल से समर्थन करती हूँ ।

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के पक्ष में अपना अभिमत रख रही हूँ ।

महामहिम राष्ट्रपति ने जैसा कहा कि सरकार के 10 साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है विशेषकर साल 2023 । इस वर्ष नए संसद भवन के तैयार होकर सुचारु होने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक मिलती है । पिछली सरकारें सिर्फ नए संसद भवन की आवश्यकता पर सोचती रहीं और इस कार्य को बस सोच तक ही सीमित रक्खा जबकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे मूर्त रूप देकर हमें गौरवान्वित होने का अवसर दिया वहीं गुलामी के एक प्रतीक से बाहर आने का सौभाग्य मिला । नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को ऊर्जा देता रहेगा; यहां नई और स्वस्थ परंपराओं की शुरुआत का भरोसा है ।

हमारे देश के वैज्ञानिकों की क्षमता आज अन्तरिक्ष में पूरा विश्व देख कर दंग है । चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है । जब देश की सरकार का नेतृत्व का नेतृत्व ईमानदार, परिश्रमी और विकसित भारत को संकल्पित है तो हमारे वैज्ञानिक आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने में पूरी तरह से सक्षम हैं ये मोदी जी नेतृत्व वाली चमत्कारिक सरकार में प्रमाणित हो गया है ।

मिशन मोड में सरकारी नौकरियां देना हमारी सरकार की एक बड़ी बड़ी उपलब्धि रही है । आदरणीय मोदी जी की सरकार युवा शक्ति को देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने में भागीदार बनाने के लिये प्रतिबद्ध है ।

नारी शक्ति वंदन कानून से महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई । अबला अब सबला बनकर देश के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को विश्वास के साथ खड़ी है और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण वाली नीतियों से संभव हो रहा है ।

भारत में जी-20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन । राम मंदिर के निर्माण का सदियों अधूरा सपना सच हुआ । देश के करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर निकले । भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से अग्रसर है जिसकी गारंटी मोदी जी ने दी थी । महोदय, चुनावी वादे की गारंटी पूरा होना मोदी सरकार इसकी पर्याय बन चुकी है परिणाम स्वरूप देश के सबसे विश्वसनीय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, ये बात चुनावों में बार बार जनता दर्शा रही है ।

देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर एक लाख के आंकड़े से भी आगे निकली, देश में मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में पांच गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई ।

डिजिटल इंडिया से बड़ा बदलाव, यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लेन-देन, खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने पर जोर, पहली बार कृषि निर्यात की नीति बनाई गई, देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है । स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को सजाने सवारने का कार्य हो रहा है । 22 जनवरी को लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए । हमारी विरासत ऐसी हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें सरकार इस लक्ष्य पर तेजी से कार्य कर रही है । जो दर्शाता है कि मोदी जी ने जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की गारंटी दी है आने वाले समय में पूर्ण होकर रहेगा ।

देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानसेवक मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए कटिबद्ध है इस बात का पूर्ण भरोसा महामहिम के अभिभाषण में दिखता है ।

जय भारत

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का पूरा समर्थन करता हूँ । मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के साथ ही हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक दूरदृष्टि, स्थिर और सशक्त मोदी सरकार के दशक के उपलब्धियों का सिलसिला हम सभी को याद दिलाया है, और जब हम एक नए युग की क़दमों पर खड़े हैं, तो हमारे नए संसद भवन के उद्घाटन से हमारे देश के यात्रा में एक महत्वपूर्ण पल का आगमन है । यह अद्वितीय समय न केवल "आज़ादी का अमृत काल" की प्रतीक है बल्कि हमारे प्रजातंत्र मूल्यों के प्रति हमारे समर्पण का साक्षात्कार भी है ।

75वें वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, हम हमारे अनगिनत नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की बलिदानों को याद करते हैं। "अमृत महोत्सव" के साथ, जिसमें मिट्टी संग्रहण, प्लाक, अमृत सरोवर, और वाटिकाएँ जैसी उपलब्धियाँ हैं, यह हमारे राष्ट्र को रूपांतरित करने के आदर्शों के प्रति हमारे सामूहिक समर्पण को दर्शाता है।

इस अवधि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना, प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन, और शांतिनिकेतन और होयसला मंदिर को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त की है। हमारे राष्ट्र की ऐतिहासिक उपलब्धियों ने आर्थिक विकास, अंतरिक्ष अन्वेषण, वैश्विक मान्यता, और खेल की जीतें का समर्थन किया है, जो हमने इन वर्षों में कदम बढ़ाए हैं।अध्यक्षजी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसका लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, और आपराधिक न्याय सुधार जैसे कानूनी सुधार हमारे प्रगतिशील और समृद्धिशील समाज के प्रति हमारे समर्पण को हाइलाइट करते हैं। इस सफलता में, माननीय मोदी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है जिसने सकारात्मक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत बनाया है। माननीय मोदी सरकार ने राष्ट्र को स्वच्छता, नारी सशक्तिकरण, और आर्थिक समृद्धि की दिशा में पगारी देने का संकल्प बनाया है और इसे पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। माननीय मोदी सरकार की नीतियों ने देश को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाई है और उसे एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।

इसके अलावा, मोदी सरकार ने भूतकाल की चुनौतियों का सामना करते हुए राम मंदिर की निर्माण योजना, धारा 370 की समाप्ति, 'तीन तलाक' पर कानूनी सुधार, और पेंशन के मामले में सुधार किया है। इन नीतियों ने राष्ट्र को एक सामूहिक और उत्तम दिशा में ले जाने में मदद की है और उसे एक मजबूत और समृद्धिशील भविष्य की दिशा में बढ़ावा दिया है।

"अमृत महोत्सव" में माननीय मोदी सरकार की अहम भूमिका ने हमें यहां तक पहुंचाया है कि हमारी शानदार उपलब्धियाँ एक सशक्त और समर्पित समाज की ओर कदम बढ़ा रही हैं । इस मौके पर, हम माननीय मोदी सरकार के प्रति हमारे आभारी और समर्पित भावनाएं साझा करते हैं, जो हमें समृद्धि और सामरिक समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करने का एक अद्वितीय संदर्भ प्रदान कर रही है ।

इस सफलता में, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है जो ने अपने कठिन निर्णयों और कदमों से देश को एक नए दिशा में मोड़ने में मदद की है । राम मंदिर की निर्माण में उनका सकारात्मक योगदान देशवासियों के भावनाओं को समर्थन देता है और धारा 370 की समाप्ति ने जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से अनुक्रमण मुक्त बना दिया है । 'तीन तलाक' पर कानूनी कदम और सैनिकों के लिए एक पेंशन की योजना से सरकार ने समाज में सामंजस्य और समर्थन को बढ़ावा दिया है ।इस सालगिरह पर, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने प्रगतिशील और नेतृत्व के माध्यम से देश को एक उच्च स्थान पर पहुंचाया है । उनके सामर्थ्यपूर्ण नेतृत्व के कारण, हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भरता, सामरिक समृद्धि, और सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है । अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण समय में, हम सभी मिलकर 'अमृत महोत्सव' के संदर्भ में और भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ रहेंगे जो नारी शक्ति, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, और युवा शक्ति को समर्पित हैं । हम आपकी नेतृत्व में एक सकारात्मक और समृद्धि से भरी भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं । माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपके प्रशासनिक दक्षता और साहस के लिए हम आपको सलामी भेजते हैं और आपकी सरकार के योजनाओं के सफल प्रवाह के लिए आभारी हैं । हम आपके साथ हैं और मिलकर एक सशक्त, समृद्धि शील, और समृद्धिस्थ भारत की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं ।

इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया, पर्यावरण केंद्रित, सर्कुलर इकॉनमी उपाय, और डिजिटल अर्थव्यवस्था और ए. आई. मिशन में भारत की मान्यता हमारे भविष्य के लिए यथासंभाव हैं । हमारी समृद्धि और सशक्त भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता वैश्विक नेतृत्व, विदेश नीति, संकट के दौरान निकासी प्रयास, सांस्कृतिक कूटनीति, और वैश्विक स्वास्थ्य पहलुओं तक पहुँचती है । माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने इन विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे देश को एक नए स्तर पर पहुंचाने की क्षमता मिली है । अध्यक्ष जी, अयोध्या में ऐतिहासिक समाधान और अमृत पीढ़ी की आकांक्षाएं हमारे भविष्य के दृष्टिकोण को और भी स्थापित करती हैं । माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक समर्थन के माध्यम से राष्ट्र को एक संविदानशील और समर्थ दिशा में मुआवजा प्रदान करने में मदद की है, जिससे समृद्धि और एकता की भावना में सुधार हुआ है । अध्यक्ष जी, जैसे हम आगे की दिशा में बढ़ते हैं, चलिए हम सभी मिलकर 'विकसित भारत के सपने को पूरा करने और सभी के लिए समृद्धि भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काम करते रहें । हम माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को उनके प्रगतिशील और नेतृत्व में दिखाए गए दृष्टिकोण के लिए हृदयपूर्वक प्रशंसा भेजते हैं, और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश को विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए योजनाएं बनाई हैं जो आने वाले समय में भी उच्च स्थान पर रखी जाएँगी । धन्यवाद ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें एक समृद्ध, सुरक्षित, और समृद्धिशील भारत की दिशा में प्रेरित किया है, जिसमें से हमने अनेक चुनौतियों का सामना करके प्रमुख मील के कदम उठाए हैं । माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण और सकारात्मक कदमों ने देश को विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त करने के लिए कई पहलुओं में समर्थन किया है, जिससे हम आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य की प्राप्ति की दिशा में समर्थ रहेंगे । हम उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में कटिबद्ध हैं और इसके लिए हम उनके साथ साझा करते हैं । धन्यवाद । जय हिन्द !

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी का आभार एवं समर्थन व्यक्त करती हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी ने नई संसद भवन में अपना पहला सम्बोधन किया । उन्होंने आज़ादी का अमृत काल के प्रारम्भ में निर्मित इस नई संसद भवन की भव्यता पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि यह इमारत एक भारत श्रेष्ट भारत का सार रखती है और भारत की समृद्धि सभ्यता संस्कृति के रूप में काम करती है ।

माननीय राष्ट्रपति जी ने सभी संसद सदस्यो को बताया कि यह वर्ष संविधान के लागू होने की 75 वी वर्षगांठ है । जिसे आज़ादी के अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है । और अमृत कलश नामक अभियान के दौरान मेरी माटी मेरे देश पहल के हिस्से के रूप में देश के हर गांव से मिट्टी दिल्ली पहुंचाई गयी तथा इसके अंतर्गत 2 लाख से ज्यादा शिला पलक स्थापित किया गया । और महामहिम ने बताया अमृत उत्सव के दौरान कर्तव्य पथ पर नेता जी की प्रतिमा स्थापित की गयी और पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्राहलय की भी स्थापना की गयी । भगवान बिरसा मुण्डा की जन्मतिथि को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया ।

महामहिम ने बताया कि भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन के सफलता पूर्वक आयोजन और एशियाई खेलों में 100 पदक जीत कर हमारे देश के खिलाडियों ने देश का गौरव बढ़ाया ।

माननीय महामहिम जी ने बताया कि समाज के हर वर्ग को उचित अवसर प्रदान करते हुए सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मन्त्र द्वारा निर्देशित समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और बाबा साहेब आंबेडकर जी से जुड़े 5 स्थानों का पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया । राष्ट्रपति जी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार चार मजबूत स्तंभों यूवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों पर विकसित भारत के निर्माण

में विश्वास रखती है । इन स्तंभों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास और संसाधन समर्पित किये गए ।

माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने नारी शक्ति को मजबूत और हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और बताया कि सरकार ने अनेक योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक बल प्रदान किया । जैसे 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के अभियान का क्रियावन्दन किया और पहली बार सशक्त बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना और मुद्रा योजना के तहत 31 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण दिया गया जिससे वे स्वरोजगार के लिए सशक्त हुई है । यह पहली महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों को दर्शाया ।

माननीय राष्ट्रपति जी ने दुनिया भर में मानवीय संकट के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला जहाँ चुनोतियाँ उत्पन्न हुई उनके तेजी से समाधान करने की बुद्धिता प्रदर्शित की गयी । ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी और वन्दे भारत जैसी सरकार की पहलों ने संकट के दौरान प्रत्येक भारतियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की और महामहिम ने स्वीकार किया की संयुक्त सत्र में मौजूद प्रतिनिधि लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं की आवाज़ है । और अमृत पीढ़ी के सपनो को पूरा करने में कोई कसार न छोड़ने की सामूहिक ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर दिया । और विकसित भारत की इस पीढ़ी की आकांक्षाओं को साकार करने में सहायक होगा और इस प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए एक जुट प्रयासों का आह्वाहन किया ।

अन्त में में माननीय प्रधानमंत्री एवं महामहिम का आभार व्यक्त करती हूँ कि आदिवासी के विकास के प्रति समर्पित हमारी सरकार ने अनेक योजनाओं से आदिवासी समाज के उत्थान का कार्य किया है और इसी प्रकार तीव्र गति से हमारी सरकार आगे भी प्रगति का कार्य करती रहेगी ।

धन्यवाद ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व ने आज प्रत्येक भारतवासी के मन मे भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा किया है । जिसका नतीजा है कि पिछला 10 साल हमारे देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है । इसका नतीजा है कि दुनिया में व्याप्त गम्भीर संकटों के बावजूद भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना है । "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है और इसी मंत्र पर चलते हुये 140 करोड़ देशवासियों का जीवन सुधारने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक को सभी जरुरी सुविधाओं को पहुँचाने के लक्ष्य के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है । इसी विश्वास के साथ मोदी सरकार देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास को प्राथमिकता दे रही है ।

मोदी सरकार ने अनेक ऐसे काम कर दिखाए है जिनको सोचना भी कभी बहुत कठिन माना जाता था । हम सभी बचपन से ही गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे थे लेकिन वास्तविकता में यह सिर्फ एक नारा ही बनकर रह गया था । मोदी जी के सशक्त नेतृत्व वाली सरकार की देन है कि आज हम पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे है । नीति आयोग के अनुसार मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले है । यह मोदी सरकार की साफ नीयत और सही विकास की सोच से ही सम्भव हो पाया है ।

मोदी सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदार नीयत से इस दिशा में निरंतर काम कर रही है । इसका परिणाम हमे कोविड 19 के समय में देखने को मिला । विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आपात स्थिति में 8 वैक्सीन्स को उपयोग करने की मंजूरी मिली जिसमें से 3 वैक्सीन भारत द्वारा बनाई गई है ये

वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाई थी ।

मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है । पहले देश में वर्ष 2014 तक जहां सिर्फ 7 एम्स थे वहीं इस एक दशक में 16 एम्स एंव 315 मेडिकल कॉलेज बने है ।

हम सभी ने यह देखा है कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में किस तरह से गरीबों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया था । लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों के जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई भी भूखा नही सोए । सरकार "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" के माध्यम से देश के 80 करोड लोगों को कोरोना काल से ही मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है । आज इस योजना की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने गरीबों की तकलिफ को समझते हुये इस योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें 11 लाख करोड़ रूपये और खर्च होने का अनुमान है ।

माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सेवाकाल के प्रारम्भ से ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है । इस सरकार के अनवरत प्रयासों का नतीजा है कि "प्रधानमंत्री आवास योजना" के तहत आज 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है ।

"हर घर जल" पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई "जल जीवन मिशन" जैसी महत्वपूर्ण योजनायें लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का बहुत बड़ा माध्यम सिद्ध हो रही है । इस योजना के तहत लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहली बार नल से पानी पहुंचा है ।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं जो किसानों को अत्यधिक सशक्त करने एंव उनकी आय को दोगुणा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है ।

सरकार आज खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर बल दे रही है । देश के 80 प्रतिशत किसान छोटे किसान है जो दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे । उनके हितों को मोदी सरकार ने हमेशा प्राथमिकता में रखा है । "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" के माध्यम से देश के 11 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को 2 लाख 80 हजार करोड रूपए की मदद दी गई है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30 हजार करोड रूपये का प्रीमियम भरा जबकि उसके बदले उन्हें डेढ लाख करोड़ रूपये का क्लेम मिला है । इसके अलावा छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, एफ.पी.ओ., सॉयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की कवरेज बढ़ाने के साथ सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है जो स्वागतयोग्य कदम है ।

पिछले 10 वर्षों में सड़क निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है । आज देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसकी कल्पना हर भारतीय को थी । आज नेशनल हाईवे की लम्बाई 90 हजार किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख 46 हजार किलोमीटर हुई है । फोर-लेन नेशनल हाइवे की लम्बाई ढ़ाई गुना बढ़ी है । गांवों में पौने 4 लाख किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनीं है । मा०मन्त्री नीतिन गडकरी जी धन्यवाद के पात्र है ।

इन 10 वर्षों में देश में रेलवे के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुये है । 25 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए है जो कई विकसित देशों के कुल रेलवे ट्रैक की लम्बाई से ज्यादा है । मैं माननीय रेल मंत्री जी एंव माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि मेरे क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी से शिवहर नई रेल लाईन के निर्माण के लिए 566 करोड़ आवंटित किये गये है । अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है । यह सब मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों से ही सम्भव हो पा रहा है ।

देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जो विकास के पैमाने में पीछे रह गये थे । सरकार ने उन जिलों को आकांक्षी जिला घोषित कर, उनके विकास पर ध्यान दिया । आकांक्षी जिले के तर्ज पर सरकार इसे ब्लॉक स्तर पर दोहराने का काम कर रही है जो कि सराहनीय काम है । इसके तहत देश के ब्लॉक्स को भी आकांक्षी प्रखंड के रूप में विकसित किया जा रहा है । मेरी सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर सीतामढ़ी एंव पूर्वी चम्पारण जिले के ब्लॉक्स को भी इस योजना में शामिल किया जाये ।

आज मोदी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नारीशक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है । इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारीशक्ति को ही समर्पित थी जिसमें दुनियां ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक को देखी । - मोदी सरकार में निश्चित रूप से देश की महिलाएं लाभान्वित एंव आत्मनिर्भर बन रही है । आज लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समुह से जुड़कर स्वावलम्बी बन रही है । मुद्रा योजना के तहत जो 46 करोड़ से ज्यादा लोन दिये गये है उनमें लगभग 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को ही मिले है । इस योजना से लाभ लेकर करोड़ों महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू किया है ।

सरकार द्वारा 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चलाया जा रहा है जो सराहनीय काम है । देश में मौजूदा सभी 33 सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश की भी मंजूरी मिली है जो कि पहले केवल लड़कों को ही इनमें पढ़ने की योजना थी । प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंर्तगत 10 करोड महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन दिये गये । मोदी सरकार ने वर्षों से लम्बित महिला आरक्षण हेतु नारी शक्ति वंदन बिल पास करवाया जिससे राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो । यह इस सरकार की ऐतिहासिक कार्यों में से एक है और इसके लिए एक महिला होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि यह नई इमारत एक भारत, श्रेष्ठ भारत का एहसास कराती है । अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी जो अब पूरी हुई है । इसपुर सनातन धर्म को गर्व है वही इस कार्य मे सभी धर्मों का भाईचारे के साथ जो सहयोग मिला वह भारत की एकता एंव अखंडता दर्शाता है । एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना हमारा भारत, हमे हमारे पूर्व माननीय केन्द्रिय मन्त्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिये, हमें गर्व क्यों न हो । हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री जी स्वः कपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिये, हमें गर्व क्यो ना हो ।

भारत में जी-20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ पूरे विश्व ने हमारा लोहा माना वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को हमने विश्व के सामने साकार कर के दिखाया, इस सफल आयोजन से सभी भारतीय गौरवांवित है । भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है यह गौरव की बात है । देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर एक लाख के आंकड़े से भी आगे निकली, देश में मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में पांच गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई ।

डिजिटल इंडिया से बड़ा बदलाव आया तथा यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लेन-देन हुआ है । इन सब में बदलते भारत की तस्वीर झलकती है ।

जब देश 2047 में स्वतंत्रता का शताबदी वर्ष मना रहा होगा तब आज की युवा पीढ़ी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा भारत विश्वगुरू के रूप में शिखर पर होगा । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कल्याणकारी एंव ऐतिहासिक कार्य हुये है और गरीब लोगो के जीवन स्तर में सुधार हुये है । आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदार नीयत के साथ समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निरंतर काम कर रही है । मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर जारी इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, संविधान और हमारी संसद की जो परंपरा है उसमे पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और अगले दिन माननीय वित्त मंत्री जी देश को सरकार का बजट पेश करती है । इसका प्रमुख कारण सरकार की नीति और नियत में समन्वय रखना है । यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है की इस देश की नीति, राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से एक किसान की बेटी और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जी ने दिया और एक आम परिवार की पृष्ठभूमि से आने वाली निर्मला सीतारमण जी ने सरकार की नियत बजट के माध्यम से देश के सामने रखी ।

बीते 10 वर्षों में पुरानी सोच को बदला गया है । पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रमों को दिल्ली के गलियारों तक ही सीमित रखा जाता था । मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है । इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G-20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया । भारत ने G-20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा वैसा पहले कभी नहीं हुआ । देशभर में हुए कार्यक्रमों के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय हुआ । जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए । पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक G-20 सम्मेलन की प्रशंसा की । ऐसे बंटे हुए माहौल में भी एकमत से दिल्ली घोषणापत्र जारी होना ऐतिहासिक है । 'वीमेन लेड डेवलपमेंट' से लेकर पर्यावरण के मुद्दों तक भारत का विजन, दिल्ली घोषणापत्र की नींव बना है ।

सरकार, भारत की युवाशक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है । इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है । इंजीनियरिंग, मेडिकल,

कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में प्रारंभ कर दी गई है। स्कूली शिक्षा में गुणवता लाने के लिए मेरी सरकार, 14 हज़ार से अधिक पीएम श्री विद्यालयों पर काम कर रही है। इनमें से 6 हज़ार से अधिक विद्यालय शुरु हो चुके हैं। सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले ज्यादा हो रहे हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन में लगभग 44% वृद्धि हुई है। नामांकन में, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 65% और ओबीसी के विद्यार्थियों की 44% से अधिक वृद्धि हुई है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10 हज़ार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए है। इनमें । करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं।

साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। वहीं पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले दशक में, MBBS की सीटों में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

विश्व में आज ऐसे उत्पादों की विशेष मांग है, जो पर्यावरण के अनुकूल हों। इसलिए सरकार, zero effect zero defect पर बल दे रही है। आज ग्रीन एनर्जी पर हमारा बहुत फोकस है। 10 वर्षों में non-fossil fuel पर आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावॉट से बढ़कर 188 गीगावॉट हो चुकी है। इस दौरान सोलर पावर कैपेसिटी में 26 गुना बढ़ोतरी हुई है। Renewable Energy Installed Capacity की दृष्टि से हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत non- fossil fuel से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कुछ दिन पहले ही घर की छत पर सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को मदद दी जाएगी। इससे बिजली का बिल भी कम होगा और अतिरिक्त बिजली की खरीद विद्युत बाजार में की जाएगी।

देश, 12 प्रतिशत इथेनॉल ब्लैंडिंग का लक्ष्य हासिल कर चुका है । बहुत ही जल्द, 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लैंडिंग का टारगेट भी पूरा होने वाला है । इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी । अभी तक सरकारी कंपनियां एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इथेनॉल खरीद चुकी हैं । इन सारे प्रयासों से अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी । कुछ दिन पहले ही, बंगाल की खाड़ी में एक नए ब्लॉक में तेल उत्पादन शुरु हुआ है । यह देश के लिए एक बड़ी सफलता है ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बताया कि किस प्रकार अमृत काल का यह 25 वर्ष का कालखंड, स्वतंत्रता की स्वर्ण शताब्दी का, और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है । और अब हमारा मिशन अगले 25 वर्षों में भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का होगा और हम सब पर जिम्मेदारी होगी क्योंकि हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है । सरकार ने अपनी सफल नीतियों से इस देश की दशा को बदला है । आज सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई है चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, युवा हो, महिलाओं हो, पिछड़ा समाज हो या छोटे उद्योग हो ।

2014 से सरकार की विचारधारा थी 'सबका साथ, सबका विकास' । समय के साथ इसमें 'सबका विश्वास' और 'सबका प्रयास' भी जुड़ गया । आज भारत में एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है, जिससे विकसित देश भी प्रेरणा ले रहे हैं । आज सिर्फ घोषणा नहीं implementation भी हो रहा है और हर वर्ग का विकास हो रहा है । हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह कार्यरत है जन विकास के लिए और इस राष्ट्रपति अभिभाषण से सरकार ने अगले 25 वर्ष का roadmap तैयार किया है और मुझे पूरा यकीन है की हमारा देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा । इन्ही शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

धन्यवाद ।

***m45 ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL):** The President's Address to the Joint Session of the Parliament on 31st January, 2024 is full of exaggerated claims to hide the real issues the nation is facing today.

The President's Address has numbered the Government's achievements from earth to moon. But the reality is that the democracy and the federal system of our country is facing major challenges in the "Amrit Kaal'.

The President's Address deliberately keeps silence on violence in Manipur continuing since May, 2023. The ongoing violence has completely devastated the state but no positive measures have been taken by the Government to resolve the issue.

The deteriorating relationship between the Union and the States is becoming a challenge to the federal structure of our nation. The conflict between the State Governors and the State Governments has reached at its high in many States including Kerala. Such confrontations have severely damaged the image of Constitutional functionaries and have created Constitutional logjam in many states. But the Union Government is ignoring this issue which is damaging our democratic values and federalism. The President's Address failed to mention a word on this matter of great concern.

Rising debt and fiscal deficit of states is a matter of great concern. The State of Kerala is facing unprecedented financial crisis and is agitating against the policies of the central Government. But the President's Address has no mention on this issue.

Agriculture sector in the country is in deep crisis and farmer suicides are rising. President's Address keeps silence on this matter of great concern.

Rising unemployment is a major reason for the rising cases of youth unrest across the country. Government is making false claims of providing employment to crores of youths.

Drug addiction among youths is an issue of great concern. Seizure of huge quantities of drugs are being reported daily. Narcotics Control Bureau data reveals manifold increase in drug abuse and trafficking in recent years. Even school children are becoming the victims of drug mafia. Unfortunately, the Government is not considering the seriousness of this issue.

The traditional fishing sector in the country is facing a crisis, unlike ever before. The traditional fishermen are struggling to survive due to job loss and no other source of income. The coastal areas in the country are the most vulnerable to the adverse effects of climate change. The demand for implementing a scheme for ensuring minimum employment in a year for traditional fishermen has not been considered yet by the Government.

In short, the President's Address is hiding the real issues with exaggerated claims of achievements.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह

परिलक्षित होता है कि केन्द्र सरकार ?सबका साथ - सबका विकास' के अपने वायदे के अनुरूप देश को तेजी से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रपति महोदय ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किए जाने का उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है और यह भी बताया है कि लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं । इन समूहों को आठ लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण और 40,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई है और महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ हुआ है । यह हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की उपलब्धियों को बताता है ।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में श्रम कौशल विकास के बारे में बताया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 करोड़ रुपये का गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान किया गया है । और पीएम-विश्वकर्मा के तहत 84 लाख कारीगरों को लाभ मिला है, जो प्रशंसनीय है ।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी उल्लेख किया है कि 10 साल में पूंजीगत व्यय पांच गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 90,000 किमी से बढ़कर 1.46 लाख किमी हो गई है. चार लेन राजमार्गों की लंबाई 2.5 गुना बढ़ गई है और 25,000 किमी से अधिक रेलवे ट्रैक बिछाए गए । भारत रेलवे के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के करीब है । 39 से ज्यादा रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो गई है । हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 149 हो गई है । उड़ान योजना के तहत लोगों ने हवाई टिकटों पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये की बचत की है तथा ब्रॉडबैंड यूजर्स 14 गुना बढ़ गए हैं ।

राष्ट्रपति महोदय ने यह भी जिक्र किया है कि भारत ने आदित्य मिशन लॉन्च किया और सैटेलाइट धरती से 15 लाख किमी दूर पहुंचा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया है तथा अंतरिक्ष क्षेत्र को स्टार्ट-अप के लिए खोल दिया गया है।

यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की है और पहली बार भारत के रक्षा बलों के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है तथा वन रैंक वन पेंशन से पूर्व सैनिकों को करीब एक लाख करोड़ रुपये मिले हैं और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत की सीमा पर आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है । इन सभी का उल्लेख भी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है ।

यह भी हमारे लिए गौरव की बात है कि सरकार ने G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं और शिखर सम्मेलन में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर के विकास की घोषणा की गई है । इसका भी उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में ऊर्जा के बारे में बताया है कि विगत 10 वर्षों में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावाट से बढ़कर 188 गीगावाट हो गई है तथा भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50 प्रतिशत स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है और सौर क्षमता 26 गुना बढ़ गई है, जबकि पवन क्षमता दोगुनी हो गई है। 10 नई परमाणु ऊर्जा योजनाओं को मंजूरी दी गई है एवं नई सौर छत स्थापना योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी तथा वन नेशन, वन पावर ग्रिड से देश में पावर ट्रांसमिशन में सुधार हुआ है और एलईडी बल्ब योजना से बिजली बिल पर 20,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है और उज्ज्वला के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इस योजना पर 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं एवं देश में 10,000 किमी गैस पाइपलाइन

बिछाई गई है । वन नेशन, वन गैस ग्रिड गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है तथा 2014-15 में लगभग दो हजार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बेचे गए । इसकी तुलना में, दिसंबर 2023 तक 2023-24 में 12 लाख ईवी बेची गई हैं । यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विगत दस वर्षों की उपलब्धि को दर्शाता है, जो प्रशंसनीय है ।

राष्ट्रपति महोदय ने देश की अर्थव्यवस्था और वित्त के संबंध में अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि भारत गंभीर वैश्विक संकट के बीच सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और लगातार दो तिमाहियों में 7.5 प्रतिशत से अधिक की विकास दर बनाए रखी है तथा वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों में मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत से अधिक थी, वह पिछले दशक में 5 प्रतिशत पर आ गई है और साथ ही पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है तथा पिछले 10 वर्षों में भारत का निर्यात 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है । विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है । यह स्वागत योग्य है ।

मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण का हार्दिक अभिनंदन और पूरजोर समर्थन करता हूं ।

धन्यवाद ।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): मैं महिला महामहिम राष्ट्रपति जी के "इस अमृत महोत्सव" में दिए गए अभिभाषण से गौरवान्वित हूँ ।

पिछले दस वर्षों में देश बदला है, इस बदलते हुए भारत के परिदृश्य को पूरा विश्व देख रहा है । जी-20 जैसे सफलतम कार्यक्रम को पूरे विश्व ने देखा है । शताब्दियों से धार्मिक आस्था रखने वालो के सपने पूरे हुए है । इस

सरकार ने महिलाओ को सम्मान देते हुए "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" पास किया है । सदियों से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं में तलाक को लेकर भय बना रहता था, अपने अंधकारमय भविष्य को देखकर मुस्लिम महिलाओं ने पीड़ाए झेली है, मैं धन्यवाद देती हूँ मानूनीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने तीन तलाक जैसे काले कानून को समाप्त कर हमारी मुस्लिम बहनों को इस भय से मुक्ति दिलाई है । महिलाओं को सम्मान देकर देश में करोड़ो इज्जतघर बनाएं गए । महिलाओं को पीने का पानी दूर से लाना पड़ता था हमारी सरकार ने हर घर नल-जल योजना से पानी पहुँचाने का कार्य किया है । देश के इतिहास में काला अध्याय के नाम से जाने वाली धारा 370 को हटाकर हमारी सरकार ने देश को एकसूत्र में बाधंने का काम किया है, आज जम्मू कश्मीर बदल रहा है, करोड़ो अरबो की योजनाएं वहीं चल रही है । हमारी सरकार के कार्यकाल में देश में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले है । 34 लाख करोड़ रूपये डीबीटी से ट्रासंफर किए जा चुके है ।

आज हम जमीन से लेकर आसमान तक देश को आगे बढ़ता देख रहे है, जहाँ जमीन पर 2 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगे है वही आसमान में भी हमने सफलता को चूमा है । पूरे विश्व में यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत चन्द्रमा ध्रुव पर झण्डा फहराने वाला पहला देश बन गया है, हमारी वैज्ञानिक प्रगति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इण्डिया को बढ़ावा दिया आज उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे है, यूपीआई से 1200 करोड़ औसतन महीने में ट्राजेक्शन हो हो रही है, 18 लाख करोड़ यूपीआई से ट्राजेंक्शन होकर दुनिया के दूसरे नम्बर पर आज भारत पहुँच गया है ।

मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विश्व में भारत को अग्रणी देशो की श्रेणी में लाने तथा सरकार के सफलतम 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूँ ।

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): I express today with a heart filled with gratitude as we gather here in the hallowed halls of Parliament, under the distinguished presence of our esteemed leader, Shri Narendra Modi ji, my support to the Motion of Thanks to Shrimati Droupadi Murmu, the hon. President of India.

In the journey towards Ek Bharat Shreshtha Bharat and Viksit Bharat, we are blessed to witness India's remarkable rise as one of the top five economies in the world. The record-breaking GST collections since 2017 stand as a testament to the economic prowess our country has achieved. The transformative vision of Digital India has not only simplified lives but also revolutionized businesses across the nation, with an astounding 1200 Crore Digital Transactions through UPI in a single month.

Our commitment to development has reached the farthest corners of our land. The remotest villages have seen the dawn of progress with the construction of 3.75 Lakh KM of new roads, connecting many of them to the mainstream for the first time. The expansion of the National Highway routes from 90,000 to 1,46,000 kilometers and the doubling of airports from 74 to 149 exemplify the Government's dedication to infrastructural growth.

The empowerment of women through schemes like Lakhpati Didi and NAMO Drone Didi, with over 10,00,00,000 women associated with self-help groups, showcases our commitment to inclusive and sustainable development. The Government's support with bank loans totaling Rs 8 lakh crore and financial assistance of

Rs 40,000 crore to these groups has played a pivotal role in fostering economic independence.

In the healthcare sector, the establishment of 16 new AIIMS and 315 medical colleges since 2014 reflects our commitment to providing accessible and quality healthcare across the nation.

However, as we celebrate these achievements, it is crucial to address the needs of the people of my constituency. I take this opportunity to bring forward some pressing demands from my parliamentary constituency.

The establishment of the PM-MITRA Mega Textile Park in Kalaburagi holds the promise of creating over 1,00,000 direct employment opportunities. I urge the concerned to intervene and expedite the policy framework for its establishment.

The long-pending approval for the second ring road in Kalaburagi and the inclusion of Koli Kabbaliga and Kurba communities in the ST list demand your urgent attention. Additionally, the development of the Kalaburagi Railway Division, announced in 2014, requires acceleration, along with the extension of Sholapur-Mumbai Vande Bharat to Kalaburagi and the restart of the Kalaburagi-Hyderabad Intercity Express. A new train between Kalaburagi and Bangalore is the need of the hour.

I extend my deepest gratitude to the hon. President for announcing the Welfare and Development Board for Banjara, Nomadic, and Semi-Nomadic Communities. I humbly request the expedited establishment of this board, urging the inclusion of the

term "Banjara" for the benefit of over 8 to 10 Crore Banjara people in our country.

In conclusion, I express my heartfelt appreciation for the transformative leadership of Shri Narendra Modi ji and the Government's unwavering commitment to the holistic development of our great nation.

Jai Hind!

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करता हूं । पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य इस देश में हुए धारा 370 से लेकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम, CAA से लेकर तीन तलाक और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने इस देश के लिए नये इतिहास की रचना की है । राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हमारे समय में हमारे जीवन की महान घटना है जिसको आने वाली पीढ़ियों को बता पाना हमारे जीवन का उत्तम क्षण है| आजादी के 65 वर्षों में जो नहीं हो सका वह पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने करके दिखाया । 2014 में जो अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी आज 5 वें स्थान पर पहुंच गई । आज बावजूद इसके की कोविड के दौरान पूरी दुनिया की इकोनॉमी में डाउनफॉल आया परंतु हमारे जीडीपी लगातार बढ़ती रही । आज हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है । हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है जो दुनिया में सबसे बेहतर है महंगाई दुनिया के सबसे कम है| इस देश में जिस प्रकार के विकास कार्य हुए पिछले 10 वर्षों में इस देश का नक्शा बदल दिया । हर घर नल से जल की बात हो या घर सौभाग्य योजना में बिजली पहुंचाने का कार्य की बात करें| हर घर शौचालय बनाकर 11.72 करोड़ बहनों को शौचालय बनाकर उनकी इज्जत का ध्यान रखा, साथ ही 10 करोड़ उज्जवला कनेक्शन देकर माता बहनों के स्वास्थ्य ध्यान रखा गया । 10 करोड लोगों को 5 लाख तक मुक्त इलाज की सुविधा देकर 60

करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ देने का कार्य हुआ । 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाए गए । 10 करोड़ किसान आज किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं । आज दुनिया का मार्गदर्शन करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां इस दुनिया के कोविड-19 जैसी महामारी से बचाया वंही 80 करोड लोगों को मार्च 2020 से दिसंबर 2028 तक 5 किलो अनाज व एक दाल देकर अन्नदाता के रूप में गरीबों की सेवा करने का कार्य किया है । आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में माननीय मोदी जी पूरी दुनिया में अलग पहचान के साथ खड़े हैं । जी-20 की बात हो या चंद्रयान-3 की या सूर्ययान की सफलता हो पूरी दुनिया हमारे देश का लोहा मानने लगी है । आर्थिक रूप से समृद्धि के साथ-साथ सामरिक रूप से सद्रण होना आज एक सशक्त नेतृत्व के कारण संभव हुआ । जिस प्रकार हर क्षेत्र में आज देश आगे बढ़ा वह चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र, नए नेशनल हाईवे की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो, रेलवे की बात हो, या शिक्षा क्षेत्र में एनइपी को लाकर इस देश में युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से जो पग उठाए गए है वह सराहनीय है कुल मिलाकर जिस प्रकार से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है और 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा और हमारे देश एक विकसित राष्ट्र बंद कर रहेगी अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले माह में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं ।

धन्यवाद ।

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): मैं महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ ।

माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार का 10 साल का लेखा जोखा पेश किया है जो काफी उत्साह जनक है । हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र

में अभूतपूर्व उन्नति की है, जिसका वर्णन करना मैं अपना दायित्व समझती हूँ।

सबसे पहले मैं विदेश नीति के बारे में जिक करूगी । आज केवल दो देशों को छोड करके, पाकिस्तान व चीन । हमारे संबंध विश्व में हर देश के साथ बहुत अच्छे है । हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है । आज विश्व दो भागों में बटा हुआ है । लेकिन हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है । हमारे संबंध दोनों गुंटों से गहरे है । सोवियत रूस पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद, हमारे रूस से संबंधे में कोई कमी नहीं आई है । बल्कि प्रतिबंधों के पहले से भी हमारा व्यापार दोनों देशों के बीच बढ़ा है । आज हम अपनी आवश्यकता का एक तिहाई कच्चा तेल रूस से आयात कर रहे है, इससे हमने अमेरिकी गुट को भी नाराज नहीं किया है, बल्कि हमारे संबंध अमेरिका से भी पहले से अधिक मधुर हुये है । हमने अमेरिका से अन्तरिक्ष क्षेत्र से लेकर रक्षा क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में अनुबंध किये है । आज हर अन्तराष्ट्रीय समस्या में भारत से परामर्श के बिना उसका समाधान नहीं होता है । इसी से आप समझ सकते है कि भारत ने अपनी विदेश नीति में कितनी ऊचीं छलांग लगाई है । इस सबका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जाता है ।

अब मैं अपनी आंतरिक नीति पर सबसे पहले बात करना चाहती हूँ । अपनी आंतरिक तकनीक पर हमने चन्द्रायन को चाँद के उस क्षेत्र में भेजने में सफलता प्राप्त की है, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुँच सका है । वहां से हमें डाटा प्राप्त हुआ है । साथ ही हमने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने सेटेलाइट को सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे स्थान पर स्थापित कर दिया है जहां से लगातार सूर्य पर होने वाली घटनाएं कैद हो सके । अंतरिक्ष तकनीक में भारत विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है । वह दिन दूर नहीं जहां हम मानव को चन्द्रमा की सतह पर उतारेगें ।

रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार का जोर मेड इन इंडिया पर है । रक्षा क्षेत्र से संबंधित ज्यादा से ज्यादा उपकरण हम अपने ही देश में बना रहे है ।

हमारी निर्भरता विदेशों पर कम से कम होती जा रही है । अभी हम काफी कुछ रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे है । उदाहरण के तौर पर हमने जो तेजस विमान विकसित किया है उसकी अनेक देशों में मांग है इसी तरह से ब्रम्होस मिसाइल की भी मांग है । इससे सिद्ध होता है कि हम रक्षा क्षेत्र में काफी आगे बढ रहे है जो एक सुखद समाचार है ।

ऊर्जा क्षेत्र में भी गैर पारम्परिक क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे है जैसे कि सौर ऊर्जा, विंड पावर इत्यादि । हमने बड़े-बड़े सोर ऊर्जा पार्क स्थापित किये है और आगे करने जा रहे है । हमारा पूरा ध्यान क्लीन ऊर्जा की तरफ है और इसमें हम पूरी तरह से सफल हो रहे है । यहां भी हम अपने लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर रहे है ।

हमारी सरकार मूल ढाचे पर विशेष ध्यान दे रही है । आज विश्वस्तरीय सड़को का निर्माण हो रहा है । हम ऐसी सड़कें तैयार कर रहे है कि जरूरत पड़ने पर उन पर हम अपने लड़ाकू विमान उतार सके । हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बेहतरीन सड़कों का जाल विछा दिया है । जो आज तक नहीं हो पाया था ।

हमारी सरकार रेलवे कार्यकल्प पर भी विशेष ध्यान दे रहीं है । जगह-जगह लाईनों का चौड़ीकरण व विद्युतीकरण हो रहा है । 1300 रेलवे स्टेशनों का कार्यकल्प किया जा रहा है । नई-नई रेलगाड़ियों का निर्माण अपने देश में ही हो रहा है । मालगाड़ियों की गति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाये । गाडियों को दुर्घटना से बचाने के लिए नए-नए तरीके खोजे जा रहे है । मुझे आशा है कि बहुत ही जल्दी हमारा रेलवे नेटवर्क विश्वस्तरीय हो जायेगा ।

सैकड़ों सालों के इन्तजार के बाद 22 जनवरी, 2024 को रामलला अपने भव्य मन्दिर में विराजमान हुए है । इसने सारे हिन्दू समाज को एक सूत्र में बांध दिया है । देश के हर कोने में खुशी का माहौल है लोग दीवाली मना

रहे है । जब इस मन्दिर का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे विपक्ष के मित्र यह कह रहे थे कि इससे हम खाड़ी देशों को नाराज कर देगें, लेकिन हुआ इसका उल्टा । न केवल भारत में इस भव्य मन्दिर का निर्माण हुआ है बल्कि आबूधाबी में भी एक भव्य और विशाल मन्दिर बनने जा रहा है । जिसका उद्‌घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी इसी महीने करेंगें ।

हमारी सरकार 80 करोड़ से भी ज्यादा गरीब नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान कर रही है जिससे कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे । सरकार ने इन व्यक्तियों के लिए इतनी सुविधा दे दी है कि वह देश में किसी भी जगह से राशन प्राप्त कर सकते है । अब सरकार ने यह सुविधा 2028 तक बढ़ा दी है ।

हमारी सरकार गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाकर दे रही है । करोड़ों लोगों को पक्के मकान, शुद्ध पेयजल, मुफ्त गैस सिलेंडर, शौचालय आदि प्रदान किये जा रहे है जिससे कि उनका जीवन स्तर सुखमय हो सके । सरकार के इन प्रयासों से (एक रिपोर्ट के अनुसार) करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गये है यह हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है । इसलिए कहा गया है कि न टपकती छत, न आंगन कच्चा, सपने नहीं हकीकत गुनते है । तभी तो सब मोदी को चुनते है ।

इन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुये अपनी वाणी को विराम देती हूँ ।

जय हिन्द, जय भारत ।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं माननीया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूं ।

संसद के बजट सत्र की शुरुआत में माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अभिभाषण एक पुरानी और महतवपूर्ण संसदीय परम्परा रही है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों का लेखा-जोखा और केंद्र सरकार का आगामी विजन देश और जनता के समक्ष रखा जाता है ।

एक समय था जब हमारे देश की गिनती पिछड़े देशों में की जाती थी, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के बल पर भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है । दुनिया में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा विकास दर 7.5 प्रतिशत के आसपास बरकरार है और आगे भी इसी रफ़्तार से बढ़ने की उम्मीद है । आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ।

आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भारत सरकार द्वारा गत दिनों में किए गए प्रयासों एवं 2047 के भारत के विजन के संदर्भ में विस्तार से बात कही है ।

भारत आज विश्व में बहुत बड़े उत्पादन हब के रूप में उभर रहा है । आज दुनिया की बड़ी- बड़ी कंपनियां भारत में अपनी उद्योग लगा रही है, आज भारत रक्षा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व निर्माण कर रहा है । आज देश में रक्षा, कृषि, खाद्यान जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है । आज भारत का रक्षा निर्यात पहले के मुकाबले 6 गुना बढ़ चुका है ।

आज भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत सेमीकंडक्टर चिप से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण कर रहा है और ऐसे ही प्रयासों के बल पर भारत में बने सामान का निर्यात लगातार बढ़ रहा है । आज हमारी सेनाएं आधुनिक युग की तकनीकों से सुसज्जित हो रही है । देश के युवाओं को सेना के माध्यम से राष्ट्र सेवा का अवसर प्रदान किया जा रहा है ।

आज भारत में 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर स्टार्टअपस् है । आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश है । देश के 11 करोड़ छोटे किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता में है, जिनको पहले नजरंदाज किया जाता रहा है । हमारी सरकार द्वारा इन छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा लगभग सवा 2 लाख 80 करोड़ रूपए से अधिक की मदद की गई है, जिसमें से लगभग 80 हजार करोड़ रूपए की मदद महिला किसानों को पहुंचाई गई है ।

ऐतिहासिक जी-20 सम्मेलन के सफल आयोजन ने भारत को पूरे विश्व में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई । हमारी सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान गाँवों में पौने 4 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया, राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 90 हजार किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख 46 हजार किलोमीटर हो गयी है ।

देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी, जो अब दोगुनी होकर 149 हो गयी है और तेजी से नए एअरपोर्टस का निर्माण कार्य चल रहा है । देश की लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है । अमृत भारत योजना के अंतर्गत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है । 25 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए, भारत जल्द ही शत प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है । 39 से ज्यादा रूट पर अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं वाली वन्दे भारत ट्रेन चल रही है ।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 लाख करोड़ रूपए की राशि से लगभग 11 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन से जल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई । ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर प्रदान किया गया है । 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किये गए । कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन वितरित किया गया और इसे 05 वर्षों के लिए बढाया भी गया,

जिस पर 11 लाख करोड़ रूपए के खर्च का अनुमान है । किसानों को सस्ती खाद, कृषि निर्यात नीति, कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रूपए से अधिक, किसानों को आसान लोन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख 50 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का क्लेम दिया गया । वर्ष 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किये गए, साथ ही 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जा रहे है ।

पिछले लगभग 10 वर्षों से ज्यादा के शासन काल में हमारी केंद्र सरकार ने देश को एक- स्थायी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब, किसान, वंचित और शोषितों के कल्याण की दिशा में तेजी से काम करते हुए "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" का निर्माण करना है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय पर आगे बढ़ रही है ।

मैं, एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण हेतु धन्यवाद देता हूँ ।

जय हिन्द, जय भारत ।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 31/01/2024 को संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों के समक्ष अपना अभिभाषण दिया ।

यूँ तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी एक परंपरा है परन्तु इस वर्ष का अभिभाषण कई मायनों में हमारे लिए बेहद खास और ऐतिहासिक रहा है । आजादी के अमृत काल की शुरुआत में बना इस भव्य भवन में महामहिम

राष्ट्रपति महोदया का यह पहला सम्बोधन था साथ ही यह वर्ष एक तरफ जहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ वही हमारे संविधान लागू होने का भी 75वां वर्ष है ।

आज़ादी के अमृतकाल "मेरी माटी, मेरा देश" अभियान के तहत में देश के कोने कोने से मिट्टी एकत्रित कर अमृत कलश में दिल्ली लाया गया जहाँ उससे अमृत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, यह बहुत ही गौरव का विषय है । इस अमृत कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने अनेकों गौरवशाली कार्य किये हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं झारखण्ड की भूमि से आता हूँ जिसे भगवान बिरसा मुंडा का पावन भूमि भी कहा जाता है । दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस सम्मान के भगवान् बिरसा मुंडा हकदार थे पिछली सरकारों में उस सम्मान से उपेक्षित रहे परन्तु मोदी जी ने इस अमृत काल में उनके जयंती को "जनजातीय गौरव दिवस"के रूप में घोषित कर ना केवल भगवान् बिरसा मुंडा को सम्मान दिया बल्कि समस्त झारखण्ड वासियों को सम्मान दिया है उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ । महामहिम ने अपने अभिभाषण में यह जिक्र किया कि कैसे बीते वर्ष भारत ने विश्व की पटल पर एक अपना अमिट छाप छोड़ने का कार्य किया है । हम चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना तिरंगा लहराने में कामयाब रहे, जब संपूर्ण विश्व गंभीर संकटों में घिरा रहा तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व भारत 'विकसित भारत' की ओर कदम बढ़ा रहा था और लगातार 2 क्वार्टर में भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत से ऊपर रही ।

हमारे देश की इस कामयाबी को आज देखकर पूर्व राष्ट्रपति डॉ अब्दुल कलाम साहब की एक बात याद आ गयी कि

"मंजिल उसी को मिलती जिसके सपनों में जान होती है,

पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है "

माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया कि गांधी जी के सपनों का विकसित भारत हमारी सरकार हौसलों से पूरा करेगी चाहे जितनी बाधाएं आये हम लड़ने को और संघर्ष करने को तैयार हैं । आज भारत का परचम समस्त घरा पर लहरा रही है । ऐतिहासिक G-20 का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर भारत ने यह साबित कर दिया कि यह नया भारत है जो विश्वगुरु बन कर फिर एक बार दुनियाभर का नेतृत्व करने में सक्षम है । हमारी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा भी जिसके परिणाम स्वरुप पहली बार भारत ने एशियाई 100 से अधिक पदक जीते साथ ही पैरा एशियाई खेलों में अधिक पदक जितने का कार्य किया है । महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने वक्तव्य में युवाओं को मिशन मोड में सरकारी नौकरी देने का जिक्र किया, निश्चित रूप से हमारी सरकार आने के बाद देश के विभिन्न स्थानों में "रोजगार मेला" का आयोजन कर युवाओं को सरकारी नौकरी मिसियों मोड में दिया जा रहा है । मुझे भी मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद में 3 बार रोजगार मेले में शामिल होकर युवाओं के बिच नियुक्ति पत्र बाटने का सौभाग्य मिला ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी को भी सशक्त करने का कार्य किया है । देश चलाने में उनकी भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" पारित किया है जिसकी महामहिम ने सराहना भी की है । अध्यक्ष महोदय, हम देश को अपनी मां मानते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम से हर माँ को सम्मान देने का कार्य किया है । और कहा जाता है

"नारी ही शक्ति है नर की,

नारी ही है शोभा घर की,

जो उसे उचित सम्मान मिले,

तो ही घर में खुशियों के फूल खिले"

महामहिम राष्ट्रपति जी अपने वक्तव्य में कहा कि कोई भी राष्ट्र, तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वह पुराणी चुनौतियों को परास्त करके अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य के निर्माण में लगाए । हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल को जनता के लिए एक स्वर्णिम काल बनाने के लिए दिन- रात एक कर दिया । हमें याद है जब हम अपने ही देश में अपने आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु कैसे संघर्ष किया था, आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है भक्त प्रभु के दर्शन कर रहे हैं । सदियों से जो संघर्ष हमारे कई पीढ़ियों ने किया उसका जब परिणाम आया तो पूरा देश दिवाली मनाया । वर्षों से एक चुनौती थी कि अगर कश्मीर से धारा-370 हटा तो ना जाने क्या होगा आज वह इतिहास हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर के लोगों का जीवन बदल रहे हैं । आतंकवाद से पीड़ित कश्मीर के भोले भाले लोगों को सरकार ने मुख्या धारा से जोड़कर विकसित करनी का कार्य किया है । कहा जाता है

"वीर पुरुष को कहाँ भला, किसी चीज़ का डर है.

उसके लिए तो चुनौतियाँ ही अवसर है"

इस वाक्य को चरितार्थ हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने पंडित गोपबंधु दास की अमर पंक्तियों का भी जिक्र किया निश्चित रूप वह "राष्ट्र सर्वोपरि" की भावना जागृत करने वाली आदर्श पंक्तियाँ हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने "नेशन फर्स्ट और पार्टी नेक्स्ट" के सिध्दांत पर काम किया है । हमारी सरकार ने 'वन रैंक, वन पेंशन' को लागू कर पूर्व सैनिकों को सम्मान देने का कार्य किया है । जहाँ पूर्व की सरकारें केवल गरीबी हटाओ का चुनावी नारेबाजी किया करती थी वहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में "गरीबों को गणेश" मानकर उनको प्राथमिकता देने का कार्य किया है ।

माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत विकसित राष्ट्र की भव्य ईमारत युवाशक्ति नारीशक्ति, किसान, और गरीब के 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी और इन स्तंभों को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है । करीब 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देने का काम किया, उज्ज्वला योजना, गैस पाइपलाइन बिछाना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड जैसे अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को सशक्त बनाने का कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार कर रही है ।

आज भारत के युवा गर्व से कह सकते हैं

"we are not job seeker, we are job creator"

यह संभव हो पाया है तो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच की वजह से ।

देश ने कभी यह भी सुना था कि कैसे देश के प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 1 रुपया देता हूँ लेकिन देश की जनता तक पहुँचते पहुँचते 4 पैसा हो जाता है और देश आज गवाह है कि कैसे एक 56 इंच सीने वाला प्रधानमंत्री जब 1 रुपया देता है तो वह एक रुपया जनता तक सीधे पहुँचती है । कोई बिचौलिया, जनता के हक का पैसा नहीं खा सकता है । मोदी जी का कहना था कि "ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा", इसी सिद्धांत पर चलकर आज देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन का स्थापना हुआ है । आज कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप हमारी सरकार पर साबित नहीं कर सकता, नहीं तो यह देश ने वह भी देखा है कि कैसे सरकार में बैठे लोग दीमक की तरह जनता खून पसीने की कमाई को चाट खाते थे । देश की जनता को पहली बार प्रधानसेवक मिला है और मैं यकी के साथ कह सकता हूँ कि उनका ये प्रधानसेवक सदैव उनके हित में फैसले लेंगे और विकसित भारत का सपना को साकार करेंगे । मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले कहना चाहता हूँ कि

" मोदी होगा तो काम भी होगा,

मोदी होगा तो देश का बड़ा नाम भी होगा,

और जबतक है मोदी देश का संपूर्ण विकास होगा"

बहुत बहुत धन्यवाद ।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): मुझे यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि अंतरिम बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं है । खासकर बिहार के सीमांचल क्षेत्र के जिलों को इस बजट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है । बजट में साफ तौर पर बिहार के साथ नाइंसाफी झलक रही है । बिहार का Northern और Northeast Region का Geographical Orientation कुछ इस प्रकार से है कि मानसून के दौरान करीब 4 माह नेपाल के तराई क्षेत्रों से निकलने वाली दर्जनों नदियां कोसी, महानंदा, मेची, कनकई आदि का अतिप्रवाह (Overflow) हर साल यहां भारी तबाही लाती है, Scientific Research के मुताबिक लगभग पूरे उत्तर बिहार की आबादी बाढ़ की मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार कोसी मेची नदी के लिंक की Proposal पर विचार कर रही है, इससे उत्तर बिहार में अवस्थित बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी, कोसी नदी की जलधारण क्षमता और बाढ़ के दौरान Overflow की Frequency इससे लिंक होने वाली नदियों से अधिक है और इस परियोजना से सीमांचल के कई जिलों में अनावश्यक रूप से बाढ़ संभावित क्षेत्रों में नया ईकोसिस्टम विकसित होगा, जिससे इस परियोजना पर अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी इस इलाके को किसी किस्म की बाढ़ से राहत नहीं मिलेगी, उल्टा नए संकट उत्पन्न होंगे । प्रतिवर्ष उत्तर बिहार और सीमांचल में बाढ़ के कारण यहां जान वो माल की भारी तबाही होती है, हजारों एकड़ जमीनें नदी में विलीन हो जाती है और

लोग बेघर होते हैं, मैंने इस सदन के माध्यम से कई बार इन मुद्दों से केंद्र सरकार को अवगत करवाया है ।

महानंदा बेसिन की मांग के साथ साथ सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिलों के नदियों की गहराईकरण और Bolder Peach/Concrete Wall के जरिए तटबंधीकरण का मांग किया, लेकिन सीमांचल के जिलों के ज्वलंत मुद्दे, यहां के लोगों की गरीबी और बेबसी केंद्र सरकार के संवेदनशीलता का विषय अब तक नही बना, इससे अधिक हम सीमांचल वासियों की और क्या बदनसीबी हो सकती है ।

किशनगंज संसदीय क्षेत्र और इसके आसपास के जिले और पड़ोसी राज्य बंगाल की जनता AMU किशनगंज शाखा पर मौजूदा केंद्र सरकार और बिहार सरकार के रुख से काफी चिंतित हैं, लोग अपने बच्चों की Higher Education के लिए Central Government के Institute के रूप में AMU किशनगंज शाखा निर्माण के लिए पिछले 10 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं । केंद्र में UPA-II कार्यकाल के दौरान AMU किशनगंज शाखा के लिए बिहार सरकार से भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, बिहार के तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में अकारण देरी हुई, वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और axe के मल्लापुरम में राज्य सरकारें जमीन उपलब्ध कराने में कोई देरी नहीं की, नतीजा यह रहा कि मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम में AMU की शाखाएं बनकर पूर्ण रूप से संचालन में हैं । वहीं AMU किशनगंज शाखा बिहार में तत्कालीन NDA सरकार के भेदभावपूर्ण नीतियों का शिकार हुई और चौतरफा दबाव पड़ने पर ऐसी भूमि उपलब्ध कराई गई जो महज 1 वर्ष में NGT की रोक लग गई, इस भूमि पर निर्माण कार्य की अनुमति केंद्र सरकार की संस्था NMCG के अधीन है, अब सीमांचल के करीब 8 जिलों की लगभग 2 करोड़ से अधिक जनता केंद्र और बिहार की NDA सरकार पर AMU किशनगंज शाखा की निर्माण की नीति और नीयत पर निगाहे बनाए रखें हैं ।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर राज्य में AIIMS के निर्माण को लेकर INTEREST दिखाया था और वर्ष 2017 में बिहार में AIIMS निर्माण के लिए बिहार सरकार को भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा था, बिहार के सभी जिलों में सबसे पहले किशनगंज जिला ने भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट सौंपी। किशनगंज जिला बिहार के करीब 10 जिले और बंगाल के 3 जिले के तकरीबन 3-4 करोड़ जनता की सुविधाओं के केंद्र में होने और बेहतर भूमि उपलब्ध कराने के बावजूद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और केंद्र और बिहार में NDA सरकार के ध्यान से वंचित रहा, वहीं दरभंगा जिला में झील में AIIMS के लिए भूमि चिन्हित किया गया, कई वर्ष बीतने के बाद भी यहां AIIMS के लिए एक ईंट भी नहीं लग पाया है। मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी से आग्रह करूंगा कि सीमांचल् की आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन और गरीबी के दृष्टि से जनहित में इस AIIMS का निर्माण किशनगंज में कराया जाए।

देश के अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ सोशल मीडिया में नफरत और जहरीला कंटेंट फैलाया जा रहा, धार्मिक स्थलों को Target किया जा रहा है। Minority Institutions पर केंद्र और राज्य सरकारों की भेदभावपूर्ण नीतियां और सहयोग के नाम पर हाथ खड़े करना Minority वर्ग की Religious और Cultural Identity और Activities पर बुरा प्रभाव डाला है। भारत के सभी वर्गों और धर्मो के लोगों में एकता और भाईचारा (Unity and Diversity) पूरी दुनिया में मिसाल है।

केंद्र सरकार देश के अंदर Minorities के खिलाफ नफरत और उन्मादी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के पर सख्त करवाई करने के लिए कानून लाए जिसके जरिए ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही AMU और JAMIA के साथ साथ तमाम Minority Institutions की Minority Status और Financial सहयोग केंद्र सरकार द्वारा सुनिचित की जाए। बिहार एवं खासकर सीमांचल में गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और

इसी कारण यहां पलायन दर बढ़ती जा रही है । अंतरिम बजट में केंद्र सरकार गरीबों एवं गरीबी की झूठी तस्वीर पेश कर रही है । देश के 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से निचले स्तर पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं । शायद इसी लिए देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार अनाज देने की जरूरत पड़ी । इन आंकड़ों से साफ है कि देश में गरीबी घटी नहीं बल्कि बढ़ी है । मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था की सच्चाई ये है कि देश में गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उनके नजदीकी पूंजीपतियों की संपत्ति लगातार तेज़ी से बढ़ रही है यही इस सरकार आर्थिक नीति है । बिहार में गरीबी हटाने के लिए सिर्फ अनाज बांटना ही काफी नहीं, इसके अलावा Effective Measure के तौर पर यहां गरीबी एवं पत्रायन के कारणों पर केंद्र को काम करना चाहिए । किशनगंज संसदीय क्षेत्र के अंर्तगत किशनगंज और पूर्णिया जिलों में चायपत्ती, अनननास की खेती होने के बावजूद भी किसानों को सरकारों से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है । आम किसानों को केंद्र और राज्य सरकार के स्कीमों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सिस्टम में बिचोलियों का बोलबाला है । ऐसे में किसानों को उनका हक मिल सके, सरकार नियंत्रित मंडी कायम किया जाए ।

श्री बिद्‌युत बरन महतो (जमशेदपुर): भारत के सभी नागरिकों की ओर से, हम सभी को संबोधित करने और देश को एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के लिए मैं राष्ट्रपति महोदया को दिल से धन्यवाद देता हूं । भारत सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं और हम सभी इसके लिए आभारी हैं ।

हमारे देश ने पिछले दस वर्षो मे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास की गति को बहुत बढ़ाया है । पिछले दस वर्षों में बुनियादी ढांचे के जो नियोजित विकास हुआ है उसकी कहानी जगजाहिर है । हमारी सरकार

ने समाज के सबसे निचले पायदान पर जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन उत्थान हेतु बुनियादी सुविधायें निर्बाध रूप से पहुंचाई है ।

एक ओर जहां मोदी सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर भव्य संसद का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कर इसे दुनिया के सबसे सफल लोकतांत्रिक प्रतीक के रूप में स्थापित किया है । वहीं दूसरी ओर, कोरोना जैसे गंभीर वैश्विक संकट के बीच भी, भारत सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख उद्योग के रूप में उभरा है और हमारे देश ने लगातार दो तिमाहियों में कुल 7.5% से अधिक की विकास दर बनाए रखी है । भारत आने वाले समय में अपनी संपूर्ण विकास यात्रा को और तेज करने के लिए क्षमता निर्माण में पूरी तरह समर्पित है ।

इस क्रम में मैं सक्षम रक्षा नीति एवं सफल विदेश नीति की भी अवश्य चर्चा करना चाहूंगा । हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित किया है जिससे भारत के रक्षा बलों के लिए पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है । इसके अलावा पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत लगभग एक लाख करोड़ रुपए की धनराशी प्रदान की गयी है । एक और प्रोग्राम जिसका नाम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसके अंतर्गत भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आधुनिक इफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है जिससे सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके और ऐसे क्षेत्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सके । आज 123 अकांक्षी जिलो को चिन्हित करके देश को एक नई दिशा दी गयी है, बेहतर स्टार्ट अप, इको सिस्टम का विकास हुआ है, देश में कौशल उन्नयन का विकास हुआ है । देश ने आजादी के बाद से असमान विकास किया था, उसका दुष्परिणाम मेरे क्षेत्र ने भी झेला था । क्षेत्रीय असमानताओं के कारण हमारे उस क्षेत्र का विकास असंभव था जिसे मोदी जी ने संभव करके बताया है । मेरा ससदीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, विकास की राह देखते देखते 75 वर्ष बीत गए । मगर हम खुश हैं कि कल के बजट में 500 करोड रुपये रेलवे के विकास के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र को मिला ।

एनएचएआई से जुड़ने के कारण राष्ट्रीय परिदृश्य मे मेरा ससदीय क्षेत्र सबसे पीछे था, वह आगे के क्रम में खड़ा हो गया है । चम्बल नदी हमारे मुहाने पर खड़ी थी । आज एक एक इंच भूमि चम्बल के पानी से सिंचित होने के लिए आगे बढ़ गई है ।

वैश्विक स्तर पर भारत की सफल विदेशनीति की खूब प्रशंसा हो रही है । इस क्रम में मैं भारत की अध्यक्षता मे पूरे वर्ष भर चलने वाले 520 कार्यक्रम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमे सरकार ने अब अफ्रीकी संघ के लिए स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं और साथ ही शिखर सम्मेलन में भारत पश्चिम एशिया यूरोप कारिडोर के विकास की घोषणा की है । इस कोरिडोर के विकास से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और पश्चिम एशिया और यूरोप के आपसी संबंध भी मजबूत होंगे और भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी ।

हमारे देश में महिलाओं को हर कार्यक्षेत्र में भागीदारी दी जानी चाहिए जिसकी शुरुआत लोकसभा और विधानसभाओं से की गयी है जिसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी को सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया है । इसके साथ ही लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं । इन समूहों को आठ लाख करोड रुपए के बैंक ऋण और 40,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है । इसके अलावा अब महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है जिससे लाखो महिलाओं को लाभ हुआ है । इन सभी प्रयासों से यह महसूस होता है की अब भारत में महिलाओं को विभिन्न स्तरों पर अनुकूल माहौल एवं प्रोत्साहन प्रदान करने से नारी सशक्तिकरण का हमारा संकल्प पूरा हो रहा है ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार PM श्री स्कूलों पर काम कर रही है जिसमें तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण हेतु विभिन्न योजनायें जैसे स्किल इंडिया आदि निश्चित तौर एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की ओर

बढ़ाया गया कदम है । सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 14,000 से अधिक पीएम श्री स्कूलों पर काम कर रही है इनमें से लगभग 6,000 स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है और इन स्कूलों में वह सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होती है । देश में एस.सी. और ओबीसी विद्यार्थियों का नामांकन 44% और एसटी विद्यार्थियों का नामांकन 65% बढ़ा है और इसके साथ साथ देश में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने के लिए भी कानून पारित किया गया है ।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का सदैव यह संकल्प रहा है कि देश के हर नागरिक को एक पक्की छत मिले जहां वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और इसके साथ ही उन्होंने अपनी अलख जगाकर एक सक्षम और सशक्त भारत के निर्माण का भी संकल्प लिया है । सबके घर गैस चूल्हा पहुंच गया है । सड़कें गांव गांव तक पहुंच गई है और स्कूलों की व्यवस्थाएं भी बनी है ।

आज देश में लगभग 4.1 करोड़ गरीब परिवारों के पास अपना पक्का घर है जिसकी लागत करीब 6 लाख करोड़ रुपये है और देश के नागरिकों की जीवन शैली में पेयजल (पीने योग्य पानी) की सुविधा को पूरी प्राथमिकता दी गयी है । जिसके लिए सरकार ने हर घर जल पहुचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया । करीब 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है । जिससे देश में हर घर जल पहुंचाने की सरकार की पहल को पूरा किया जा रहा है । शहरों की झुग्गी बस्तियों में जबरदस्त सुधार हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनने का क्रम बहुत बढ़ा है । एक समय था जब कुओं से पानी लाना पड़ता था और पानी दूषित होता था । 2024 में घर में पीने का पानी टोटी द्वारा चूल्हे पर उपलब्ध होगा । देश के नागरिकों की जीवन शैली में पेयजल (पीने योग्य पानी) की सुविधा को पूरी प्राथमिकता दी गयी है जिसके लिए सरकार ने हर घर जल पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया । जल जीवन मिशन के तहत पिछले तीन वर्षों में लगभग 11 करोड परिवारों को

?पाइप वाटर सप्लाई? की सुविधा से जोड़े जा चुके है जो इस सरकार की बड़ी उपलब्धि में से एक है ।

स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए देशभर में कुल 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण किए गए है जिससे खुले में शौच से मुक्ति हुई है और जनता का खुले में शौच से होने वाली कई बीमारियों से बचाव हुआ है ।

आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश है । मेक इन इंडिया की नीति के तहत आज भारत प्रोडक्शन में दुनिया में अव्वल स्थान पर जा रहा है । इससे पूरे देश में एक नया रोजगार मिलेगा । डिजिटल इंडिया में भारत समग्र विश्व में अग्रसर है । सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है । जो एक नये युग का डिजिटल बुनियादी ढाचा विकसित करेगा । सरकार ने मिशन मोड पर सिकल सेल एनीमिया को नेस्तनाबूद करने करने के लिए एक योजना बनाई है । कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही हैँ ।

हमारे किसान भाइयों की आय में बढ़ोतरी और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कोविड 19 महामारी फैलने कै बाद से 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन दिया जार रहा है जिससे देश में हर घर में अन्न की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है और इस पहल को अब अगले पांच वर्षो के लिए बढा दिया गया है ।

अन्न के साथ ही किसानो के बैंक खातो में पी.एम. किसान स्कीम के तहत अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं । सरकार की ऐसी कई योजनाएं है जिसमे पीएम फसल बीमा योजना भी है जिसके तहत किसानों को किसी कारण फसल खराब होने पर अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए के क्लेम मिले हैं । पिछले एक दशक में किसानों को धान और गेहूँ की एमएसपी के तोर पर सरकार द्वारा लगभग 18 लाख करोड रुपये मिले हैं । यह 2014 से पहले के 10 साल में भुगतान की गई रकम से 2.5 गुना ज्यादा है ।

देश के विकास में देश की अर्थव्यवस्था और वित्त एक अहम हिस्सा होती है । ऐसे में जब देश गंभीर वैश्विक संकट में था तब भी भारत सबसे लेजी से बढती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और देश ने त्रगातार दो तिमाहियो में 7.5% से अधिक की विकास दर बरकरार रखी है । जैसा की हम सभी जानते हैं, वर्ष 2014 से पहले 10 वर्षो में कुल मुद्रास्फीति 8% से अधिक थी और पिछले दशक में यह 5% पर रही है और देश में इस वर्ष जीएसटी भुगतान करने वालो की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों की संख्या भी पहले से काफी आधिक है ।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का पूर्ण विश्वास के साथ समर्थन करता हूं कि आजादी के स्वर्णिम काल से वर्ष 2047 तक का काल भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रेरणादायी रहेगा ।

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आनंद): मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के पक्ष में अपना अभिमत रख रहा हूँ ।

महामहिम राष्ट्रपति ने जैसा कहा कि सरकार के 10 सात्र ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है विशेषकर साल 2023 । इस वर्ष नए संसद भवन के तैयार होकर सुचारु होने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक मिलती है । पिछली सरकार सिर्फ नए संसद भवन की आवश्यकता पर सोचती रहीं और इस कार्य को बस सोच तक ही सीमित रक्खा जबकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे मूर्त रूप देकर हमें गौरवान्वित होने का अवसर दिया वहीं गुलामी के एक प्रतीक से बाहर आने का सौभाग्य मिला । नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को ऊर्जी देता रहेगा; यहां नई और स्वस्थ परंपराओं की शुरुआत का भरोसा है । महोदय, हमारे देश के वैज्ञानिकों की क्षमता आज अन्तरिक्ष में पूरा विश्व देख कर दंग है । चंद्रमा के दक्षिणी धुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है । जब देश की

सरकार का नेतृत्व का नेतृत्व ईमानदार, परिश्रमी और विकसित भारत को संकल्पित है तो हमारे वैज्ञानिक आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने में पूरी तरह से सक्षम हैं ये मोदी जी नेतृत्व वाली चमत्कारिक सरकार में प्रमाणित हो गया है ।

मिशन मोड में सरकारी नौकरियां देना हमारी सरकार की एक बड़ी बड़ी उपलब्धि रही है । आदरणीय मोदी जी की सरकार युवा शक्ति को देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने में भागीदार बनाने के लिये प्रतिबद्ध है ।

नारी शक्ति वंदन कानून से महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई । अबला अब सबला बनकर देश के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को विश्वास के साथ खड़ी है और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण वाली नीतियों से संभव हो रहा है । महोदय, भारत में जी 20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन । राम मंदिर के निर्माण का सदियों अधूरा सपना सच हुआ । देश के करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर निकले । भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से अग्रसर है जिसकी गारंटी मोदी जी ने दी थी । महोदय, चुनावी वादे की गारंटी पूरा होना मोदी सरकार इसकी पर्याय बन चुकी है परिणाम स्वरूप देश के सबसे विश्वसनीय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, ये बात चुनावों में बार बार जनता दर्शा रही है । महोदय, देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर एक लाख के आंकड़े से भी आगे निकली, देश में मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में पांच गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई । डिजिटल इंडिया से बड़ा बदलाव, यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपये का रिकार्ड लेन देन, खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने पर जोर, पहली बार कृषि निर्यात की नीति बनाई गई, देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है । स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को सजाने सवारने का कार्य हो रहा है । 22 जनवरी को

लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए । हमारी विरासत ऐसी हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें सरकार इस लक्ष्य पर तेजी से कार्य कर रही है । जो दर्शाता है कि मोदी जी ने जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की गारंटी दी है आने वाले समय में पूर्ण होकर रहेगा । देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानसेवक मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार रिफार्म परफार्म और ट्रांसफार्म के लिए कटिबद्ध है इस बात का पूर्ण भरोसा महामहिम के अभिभाषण में दिखता है । जय भारत ।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): भारत के सभी नागरिकों की ओर से मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को हम सभी को संबोधित करने और देश को एक मजबूत, सुरक्षित, और समृद्ध भविष्य की दिशा में अग्रसर रखने के लिए हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ । भारत सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है और हम सभी इसके लिए कृतज्ञ हैं ।

हमारे देश ने पिछले दस वर्षों मे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास की गति को बहुत बढ़ाया है । पिछले दस वर्षों में बुनियादी ढांचे के जो नियोजित विकास हुआ है उसकी कहानी जगजाहिर है । हमारी सरकार ने समाज के सबसे निचले पायदान पर जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन उत्थान हेतु बुनियादी सुविधायें निर्बाध रूप से पहुंचाई है ।

एक ओर जहां मोदी सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर भव्य संसद का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कर इसे दुनिया के सबसे सफल लोकतांत्रिक प्रतीक के रूप में स्थापित किया है । वहीं दूसरी ओर, कोरोना जैसे गंभीर वैश्विक संकट के बीच भी, भारत सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख उद्योग के रूप में उभरा है और हमारे देश ने लगातार दो तिमाहियों में कुल 7.5% से अधिक की

विकास दर बनाए रखी है । भारत आने वाले समय में अपनी संपूर्ण विकास यात्रा को और तेज करने के लिए क्षमता निर्माण में पूरी तरह समर्पित है ।

इस क्रम मे मै सक्षम रक्षा नीति एवं सफल विदेश नीति की भी अवश्य चर्चा करना चाहूंगा । हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित किया है जिससे भारत के रक्षा बलों के लिए पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है । इसके अलावा पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत लगभग एक लाख करोड़ रुपए की धनराशी प्रदान की गयी है । एक और प्रोग्राम जिसका नाम वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है इसके अंतर्गत भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है जिससे सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके और ऐसे क्षेत्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सके ।

वैश्विक स्तर पर भारत की सफल विदेशनीति की खूब प्रशंसा हो रही है । इस क्रम में मैं भारत की अध्यक्षता मे पूरे वर्ष भर चलने वाले G20 कार्यक्रम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमे सरकार ने अब अफ्रीकी संघ के लिए स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने के प्रयास किए है और साथ ही शिखर सम्मेलन में भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है । इस कोरिडोर के विकास से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भारत और पश्चिम एशिया और यूरोप के आपसी संबंध भी मजबूत होंगे और भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी ।

हमारे देश में महिलाओं को हर कार्यक्षेत्र में भागीदारी दी जानी चाहिए जिसकी शुरुआत लोकसभा और विधानसभाओं से की गयी है जिसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी को सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया है । इसके साथ ही लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहाँ से जुड़ी हैं । इन समूहों को आठ लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋण और 40,000 करोड़ रुपए की वित्तीय

सहायता दी गई है । इसके अलावा अब महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है जिससे लाखो महिलाओं को लाभ हुआ है । इन सभी प्रयासों से यह महसूस होता है की अब भारत में महिलाओं को विभिन्न स्तरों पर अनुकूल माहौल एवं प्रोत्साहन प्रदान करने से नारी सशक्तिकरण का हमारा संकल्प पूरा हो रहा है ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार PM श्री स्कूलों पर काम कर रही है जिसमे तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण हेतु विभिन्न योजनायें जैसे स्किल इंडिया आदि निश्चित तौर एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया गया कदम है । सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 14,000 से अधिक पीएम श्री स्कूलों पर काम कर रही है इनमें से लगभग 6,000 स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है और इन स्कूलों में वह सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होती है । देश में एस.सी. और ओबीसी विद्यार्थियों का नामांकन 44% और एसटी विद्यार्थियों का नामांकन 65% बढ़ा है और इसके साथ-साथ देश में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने के लिए भी कानून पारित किया गया है ।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का सदैव यह संकल्प रहा है कि देश के हर नागरिक को एक पक्की छत मिले जहां वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और इसके साथ ही उन्होंने अपनी अलख जगाकर एक सक्षम और सशक्त भारत के निर्माण का भी संकल्प लिया है । आज देश में लगभग 4.1 करोड़ गरीब परिवारों के पास अपना पक्का घर है जिसकी लागत करीब 6 लाख करोड़ रुपये है और देश के नागरिकों की जीवन शैली में पेयजल (पीने योग्य पानी) की सुविधा को पूरी प्राथमिकता दी गयी है जिसके लिए सरकार ने हर घर जल पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया । करीब 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है जिससे देश में हर घर जल पहुंचाने की सरकार की पहल को पूरा किया जा रहा है ।

स्वच्छता और साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए देशभर में कुल 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण किए गए है जिससे खुले में शौच से मुक्ति हुई है और जनता का खुले में शौच से होने वाली कई बीमारियों से बचाव हुआ है ।

प्राचीन समय में ऋषि-मुनि आशीर्वाद देते थे आयुष्मान भव: आज के आधुनिक समय में भारत के लोगो को आयुष्मान भारत योजना के रूप में ऐसा आशीर्वाद मिलता है ।

हमारे किसान भाइयों की आय में बढ़ोतरी और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है जिससे देश में हर घर में अन्न की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है और इस पहल को अब अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है । अन्न के साथ ही किसानो के बैंक खातो में पी.एम किसान स्कीम के तहत अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं । सरकार की ऐसी कई योजनाएं है जिसमे पीएम फसल बीमा योजना भी है जिसके तहत किसानों को किसी कारण फसल खराब होने पर अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए के क्लेम मिले हैं । पिछले एक दशक में किसानों को धान और गेहूं की एमएसपी के तौर पर सरकार द्वारा लगभग 18 लाख करोड़ रुपये मिले हैं । यह 2014 से पहले के 10 साल में भुगतान की गई रकम से 2.5 गुना ज्यादा है ।

देश के विकास में देश की अर्थव्यवस्था और वित्त एक अहम हिस्सा होती है । ऐसे में जब देश गंभीर वैश्विक संकट में था तब भी भारत सबसे तेजी से बढती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और देश ने लगातार दो तिमाहियों में 7.5% से अधिक की विकास दर बरकरार रखी है । जैसा की हम सभी जानते है वर्ष 2014 से पहले 10 वर्षों में कुल मुद्रास्फीति 8% से अधिक थी और पिछले दशक में यह 5% पर रही है और देश में इस वर्ष जीएसटी भुगतान करने वालो की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों की संख्या भी पहले से काफी आधिक है ।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का पूर्ण विश्वास के साथ समर्थन करता हूं कि आजादी के स्वर्णिम काल से वर्ष 2047 तक का काल भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रेरणादायी रहेगा ।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Reacting to the President?s Address, my party Shiromani Akali Dal (Amritsar) states that the present BJP Union Government of Premier Modi has not laid out any policy for farming sector. It has not implemented the Swaminathan Report and not framed any legislation on the Minimum Support Price (MSP). The Defence policy is also weak. There are no amphibian tanks or infantry vehicles. Four-year tenure for a soldier has made the military weak as there will only be immature and ill-trained fighting soldiers. They would not have enough experience, technical and physical fitness.

The Sikh minority has suffered a lot both politically and economically. There is no Sikh representation amongst Judges in the Supreme Court, Election Commission and Secretaries to the Government of India. There are no Sikh commanders in the Army, Navy, Air Force and Paramilitary Forces. The Union Government is not opening the border at Wagah for trade and religious pilgrimage to Pakistan. Our Party opposes the Union Government?s policy of assassination of Sikh leaders in Canada, United Kingdom, Pakistan, and Haryana and Panjab in India. Sikh leaders such as Hardeep Singh Nijjar, Ripudaman Singh Malik, Suckdool Singh were assassinated in Canada; Avtar Sigh Khanda in UK; Paramjit Singh Panjwar and Rode

in Pakistan, Deep Singh Sidhu in Haryana and Moose Wala were killed in Panjab.

There is extreme poverty in rural and urban areas of Punjab, specially people living in slums have no roof over their heads. Unemployment has become a scourge. Religious fanaticism has endangered unity. Operation Bluestar of 1984 against the Sikhs was a genocide and an act of vandalism where innumerable crimes were committed against the Sikh people. These policies continue like the policies continued against Jews in Germany after passing the Nuremberg Laws of 1935. As a result, Sikhs are fleeing from this country and are seeking refuse and asylum in Western democracies.

Tribals, minorities like Muslims and Sikh's are being killed in extrajudicial murders, like the massacre of 43 Sikhs in village Chittisingh Pora in Kashmir in 2000. These atrocities have been perpetrated with impunity as the recent massacre of three Muslims by the Army in Kashmir. Sikh prisoners have been in jails for 32 years and we see no justice in the future. Young Sikhs are jailed in Dibrugarh in Assam under the draconian laws like N.S.A. People are crying against the raids of NIA, CBI, ED.

In terms of foreign policy, citizens do not understand the silence of the Union Government against the Russian annexation of the territory of Ukraine. In terms of defence policy, our party does not understand the inactivity of the Union Government in liberating Ladakh territory - 39, 000 sq. kms in 1962 and 14,000 sq. kms in 2020 and 2022. Our party also denounces the pulling down of the Islamic Mosque at Ayodhya in 1992 and building a Hindu temple

over it, whose inauguration was done by Premier Modi against the secular credentials of the Constitution. We fear the Islamic mosques in Mathura and Banaras are also in danger.

Our Party wants that the debt of farmers should be waived in the interest of the economy of the Country as indebted farmers are committing suicide in lots. In Parliament, the Speaker should allow a minority like me to speak and what little we speak is expunged from my speech by the Speaker.

Territorial water issues related to Sikhs should be resolved in Panjabi speaking areas of Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and Chandigarh. The international riparian laws must be respected and water of Sutlej, Beas and Ravi rivers must be given back to the Panjab. Kashmiri Sikhs should be given equal facilities as Kashmiri pandits and Punjabi language should be recognized as official language. Thank you.

SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): I express my words on the Motion of Thanks on the President's Address.

I extend my sincere thanks to the hon. President for her comprehensive speech. Hon. President not only encapsulated the remarkable achievements of our Government, but has also ignited a flame of hope and pride within each one of us.

India under the leadership of hon. Prime Minister Narendra Modi ji has taken a leap of development.

I would like to compare the achievements of Government between 2004 ? 2014 and 2014-2024. The period of 2004-2014 is period of scams and the one between 2014-2024 is period of development. The achievements of the UPA Government can be summed into 2G scam, 3G scam, coal scam, Common Wealth scam and so on.

Under the leadership of Modi ji, India has lifted more than 25 crore people out of poverty. Modi ji has redefined equation of caste. Now there are four castes in modern India and they are poor, women, farmers and youth.

Modi ji has effectively dealt with poverty with various schemes.

PM Jan Dhan Yojana: It has helped more than 50 crore people have bank accounts. Due to PM JDY, Direct Benefit Transfer is possible today which has saved lakhs of crores rupees to the Government, and it has helped poor without any hassle.

Ayushman Bharat: More than 10 crore families have access to quality health care due to Ayushman Bharat.

More than 120 crore Indians received free vaccination during the Covid.

80 crore+ Indians now receive free ration so that nobody needs to starve to death.

- Har Ghar Jal has ensured tap water connectivity to poor so that women in the poor families need not walk miles to access

potable water.

- 18,000 villages have received electricity under Modi Ji's Government.

Women empowerment has become the *mantra* of Modi Ji's Government.

Modi Ji, through Nari Shakti Vandan Abhiyan, has ensured that there is

adequate representation of women in the Parliament.

Through Ujjwala Yojana, more than 10 crore women started using LPG for the first time.

The age-old oppressive tradition of triple talaq was abolished through this

august House.

Under Modi Ji?s leadership, SHGs are being empowered. 15,000 drones are being given to the SHGs on subsidized rates to address the problems of farm through women. Government has set a new agenda to make more three crore Lakhpati Didis.

Maternity leave was extended up to 26 weeks.

For decades, India kept saying that farmers are the backbone of India, however nothing was done to strengthen farmers.

Modi ji started with doubling the farmers? income.

Under PM Kisan Samman Nidhi, all the farmers get Rs. 6,000 annually to sustain farming and sowing, without having to borrow from moneylenders.

All the farmers have access to adequate irrigation through PM Krishi Sinchayi Yojana.

PM Fasal Bima Yojana has ensured insurance against crop damage to the poor farmers.

The cold storage facility infrastructure has been improved which has helped the farmers to store produce without risk.

Farm Export Policy has fetched good price to the farmers on the produce.

Prime Minister Modi Ji has prioritized the youth in nation-building.

NEP 2020 was formulated and is being implemented to ensure bright future for India and the youth of India

To set a model in scholastic education, 14,000 PM SHRI schools are being developed.

The number of IITs, IIMs, AIIMS, medical colleges and universities has

increased significantly in the last 10 years.

Number of medals won by Indian athletes at Olympics, Asian Games and other tournaments has significantly improved because of Khelo

India and other initiatives.

Capital Expenditure under Modi Ji?s Government has increased significantly. In the recently delivered Budget Speech, hon. Finance Minister has allocated Rs. 11 lakh crore+ for infrastructure development. The construction of National Highways is going on at a historic pace, ensuring connectivity and development. The new railway lines are being laid and electrification of railway is nearing 100 per cent.

I would also like to mention some of the developments in my own constituency (Bengaluru Central).

In 2015, Bengaluru was commissioned under Smart City Mission resulting in multiple infrastructure developments and easing the lives of the citizens.

40 years of demand for suburban rail concluded in 2020 when hon. Finance Minister announced implementation of Suburban Rail at a cost of Rs. 18,000 crore.

To ease the traffic congestion in Bengaluru and further development of

Bengaluru Metro, the Government sanctioned more than Rs. 26,000 crores.

Nirbhaya Fund has ensured safety and security of women and children in the city.

The most Important of all, 500 years of injustice has been resolved by building a grand Ram Lalla Mandir at Ayodhya under Modiji's leadership.

The achievements of Modi Ji's Government are numerous and profound. I conclude my words in support of Motion of Thanks on the President's Address.

Thank you.

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): I am grateful for the opportunity to participate on the Motion of thanks to the President?s Address.

Hon. President read out the speech prepared by this Government in this House.

This BJP Government has prepared a speech similar to their election campaign and transformed it into the President?s speech

At the beginning of his speech, the hon. President proudly mentioned that she will be addressing for the first time in this new Parliament building.

The fact that India?s first female citizen has to wait for this day to enter the new Parliament building, the bedrock of Indian democracy, speaks volumes for the plight of this Government. She should have been invited to inaugurate this new Parliament building.

But this Government missed it, which is a big mistake. The hon. President further mentioned that this new Parliament building will witness constructive dialogue and policies. That idea is great and can add lubrication to democracy. But I would like to point out that the reality of this Government is exactly the opposite.

It was during the last 10 years of BJP?s rule that parliamentary democracy was questioned more than ever before in the history of independent India.

It is this Government that made a huge historical mistake by suspending the entire opposition Parliamentarians in the last parliamentary session and passing the Bills without recording the views of the opposition Parliamentarians.

In her speech, the hon. President proudly stated that the steps being taken by the Union Government in internal security are visible and that all the market areas that were bombed in Jammu and Kashmir are now crowded. How can the BJP Government take pride in dividing Jammu and Kashmir, one of the most beautiful parts of India, into two parts, without holding elections there, without establishing a State Government, without asking the people's thoughts, and indirectly ruling through the Governor, who is the representative of the Union Government?

Hon. President in her speech said that the Indian Army is destroying a befitting response to terrorism and India is raising its voice to counter terrorism on a global scale.

I would like to ask here why this Government, which promotes global security and global peace, kept silent about Manipur, a part of India, when it was burning. Why is Manipur still not visible in the eyes of this Government which claims that peace has returned to the North Eastern states? Even though our hon. President belongs to Scheduled Tribes, she could not utter a single word about the atrocities in the North Eastern State. Perhaps if the hon. President had been able to make changes in the speech prepared by this Government, they would have had that opportunity. At least those people could have been consoled. It may be excluded considering that it is not hereditary. But the misfortune of this Government is that Governors do not follow that tradition in non-BJP-ruled States.

What this Government claims as their achievement is an empty field like the AIIMS hospital they have built in our Madurai. Growth, development is written and written but the reality is completely opposite. A proverb in Tamil says, 'Ettuchu surakkai Karikku uthavaathu.? Similarly, these are all the projects and development of this Government. Practically they did not help anyone.

It is mentioned that concrete houses have been provided to 4 crore 10 lakh poor families. People will understand the reality of this if they calculate how much the funds provided by the Government and how much the State Government's funds are distributed.

The hon. President said that a developed India is based on the four pillars of youth, women, farmers and the poor. I would like to place on record here that this Government is crushing these four pillars.

It is under this regime that the youth are suffering from unprecedented unemployment. Statistics show that unemployment has risen from 5.4 per cent in 2014 to 10.5 per cent in October 2023. But this Government is proud of providing employment to lakhs of youth. To whom was it given? When was it delivered? The question is not yet answered. Next, women, you are proud that we have passed the reservation Bill for women. But how are you going to implement it? When are you going to implement it? What plan do you have to implement? If so, there is no answer.

Crimes against women are increasing in this regime. Today women are insecure. Statistics show that 60 per cent of crimes against women occur in the 17 States ruled by the BJP and its allies, and 70 per cent of sexual violence against women occurs in states ruled by the BJP and its allies. In 2022 alone, 4.45 lakh cases of assault on women were reported. According to the National Crime Records Bureau report, 51 FIRs are reported every hour.

Next, farmers, before coming to power, this Government promised to 'double the income of farmers'. Now you have completed 10 years. Has the income of farmers doubled? Our farmers of Tamil Nadu continued to protest in the capital. Our hon. Prime Minister is not ready to meet them even once.

Is this the Government to improve the farmers? This Government brought three anti-agriculture laws against farmers. How can we forget that the farmers sacrificed their lives by fighting against it. Farmers have been demanding a minimum reference price for their produce. When is this Government going to implement it?

You said in the election promise that you will enact a law for that; five years are about to end, when are you going to fulfil it?

Next the poor, this Government is claiming that it has uplifted the poor.

According to the Niti Aayog, the Union Government has lifted 25 crore people out of poverty in the past ten years. Among 125 countries on the Global Hunger Index, which ranks countries with the highest number of hungry people India is at 111th position. This Government has forgotten what a shame this is.

In this regime, none of the four pillars that you mention - youth, women, farmers and the poor - have achieved the development you mentioned. Rather I would like to point out here that they have experienced a huge decline. I am obliged to record here with regret that it was during this regime that the minority people were subjected to oppression and oppression like never before in the history of Indian independence. The actions of this Government are against the diversity of the country.

The places of worship of the minorities are under great threat today. The Varanasi court's permission for Hindus to worship in the southern basement of the Gyanvapi Masjid in Varanasi is in flagrant violation of the Places of Worship Act, 1991. The Places of Worship Act, 1991 stipulates that all post-1947 places of worship, except the Babri Masjid, should be preserved as they are. According to this Act, if a place of worship of one religion or a religious sect was encroached upon by another religion or another sect of the same

religion before 15 August 1947, no encroachment action can be taken under this Act. However, in the case of Gyanvapi Mosque, the Varanasi Court has allowed Hindus to perform pujas and worship in the southern basement of the mosque by allowing the archaeology department to enter the mosque, which is a blatant violation of the Protection of Places of Worship Act. It is feared that similar actions followed in the Babri Masjid case will be followed in the Gyanvapi Masjid case.

Oppressing and threatening minorities is against the diversity of the country. Maintaining harmony is what makes a healthy nation. I urge the Union Government to act honestly on the basis of the law in the matter of Gyanvapi Masjid. Recently, an 800-year-old mosque in Delhi has been demolished. Such acts of threatening minorities are a disgrace to the entire nation.

BJP-affiliated Union Minister of State Shantanu Thakur says "CAA will be implemented not only in West Bengal but across India in seven days". The BJP Government brought in the discriminatory Citizenship Amendment Act, led to a series of protests across the country, disturbed the peace of the country and made the entire country bow down in the world arena. Various state Governments including Tamil Nadu, Kerala and West Bengal have announced that they will not implement the BJP Government's Citizenship Amendment Act, which betrays Eelam Tamils and Muslims. India will soon put an end to the thoughts of the BJP Government which are destroying the harmony and peace of the country. BJP's desire to burn reconciliation and cool it down will never be fulfilled.

Here I would like to raise an important issue related to my Ramanathapuram parliamentary constituency. We are proud that India is the strongest country in the world. But I would like to record here with regret that we are unable to protect our fishermen from the Sri Lankan Navy, a country that is smaller than us in all respects, a country that is dependent on us for various needs. The Sri Lankan Navy has detained two barges and 23 fishermen who went fishing from Rameswaram two days ago. I have spoken many times in this House for five years that a permanent solution should be reached. I would like to strongly ask here, what action has been taken by this Government so far. After the families of the fishermen arrested by the Sri Lankan Navy made a request to the Union Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman, who visited Rameswaram to participate in an event in November last year, considering the need for immediate action in the run-up to the elections, she immediately contacted the officials of the Foreign Affairs and Consular Affairs and that night 22 fishermen were released. Action has been taken to free the two fishing boats.

The Union Minister has confirmed what we have been saying for so many years that fishermen can be freed overnight if the Union Government thinks so. Through this action, it has been proved that the liberation of the fishermen is under the authority of the Union Government. So why was this power not exercised by the Union Government for so many years? Even during the last parliamentary elections, fishermen were immediately released like this. Why is the concern for the fishermen that comes only during the elections not come to you at other times? Why is the plight of the fishermen visible

to the eyes of the Union Government at the time of the elections, and why does it refuse to be known at other times? Year after year we have been voicing that the fishermen of our area are brutally attacked by the Sri Lankan Navy, their lives are lost, their boats are arrested and their livelihood is completely affected.

I have spoken in the same House many times and have personally met the Union. Ministers and urged them. If you are able to use your power at this time of elections after maintaining fake silence then today you have shown the light of your concern for the people. We are constantly asking that this consideration which comes only during elections should also come at other times. Tamil Nadu Government, Hon. Tamil Nadu Chief Minister Thalapathy M. Stalin has been insisting every time fishermen are arrested immediately to the Union Ministers of External Affairs and all important representatives of the Union Government including the Prime Minister. He has repeatedly emphasized. Why did they go unheeded? The boats of the arrested fishermen are their livelihood. The Tamil Nadu Government has provided a financial assistance of Rs. 5 lakh each to the boats. The Union Government, which was unwilling to provide even that financial assistance for all these years, is now playing a political drama focusing on elections, which is against the people.

This Government has been a colossal failure on all fronts. This Government has prepared a speech to hide its failures and submitted it to the President. When you go to vote, people will remind you of

issues you had better forget. I will conclude by saying that India will soon decide on this.

Thank you.

DR. T. SUMATHY (*A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I am here today in a moment of grave concern for our nation.

In the winter of 2023, India found itself grappling with a formidable challenge as the cost of living surged to a four-month high, reaching 5.7%, a significant escalation from the previous month?s 5.55 per cent. At the core of this issue lies the painful reality of rising prices, particularly in essential items, with a staggering 9.5 per cent increase nationwide and a distressing 10.42 per cent for our urban constituents.

The heart of this matter lies in the unprecedented surge in the cost of food, a basic necessity for every household. Families across the country are feeling the pinch as the prices of vegetables soar, making it increasingly difficult for them to put food on the table. The impact is not just economic; it is deeply personal, affecting the lives of ordinary people who are struggling to meet their basic needs. Point no. 19 of the President's Speech emphasizes about Rs. 18 lakh crore received as MSP for wheat and paddy crops in the last decade. However, let us not forget that the very government championing this achievement introduced three controversial farm bills that threaten to

dismantle the Minimum Support Price (MSP) system, jeopardizing the livelihoods of our farmers.

Adding to our concerns is the uncertain future of staple food items such as rice, wheat, and pulses. The anticipated drops in production, coupled with delays in sowing due to challenging weather conditions, threaten the stability of our food supply. This predicament not only poses an immediate threat to the livelihoods of our farmers but also jeopardizes the food security of our nation.

As we address this economic crisis, we must not lose sight of the human aspect behind the numbers. The inflationary struggles paint a vivid and distressing picture of the emotional toll on individuals and families, particularly those already burdened by poverty. It is not merely a statistical challenge; it is about real people facing genuine hardships as the prices of everyday essentials skyrocket. Sir, the overall unemployment rate in India as of now has gone beyond 10 per cent. In 2014, the unemployment rate was 5.4 per cent, as of now it is 10.03 per cent. The Unemployment rate among the age group 25-35 has touched 30 per cent. This shows that 40 per cent of our youth population is unemployed. Another 30 per cent of the population is under-employed. Only the 30 per cent youth population are fortunate enough to get a regular job either in Government or in PSUs or in private entities Around 60 per cent of job seekers are mentally distressed and physically worn out.

I would also like to express my views on the intricate challenges faced by our nation, particularly in the realm of poverty alleviation and women's empowerment. While it is commendable that

we have successfully lifted 25 crore people out of poverty in the past decade, the recent Global Hunger Index ranking of 111 out of 125 countries for India is a stark reminder of the persistent structural inequalities that mar our progress. The Government which boasts that it provides free ration for 81 crore people below poverty line for next five years is indeed indebted to those poor farmers who produce such humongous quantities of food grains toiling in hot sun and braving hostile socio-economic and climatic conditions. The President?s Address has failed to thank those real warriors but for them the country would have been in dire straits during the covid pandemic and aftermath.

In the journey towards inclusive development, it is disheartening to note that despite significant achievements in various domains, structural disparities endure in livelihoods, sanitation, health access, and crucially, women's empowerment. Today, I would like to draw your attention specifically to the alarming decline in the labour force participation rates among women since 2004-05, both in urban areas (22.3 per cent) and rural areas (26.6 per cent). This decline signals not just missed opportunities but fading aspirations, particularly for the female workforce. The challenges faced by our women extend beyond mere numbers. The absence of hygienic working conditions compounds the struggles of the female workforce, adding a critical dimension to this narrative. It is a reality that we cannot afford to overlook or underestimate.

Looking at Tamil Nadu?s economic landscape, where women play a pivotal yet complex role. While the State has witnessed

commendable achievements in education and work participation, a disheartening paradox looms large ? the persistence of a higher wage gap. In Tamil Nadu, women entrepreneurs find themselves earning a mere 37 paise for every rupee earned by their male counterparts. This stark wage disparity casts a shadow over the progress made in other realms.

The economic downturn is not just a statistic but a tangible loss of livelihoods, particularly for women. Tamil Nadu, once a beacon with the highest share of employment in manufacturing across the nation at 20 per cent in 2011-12, has seen a gradual decline to 16.8 per cent in 2020-21. This translates into the loss of 700,000 jobs in the manufacturing sector over the past decade, disproportionately affecting women.

Amidst the achievements, a gloomy trend emerges. Despite educational and participatory advancements, persistent challenges such as the widening wage gap and employment losses reveal the urgent need for a more nuanced and empathetic approach. We must ensure the strides made in one aspect of women's lives do not falter in others.

Moving on to Point No 18, the hon. President spoke about women's empowerment, but the claims made regarding the achievements in ensuring equality for women are, unfortunately, misleading. While the Government aims to make 2 crore women ? Lakhpati Didis? with the help of technology (drones) to promote agricultural activities, the reality in rural areas exposes the lack of technology, particularly the unavailability of drones. How can we

bridge the gap between rural areas and progressive technology? This question remains unanswered.

Moreover, the assurances of social security highlighted in the speech are contradicted by the alarming rise in crimes against women, as evidenced by the National Crime Records Bureau (NCRB) data, which reveals a stark contradiction. With 4,45,256 cases registered in 2022 alone, equating to nearly 51 FIRs every hour, it is evident that the promised social security is far from reality. Speaking of ?Crime Against Women? let us not forget about the horrific Manipur violence incident which shook the conscience of the country. Women belonging to the Kuki-Zu community were subjected to heinous acts of gang rape, public humiliation (paraded naked), and filming, which was conveniently omitted. Yet, the hon. President highlighted a reduction in separatist incidents in North-Eastern States.

I am dismayed to find the phrases like ?in last 10 years? or ? decade ago? found mentioned more than 32 times in her speech while narrating the achievements of this Government in the last 10 years. The Nation also wants to know the reverse side which is terrible. It is quite understandable that the President?s Address on the election year would sound like that and it is more of a teaser to the election campaign of the Ruling Party for the coming Lok Sabha polls. I would like to record in this august House what really matters and what really missing in the President?s Address. The Hon'ble President has failed to mention the failures of this Government on crucial fronts. Several important issues and problems are conspicuously missing from her speech. I just mentioned about the Manipur

violence. It is unfortunate that the hon. Prime Minister Narendra Modi has not visited the State and took any action on its situation. When there were floods in Tamil Nadu or Kerala or any other parts of country except Gujarat and Uttar Pradesh, the PM?s itinerary conveniently avoids such destinations which were devastated by floods. What is more painful for the distressed people was that his international sojourns were planned quite often. The hon. President has failed to mention in her Address about the achievement made by the hon. Prime Minister through his 75 foreign trips visiting around 70 countries. The recent floods in Tamil Nadu in December have added to the woes of our citizens. The Disaster Management Department reports over 7,417 houses damaged, 1.07 lakh cattle lost, and 2.24 lakh acres of crops devastated. This compounding crisis demands our urgent attention and decisive action.

I would also like to shed light on the current state of education in our nation, as revealed by the Annual Status of Education Report. While progress has been made with 86.8 per cent of 14-18-year-olds currently enrolled in educational institutions, it becomes evident that we are falling short of the ambitious 100 per cent enrollment target set by the National Education Policy, 2020 for 2030.

Delving deeper into the report, a nuanced reality emerges when examining the skills aspect. While nearly three-fourths of rural youth exhibit proficiency in reading a Standard-2 level text, less than half display the ability to perform simple division. This disparity underscores significant gaps in our educational strategies, emphasizing the urgent need for targeted improvements in pedagogy

to ensure a holistic and effective learning experience for our youth. Despite relative success in primary education, a critical issue surfaces in the realm of competitive exams, posing harm to both students and the education system at large. A tragic incident in Rajasthan?s Kota on January 29 serves as a stark reminder of the devastating impact of the pressure associated with competitive exams. An 18-year-old JEE aspirant took her own life, citing the unbearable stress of the exam in her suicide note. This heart-wrenching incident is not isolated, as it adds to a distressing trend with 33 students having died by suicide across Indian Institutes of Technology (IITs) since 2018.

The toll of competitive exams on the mental well-being of our students raises serious questions about our education system?s priorities. It compels us to reflect on the need for a more compassionate and supportive approach to education. As custodians of the nation?s future, we must ensure that our education system fosters a conducive environment for learning, growth, and well-being.

The Government has been boasting about the mantra of ?Sabka Saath, Sabika Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas? for quite some time now. The same mantra was reiterated by the hon. President in Point No. 23, emphasizing that fair opportunities have been provided to economically weaker sections, Other Backward Classes, and Constitutional Status has been granted to the National Commission for Backward Classes, among other claims. However, the President?s address blatantly ignored the plight of students and scholars availing the Maulana Azad National Fellowship (MANF). If we genuinely believe in providing equal opportunities, why not

increase the funds allocated to MANF? This selective approach toward equality raises pertinent questions about the Government's commitment to its proclaimed mantra. While we hear the hollow promises of inclusivity and equal opportunities, the reality of students/scholars pursuing education under MANF remains overlooked.

In the last 10 years, more than 8,000 students belonging to the SC/ST/OBC and minority communities have dropped out from IITs, IIMSs, IIITs, NITs, IISERs and 50 students died by suicide inside the campuses across the country. This is very pathetic and shows the precarious conditions prevailing in IITs, NITs, IIMs across the country. There have been several thousand dropouts occurred in Central Universities across the country. The highest number of dropouts was of OBC students.

Though the Government cites many reasons, harassment and subjugation of students from poor and most backward areas by some group of students practicing caste chauvinism and caste arrogance is the major reason. Despite the Government?s claim of expanding reservations to economically weaker sections in the General category, the UGC draft guidelines hinted at a disheartening shift in policy. The proposal suggested that any vacancy reserved for SC, ST, and OBC candidates could be arbitrarily labelled as ?unserved? if a sufficient number of candidates from these categories were not available. While these guidelines have since been withdrawn, the initial issuance of such regressive directives raises a poignant question that echoes in the corridors of justice and equality.

Why were guidelines introduced that blatantly contradicted the constitutional provisions of equality and justice? The very essence of our democratic principles rest on the foundation of equal opportunities for all citizens, regardless of their background. Such proposals not only undermine the principles of inclusivity but also beg scrutiny into the motivations behind policies that threaten the bedrock of our commitment to fairness. Reservations have been a vital instrument to address historical injustices and provide marginalized communities with a fair chance to participate in the nation?s development. Any attempt to dilute or manipulate these provisions sends a troubling message to our citizens. It challenges the very fabric of democracy, which is built upon the ideals of justice, liberty, equality and fraternity.

The withdrawal of these guidelines is a welcome step, but it does not absolve us from the responsibility of critically examining the underlying motivations and addressing the soot causes that led to such proposals.

Talking about equality, also reminds me that the Supreme Court has declined to legalize same sex marriage, leaving it to Parliament to legislate on the subject. Now, it is up to the Union Government to ensure that justice is done for all. The hon. Supreme Court has said the State must take ?remedial action? because if it regulates marriage only for heterosexual couples, it ?adversely impacts? the LGBTQIA+ community, resulting in their exclusion, and ?denial of entitlements/benefits,? and that ?this injustice and inequity results in discrimination?. It has set down a set of guidelines,

from setting up a committee chaired by the Cabinet Secretary to define the scope of entitlements of queer couples who are in unions, to directing police stations as not harness the community.

The attack and atrocities against SC/ST and oppressed communities is on the rise since 2014. There are several thousands of such incidents happened but not been reported or registered shows the dark and ugly side of the society we are in. There is an urgent need for a comprehensive law to provide socio economic and political security and safety for the people belonging to SC and ST as well as from other vulnerable communities. In the last ten years, India has seen an outbreak of religious crimes. Mobs have targeted people mainly because of their caste and religion. Since 2014, hundreds of cases of lynching occurred and mostly motivated by religious and caste hatred. The onus and responsibility are not only on the Government but also on the socio-political system and stakeholders. The President?s Address is silent on this very dangerous issue, which may ruin the life and nature of our future generations.

It is also important for me to talk about the escalating threats posed by the misuse of Artificial Intelligence and the apparent lapses in addressing cybersecurity issues.

Last month, Prime Minister Modi rightly flagged the potential threat of Artificial Intelligence tools falling into the wrong hands, specifically those of terrorists. His call for a global framework to ensure the ethical use of Al resonates with the urgency of the situation. As we delve into the realms of technological advancements, it becomes imperative for us to collectively address the ethical

dimensions of Al, safeguarding our world from potential harms. However, even as we discuss global frameworks, we must confront pressing issues on the domestic front. The Government is yet to provide satisfactory answers regarding allegations of Government snooping, particularly following alerts from tech giant Apple about a "state-sponsored attacker" targeting digital devices. The citizens of our nation deserve transparency and accountability when it comes to matters of privacy and digital security.

Equally troubling is the silence surrounding one of the largest data breaches in Indian history. Details of over 81.5 crore Indian citizens are reportedly on sale on the dark web, including critical information such as Aadhaar and passport details, names, phone numbers, and addresses. This breach not only compromises the privacy and security of our citizens but also calls into question the robustness of our data protection measures. Furthermore, the rise of deep fake technology presents a formidable challenge to our cybersecurity efforts. Researchers have noted a staggering 230 per cent increase in deep fake usage by cybercriminals and scammers. It is predicted that this technology could replace phishing in the coming years, underscoring the urgent need for comprehensive legislation and safeguards to counter this evolving threat.

There is an unprecedented increase in cyber-crimes and cyber fraud in the country. The number of reported cybercrimes in India increased by more than 10-fold in the last ten years. We need to enact strict laws and take stringent action to curb and stop the menace of cyber-crimes and cyber frauds in the coming years. Fake news spread

through social media in the country has become a serious problem, with the potential of it resulting in mob violence, social unrest. The damage caused due to fake news on social media has increased due to the growth of the internet penetration in India, which has risen from 137 million internet users in 2012 to over 600 million in 2019. There is an urgent need to chalk out a comprehensive policy and enactment of Law to curb and control fake news emanating from within and outside the country. The President?s Address is not surprisingly silent about the urgent need for such as important policy decision by the Union Government to save the life and nature of the people of this country.

Talking about security, reminds me point 17, the hon. President applauds a 50 per cent discount on Indian Railways, a commendable step for the welfare of the citizens Yet, we must question why the horrific incident in Balasore district, Odisha, on Jume 3, 2023, which claimed 300 lives and left over 1,100 people severely injured, was conveniently omitted. The Comptroller and Auditor General of India? s report points to systemic failures, such as track defects and outdated signalling equipment, which the Government seems eager to overlook.

When compared to the amount Tamil Nadu is giving the Union government as tax revenue, it is receiving back very less. The Union Government has offered the State nothing but the State's tax share. Tamil Nadu is providing 9.16 per cent of the GDP to the Centre, but the Union Government shared only 6.07 per cent tax revenue to Tamil Nadu.

The President?s Address failed to mention the anomalies and indifferences in the devolution of funds to productive States like Tamil Nadu. Sir, Tamil Nadu continues to be one of the largest contributors to the country's direct tax revenues. The Union Government is betraying Tamil Nadu on many counts including the devolution of tax revenue with data. In devolution of share of tax revenue, Tamil Nadu is not getting its due share. For example, for every one rupee that TN gives the Centre, it gets back 29 paise and incidentally all BJP ruled States or their electorally prospective States are getting the lion's share. This is unjustifiable, Sir.

There is a bias and injustice shown by the Union Government to Tamil Nadu in the devolution of funds. The hon. Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman says that she followed the recommendations of Finance Commission.

The Government has initiated the 16th Finance commission and elected its Chairman, and Members are to be selected. The Finance Commission is appointed by the President under Article 280 of the Constitution. A Working Group, headed by the Finance Secretary was subsequently formed to aid in formulating the Terms of Reference (ToR). The Cabinet approves the Terms of Reference for the Finance Commission. It is a process supervised and finalized by a group of people under the aegis of the Union Government. My humble request to the Government is to increase the devolution of funds from the divisible pool of Central funds from the present 43 per cent to 50 per cent.

Another issue affecting fiscal autonomy of productive States like Tamil Nadu is the arbitrary increases on cess and surcharge, which are non-divisible with states. This has eroded a State's fiscal resources. The share of cesses and surcharges in the gross tax revenue of the Union government has doubled to 21 per cent from 10.4 per cent in 2011-12. Therefore, I request the Government to share 50 per cent of total Cess and Surcharges collected from the States with the respective State Government.

India cannot be treated as a super economy until we get rid of the following characteristics such as low per capita income, heavy population pressure. Prevalence of chronic unemployment and under-employment, unequal distribution of wealth and or assets, poor quality of human capital, prevalence of low levels of technology, low level of living of an average Indian, all these signify the demographic characteristics of an underdeveloped country.

During the fateful month of December 2023, eight districts of Tamil Nadu devastated by two back-to-back floods arising out of heavy rainfall hitherto recorded. The Greater Chennai Tiruvallur, Chengalpattu and Kanchipuram were affected very badly as 34 cms rain poured in less than 36 hours on 4-5 December 2023. Four southern districts Thoothukudi, Tirunelveli, Kanyakumari and Tenkasi were inundated and affected very badly due to heavy downpour of 95 cms in just two days. There was heavy loss of properties belonging to both Government and people. The Government of Tamil Nadu has swung into action swiftly and because of that loss of life is minimal. The hon. Chief Minister of

Tamil Nadu Thalapathy M.K Stalin has requested the Prime Minister Narendra Modi to declare the floods as a ?calamity of severe nature? and allot required amount of funds for carrying out relief and rehabilitation works in the affected districts.

An All-Party delegation from Tamil Nadu met and urged the Union Home Minister Shri Amit Shah to take immediate action on the memorandum submitted by the State Government seeking Rs. 37,907 crore towards interim and permanent restoration in the flood-affected districts of Tamil Nadu. Home Minister has promised that the Centre is duty-bound to support the people and would certainly release the funds by January 27. But so far, we have not received any relief funds from the centre. There is no mention in the President?s Address about the measures taken by the Government to provide adequate financial support for relief and rehabilitation works in Tamil Nadu which is affected badly due to heavy rains and floods. Therefore, I urge the Union Government to release the requested relief funds immediately to serve the people who were battered by extremely heavy rain in Tamil Nadu.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thalapathy M.K. Stalin is an amalgam of Thanthai Periyar, Perarignar Anna and Dr. Kalaignar. Today, he is leading us from the front in our forward march with vigour and valour. For India to become a developed nation, it needs to follow the Dravidian Model of Government and Governance as proved by Tamil Nadu under the dynamic leadership of our mercurial leaders Perarignar Anna, Muthamilarignar Dr. Kalaignar and Thalapathy Muthuvel Karunanidhi Stalin. They have

given a direction for us to travel for many more centuries. They have inculcated in us the lessons of life to combat any adversaries. They have trained us in creating a State with progress, prosperity and peace. They have taught us the importance of communal harmony and peaceful coexistence.

I request the Government that it is of utmost importance that we conduct a nationwide census. In October, hon. Chief Minister M.K. Stalin wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi requesting his intervention to integrate a caste census with the proposed national decadal census. In his letter he wrote, ?Only an integrated census at the national level could provide comprehensive and reliable data on the caste composition of the society and its reflection on the socioeconomic indicators. This would enable evidence-based policymaking and ensure equitable and inclusive development?.

Unfortunately, the Additional Registrar General of India (RGI) informed that the Competent Authority has decided to further extend the date of freezing of administrative boundaries up to June 30, 2024. This has implications for a variety of programmes and estimations that the Government and others make over the needs of the population, as the Census is the largest public body of data about the country available and updated. It may even render those seen as needing extra care under the National Food Security Act among the uncounted and therefore not helped by Government schemes. The Women's Reservation Bill passed in the special session of Parliament

is contingent on the next delimitation, which depends on the next census.

This deliberate manipulation of information leads us to question the authenticity of the entire narrative presented by the Government. It is not just about acknowledging accomplishments but also addressing the failures and hardships faced by the citizens of this country. We stand here, not just as critics but as guardians of truth and voice of the countless citizens whose struggles are conveniently omitted from the hon. President's grand narrative

Thank You.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने संसद के अतंरिम बजट सत्र के प्रथम दिन सरकार के गौरवशाली एवं रचनात्मक विकास के एजेण्डे को नए संसद भवन में प्रस्तुत किया ।

हमारे देश ने आजादी के 75 सालों बाद अमृत काल में प्रवेश किया है । 25 साल का यह अमृत कालखंड विकसित भारत के निर्माण का काल है जिसमें भारत गरीबी रहित होगा तथा जिसमें समृद्ध मध्यम वर्ग अपने युवाओं और महिलाओं द्वारा निर्देशित होगा । हमारी सरकार ने अपने लगभग 10 सालों के कार्यकाल में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं तथा इससे हर भारतीय को आत्मविश्वास मिला है ।

भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति ऐतिहासिक जी-20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन में स्पष्ट रूप से देखी गयी । इसके अतिरिक्त,

एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीता । पैरा एशियाई खेलों में भी भारत को 100 से अधिक पदक प्राप्त हुए ।

हमारी सरकार विकसित भारत के चार स्तम्भ - युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों को सशक्त करने हेतु तन मन धन से प्रयासरत है । हमारे प्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल के विगत 10 साल इस शताब्दी का स्वर्णिम युग है । हमारी सरकार ने शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी सम्प्रदाय हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के मिले । हमारी सरकार ने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ कभी समझौता नहीं किया है । हमारी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की नीति से आज जो एक रुपया आमजन को भेजा जाता है, वह पूरा का पूरा रुपया उस तक पहुंचता है न कि पहले की सरकारों की तरह केवल 15 पैसे ।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा देश की आजादी के 75 साल होने पर 2047 तक केसा राष्ट्र बनाएंगे इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की हैं । हम 2047 तक अतीत के गौरव से जुड़ा हुआ आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत एवं सम्पन्न भारत का निर्माण करेंगे जिसमें आधुनिकता के साथ-साथ मानवीय दायित्वों पर पूरा बल होगा । प्राचीन भारत के स्वर्णिम और गौरवशाली नींव पर नये भारत का नवनिर्माण होगा । हमारी सरकार ?सबका साथ, सबका विकास? के साथ 'सबका विश्वास' और 'सबका प्रयास' के मंत्र को लेकर कर्तव्य पथ पर विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही हैं । सतत व समर्पित प्रयासों से विगत 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना संभव हो पाया है । यदि विगत की सरकारों ने इस दिशा में कोई प्रयास किया होता तो 2014 में शासन की बागडोर संभालते हमारी सरकार

को 80 करोड़ लोग निर्धनता की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हुए नहीं मिलते ।

हमारी सरकार ने देश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए हैं, चाहे वह महिला उत्थान हो अथवा आदिवासी उत्थान । आज यदि एक आदिवासी महिला विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति है तो एक दूसरी महिला विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था की एक सफल वित्त मंत्री साबित हुई है । आयुष्मान भारत से समाज के सभी वर्गों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आज उपलब्ध है । किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है वहीं प्रधान मंत्री मानधन योजना के माध्यम से उन्हें हर साल बीज व अन्य कृषि सामान खरीदने के लिए विगत 5 सालों से हर साल 6 हजार रूपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है ।

हमारे देश का हज कोटा विगत दस सालों में काफी बढ़ा है । आज भारत के पासपोर्ट वाले हमारे नागरिक जिस भी देश में पहुंचते हैं उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है । मुस्लिम महिलाओं को अब तीन तलाक का शिकार नहीं होना पड़ता है । सरकार ने तीन तलाक हटाकर देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम किया है । महिलाओं की स्थिति में आज जितना सुधार हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, चाहे यह घरेलू गैस हो अथवा पेय जल आपूर्ति । प्रधान मंत्री शहरी व ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आगामी साल में दो करोड़ घर और उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है । यह हमारी ही सरकार है जिसने संसद व विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है ।

तीन दशक के इंतजार के बाद पारित हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम से विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई हैं । रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लगातार जारी रखा है ।

हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे थे । अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं । यह हमारी ही सरकार है जिसने गरीबों को दरिद्र नारायण समझते हुए उन्हें ईश्वर के समतुल्य मानते हुए उनके विकास के लिए सैंकड़ों योजनाएं लाकर गरीबी को हटाने का कार्य किया है और उसी प्रयासों का परिणाम है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं तथा इस दिशा में सतत प्रयास जारी हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास और विरासत की राजनीति कर रही है । एक तरह हम अपने तीर्थों के उस गौरव को वापस लाये है जिसे पहले के शासनकाल में भुला दिया गया था, वहीं वर्तमान सरकार ने विकास को भी काफी महत्व दिया है । आजादी के बाद जो लोग लम्बे समय तक सत्ता में रहे वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके और उन्होने राजनैतिक फायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने की प्रवृत्त स्थापित की । कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी ही जड़ो को काटकर प्रगति नहीं कर सकता । हमारी सरकार ने पवित्र अयोध्याधाम में भव्य, नव्य एवं दिव्य श्रीराम मंदिर बनाकर करोड़ों भारतीयों की आस्था को अभिव्यक्ति का स्वर दिया है । श्रीराम जन्मभूमि मंदिर एक राष्ट्र मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित होगा और रामराज्य की परिकल्पना को साकार रूप देने में सफल होगा । देश की 140 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का 500 वर्षों के संघर्ष को समाप्त कर भारत की जनआकांक्षा को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का कोटि-कोटि अभिनन्दन एवं वन्दन । सियावर रामचन्द्र जी की जय ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता

हूं ।

धन्यवाद ।

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): The President?s Address has to be seen as a summary of last ten years of rule under Shri Narendra Modi. In her speech, ten years or decade found mentioned in 33 places while narrating the achievements of this Government in the last ten years. It is understandable that the President?s Address on the election year would always sound like that and it is more of a teaser to the campaign of the ruling party in the forthcoming Lok Sabha polls.

The hon. President has failed to mention thousands of failures of this Government. Several important issues and problems are conspicuously missing from her speech. What is happening in Manipur, the President Address fails to mention whether any appropriate steps being taken by the Government to stop the ethnic violence in Manipur and to restore peace and normalcy in various parts of the State of Manipur in the country. We demand a concrete answer from the hon. Prime Minister on this burning issue. Incidentally, the hon. President Address has failed to mention about the 75 foreign trips made by the hon. Prime Minister in the last ten years.

The summary of his international travels includes one visit to 38 countries, including Argentina, Bahrain, Belgium, Canada, Denmark, Egypt, Fiji, Greece, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kenya, Laos, Mauritius, Mexico, Mongolia, Mozambique, Netherlands, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Palestine, Philippines, Portugal, Qatar, Rwanda, Seychelles, Spain, Sweden,

Tajikistan, Tanzania, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Vatican City, and Vietnam. Two visits to 14 countries, including Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Maldives, Myanmar, Saudi Arabia, South Korea, Switzerland, and Thailand. Three visits to five countries, including Indonesia, South Africa, Sri Lanka, the United Kingdom, and Uzbekistan. Four visits to Singapore. Five visits to China, Nepal, and Russia. Six or more visits to Germany and the United Arab Emirates. Seven visits to France and Japan. Eight visits to the United States. The hon. President has failed to mention this in her Address summarizing the achievements of this Government in the last ten years.

The hon. President has hailed that India has emerged as the fastest growing major economy, amidst serious global crises, consistently maintaining a growth rate of over 7.5 per cent for two consecutive quarters. But whether the fruit of this growth has evenly spread across all sections of the people and percolated into the life of poorest of the poor is a million-dollar question.

When compared to the amount Tamil Nadu is giving the Union Government as tax revenue, it is receiving back very less. The Union Government has offered the State nothing but the State?s tax share. Tamil Nadu is providing 9.16 per cent of the GDP to the Centre, but the Union Government shared only 6.07 per cent tax revenue to Tamil Nadu.

Tamil Nadu continues to be one of the largest contributors to the country?s direct tax revenues, the Union Government of betraying

Tamil Nadu on many counts including the devolution of tax revenue with data. In devolution of share of tax revenue, Tamil Nadu is not getting its due share. For example, for every one rupee that Tamil Nadu gives the Centre, it gets back 29 paise and incidentally all BJP ruled States or their electorally prospective States are getting the lion?s share. This is unjustifiable, Sir.

There is a bias and injustice shown by the Union Government to Tamil Nadu in the devolution of funds. The hon. Finance Minister, Nirmala Sitharaman says that she followed the recommendations of the Finance Commission. Sir, the Government has initiated the 16th Finance Commission and elected its Chairman, and members are to be selected. The Finance Commission is appointed by the President under Article 280 of the Constitution. A Working Group, headed by the Finance Secretary was subsequently formed to aid in formulating the Terms of Reference (ToR). The Cabinet approves the Terms of Reference for the Finance Commission. It is a process supervised and finalized by a group of people under the aegis of the Union Government. My humble request to the Government is to increase the devolution of funds from the divisible pool of Central funds from the present 43 per cent to 50 per cent.

Another issue affecting fiscal autonomy of States is arbitrary increases on cess and surcharge, which are non-divisible with States. This has eroded a State?s fiscal resources. The share of cesses and surcharges in the gross tax revenue of the Union Government has doubled to 21 per cent from 10.4 per cent in 2011-12. Therefore, I request the Government to share 50 per cent of total cess and

surcharges collected from the States with the respective State Government.

For the State?s growth to be sustained, it will need more fiscal autonomy. When the Centre forces schemes on developed States such as Tamil Nadu, it only thwarts growth. Only if an individual State grows, can the country grow. Sir, from 2014-15 to 2021-22, Tamil Nadu had contributed Rs 5.16 lakh crore to the country?s direct tax revenues, but in return, the State received only Rs. 2.08 lakh crore. Tamil Nadu faced a huge revenue loss. I would like to request the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman to allocate more funds to Tamil Nadu because Tamil Nadu deserves more.

Every State has its own, unique economy model for growth and development. In the 1960?s the per capita income of Tamil Nadu was the same as that of northern States such as UP. However, Tamil Nadu?s Dravidian model socio-economic policies has increased its per capita income to thrice that of UP. The State was able to achieve it because of emphasis on equitable growth, targeted interventions and affirmative action. The State policies recognize that in a stratified society such as India, trickledown economics does not always work.

Tamil Nadu has adopted a trickle up economics model, which is associated with boosting demand side economics through targeted interventions. The mid-day meal policy for promoting school education, the National Rural Employment Guarantee Act, hailed as revolutionary welfare initiatives, have been gifts of the Tamil Nadu Government to the country. Most recently, the transfer of Rs. 1,000 to women every month being taken up by other States also began in

Tamil Nadu. To centralize policy planning and diminish funds for the State Government to experiment in policy is to deprive India of the benefits of its diverse ?laboratories? for innovation. The makers of the Constitution placed most subjects relating to improving development indicators such as health and education in the State List.

There is no doubt that India is the fastest growing economy in the world. But the promise of this Government about achieving five trillion-dollar economy by 2023 is yet to be achieved. Indian exports have grown but the value of imports has overtaken the exports and in the dollar economy, we need to shell extra rupees for every dollar of imports we are making. Our trade deficit is too wide as a result the dependence on foreign countries, especially China is increasing. This is not a good sign of growing economy.

India cannot be treated as a super economy until we are get rid of the following characteristics, such as low per capita income, heavy population pressure, prevalence of chronic unemployment and under-employment, unequal distribution of wealth and/or assets, poor quality of human capital, prevalence of low levels of technology, low level of living of an average Indian. All these signifies the demographic characteristics of an underdeveloped country. The economic inequality among people is widening every day. The inflation is growing higher and higher. The prices of essential commodities are escalating and the unemployment ratio is very high. Unemployment is a critical issue that continues to challenge the economic landscape of India.

As one of the world?s most populous nations with a diverse workforce, fluctuations in the unemployment rate have far-reaching implications for the country?s growth and development. Unemployment remains a pressing concern in India, with fluctuations observed across different regions and sectors. The overall unemployment rate in India as of October 2023 has gone beyond 10 per cent. In 2014, the unemployment rate was 5.4 per cent, as of now it is 10.03 per cent. The unemployment rate among the age group 25-35 has touched 30 per cent. This shows that 40 per cent of our youth population is unemployed. Another 30 per cent of the population is underemployed. Only the 30 per cent people are fortunate enough to get a regular job either in Government or in PSUs or in private entities. Around 60 per cent of job seekers are mentally distressed and physically worn out. It is distressing to see the large chunk of population, particularly the unemployed youths were exploited in the name of communal politics and subverted missions. It is not good for the nation, Sir. Education, employment and empowerment are the three important keys for building a successful nation.

Indian education system at the moment is very much wanting. It is disheartening to see the Gross Enrolment Ratio of our country is still very low comparing to countries, like Canada, Japan, Korea, USA and European Union. The National Education Policy has set the target of reaching 50 per cent GER in 2035. Sir, Tamil Nadu has reached this milestone way back in 2020. This was possible because of one man. He is Thanthai Periyar. He propounded the Dravidian Code and propelled the people of Tamil Nadu with equality, social justice and brotherhood. Perarignar Anna, the founder of Dravida

Munnetra Kazhagam and Muthamilarignar Dr. Kalaignar has followed the principle of Onre Kulam Oruvane Deivam and Kadamai, Kanniyam, Kattuppadu. With their superlative enlightening speeches, they have energized the heart and soul of Tamil people and paved way for the equitable growth in Tamil Nadu. The visionary schemes of Dr. Kalaignar has shaped Tamil Nadu and helped the people of Tamil Nadu to progress in life. Because of the three leaders, Tamil Nadu could achieve such an equitable growth across the State.

In December 2023, eight Districts of Tamil Nadu were devastated by two back to back floods due to unprecedented heavy rainfall. The Greater Chennai, Tiruvallur, Chengalpattu and Kanchipuram were affected very badly as 34 centimetres rain poured in less than 36 hours on 4^{th} and 5^{th} December, 2023. Four southern districts ? Thoothukudi, Tirunelveli, Kanyakumari, and Tenkasi were inundated and affected very badly due to heavy downpour of 95 centimetres in just two days. There was heavy loss of properties belonging to both Government and people. The Government of Tamil Nadu has swung into action swiftly and because of that loss of life is minimal.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Thalapathy M.K Stalin has requested the Prime Minister, Narendra Modi to declare the floods as a ?calamity of severe nature? and allot required amount of funds for carrying out relief and rehabilitation works in the affected districts.

An all-Party delegation from Tamil Nadu met and urged the Union Home Minister, Shri Amit Shah to take immediate action on

the memorandum submitted by the State Government seeking Rs. 37,907 crore towards interim and permanent restoration in the flood-affected districts of Tamil Nadu. Home Minister has promised that the Centre is duty-bound to support the people and would certainly release the funds by 27th January. But so far, we have not received any relief funds from the Centre. There is no mention in the President Address about the measures taken by the Government to provide adequate financial support for relief and rehabilitation works in Tamil Nadu which is affected badly due to heavy rains and floods. Therefore, I urge the Union Government to release the requested relief funds immediately to serve the people who were battered by extremely heavy rain and floods in Tamil Nadu.

Ambur and Vaniyambadi are two important commercial towns in my Vellore Lok Sabha constituency. Both contribute substantially to foreign exchange and exchequer. Sir, as far as the flyovers are concerned, the Perumugai Flyover at the cost of Rs. 21 crore is under progress. The Kandaneri, Vettuvanam works at the cost of Rs. 75 crore, though the tender is finalized, the work has not started so far. The Ambur Reddy Thoppu Bridge, the work has been stopped. The Ambur New Town Bridge at LC-81 RoB is the need of the hour. People do not want underbridge as it will be a problem for commuters. Construction of Rail Over Bridges at Vaniyambadi and Reddy Thoppu in Ambur are pending for several years.

These two RoBs are very important for the passage of commuters of all walks of life, including office goers, school and college students. At Reddy Thoppu, the existing under passage is

awfully inadequate for large number of commuters who have no other way to cross from both sides. During rainy seasons, the underpass is inundated with both rain and sewerage water. This is the plight of the people of Ambur, which can be solved only by construction of Rail Over Bridge at Reddy Thoppu, Ambur. It will benefit people residing at New Bethlehem, Kambikollai, Nathiseelapuram, Malaimedu, M.V Sami Nagar, and also the hilly villages of Naickeneri, Panagatteri.

In Vaniyambadi New Town, the level crossing LC-81 is the only access point for those entering the town from the National Highway. As more than 120 trains cross the area in both directions, it results in the gate being closed frequently. The Southern Railway has proposed a road over bridge estimated at Rs. 18 crore but it is yet to be constructed. Therefore, I urge the Government to fulfil the long pending demand that a flyover bridge has to be constructed immediately at Reddy Thoppu, Ambur and Vaniyambadi to ease traffic, passage of commuters and vehicles.

The President Address fails to mention the appropriate steps taken by the Government to expedite the completion of Vellore Airport and commence flight services to and from Vellore Airport. The Address also fails to mention the steps taken by the Government to expedite the station redevelopment works at Katpadi Railway Station and development of infrastructure facilities and passenger amenities at Ambur and Vaniyambadi railway stations in Tamil Nadu. The President Address fails to mention various remedial steps taken by the Government to stop the suicide by thousands of farmers during last few years in various parts of the country.

One farmer/farm labour dies by suicide every hour in India. An emerging and worrying trend from the NCRB data was that death by suicide of agricultural labourers was higher than cultivators. Since 2019, more than 50,000 farmers/ farm workers died by committing suicide. How many thousands of farmers and farm workers are living dead in India, we do not know. There is no mention about the remedial steps taken by the Government to stop the death of farmers/farm workers by committing suicide in various parts of the country.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Thalapathy M.K. Stalin is an amalgam of Thanthai Periyar, Perarignar Anna and Dr. Kalaignar. Today, he is leading us from the front in our forward march with vigour and valour. For India to become a developed nation, it needs to follow the Dravidian Model of Government and Governance as proved by Tamil Nadu under the dynamic leadership of our mercurial leaders, Perarignar Anna, Muthamilarignar Dr. Kalaignar and Thalapathy Muthuvel Karunanidhi Stalin. They have given us a direction for us to travel for many more centuries. They have inculcated us with lessons of life to combat any adversaries. They have trained us in creating a State with progress prosperity and peace. They have taught us the importance of communal harmony and peaceful coexistence.

With a population of 85 million, of which 80 per cent are literate, Tamil Nadu is an innovation-based economy with a strong performance in manufacturing and services, health, education, and safety of women are other domains in which the State has made

impressive strides. The State ranks ?second lowest? next only to Kerala in terms of Infant Mortality Rate (20) and birth rate (15.4). To sustain growth, the State has initiated many innovative flagship programmes. Distribution of laptops to students at the higher secondary level is now followed by other States. The special cash incentive of Rs. 5,000 per child is significantly reducing dropouts at the secondary level.

I would like to request the hon. Finance Minister to allocate five per cent of our country?s GDP for healthcare and medical infrastructure, women and child welfare and health related projects. In the same way, five per cent of GDP should be allocated for the development of education, skill training and entrepreneurship development.

I would like to place on record in this august House that our Dravidian Model legacy will continue to flourish Tamil Nadu and India through our youth leaders spearheaded by the rising sun and youth icon of Tamil Nadu, Shri Udhayanidhi Stalin.

Thank You.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): We all know that as a ritual, the President's speech is written by the Government. In fact, we all also know whose office it comes from. However, the President mentioned 'Amrit Kaal' six times in her speech. Further, there were

very selected data points provided by the Government that deceived the President of the actual reality of this Government.

I strongly feel that the Government has conducted a grave transgression by misinforming the President and the citizens that it is Amrit Kaal and just depict the data points that show only half a picture. Let me remind about some numbers and instances. Then feel free to tell me if we are living in 'Amrit Kaal' or a deep dark chamber of governance. Financial savings of households is at a fifty-year low. It fell to 5.1 per cent in 2022-2023 from 7.2 per cent in the previous financial year. Between October and December 2023, the unemployment among individuals in the age group of 20 to 24 grew to 45 per cent. Unemployment stood at 14 per cent for the age group of 25-29, a record 14-quarter high. And we heard no words regarding the same by the President.

Today, an agricultural labourer earns barely over Rs. 11,000 a month. If one normalises it for inflation, then this amount translates to Rs. 6,300. The hon. President said and I quote "My Government is of the firm opinion that corruption is the biggest enemy of democracy and social justice." However, I want to know what happened to the corruption in Ayushman Bharat Scheme. A CAG report depicted that in more than 2 lakh cases, the date of surgery was shown after the date of discharge. The same report depicted that there were more than 1.57 lakh 'Unique' IDs that appeared in the database more than once.

Well, let me remind everyone in this House of some instances that happened. For the first time since 2001, the Parliament was attacked and this time neither the Home Minister nor the Prime

Minister came to the House and spoke a word on it. However, in 2001 there was a two-day discussion and the Foreign Minister, the Home Minister and even the Prime Minister spoke in the discussion. In fact, 146 MPs were suspended for even demanding a discussion on these attacks. 1/5th of the voice of India was silenced and, in the darkness, several key legislations -- be it the Criminal Bills or the Telecommunication Bill -- were passed.

The House in which we passed the historic Women Reservation Bill was the same House where we expelled a women MP without even letting her speak even once. Some Members of these sacred chambers are accused of grave crimes against our women athletes who have made us proud in the entire world and yet we have done nothing for them. Even the Ministers of this Government have given misogynistic comments against the only women Chief Minister in the country, Shrimati Mamata Banerjee.

I would also like to remind that this Government has starved the States of their rightful dues. An amount of Rs. 9,330 crore of Awaas Yojana, Rs. 6,900 crore of MGNREGA, paddy procurement under NFSA of Rs. 7,000 crore are still due to the State of West Bengal. Total dues including GST compensation, cyclone relief, National Health Mission, Performance Grant and others is over Rs. 1 lakh crore to Bengal. When will Bengal get it?

Hence, I say this with no doubt that this Government has absolutely no regard for federalism or for the Constitution. The Indian economy is expected to grow at 6.95 per cent in the current Financial Year, and the Bengal economy is expected to grow at a

higher rate of 8.41 per cent. Yet this Government does not give us the respect we deserve.

Thus, all of these instances and the real data makes me wonder whether we are after all living in Amrit Kaal or just deep dark chamber of governance. Thank you.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मैं माननीया महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

माननीया महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार का 10 साल का लेखा जोखा पेश किया है जो काफी उत्साह जनक है । हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षो में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है, जिसका वर्णन करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ ।

सबसे पहले मैं विदेश नीति के बारे में जिक करूगा । हमारे संबंध विश्व में हर देश के साथ बहुत अच्छे है। हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। आज विश्व दो भागों में बटा हुआ है । लेकिन हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। हमारे संबंध दोनों गुंटों से गहरे है। हमने अमेरिका से अन्तरिक्ष क्षेत्र से लेकर रक्षा क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में अनुबंध किये है । आज हर अन्तराष्ट्रीय समस्या में भारत से परामर्श के बिना उसका समाधान नहीं होता है। इसी से आप समझ सकते है कि भारत ने अपनी विदेश नीति में कितनी ऊचीं छलांग लगाई है। इस सबका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है ।

अब मैं अपनी आंतरिक नीति पर सबसे पहले बात करना चाहता है । अपनी आंतरिक तकनीक पर हमने चन्द्रायन को चॉद के उस क्षेत्र में भेजने में सफलता प्राप्त की है, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुँच सका है । वहां

से हमें डाटा प्राप्त हुआ है। साथ ही हमने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने सेटेलाइट को सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे स्थान पर स्थापित कर दिया है जहां से लगातार सूर्य पर होने वाली घटनाएं कैद हो सके । अंतरिक्ष तकनीक में भारत विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है। वह दिन दूर नहीं जहां हम मानव को चन्द्रमा की सतह पर उतारेगें ।

रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार का जोर मेड इन इंडिया पर है । रक्षा क्षेत्र से संबंधित ज्यादा से ज्यादा उपकरण हम अपने ही देश में बना रहे है । हमारी निर्भरता विदेशों पर कम से कम होती जा रही है । अभी हम काफी कुछ रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे है । उदाहरण के तौर पर हमने जो तेजस विमान विकसित किया है उसकी अनेक देशों में मांग है इसी तरह से ब्रम्होस मिसाइल की भी मांग है । इससे सिद्ध होता है कि हम रक्षा क्षेत्र में काफी आगे बढ रहे है जो एक सुखद समाचार है ।

ऊर्जा क्षेत्र में भी गैर पारम्परिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जैसे कि सौर ऊर्जा, विंड पावर इत्यादि । हमने बड़े-बड़े सोर ऊर्जा पार्क स्थापित किये है और आगे करने जा रहे है। हमारा पूरा ध्यान क्लीन ऊर्जा की तरफ है और इसमें हम पूरी तरह से सफल हो रहे है। यहां भी हम अपने लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर रहे है ।

हमारी सरकार मूल ढांचे पर विशेष ध्यान दे रही ।

भारतीय अर्थव्यवस्था का सकारात्मक परिवर्तनः यह अंतरिम बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है, जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाएगा। यह बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है, जो मोदी सरकार के "सबका साथ, सबका विकास" के आदर्श वाक्य के अनुरूप, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) को शामिल करता है । इस बजट में भारत के जी-20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी

सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया, जिसमें प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए, भारत को दुनिया भर में विश्वगुरु के रूप में पेंश किया गया ।

सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय मजबूतीः उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और निराशाजनक कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद, मोदी सरकार ने सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने, धीरे-धीरे पूंजीगत व्यय परिव्यय में वृद्धि और लक्षित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की लक्षित त्रि-आयामी नीति के माध्यम से सकारात्मक राजकोषीय समेकन हासिल किया है । इन सक्रिय उपायों के परिणामस्वरूप, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% तक कम रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 5.9% था । इसने देश को वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय समेकन पूरा करने की स्थिति में ला दिया है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम होने की उम्मीद है। भारत को 2014 से पहले की नाजुक अर्थव्यवस्था से आर्थिक प्रबंधन में विश्व नेता बनाने के मोदी सरकार के प्रयासों को रेखांकित करने के लिए, सरकार कुप्रबंधन के पिछले दौर से सबक लेने के लिए संसद के समक्ष एक श्वेत पत्र रखेगी ।

पूंजीगत व्यय प्रेरित विकासः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निरंतर और दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च का बजट बढ़ाकर ₹ 11,11,111 करोड़ कर दिया गया है जो देश के सकल घरेलु उत्पाद का 3.4% है। यह यू.पी.ए सरकार के समय वित्तीय वर्ष 2013-14 में खर्च के लिए आवंटित ₹2,57,641 करोड़ की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो सकल घरेलु उत्पाद का केवल 2.8% था । इसका तात्पर्य है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च चार गुना बढ़ाया गया है, और इस वृद्धि से आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास

सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर लगभग 2.45 गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है ।

बुनियादी ढांचे का विकासः मोदी सरकार ने देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है । इस प्रयास का एक उल्लेखनीय उदाहरण हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि है, जो अब 149 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा 2014 तक मौजूद हवाई अड्डों की संख्या की तुलना में दोगुनी वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना ने हवाई यात्रा को सबके लिए सुलभ बना दिया, जिससे टियर-II और टियर-III शहरों के मध्यम वर्ग के नागरिकों को अपनी विमानन अकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया गया। यह अंतरिम बजट भी उसी राह पर है और उड़ान योजना के अंतर्गत नए हवाई अड्डों के निर्माण और यात्री ट्रेनों को सुरक्षित बनाते हुए रेलवे प्रणाली में भीड़भाड़ कम करने पर बहुत बल देता है । ऐसे में, मध्यम वर्ग के भारतीयों के लिए सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत रेलगाड़ी के मानकों के हिसाब से परिवर्तित किया जाएगा । इसके अलावा, बजट में नमो-इंडिया के तत्वावधान में शहरी परिवर्तन के प्रमुख इंजन के रूप में मेट्रो रेल की कल्पना की गई है, जबकि लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री-गति शक्ति के अंतर्गत तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर भी प्रस्तावित किए गए हैं ।

सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल का बोधः मोदी सरकार को ज्ञात है कि भारत का "अमृत काल", उसका "कर्तव्य काल" भी है, जिसके दौरान गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की सफलता की कहानी में योगदान देना होगा । इस प्रकार, सरकार ने 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी और बिना किसी भ्रष्टाचार के डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में अंतहीन काम किया है, जिसके माध्यम से ₹34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ

सीधे प्रधानमंत्री-जन धन खातों में स्थानांतरित किए गए हैं, जिसके कारण सरकार को ₹2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण ने 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, जो पिछले प्रशासन के बिल्कुल विपरीत है, जहां एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचते थे। व्यापक सामाजिक परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, बजट में अगले पांच वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है । मध्यम वर्ग की आवास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वयं के घरों की खरीद या निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह दूरदर्शी पहल समावेशी विकास और अपने नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाती है ।

भारत की सफलता की कहानी के शीर्ष पर नारी शक्तिः मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर काफी जोर दिया है, जिसे सामाजिक स्वायत्तता, वित्तीय समावेशन और महिलाओं के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उपायों से मदद मिली है । उदाहरण के लिए, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, 2.4 करोड़ घरों में से 26.6% पूरी तरह से महिलाओं के नाम बर हैं, और लगभग 70% संयुक्त रूप से पत्नी और पति के नाम पर हैं। इसी तरह, नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख एसएचजी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं । उनकी सफलता ने लगभग एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है । इस प्रकार, अंतरिम बजट में लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है । मोदी सरकार 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा देकर भारतीय महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी। बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन में देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में और तेजी लाई

जाएगी। इसके अलावा, आयुष्मान भारत का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस योजना को सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा ।

अन्नदाता का सर्व समावेशी विकास और कल्याणः मोदी सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल में, निरंतर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि किसान देश के विकास के केंद्र बिंदु पर बने रहें। इस दिशा में छोटे और सीमांत किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री-किसान जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है और 1.8 करोड़ किसानों को ₹3 लाख करोड़ व्यपार क्षमताओं के साथ सेवाएं प्रदान कर रहा है । इसलिए, किसान कल्याण की भावना के साथ मोदी सरकार पूरे देश में नैनो-डी.ए.पी के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करेगी । आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए, तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान लाया जाएगा । इसके अलावा, डेयरी विकास के लिए एक नए व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को सफल बनाया जाएगा । दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार के द्वारा दुध उत्पादन में नंबर एक के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य पालन के लिए मोदी सरकार के द्वारा एक पृथक विभाग का निर्माण किया गया । वर्ष 2023-24 में आवंटित ₹2,025 करोड़ की तुलना में इस क्षेत्र को वर्ष 2024-25 में ₹2,352 करोड़ की अधिक राशि का आवंटन नील क्रांति 2.0 को सफल बनाया जाएगा । इसके अतिरिक्त 5 समेकित एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी ।

पंचामृत लक्ष्यों को पूरा करने की ओर अग्रसरः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में कॉप-26 शिखर सम्मेलन में "पंचामृत" का लक्ष्य रखा था । उन्होंने भारत के लिए पांच सतत विकास और पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना की थी और मोदी सरकार ने उन्हें प्राप्त करने की दिशा में

लगातार काम किया है । भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा 50% स्थापित ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसमें से वर्तमान में 43.9% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है । पंचामृत के दृष्टिकोण को लागू करते हुए, अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सूर्योदय योजना की शुरूआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट निशुल्क बिजली प्राप्ति के लक्ष्य हेतु 1 करोड़ घरों को छत आधारित सोलर पैनल प्रदान किए जाएंगे। इससे प्रति वर्ष प्रत्येक घर को ₹12 से ₹18 हजार की बचत होगी ।

अमृत पीढ़ी के लिए रोजगार सुनिश्चित करनाः वर्ष 2014 से औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि हुई है जो 'सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य को साकार करने के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को साबित करता है जिसने नागरिकों के जीवन को बदल दिया है । उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने युवाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए के लिए 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनकी कुल राशि ₹22.5 लाख करोड़ है । इसके अतिरिक्त, फंड ऑफ फंड्स, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टार्ट अप क्रेडिट गारंटी योजनाओं ने भी युवाओं की सहायता की है, जो अब रोजगारदाता हैं । इसलिए, देश की अमृत पीढ़ी को प्रगति के पथ पर सुनिश्चित बनाए रखने के लिए, संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा स्टार्टअप निवेशों के टैक्स लाभों को 31-3-2025 तक बढ़ाया जा रहा है जो कि 2024 में ही समाप्त होने वाले थे । इसके अलावा, निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण अवधि के साथ 1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा ।

प्रभावी शासन के मूल में पारदर्शिता लानाः पारदर्शिता हमेशा मोदी सरकार के 'सुशासन मॉडल का एक प्रमुख पहलू रही है जो न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, और अधिकतम शासन के मार्ग पर कार्य करती है । सुशासन का यह मॉडल मूल रूप से हर चीज के केंद्र में आम नागरिक को रखता है । इस

मॉडल के आधार पर, करदाता अब फेसलेस मूल्यांकन की सेवा का आनंद ले रहा है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-2014 में जहां रिफंड प्राप्त करने का औसत समय 93 दिन हुआ करता था, अब यह घटकर पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 10 दिन का हो गया है । वित्तीय वर्ष 2010 तेक तत्काल प्रभाव से, मोदी सरकार ₹25,000 तक की बकाया कर मांगों और वित्तीय वर्ष 2011-2015 के लिए ₹10,000 तक की छूट प्रदान की है। इस पहल के माध्यम से एक करोड़ करदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है ।

सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ बनानाः मोदी सरकार ने राज्यों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को लागू करने का आग्रह करके लगातार संघवाद का समर्थन किया है । इसके अतिरिक्त जी.एस.टी. के लागू किए जाने के बाद वर्ष 2017-18 से लेकर 2022-23 तक की अवधि में, राज्यों के मुआवजे के साथ-साथ, राज्यों के एस.जी.एस.टी. से राजस्व में, 1.22 की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है । जबकि जी.एस.टी के लागू होने से पहले यह केवल 0.72 थी । इसके अतिरिक्त सरकार ने "पूर्वोदय" पहल के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थायी शांति और विकास लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । वर्तमान अंतरिम बजट विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कुल ₹1.30 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके संघवाद के प्रति सरकार के समर्पण को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त, यह बजट राज्य सरकारों को नए लक्ष्यों से जुड़े सुधारों को लागू करने में समर्थन प्रदान करने के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹75,000 करोड़ आवंटित करता है । राज्य सरकारों को आध्यात्मिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और लक्षद्वीप जैसे द्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल की जाएगी । सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बेहतरीन सड़कों का जाल विछा दिया है। जो आज तक नहीं हो पाया था ।

हमारी सरकार रेलवे कार्यकल्प पर भी विशेष ध्यान दे रहीं है । जगह-जगह लाईनों का चौड़ीकरण व विधुतीकरण हो रहा है । 1300 रेलवे स्टेशनों का कार्यकल्प किया जा रहा है । नई-नई रेलगाड़ियों का निर्माण अपने देश में ही हो रहा है । मालगाड़ियों की गति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीध्यतिशीघ्र पहुँच जाये। गाडियों को दुर्घटना से बचाने के लिए नए-नए तरीके खोजे जा रहे है । मुझे आशा है कि बहुत ही जल्दी हमारा रेलवे नेटवर्क विश्वस्तरीय हो जायेगा ।

सैकड़ों सालों के इन्तजार के बाद 22 जनवरी, 2024 को रामलला अपने भव्य मन्दिर में विराजमान हुए है । इसने सारे हिन्दू समाज को एक सूत्र में बांध दिया है । देश के हर कोने में खुशी का माहौल है लोग दीवाली मना रहे है । जब इस मन्दिर का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे विपक्ष के मित्र यह कह रहे थे कि इससे हम खाड़ी देशों को नाराज न केवल भारत में इस भव्य मन्दिर का निर्माण हुआ हे बल्कि आबूधाबी में भी एक भव्य और विशाल मन्दिर बनने जा रहा है । जिसका उद्‌घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी इसी महीने करेंगें ।

हमारी सरकार 80 करोड़ से भी ज्यादा गरीब नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान कर रही है जिससे कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। सरकार ने इन व्यक्तियों के लिए इतनी सुविधा vec 4 दी है कि वह देश माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाकर दे रही है । करोड़ों लोगों को पक्के मकान, शुद्ध पेयजल, मुफ्त गैस सिलेंडर, शौचालय आदि प्रदान किये जा रहे है जिससे कि उनका जीवन स्तर सुखमय हो सके । सरकार के इन प्रयासों से (एक रिपोर्ट के अनुसार) करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गये है यह हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है । इसलिए कहा गया है कि- न टपकती छत, न आंगन कच्चा, सपने नहीं हकीकत गुनते है । तभी तो सब मोदी को चुनते है ।

इन शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ ।

जय हिन्द, जय भारत ।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मैं माननीया महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

माननीया महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार का 10 साल का लेखा जोखा पेश किया है, जो काफी उत्साह जनक है । हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है, जिसका वर्णन करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ ।

सबसे पहले मैं विदेश नीति के बारे में जिक्र करूगा । आज केवल दो देशों को छोड करके, पाकिस्तान व चीन, हमारे संबंध विश्व में हर देश के साथ बहुत अच्छे है । हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है । आज विश्व दो भागों में बटा हुआ है, लेकिन हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है । हमारे संबंध दोनों गुटों से गहरे है । सोवियत रूस पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद, हमारे रूस से संबंध में कोई कमी नहीं आई है । बल्कि प्रतिबंधों के पहले से भी हमारा व्यापार दोनों देशों के बीच बढा है । आज हम अपनी आवश्यकता का एक-तिहाई कच्चा तेल रूस से आयात कर रहे है, इससे हमने अमेरिकी गुट को भी नाराज नहीं किया है, बल्कि हमारे संबंध अमेरिका से भी पहले से अधिक मधुर हुये है । हमने अमेरिका से अन्तरिक्ष क्षेत्र से लेकर रक्षा क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में अनुबंध किये है । आज हर अन्तर्राष्ट्रीय समस्या में भारत से परामर्श के बिना उसका समाधान नहीं होता है । इसी से आप समझ सकते है कि भारत ने अपनी विदेश नीति में कितनी ऊचीं छलांग लगाई है । इस सबका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जाता है ।

अब मैं अपनी आंतरिक नीति पर सबसे पहले बात करना चाहता हैं । अपनी आंतरिक तकनीक पर हमने चन्द्रायन को चाँद के उस क्षेत्र में भेजने में सफलता प्राप्त की है, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुँच सका है । वहां

से हमें डाटा प्राप्त हुआ है । साथ ही हमने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने सेटेलाइट को सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे स्थान पर स्थापित कर दिया है जहां से लगातार सूर्य पर होने वाली घटनाएं कैद हो सकें । अंतरिक्ष तकनीक में भारत विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है । वह दिन दूर नहीं जहां हम मानव को चन्द्रमा की सतह पर उतारेगें ।

रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार का जोर मेड इन इंडिया पर है । रक्षा क्षेत्र से संबंधित ज्यादा से ज्यादा उपकरण हम अपने ही देश में बना रहे है । हमारी निर्भरता विदेशों पर कम से कम होती जा रही है । अभी हम काफी कुछ रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे है । उदाहरण के तौर पर हमने जो तेजस विमान विकसित किया है उसकी अनेक देशों में मांग है इसी तरह से ब्रम्होस मिसाइल की भी मांग है । इससे सिद्ध होता है कि हम रक्षा क्षेत्र में काफी आगे बढ रहे है जो एक सुखद समाचार है ।

ऊर्जा क्षेत्र में भी गैर पारम्परिक क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, विंड पावर इत्यादि । हमने बड़े-बड़े सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किये हैं और आगे करने जा रहे हैं । हमारा पूरा ध्यान क्लीन ऊर्जा पर है ।

हमारी सरकार मूल ढांचे पर विशेष ध्यान दे रहीं है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था का सकारात्मक परिवर्तनः यह अंतरिम बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है । जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाएगा । यह बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है । जो मोदी सरकार के "सबका साथ, सबका विकास" के आदर्श वाक्य के अनुरूप, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) को शामिल करता है । इस बजट में भारत के जी-20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया, जिसमें प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के

साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए, भारत को दुनिया भर में विश्वगुरु के रूप में पेश किया गया।

सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय मजबूतीः उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और निराशाजनक कार्पोरेट क्षेत्र के साथ एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद, मोदी सरकार ने सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने, धीरे-धीरे पूंजीगत व्यय परिव्यय में वृद्धि और लक्षित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की लक्षित वि-आयामी नीति के माध्यम से सकारात्मक राजकोषीय समेकन हासिल किया है। इन सक्रिय उपायों के परिणामस्वरूप, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% तक कम रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 5.9% था। इसने देश को वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय समेकन पूरा करने की स्थिति में ला दिया है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम होने की उम्मीद है। भारत को 2014 से पहले की नाजुक अर्थव्यवस्था से आर्थिक प्रबंधन में विश्व नेता बनाने के मोदी सरकार के प्रयासों को रेखांकित करने के लिए, सरकार कुप्रबंधन के पिछले दौर से सबक लेने के लिए संसद के समक्ष एक श्वेत पत्र रखेगी।

पूंजीगत व्यय प्रेरित विकासः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निरंतर और दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च का बजट बढ़ाकर ₹ 11,11,111 करोड़ कर दिया गया है जो देश के सकल घरेलु उत्पाद का 3.4% है। यह यू.पी.ए सरकार के समय वित्तीय वर्ष 2013-14 में खर्च के लिए आवंटित ₹2,57,641 करोड़ की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो सकल घरेलु उत्पाद का केवल 2.8% था। इसका तात्पर्य है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च चार गुना बढ़ाया गया है, और इस वृद्धि से आधारभूत संरखना और सामाजिक विकास सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर लगभग 2.45 गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

बुनियादी ढांचे का विकासः मोदी सरकार ने देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। इस प्रयास का एक उल्लेखनीय उदाहरण हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि है, जो अब 149 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा 2014 तक मौजूद हवाई अड्डों की संख्या की तुलना में दोगुनी वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई उडान योजना ने हवाई यात्रा को सबके लिए सुलभ बना दिया, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों के मध्यम वर्ग के नागरिकों को अपनी विमानन आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया गया। यह अंतरिम बजट भी उसी राह पर है और उड़ान योजना के अंतर्गत नए हवाई अड्डों के निर्माण और यात्री ट्रेनों को सुरक्षित बनाते हुए रेलवे प्रणाली में भीडभाड कम करने पर बहुत बल देता है। ऐसे में, मध्यम वर्ग के भारतीयों के लिए सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत रेलगाड़ी के मानकों के हिसाब से परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा, बजट में नमो इंडिया के तत्वावधान में शहरी परिवर्तन के प्रमुख इंजन के रूप में मेट्रो रेल की कल्पना की गई है, जबकि लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री-गति शक्ति के अंतर्गत तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर भी प्रस्तावित किए गए हैं।

सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल का बोधः मोदी सरकार को ज्ञात है कि भारत का "अमृत काल", उसका "कर्तव्य काल" भी है, जिसके दौरान गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की सफलता की कहानी में योगदान देना होगा। इस प्रकार, सरकार ने 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी और बिना किसी भ्रष्टाचार के डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में अंतहीन काम किया है, जिसके माध्यम से ₹34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ सीधे प्रधानमंत्री-जन धन खातों में स्थानांतरित किए गए हैं, जिसके कारण सरकार को ₹2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण ने 17 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, जो पिछले

प्रशासन के बिल्कुल विपरीत है, जहां एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचते थे । व्यापक सामाजिक परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, बजट में अगले पांच वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है । मध्यम वर्ग की आवास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वयं के घरों की खरीद या निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी । यह दूरदर्शी पहल समावेशी विकास और अपने नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाती है ।

भारत की सफलता की कहानी के शीर्ष पर नारी शक्तिः मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर काफी जोर दिया है, जिसे सामाजिक स्वायत्तता, वित्तीय समावेशन और महिलाओं के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उपायों से मदद मिली है । उदाहरण के लिए, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, 2.4 करोड़ घरों में से 26.6% पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर हैं, और लगभग 70% संयुक्त रूप से पत्नी और पति के नाम पर है । इसी तरह, नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख एसएचजी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं । उनकी सफलता ने लगभग एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है । इस प्रकार, अंतरिम बजट में लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है । मोदी सरकार 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा देकर भारतीय महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी । बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन में देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में और तेजी लाई आएगी । इसके अलावा, आयुष्मान भारत का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस योजना की सभी आशा, आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा ।

अन्नदाता का सर्व समावेशी विकास और कल्याण: मोदी सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल में, निरंतर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए है कि किसान देश के विकास के केंद्र बिंदु पर बने रहे । इस दिशा में छोटे और सीमांत किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री-किसान जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है और 1.8 करोड़ किसानों को 13 लाख करोड़ व्यपार क्षमताओं के साथ सेवाएं प्रदान कर रहा है । इसलिए, किसान कल्याण की भावना के साथ मोदी सरकार पूरे देश में नैनो-डी.ए.पी के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करेगी । आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए, तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान लाया जाएगा । इसके अलावा, डेयरी विकास के लिए एक नए व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को सफल बनाया जाएगा । दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार के द्वारा दूध उत्पादन में नंबर एक के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा । मत्स्य पालन के लिए मोदी सरकार के द्वारा एक पृथक विभाग का निर्माण किया गया । वर्ष 2023-24 में आवंटित ₹2.025 करोड़ की तुलना में इस क्षेत्र को वर्ष 2024-25 में ₹2,352 करोड़ की अधिक राशि का आवंटन नील क्रांति 2.0 को सफल बनाया जाएगा । इसके अतिरिक्त 5 समेकित एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी ।

पंचामृत लक्ष्यों को पूरा करने की ओर अग्रसरः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में कॉप-26 शिखर सम्मेलन में "पंचामृत" का लक्ष्य रखा था । उन्होंने भारत के लिए पांच सतत विकास और पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना की थी और मोदी सरकार ने उन्हें प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम किया है । भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा 50% स्थापित ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसमें से वर्तमान में 43.9% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है । पंचामृत के दृष्टिकोण को लागू करते हुए, अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

जी द्वारा सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट निशुल्क बिजली प्राप्ति के लक्ष्य हेतु 1 करोड़ घरों को छत आधारित सोलर पैनल प्रदान किए जाएंगे । इससे प्रति वर्ष प्रत्येक घर को 12 से 18 हजार की बचत होगी ।

अमृत पीढ़ी के लिए रोजगार सुनिश्चित करनाः वर्ष 2014 से औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि हुई है जो 'सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य को साकार करने के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को साबित करता है जिसने नागरिकों के जीवन को बदल दिया है । उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने युवाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए के लिए 43 करोड़ स्वीकृत किए है, जिनकी कुन राशि ₹225 लाख करोड़ है । इसके अतिरिक्त, फंड ऑफ फंड्स, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टार्ट अप क्रेडिट गारंटी योजनाओं ने भी युवाओं की सहायता की है, जो अब रोजगारदाता है । इसलिए, देश की अमृत पीढ़ी को प्रगति के पथ पर सुनिश्चित बनाए रखने के लिए, संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा स्टार्टअप निवेशों के टैक्स लाभों को 31-3-2025 तक बढ़ाया जा रहा है जो कि 2024 में ही समाप्त होने वाले थे । इसके अलावा, निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण अवधि के साथ 1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा ।

प्रभावी शासन के मूल में पारदर्शिता लानाः पारदर्शिता हमेशा मोदी सरकार के 'सुशासन मॉडल का एक प्रमुख पहलू रही है, जो न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, और अधिकतम शासन के मार्ग पर कार्य करती है । सुशासन का यह मॉडल मूल रूप से हर चीज के केंद्र में आम नागरिक को रखता है । इस मॉडल के आधार पर, करदाता अब फेसलेस मूल्यांकन की सेवा का आनंद ले रहा है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-2014 में जहा रिफंड प्राप्त करने का औसत समय 93 दिन हुआ करता था, अब यह घटकर पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 10 दिन का हो गया है । वित्तीय वर्ष 2010 तक तत्काल प्रभाव से, मोदी

सरकार ₹25,000 तक की बकाया कर मांगों और वित्तीय वर्ष 2011-2015 के लिए 10,000 तक की छूट प्रदान की है। इस पहल के माध्यम से एक करोड़ करदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ बनानाः मोदी सरकार ने राज्यों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को लागू करने का आग्रह करके लगातार संघवाद का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त जी.एस.टी. के लागू किए जाने के बाद वर्ष 2017-18 से लेकर 2022-23 तक की अवधि में, राज्यों के मुआवजे के साथ-साथ, राज्यों के एस.जी.एस.टी. से राजस्व में, 1.22 की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। जबकि जी.एस.टी के लागू होने से पहले यह केवल 0.72 थी। इसके अतिरिक्त सरकार ने "पूर्वोदय" पहल के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थायी शांति और विकास लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान अंतरिम बजट विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कुल ₹1.30 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके संघवाद के प्रति सरकार के समर्पण को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त, यह बजट राज्य सरकारों को नए लक्ष्यों से जुड़े सुधारों को लागू करने में समर्थन प्रदान करने के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹75,000 करोड़ आवंटित करता है। राज्य सरकारों को आध्यात्मिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और लक्षद्वीप जैसे द्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल की जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बेहतरीन सड़कों का जाल बिछा दिया है। जो आज तक नहीं हो पाया था।

हमारी सरकार रेलवे कार्यकल्प पर भी विशेष ध्यान दे रही है। जगह-जगह लाईनों का चौड़ीकरण व विद्युतीकरण हो रहा है। 1300 रेलवे स्टेशनों का कार्यकल्प किया जा रहा है। नई-नई रेलगाड़ियों का निर्माण अपने देश में ही हो रहा है। मालगाड़ियों की गति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाये।

गाडियों को दुर्घटना से बचाने के लिए नए-नए तरीके खोजे जा रहे हैं । मुझे आशा है कि बहुत ही जल्दी हमारा रेलवे नेटवर्क विश्वस्तरीय हो जायेगा ।

सैकड़ों सालों के इन्तजार के बाद 22 जनवरी, 2024 को रामलला अपने भव्य मन्दिर में विराजमान हुए है । इसने सारे हिन्दू समाज को एक सूत्र में बांध दिया है । देश के हर कोने में खुशी का माहौल है लोग दीवाली मना रहे है । जब इस मन्दिर का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे विपक्ष के मित्र यह कह रहे थे कि इससे हम खाड़ी देशों को नाराज न केवल भारत में इस भव्य मन्दिर का निर्माण हुआ हे बल्कि आबूधाबी में भी एक भव्य और विशाल मन्दिर बनने जा रहा है, जिसका उद्‌घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी इसी महीने करेंगें ।

हमारी सरकार 80 करोड़ से भी ज्यादा गरीब नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान कर रही है जिससे कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे । सरकार ने इन व्यक्तियों के लिए इतनी सुविधा दे दी है ।

हमारी सरकार गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाकर दे रही है । करोड़ों लोगों को पक्के मकान, शुद्ध पेयजल, मुफ्त गैस सिलेंडर, शौचालय आदि प्रदान किये जा रहे है जिससे कि उनका जीवन स्तर सुखमय हो सके । सरकार के इन प्रयासों से (एक रिपोर्ट के अनुसार) करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गये है यह हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है । इसलिए कहा गया है कि न टपकती छत, न आंगन कच्चा, सपने नहीं हकीकत गुनते है । तभी तो सब मोदी को चुनते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे (लातूर): मैं संसद के समक्ष दिनांक 31 जनवरी, 2024 को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मेरी सहयोगी

डा. हीना विजयकुमार गावित द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । हमारे देश ने आजादी के 76 सालों बाद अमृत काल में प्रवेश किया है । 25 साल का यह अमृत कालखंड विकसित भारत के निर्माण का काल है, जिसमें भारत गरीबी रहित होगा तथा जिसमें समृद्ध मध्यम वर्ग अपने युवाओं और महिलाओं द्वारा निर्देशित होगा । हमारी सरकार ने अपने लगभग 10 सालों के कार्यकाल में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं तथा इससे हर भारतीय को आत्मविश्वास मिला है ।

हमारी सरकार विकसित भारत के चार स्तंभ - युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त करने हेतु तन-मन-धन से प्रयासरत है । जैसे हमारे देश के इतिहास में गुप्तकाल स्वर्ण युग था, इसी प्रकार हमारे प्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल के विगत 10 साल का कार्यकाल इस शताब्दी का स्वर्ण युग है । हमारी सरकार ने शुरू से ही तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की । कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी सम्प्रदाय हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के मिले । हमारी सरकार ने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ कभी समझौता नहीं किया है । हमारी सरकार की डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर की नीति से आज जो एक रुपया आम जन को भेजा जाता है, वह पूरा का पूरा रुपया उस तक पहुँचता है, न कि पहले की सरकारों की तरह केवल 15 पैसे । विगत 10 सालों में हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए हमारी सरकार के सतत व समर्पित प्रयासों से विगत 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना संभव हो पाया है । यदि विगत की सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास किया होता तो 2014 में शासन की बागडोर संभालते हुए हमारी सरकार को 80 करोड़ लोग निर्धनता की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हुए नहीं मिलते ।

हमारी सरकार ने देश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए हैं । चाहे वह महिला उत्थान हो अथवा आदिवासी उत्थान । आज यदि एक आदिवासी महिला विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति है तो एक दूसरी महिला विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था की एक सफल वित्त मंत्री साबित हुई है । आयुष्मान भारत से समाज के सभी वर्गों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा आज उपलब्ध है । किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है । वहीं प्रधानमंत्री मानधन योजना के माध्यम से उन्हें हर साल बीज व अन्य कृषि सामान खरीदने के लिए विगत 5 वर्षों से हर साल 6 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है ।

हमारे देश का हज कोटा विगत दस सालों में काफी बढ़ा है । आज भारत के पासपोर्ट वाले हमारे नागरिक जिस भी देश में पहुँचते हैं, उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है । मुस्लिम महिलाएं अब तीन तलाक का शिकार नहीं होती हैं । सरकार ने तीन तलाक हटाकर देश की 14-20 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय करने का काम किया है ।

महिलाओं की स्थिति में आज जितना सुधार हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ । चाहे वह घरेलू गैस हो अथवा पेयजल आपूर्ति । प्रधानमंत्री शहरी व ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आगामी साल में दो करोड़ घर और उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है । यह हमारी ही सरकार है जिसने संसद व विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है ।

यह हमारी ही सरकार है जिसने गरीबों को दरिद्र नारायण समझते हुए उन्हें ईश्वर के समतुल्य मानते हुए उनके विकास के लिए सैकड़ों योजनाएं लाकर गरीबी को हटाने का कार्य किया है और उसी प्रयासों का परिणाम है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं तथा इस दिशा में सतत प्रयास जारी हैं ।

यहां मैं अपने लातूर क्षेत्र की कतिपय समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । लातूर में कोच फैक्ट्री का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया परन्तु अभी तक उसमें कोच निर्माण कार्य चालू नहीं हो पाया है । इस सिलसिले में मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर कोच फैक्ट्री के लिए कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय स्रोतों से की जाए तथा फैक्ट्री में कम से कम 70 प्रतिशत कर्मचारियों की भर्ती स्थानीय युवाओं में से की जाए ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी के संकट से मुक्ति मिल सके ।

लातूर स्टेशन पर पिट लाइन नहीं होने के कारण यहां कोच मेंटीनेंस सुविधा नहीं है । लातूर में रेल कोच फैक्ट्री तथा सीआरपीएफ का केन्द्र होने के कारण यहां से यात्री व माल यातायात कई गुना बढ़ गया है तथा यहां से नई रेल सेवाएं शुरू किए जाने की तत्काल आवश्यकता है । पिट लाइन नहीं होने के कारण विगत 75 सालों से यहां से किसी नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं की जा सकी है । यहां से नई रेल सेवाएं शुरू करने की भी तत्काल आवश्यकता है । अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि आगामी बजट में पिट लाइन के हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर इसका निर्माण शीघ्रातिशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता

हूं ।

श्री विनोद लखमशी चावड़ा (कच्छ): मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ । जिस प्रकार भारत की राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों और भावी योजनाओं पर विचार प्रस्तुत किये उसका में सन्मान करता हूँ । आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की

ओर अग्रसर हो रहा है. यह सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से ही सम्भव हो रहा है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चार साल सात मास पूरे किये है । ये गरीबों, विकास वचितों के लिये काम करती सरकार हे किसानों, दलित ओर वनवासी वधुओं के लिये काम करती सरकार है ।

लोकतंत्र में लोगो से फिर से मिला जनादेश नये भारत के निर्माण के लिये दिया गया है एक ऐसा नया भारत जिसमे हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो और जो 21वी सदी में विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करे एक ऐसा नया भारत जो चोथी औध्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाये ओर विश्व मंच पे हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचे ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सांसद के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमनरी श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा एक शस्क्त भारत के निर्माण की दिशा के संबंध में उठाये गये क्रांतिकारी कदम की हमे जानकारी दी जो किसानो, महिलाओ, गरीबो ओर युवाओं सहित आम लोगो के लिये उत्साहवर्धक हे, अभिभाषण में देश की गौरवमयी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था की तस्वीरों की झलक थी । आजादी का अमृतकाल, चन्द्रयान- 3, मेरी माटी मेरा देश अभियान की सराहना की है और

इस उत्सव के दौरान:

1. मेरी माटी, मेरा देश अभियान के तहत, देश भर के हर गाँव क मिट्टी के साथ अमृत कलश दल लाए गए

2. दो लाख से जादा शिला फल कम स्थापित किए गए ।

3. तीन करोड़ से ज्यादा लोग ने पंच पाण के शपथ ली ।

4. 70 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बने ।

5. दो लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ ।

6. दो करोड़ से ज्यादा पेड़-पौधे लगाए गए ।

7. 16 करोड़ से ज्यादा लोग ने तिरंगे के साथ से फ अपलोड की ।

अमृत महोत्सव के दौरान ही:

1. कर्तव्य पथ पर नेता जी सुभाष चंद्रबोस की प्रतिमा स्थापित की गई ।

2. राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियो को समर्पित म्यूजियम खोला गया ।

3. शांति निकेतन और होयसला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए ।

4. साहबजादों की याद में वीर बाल दीवस घोषत हुआ ।

5. भगवान बरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दीवस घोषत किया गया ।

6. विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए,14 अगत को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषत किया गया ।

और उपलब्धियां जो आज दिख रही हैं, वे बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार हैं:

हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे थे । अब हम जीवन म पहल बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं । नीति आयोग के अनुसार, मेरी सरकार के एक दशक के कार्य काल में, करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं । यह प्रत्येक गरीब में विश्वास

जगाने वाली बात है । जब 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है ।

पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत क बढती साख है । आज दुनिया भारत को देखना और जानना चाहती है । इसके अलावा, शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है । जगह-जगह एयरपोर्ट बनने से भी बहुत फायदा हो रहा है । नॉथ-ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं । अंडमान नकोबार और लक्षदीप को लेकर उत्साह चरम पर है, सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है, जिससे भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है, बीते एक वर्ष में साढ़े आठ करोड़ लोग काशी गए है । 5 करोड़ से अधक लोग ने महाकाल के दर्शन किये हैं ।

19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है । अयोध्या धाम में ही 1 प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, भारत को मीटंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बताना चाहती है, इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसा इन्फ्राटेकचर बनाया जा रहा है, आने वाले समय में टूरिस्म, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा ।

नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एकात्म मानवता के दर्शन माध्यम से अंत्योदय की कल्पना को साकार करते हुए 'सबका साथ सबका विकास' के मजबूत संकल्प को मूर्तिमंत किया है ।

इस तरह हमारी सरकार सर्वागीण विकास के लिये हरेक पहेलु पर विकास कर रही हे 'मेक इन इंडिया', स्कील इंडिया आदि के एकीकृत पहल के माध्यम से रोजगार सर्जन प्रशस्त हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र मे उत्कृष्टता एवम अनुसंधानो को प्रोत्साहन, स्वास्थय, स्वछता, तथा कुपोषण को झड़ से

खत्म करने हमारी सरकार कृत-संकल्पित है, आइये हम सब मिलकर स्वामी विवेकानंद ओर महात्मा गांधीजी के सपनों के एक समृध्ध भारत के निर्माण दिशा में आगे बढ़े, और हमारी सरकार ने ऐसे अनेक अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

जय हिन्द । जय भारत ।

श्री देवजी पटेल (जालौर): मैं संसद के समक्ष दिनांक 31 जनवरी, 2024 को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मेरी सहयोगी डा. हीना विजयकुमार गावित द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । हमारा देश ने आजादी के 76 सालों बाद अमृत काल में प्रवेश किया है । 25 साल का यह अमृत कालखंड विकसित भारत के निर्माण का काल है जिसमें भारत गरीबी रहित होगा तथा जिसमें समृद्ध मध्यम वर्ग अपने युवाओं और महिलाओं द्वारा निर्देशित होगा । हमारी सरकार ने अपने लगभग 10 सालों के कार्यकाल में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं तथा इससे हर भारतीय को आत्मविश्वास मिला है । इस कार्यकाल के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने अनेकों बड़े फैसले लिए आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली सैंकड़ों योजनाओं से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया । इन 9 सालों में भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ।

हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 10 सालों के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने, जनधन योजना के तहत देशभर में 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए गए मुद्रा योजना में लोगों को बिना गारंटी के 40.82 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ का सस्ती दर पर कर्ज दिया गया । पीएम आवास

योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 3.45 करोड़ घर बनाए गए, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन की पहुंच बनी, जन आरोग्य योजना के तहत 4.44 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज हुआ तथा किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है । घर जल योजना के तहत अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है । वहीं, कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है । यह सब कोई साधारण उपलब्धि नहीं है । हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जब जब जरूरत पड़ी कड़े फैसले लेने से भी कभी पीछे नहीं हटे, चाहे वह 2016 में नोटबंदी का फैसला हो, या 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला । चाहे वह 2019 में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला हो अथवा 2021 में कोरोना से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन के जरिये टीकाकरण अभियान इस सबका परिणाम है कि विगत दस सालों की अल्पव कार्यावधि के दौरान आज देश में हर क्षेत्र चहुंमुखी विकास हुआ है । यह सब इन आंकड़ों से स्पष्ट दिखाई देता है । देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से बढ़कर 692 हो चुकी है, एम्स की संख्या 6 से बढ़कर 24 हो चुकी है, 16 आईआईटी संस्थान की संख्या 9 बढ़कर 23 हो चुकी हैं तथा 13 आईआईएम से बढ़कर अब 20 हो चुके हैं । भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट से बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई, 13 करोड़ गैस कनैक्शन बढ़कर 31 करोड़ हो गए हैं । देश में नेशनल हाईवे की लम्बाई 91.287 किमी. से बढ़कर 1.44 किलोमीटर से ज्यादा हो गई, रेल मार्गों का 21.614 किमी. हिस्सा इलैक्ट्रिफिकेशन बढ़कर 58.812 किमी. तक पहुंच गया है ।

दरअसल हमारी सरकार विकसित भारत के चार स्तंभीय युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त करने हेतु तन मन धन से

प्रयासरत है । हमारे प्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल के विगत 10 साल का कार्यकाल इस शताब्दी का स्वर्ण युग है । हमारी सरकार ने शुरू से ही तुष्टीककरण की राजनीति नहीं की कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी सम्प्रदा हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के मिले । हमारी सरकार ने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और परिवार वाद के साथ कभी समझौता नहीं किया है । हमारी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की नीति से आज जो एक रूपया आम जन को भेजा जाता है वह पूरा का पूरा रूपया उस तक पहुंचता है न कि पहले की सरकारों की तरह केवल 15 पैसे विगत दस सालों में सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए हमारी सरकार के सतत व समर्पित प्रयासों से विगत 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना संभव हो पाया है । यदि विगत की सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास किया होता तो 2014 में शासन की बागडोर संभालते हुए हमारी सरकार को 80 करोड़ लोग निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हुए नहीं मिलते ।

हमारी सरकार ने देश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं । चाहे वह महिला हो अथवा आदिवासी उत्थान आज यदि एक आदिवासी महिला विश्वव की सबसे बड़े लोकतंत्र की महामहिम राष्ट्रपति है तो एक दूसरी महिला विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था की एक सफल वित्त मंत्री साबित हुई हैं । आज भारत के पासपोर्ट वाले हमारे नागरिक जिस भी देश में पहुंचते हैं उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है । मुस्लिम महिलाओं को अब तीन तलाक का शिकार नहीं होता । सरकार ने तीन तलाक हटाकर देश की 14-20 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम किया है ।

महिलाओं की स्थिति में आज जितना सुधार हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, चाहे वह घरूलू गैस हो अथवा पेय जल आपूर्ति । प्रधान मंत्री शहरी व

ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हें और आगामी साल में दो करोड़ घर और उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है । यह हमारी ही सरकार है जिसने संसद में विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है । सैल्फ हैल्प ग्रुप के माध्यम से व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने की घोषणा बनाए जाने का निर्णय प्रशंसनीय है तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मील का पत्थर साबित होगा ।

यह हमारी ही सरकार है जिसने गरीबों को दरिद्र नारायण समझते हुए उन्हें ईश्वर के समतुल्यी मानते हुए उनके विकास के लिए सैंकड़ों योजनाएं लाकर गरीबी को हटाने का कार्य किया है और उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विगत दस सालों की अल्प कालावधि में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं तथा इस दिशा में सतत प्रयास जारी है ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर) : महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण का मैं हृदय से समर्थन करता हूं ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह परिलक्षित होता है कि केन्द्र सरकार ?सबका साथ सबका विकास? के अपने वायदे के अनुरूप देश को तेजी से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है । यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के लाडले प्रधान मंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में देश के गरीब, दलित और आदिवासी समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं । पिछले एक दशक के दौरान हजारों आदिवासी गांवों को बिजली और सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के विकास पर केंद्रित है और आदिवासी परिवारों में सिकल सेल

एनीमिया से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है । अब तक 1.4 करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है । राष्ट्रपति जी ने इसका उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है, जो प्रशंसनीय है । केन्द्र सरकार ने आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक बढ़ाया है । इसका जिक भी राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है, जो स्वागतयोग्य है ।

राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में शिक्षा के बारे में उल्लेख किया है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 14,000 से अधिक पीएम श्री स्कूलों पर काम कर रही है । इनमें से करीब 6,000 ने काम करना शुरू कर दिया है तथा शिक्षा में ड्रॉपआउट दर कम हुई है । एससी और ओबीसी के छात्रों का नामांकन 44 प्रतिशत तथा एसटी के छात्रों का नामांकन 65 प्रतिशत बढ़ा है । देश में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया है । राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में श्रम कौशल विकास के बारे में बताया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 करोड़ रुपये का गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान किया गया है और पीएम-विश्वकर्मा के तहत 84 लाख कारीगरों को लाभ मिला है, जो प्रशंसनीय है ।

राष्ट्रपति महोदया ने कृषि एवं खाद्य के संबंध में अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है । इसे पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है तथा किसानों को अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं और पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपये के क्लेम मिले हैं । किसानों को पिछले एक दशक में धान और गेहूं के एमएसपी के रूप में 18 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जो 2014 से पहले के 10 वर्षों में भुगतान से 2.5 गुना अधिक है । तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं और पिछले एक दशक में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए 11 लाख

करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं तथा मछली उत्पादन 95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन हो गया है । मत्स्य पालन में निर्यात दोगुना हो गया है । यह भी हमारे लाडले प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धि को दर्शाता है ।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य के बारे में यह भी बताया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे नागरिकों को लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली है और कोरोनरी स्टेंट, घुटने के प्रत्यारोपण और कैंसर की दवाओं की कीमतें कम कर दी गई हैं । इससे मरीजों को सालाना लगभग 27,000 करोड़ रुपये की बचत हो रही है तथा 16 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं । एमबीबीएस की सीटें दोगुनी से ज्यादा हो गई हैं । राष्ट्रपति महोदया ने शहरी एवं ग्रामीण व्यवस्था के बारे में बताया है कि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 5 से 20 शहरों तक हो गया है तथा 4.1 करोड़ गरीब परिवारों के पास अपना पक्का घर है, जिसकी कीमत लगभग छह लाख करोड़ रुपये है और लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच गया है । इस पर करीब चार लाख करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं एवं 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच की समाप्ति से कई बीमारियों पर रोक लगी है, जो प्रशंसनीय है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रपति महोदया ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किए जाने का उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है और यह भी बताया है कि लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं । इन समूहों को आठ लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण और 40,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई है । महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ हुआ है । यह हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री

नरेन्द्र मोदी जी की उपलब्धियों को बताता है । राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में यह भी उल्लेख किया है कि 10 साल में पूंजीगत व्यय पांच गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 90,000 किमी से बढ़कर 1. 46 लाख किमी हो गई है । चार लेन राजमार्गों की लंबाई 2.5 गुना बढ़ गई है और 25,000 किमी से अधिक रेलवे ट्रैक बिछाए गए । भारतीय रेलवे सौ प्रतिशत विद्युतीकरण के करीब है और 39 से ज्यादा रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं तथा प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो गई है । हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 149 हो गई है । उड़ान योजना के तहत लोगों ने हवाई टिकटों पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये की बचत की है तथा ब्रॉडबैंड यूजर्स 14 गुना बढ़ गए हैं ।

अंत में मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण का हृदय से समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Thank you for giving me an opportunity to express my view on the Motion of Thanks to the President Address. Article 87 of the Constitution provides two instances when the President specially addresses both the Houses of Parliament. The President of India addresses both the Rajya Sabha and the Lok Sabha at the beginning of the first Session after each General Elections when the reconstituted Lower House meets for the first time. The President also addresses both the Houses at beginning of the first Session of each year.

The President's Address essentially highlights the Government's policy priorities and plans for the upcoming year. The

Address provides a broad framework of the Government's agenda and direction. The President?s Address recognized the challenges pertaining to development that are faced by remote and faraway islands like Andaman & Nicobar and how development of modern facilities on the islands which include roads, air connectivity and high-speed internet facilities are required. The President also highlighted the immense potential of tourism in Andaman and Nicobar Islands which can only be improved through investment and increase in budget for Andaman & Nicobar Islands.

Andaman and Nicobar Islands will be a huge contributor to the 5 trillion Dollar economy target due its unexplored potential and resources in the area of fisheries, adventure sports and tourism.

In order to ensure a holistic growth for Andaman and Nicobar Islands, I would want to put forward the following suggestions and demands before the Government: Increasing the budget of Andaman and Nicobar Islands from Rs. 5,987 crore to Rs. 25,000 crore as one time investment to develop infrastructure so that the Islands start generating their own revenue and do not need to depend on Central Government rather contribute to the Central Government revenue; to fill up all the 10,000 vacant posts of Andaman and Nicobar Administration through the youths of the Islands and stop online recruitment; to create more jobs and promote tourism through marine, adventure, culinary, eco, World War-Il tourism and cultural tourism along with the establishment of Freedom Struggle tourism at various places in Andaman and Nicobar Islands; emphasis on fisheries sector that need creation of more cold storage chain, facilities to export fish

products from the Islands, deep sea fishing, generation of employment through Information Technology Infrastructure in Andaman and Nicobar Islands by creating IT Park ? a separate Island to be earmarked, creation of call centres, BPOs, data centres, and laying second OFC cable from Diglipur to Puri; construct India's biggest ship building and ship repairing dry dock in the Islands to generate employment and revenue; need to establish a Legislative Assembly for Andaman and Nicobar Islands on the lines of Delhi and Puducherry; creating Andaman and Nicobar Public Service Commission for the Islanders; starting PG Courses in Medical College so that the local doctors do specialization courses and serve the Islanders; providing facilities for cardiac, biliary and neuro treatment at par with mainland; commissioning super specialist Doctors from New Delhi to Andaman and Nicobar Islands on deputation; demand for constructing trauma centre, ultra sound machine in PHC and purchasing of modern ambulance for all the Islands; air ambulance for providing better facilities to residents of Andaman and Nicobar Islands; constructing bridge from Chatham to Bamboo flat; constructing bridge between Minni Bay to Mithakhari; increasing the pension of old age, widow, destitute and *divyang* from Rs. 2500 to Rs. 5000; starting air connectivity from Port Blair to Madurai, Port Blair to Kochi, Port Blair to Ranchi, and vice versa; giving air subsidies to the Islanders in terms of North-Eastern States and start night flight from the Islands; purchasing three new aeroplanes ? it Boeing 737 with 180 Pax capacity ? for the Andaman & Nicobar Administration for the welfare of the Islanders as well as to develop tourism and trade which will boost the economy of the Islands; increasing the salary of Anganwadi and ASHA workers;

regularizing all 902 Casual and DRM's working in Port Blair Municipal Council; regularising the service of all contract and casual workers in Andaman and Nicobar Administration; providing unemployment allowance of Rs. 3000 to the youths of Andaman and Nicobar Islands; installing a desalination plant to solve the water crisis; constructing one more dam apart from Dhanikhari Dam; Construct Dam at Khudirampur (Diglipur), Parnasala (Rangat); early start of second phase of Rutland water project; early start of Flat Bay water project; resettling and rehabilitating Katchal Tamil settlers; establishing a Central University in Andaman and Nicobar Islands instead of deemed university; providing adequate compensation or return the land that was submerged as a result of the disaster to the victims of 2004 Tsunami in Andaman and Nicobar Islands; providing FM radio throughout Andaman and Nicobar Islands; establishing a separate commission for women for Andaman and Nicobar Islands; creating a women's college and a fisheries college; early start of International flights from Port Blair to South Eastern countries to generate tourism and socio economic development; regularizing all the left out cases of land of Pre 1961; providing 5 acres of land to the extended families of Pre 1942 and settler categories; providing 200 sq. metre of land to all landless Islanders; regularizing all the encroachment prior to 2012; providing more funds to PRIs and Municipal Council; resuming flight from Port Blair to Car Nicobar and vice versa; connecting Shaheed Deep, Neil Island, with OFC cable; early start of procuring copra at MSP rate; bringing paddy and areca nut under MSP; early completion of the National Highway in the Islands; sanctioning two numbers of Sainik Schools, one at Diglipur and the other at Campbell Bay; constructing a world class

cricket stadium in Andaman and Nicobar Island; promoting sports along with necessary infrastructure to promote other sports like Football, Cycling and swimming; constructing a playground and gymnasium at all 70 Panchayats and 24 Municipal wards including tribal areas; and constructing a new jetty at Shoal Bay to promote tourism.

I request the Government to kindly consider these requests and constitute a committee which will analyse the potential of Andaman and Nicobar Islands and propose an investment plan to boost the economy.

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): महामहिम राष्ट्रपति जी का 2024 का यह अभिभाषण कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है । सर्वप्रथम हम हमारे इस महान भारत देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे और हमारी सरकार, जो 2014 से प्रयासरत है कि वह महात्मा गाँधी जी, बाबा साहेब आंबेडकर जी, सरदार पटेल जी, दीन दयाल उपाध्याय जी, मदन मोहन मालवीय जी जैसे महापुरुषों के सपनों का जो भारत है, उसका निर्माण करे और आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है, उसकी पूर्ती के लिए कार्य करें । अपने अभिभाषण के माध्यम से राष्ट्रपति जी सरकार की प्राथमिकता, योजनाएं और आगामी समय में देश के विकास के लिए किस प्रकार कार्य करेगी उसका विवरण करते हैं ।

आज कांग्रेस हो या कोई और विपक्षी दल, ये अपना वक्त और पूरा जोर सिर्फ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की निंदा करने में लगा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सरकार की हर एक उपलब्धि को तथ्यों और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

एक दशक पहले देश में केवल कुछ सौ स्टार्ट-अप थे, जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए हैं । दिसंबर 2017 में, 98 लाख लोग GST देते थे, आज इनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख है । 2014 से पहले के 10 वर्षों में, लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे । पिछले 10 वर्षों में, देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं । 2014-15 में, लगभग 2 हज़ार इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे । जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं ।

बीते दशक में, सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है । इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं । इस दौरान देश को Insolvency and Bankruptcy Code मिला है । देश को GST के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है । 10 वर्षों में, कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है । साथ ही, फिस्कल डेफिसिट भी नियंत्रण में है । आज हमारे फोरेक्स रिज़र्व 600 अरब डॉलर से ज्यादा हैं । हमारा बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था, वह आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है । बैंकों का NPA जो कभी डबल डिजिट में होता था, वह आज लगभग 4 प्रतिशत ही है । मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुके हैं । भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है ।

सरकार ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता को लाभ पहुंचाया है । जैसे जन-धन योजना में करोड़ों नए बैंक अकाउंट खोले गए, जिसने आर्थिक समग्रता को बढ़ावा दिया, आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक लाभकारी योजना है जिससे गरीब परिवारों को इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी । जन औषधि केंद्र की माध्यम से सस्ती दवा देश और बाहर दी जा रही हैं । बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से देश की बेटियों की शिक्षा के महत्त्व और इस संवेदनशील मुद्दे पर जागरूकता बढ़ी है । उज्ज्वला योजना में करोड़ों महिलाओं को गैस सिलिंडर दिए गए हैं, जिससे उनका सशक्तिकरण हुआ है । प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए मकान बनाये गए हैं, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ने स्वरोज़गार के लिए अवसर

बनाये हैं और GST के कार्यान्वन से एक देश एक टैक्स का सपना साकार हुआ है ।

देश की जनता के हित में हमारी सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास की विचारधारा का पालन करते हुए देश के समग्र विकास के लिए कार्य किया है ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से आने वाले वक़्त में हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, रोज़गार, किसान कल्याण और युवाओं के लिए अवसर जैसे विभिन्न मुद्दों पर व्यापक कार्य करने हैं, जिससे हम महात्मा गाँधी के भारत का निर्माण कर सकें और हर समुदाय का विकास करते हुए इस महान देश को आगे ले जा सकें ।

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पूरा समर्थन करता हूँ ।

***m72 SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. When we analyse the problems relating to socio, economic and political spheres of life during the last 10 years, it gives a clear picture about the stature of the present government. This Government has come to power in a democratic manner. But they have come to power after learning how to ignore democracy. Their Guru Golwalkar had only taught them not to accept democracy. It is clearly evident from the experience which we have had during the last 10 years that they do not wish to accept democracy. They mention at the very beginning that they aspire for an India which is free from Congress. If they come to Tamil Nadu, they raise voice in such a fashion expressing their desire to see Tamil Nadu without Kazhaghams (Parties). They are disgusted with the concept of opposition parties. In a democratic setup, opposition parties are very much need and a necessity as well. But those who think that the opposition parties should never exist are not qualified to be our rulers in a democratic set-up. They are the ones who are ruling us today.

ED, CBI and other such agencies are being misused by the Government as instruments to fulfil their political vendetta. These agencies are being used as weapons to take revenge against the opposition parties. This again is experienced by us. I want to say something about our economy. This Government talks high about being self-reliant. But during the last 10 years, India has been subjected to loot by way of FDI. What is happening in the Dandakaranya forests today? Vedanta started exploiting the limitless and abundant natural resources of that area. Many other foreign companies have also started exploiting these natural resources. Through this, all our natural resources have been looted by foreigners during last ten years. Similarly, what happened to our Indian markets? Foreign products have taken control over our Indian markets with the help of the present day Government. That?s why I say our villages are becoming vacant places. Farming, which is the livelihood of rural areas, has completely been ruined. Rural economy has been shattered. As a result of this, labourers have started migrating towards cities from villages. Rural areas have been emptied and agriculture has been ruined under the present Government. I searched throughout this President's Address using a magnifying glass to find a mention about labourers. But I could not find any such mention. Even our Prime Minister, in this Independence Day Address and in various other speeches has time and again mentioned that Adanis and Ambanis are the creators of social wealth. I don?t know from where he learnt these economic lessons. Are the Ambanis and Adanis-the wealth creators? In fact, labourers and farmers are the real creators of social wealth. They are the actual Gods and Brahmas who created this social wealth. But this government has not accepted

them. That is why the rights of labourers acquired by them after 100 years of long struggle have been snatched away by this Government in a cruel manner. This seems to be a government which is anti-labour. Similarly, they said 'good days will come'. Have you seen any such ?good days?? Do they have any moral responsibility to stand under the motto, 'Satyameva Jayate'? They said ' good days have come'. I will cite an example of good days of the then UPA Government. When Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister, sugar was sold in ration shops at the rate of Rs. 12.50 per kg.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI K. SUBBARAYAN: I will conclude in two minutes Sir.

I want a reply from the ruling side. When the government led by Dr. Manomhan Singh was in power, cost of one kg sugar in ration shops was Rs. 12.50. But this has gone up to Rs. 25 per kg during the rule of present Government who promised to bring ?good days?. Is that a sign of good governance? I have a long list of such statistical things to share with you to prove how this present Government has failed in all spheres of life, be it political, economic or social. They are unfit to rule. There are so many examples to cite. I cannot explain in one or two minutes. Just because of the reason I am unable to explain it fully due to paucity of time, those in the Government will overpower in their summarising speech at the end. They think that they can conduct the government by bulldozing everything. I want to remind you that it is a cyclic process. This Government will be soon taught a lesson by the people. During the 2024 election, the results will not be in favour of the present Government. Vanakkam.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Thank you very much Chairman, Sir. I strongly oppose the Motion of Thanks.

Sir, the Amrit Kaal of India has become Mrityu Kaal for our Constitution. All the cardinal principles of the Constitution are being gradually and systematically undermined in India. The rule of law has been selectively ignored, the power structure has become increasingly oligarchic, and individual freedoms are muzzled. Moreover, federalism, a vital principle of Constitution designed to obviate the concentration of power in a few hands, has been practically nullified in India.

The Judiciary and the fourth-branch institutions like the Election Commission of India and the Central Information Commission are substantially enfeebled. Parliament has been reduced to an ornamental institution for mechanical law-making. The Press and civil society are systematically weakened. When the Constitution completes 74 years of its existence, the arch-operators of the Constitution are transmuting it into an empty shell apparatus.

The consecration of the Ram Temple by the Prime Minister and other high dignitaries of State marks the virtual demise of the secularism of the Indian republic. The painful demise of secular India occurred on 22nd January. It is also the death anniversary of George Jacob Holyoake, an English writer, editor, and coiner of the word "secularism". Sir, when K.M. Munshi, who spearheaded the reconstruction of the Somnath Temple, approached Dr. Rajendra

Prasad, the then President of India, to inaugurate the newly-reconstructed temple and ceremoniously install the jyotirlingam, Dr. Rajendra Prasad replied positively.

But he added: "I would do the same with a mosque or a church if I were invited.? This is the core of Indian secularism. Our State is neither irreligious nor anti-religious. However, Prime Minister Shri Modi in his speech at Ayodhya made no consoling reference to the masjid demolished for building the temple, nor did he say anything about the reconstruction of the masjid at another site. This marks a fundamental deviation from secularism. Mr. Prime Minister lacks Dr. Rajendra Prasad's secular tenderness.

Sir, the Indian Republic has its unique majestic temple - its Constitution. The Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy are the temples of twin *shikharas*. Socialism, secularism, and democracy are the *mandapas* that provide space for all the devotees of the Republic. The Preamble is the *garbhagriha* for housing the deity. The concept of justice (social, economic, and political) is the *vigraha* installed therein. Liberty, equality, and fraternity are the three holy vestibules leading toward the deity, that is, justice. The Prime Minister of the Republic is supposed to be the priest of this temple and this temple only.

Sir, while India's new National Flag was unfurled for the first time at the India Gate on 15^{th} August, 1947, a rainbow formed on the horizon. It symbolised the newly born rainbow nation, displaying the cultural diversity that evolved from millennia of civilisational

osmosis. Sir, alarmingly, this rainbow has nearly faded during the Prime Ministership of Shri Narendra Modi.

Thank you very much, Sir.

-

15.00 hrs

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): सभापति महोदय, सत्रहवीं लोक सभा के इस अंतिम सत्र में नये संसद भवन में, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने और अपना समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, हम विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहे हैं । भारत का यह अमृतकाल चल रहा है । जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो देखने में आता है कि जिस तरह से सभ्यता का क्रमिक विकास होता है, उसी तरह से देश की आजादी के बाद हमारे देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के इस दस साल के कार्यकाल में तेजी के साथ विकास करने का क्रम प्रारंभ हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि एक इतिहास रचने का काम वर्तमान प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है । भारतीय जनसंघ के समय के जिस प्रण को लेकर जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का जो सफर है, उसको पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक तेज गति के साथ किया है । उस समय के कार्यकाल में आजादी के बाद देश में कृषि को बढ़ावा न देकर उद्योग को बढ़ावा दिया गया, जबकि हम कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है । हमने उस समय कृषि पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम अनेक तरह की झंझावातों में फंसे

रहे और देश काफी पीछे रहा । आज मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्रता के बाद जिस तेजी के साथ भारत का दृश्य बदला है, मुझे वे दिन याद आते हैं । यदि मैं वर्ष 1975 से लेकर आज तक के दृश्य को याद करूं तो देखने को मिलता है कि किसान की क्या हालत थी? गांव के मजदूर की और महिलाओं की क्या हालत थी? गांव की सड़कों की, पानी तथा अन्य सारी चीजों की क्या हालत थी? उस समय नेता ?गरीबी हटाओ? का नारा देते थे और नारा देकर चार चुनाव जीत लिये । 15 परसेंट पैसा गांव तक पहुंचता है और यह बोलने वाले भी तत्कालीन प्रधान मंत्री होते थे ।

सभापति महोदय, अब आप देखिए कि किस तरह से मोदी जी ने इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किस तेजी के साथ सारे काम को करने का प्रयत्न किया है । जब हम कहते हैं कि ?मोदी है तो मुमकिन है? तो इतने कम सालों में, दस सालों में कितने बड़े-बड़े काम करने का काम किया है । चाहे तीन तलाक का कानून हो, चाहे धारा 370 हटाने का काम हो, चाहे नागरिकता देने का काम हो, वन रैंक, वन पेंशन, वन नेशन, वन राशन कार्ड, 76 कानूनों को हटाना, गुलामी के काननूों को समाप्त करना, सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाना, मेरी माटी, मेरा देश जैसा कार्यक्रम बनाकर सभी को एकजुट करना, 16 करोड़ लोगों के साथ तिरंगे की सेल्फी लेकर दिखाना कि एक आवाज में कैसे सारा देश एक है । नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाना, जी-20 का सफल कार्यान्वयन और सबसे बड़ी बात आतंकवाद और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया । इस तरह से सारे देश को एक रक्षा सूत्र में बांधने का काम किया ।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा, जैसा अन्य वक्ताओं ने भी कहा है, वैसे ही मैं भी कहना चाहता हूं कि सभ्यता का एक क्रमिक विकास हुआ है । मोदी जी के दस साल के कार्यकाल में ?गरीबी हटाओ? केवल नारा नहीं रहा, बल्कि गरीबी हटाने के लिए हकीकत में जमीनी स्तर पर काम किया गया । पहले जो भ्रष्टाचार की जड़ थी, जैसा तत्कालीन प्रधान मंत्री कहते थे कि 100

में से केवल 15 परसेंट पैसा ही लाभार्थी तक पहुंचता है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने सबसे पहले जन-धन खाता खोलकर लोगों के खाते में पूरा पैसा देने का काम किया । उसके कारण आज भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है ।

गरीब महिलाओं को 11 करोड़ शौचालय बनाकर देने का काम किया गया, जिसके बारे में कभी विचार नहीं किया जाता था । 4 करोड़ आवास देने का काम किया गया, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने का काम किया गया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस देने का काम किया गया और 11 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया गया । इस तरह से गांव के गरीब की किस्मत को बदलने का काम प्रारंभ किया गया । इतना ही नहीं गांव के गरीब व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाएं तो उनके लिए चिकित्सा सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड बनाकर देने का काम किया गया । इसके साथ एक नई योजना, जब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में गए तो एक स्टॉल हमेशा लगा मिला, जिसे प्रधान मंत्री जी ने लगवाया, उसमें 11 प्रकार की जांच ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही थी । हमारे सीएचओ गांव में जांच कर रहे हैं, यानी कल तक जब कोई बीमार पड़ता था और प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जाता था तो 200-400 रुपये की फीस लगती थी और दवाई का पैसा लगता था । गरीब इलाज के अभाव में मर जाता था । इलाज नहीं करवा पाता था और परेशान होता था ।

सभापति महोदय, पूरी जांच कराकर सारी बीमारियों की पहचान करने का काम किया गया, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, सर्वाइकल कैंसर की बात हो, टीबी जैसी बीमारी की जांच हो या उसको खून की कमी हो, सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है । हमारी बहनों की गर्भावस्था की जांच, इस तरह की 11 प्रकार की जांच गांव में करके देने का काम यदि आज तक कभी किसी कार्यकाल में हुआ है तो वह हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, जिसके बारे में गरीब कभी सोच ही

नहीं सकता था । गरीब को पांच लाख रुपये तक का इलाज कराने की सुविधा आयुष्मान कार्ड देकर की गई है ।

सभापति महोदय, जब आदमी को दो पैसे कमाने की आवश्यकता पड़ी, तो स्वयं सहायता समूह बनाकर लोगों को काम दिया । ?नमो ड्रोन दीदी योजना? दी । तीन करोड़ बहनों को ?लखपति दीदी? बनाने की योजना पर काम किया है । एक करोड़ बहनें लखपति बन गई हैं और एक करोड़ बहनों का लक्ष्य फिर बढ़ा दिया है । इसका मतलब है कि हम तीन करोड़ बहनों को ?लखपति दीदी? बनाने का काम करेंगे ।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में एक और बड़ा वर्ग आता है, जिसको हम नाई, धोबी, कुम्हार, कहार, लोहार, चर्मकार, वंशकार इत्यादि कहते हैं । ये उस वर्ग के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में धंधा करते हैं और जिनका राजनीति से दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं होता है । उनकी राजनीतिक पहुंच भी नहीं होती है । ऐसे लोगों की पहचान करके, उन लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से 500 रुपये देना, उनको एक, दो या तीन लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देना चाहिए, ताकि उनको समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके । यदि किसी ने उनको सम्मान के साथ जीवन जीने पर विचार किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है ।

सभापति महोदय, मुद्रा लोन देकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ दिया है । ग्रामीण लोगों को गरीबी से उभारकर सम्मान के साथ समाज के समक्ष खड़ा किया है । उसी का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं । हम आज केवल ?गरीबी हटाओ? का नारा सुनते थे, मैंने अपने जीवन में केवल ?गरीबी हटाओ? का नारा सुना है । आज पहली बार प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उनके साथ काम करके खुशी होती है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है ।

सभापति महोदय, मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं । जब मैं पिछली सरकारों को देखता था, मैं मध्य प्रदेश राज्य से आता हूं, मैं वहां देखता था कि किसान को 18 प्रतिशत ब्याज पर लोन मिलता था । आज कांग्रेस पार्टी के लोग किसानों के नाम पर बड़ा रोना रोते हैं और आंसू बहाते हैं । वे किस तरह से उनको बेइज्जत करते थे । कुर्की-डिक्री होती थी । उनकी गाय, भैंस और बकरी को ले जाते थे । घरों के कुंडी-घघरी तक उठाकर ले जाते थे । गांव के लोग अपना बैल या जानवर बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगलों में रहते थे । कुर्की-डिक्री करके उनकी बेइज्जती करते थे । उनके बेटे-बेटियों की शादियां नहीं होती थी । मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद उनको जीरो प्रतिशत पर ब्याज दिया गया । आदरणीय मोदी जी ने सम्मान निधि देकर किसान को सम्मान देने का काम किया है । मैं आज कह सकता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में सिर्फ सवा साल का कार्यकाल छोड़ दें, तो वहां बीस सालों में किसी भी किसान की कुर्की-डिक्री नहीं हुई है और उसको अपनी जमीन से वंचित नहीं होना पड़ा है । यह हमारी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी की सरकार में किसानों का सम्मान हुआ है ।

सभापति महोदय, आज मोदी जी जिस तरह से चाहते हैं, उनका प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर है, क्योंकि जीवन को बचाने का काम करना है । आप भी डॉक्टर हैं । मैंने भी अपने जीवन में 15 सालों तक प्रैक्टिस की है । हम जानते हैं कि यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भोजन अच्छा नहीं होगा, यदि वह जैविक नहीं होगा, हमने अन्न उत्पादन करने और फसल बढ़ाने के लिए जिस तरह से पेस्टिसाइड्स और डीएपी यूरिया का मनमाने तरीके से दुरुपयोग किया है, आज वही हमारे लिए काल बन गया है । उसके कारण नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं । इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं कि हम पहले प्राकृतिक खेती करते थे, जिस तरह से मक्का, रागी, कोदो, कुटकी पैदा करते थे, आज जिसको मिलेट्स कहते हैं, वह सबसे अच्छा अन्न है । आज मोदी जी देश के सभी किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि उसका उत्पादन करें ।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, चाहे किसानों को आगे बढ़ाने की योजनाए हो, चाहे सुलभ ऋण देना हो, चाहे उनके घरों में बिजली देना हो, ये काम किए गए हैं । युवाओं के लिए ?स्टार्ट-अप इंडिया? और ?स्टैंड-अप इंडिया? योजना है । ?पीएम विश्वकर्मा योजना? है, ?खेलो इंडिया योजना? बनाकर लोगों को लाभ दे रहे हैं । ?नारी शक्ति वंदन अधिनियम? पास किया गया है ।

सभापति महोदय, मैं कल हमारे मित्र को सुन रहा था, आज वे बैठकर रो रहे हैं । वे जरा यह भी याद कर लें कि उन्होंने शाहबानो प्रकरण में क्या किया था । वे दूसरों को उपदेश न दें । वे पहले अपनी पीठ देख लें, क्योंकि शाहबानों प्रकरण में कानून बदलने तक का काम किया गया था । आज मोदी जी के कार्यकाल में नारी शक्ति को सम्मान मिला है । उनको राजनैतिक रूप से भी 33 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा । नारियों के सम्मान के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं सड़कों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा । हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जहां हम पहले देखते थे कि चलने के लिए न तो सड़क है, न ही बिजली है, न ही पानी है और न ही शिक्षा है, आज कितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है । मेरे यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय एक सड़क बननी थी, जिसे नहीं बनने दिया गया । उसको 10 सालों तक रोककर रखा गया । जब श्री मोदी जी प्रधानमंत्री और आदरणीय गडकरी जी मंत्री बने, तब पहली बार एशिया का ऐसा पहला साउंडप्रूफ ब्रिज बनाया गया है, जिसके नीचे से पेंच नेशनल पार्क के पशु-पक्षी जाते हैं । उसके ऊपर सारा ट्रैफिक चलता है ।?(व्यवधान) इस तरह का काम किया गया है । मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

डॉ. ढालसिंह बिसेन : सभापति महोदय, अटल जी के समय पर रेल बनाने की घोषणा हुई थी । वह कभी नहीं हुआ ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. ढालसिंह बिसेन जी, अभी बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है ।

? (व्यवधान)

डॉ. ढालसिंह बिसेन : सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जिले और मेरी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार बड़ी रेल लाइन बनी है, जिसके कारण आज लोग खुश हैं । सन् 1998 से 2003 के बीच में आदरणीय अटल जी ने घोषणा की थी । श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे क्षेत्र के लोगों ने बड़ी रेल लाइन को देखा है । इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हमारी संस्कृति की विरासत को बचाने का काम भी किया गया है । ? (व्यवधान)

मैं राम मंदिर की बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा । राम मंदिर के लिए हम भी जेल गए थे । मैं उस समय विधायक था । हमारी सरकार उस समय गिरा दी गई थी । आज राम मंदिर को बनाकर देश के करोड़ों देशवासियों का सम्मान बढ़ा है और संस्कृति बची है । इस तरह से आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के कार्यकाल में यह सब संभव हुआ । मैं बस एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । हम जिस तरह से नागरिक होने के कर्त्तव्यों को निभाते हैं, उसके लिए एक बात कहते हुए मैं कहूंगा कि ? ?देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें? । इसलिए हम भी अपने नागरिक होने का कर्त्तव्य निभाते हुए वर्ष 2047 का विकसित भारत बनाने में अपना पूर्ण योगदान करेंगे । इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Nama Nageswara Rao.

We are short of time. आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिएगा ।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : ऑनरेबल चेयरमैन, हम तो पहले आदमी है और हमारे आठ मैंबर्स हैं, लेकिन हम पार्टी से अकेले बोलने वाले हैं ।

माननीय सभापति : आप बोलिए, लेकिन समय से बोलिए ।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President?s Address. अभी 75 साल कम्प्लीट हो गए हैं । पिछले 75 साल में क्या-क्या हुआ, प्रेसीडेंट ने उसको बताते हुए, इन दस साल में क्या हुआ है, वह बताया है । उसके बारे में 32 पेज की बुक पार्लियामेंट मैंबर्स को मिली है और ये सब उन 32 पेजों पर उल्लेख किया गया है । उस बुक में पेज नंबर चार पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना के बारे में बताया गया है । इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने पिछले 20 सालों से फाइट की है । मैं 15^{th} लोक सभा में भी मैंबर ऑफ पार्लियामेंट था । उस समय खम्मम डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए हमने फाइट की थी । एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जब स्टेट डिवाइड हो रहा था, उस समय हमारे नेताजी केसीआर साहब और हम लोगों की डिमांड थी, उसकी वजह से वर्ष 2014 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह रखा गया था, लेकिन उसको कम्प्लीट करने में दस साल लग गए हैं । पेज नंबर 6 पर नीति आयोग के बारे में उल्लेख करते हुए कहा गया कि 25 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट किया गया है । हमारा देश बहुत बड़ा है । हमारा देश 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है । यह बताया गया कि 25 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट किया गया है । अगर हम लोग परकैपिटा इनकम के बारे में देखें तो हम वर्ल्ड में बहुत पीछे हैं ।

परकैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना है, उसके बारे में नहीं बताया गया है ।

सर, हम लोगों की जीडीपी अभी सिंगल डिजिट में है । जब तक जीडीपी डबल डिजिट में नहीं जाएगी, इस कंट्री को डेवलपमेंट के लिए काफी टाइम लगेगा । चाइना हम लोगों से पीछे था, लेकिन पिछले 30 सालों में चाइना बहुत आगे बढ़ गया है और वह डेवलप्ड कंट्रीज में आ गया है । पेज नंबर 14 में नेशनल हाइवेज़ के बारे में बात की गई थी । हम लोगों को नेशनल हाइवेज़ को जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए । देश में काफी नेशनल हाइवेज़ बन गए हैं । ईवन, हमारी कॉन्स्टीट्यूवेंसी में पिछले पांच सालों में खम्मम से सूर्यपेट, खम्मम से नागपुर, खम्मम से राजमुंदरी, खम्मम से अमरावती हाइवेज़ बने हैं । इसी तरह से पूरे देश में नेशनल हाइवेज़ काफी बढ़े हैं । रीज़नल रिंग रोड में हैदराबाद एक ही सिटी है और इंडिया में आउटर रिंग रोड़ कंप्लीट हो गया है और रीजनल रिंग रोड भी हम लोगों ने कम्प्लीट करवा लिया है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अहमदाबाद में भी रिंग रोड है ।

श्री नामा नागेश्वर राव : सर, पेज नंबर 13 में यह बात उल्लेख थी कि पाइप्ड वाटर पहली बार 11 करोड़ लोगों को दिया है । ड्रिंकिंग वाटर में पहला स्टेट था, जब हमारे नेता केसीआर साहब मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने पूरे तेलंगाना को मिशन भागीरथ से पहली बार घर-घर पानी दिया था । इसी पार्लियामेंट में बहुत दफा क्वेश्चन किया गया था और इसी पार्लियामेंट में यह बात भी एग्री की गई है कि केवल उसी स्टेट ने सौ प्रतिशत ड्रिंकिंग वाटर दिया है । मिशन भगीरा को आपने ?हर घर जल? बना दिया है । यह बहुत अच्छी स्कीम है । इसमें गरीब लोगों को पानी मिलना चाहिए । पेज नंबर 17 पर किसान के बारे में उल्लेख किया था । हम भी किसान के बेटे हैं । गरीबी क्या होती है, विलेज क्या होता है और विलेज में क्या दिक्कत होती है, यह सब हमने अपनी आंख से देखा है । पीएम साहब ने पीएम सम्मान निधि के नाम से 6000 रुपये

किसानों को देने के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा है । लेकिन हमारे नेता केसीआर साहब ने देश में पहली बार रायथु बंधू नाम से प्रति एकड़ हर किसान को दस हजार रुपये देने का काम किया है । उसी को आप लोगों ने कॉपी किया है । लेकिन हम लोगों ने यह सोचा था कि इसे 6000 रुपये की बजाय दस हजार रुपये देंगे । अगर आप यह देंगे तो अच्छा होगा । इस पर आपको सोचना चाहिए । ऑयल सीड्स के बारे में भी कहा गया है । मलेशिया और इंडोनेशिया से हम पॉम ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं । पॉम ऑयल के किसान हमारी कंट्री में भी हैं । मेरी कांस्टीट्यूएंसी में भी काफी पॉम ऑयल के फार्मर्स हैं । पूरे देश में खम्मम डिस्ट्रिक्ट में पॉम ऑयल सबसे ज्यादा होता है । पॉम ऑयल का किसान आज के दिन काफी परेशान हो रहा है । इंडोनेशिया और मलेशिया में एक-एक फार्मर पांच हजार एकड़ डालता है । वह कॉर्पोरेट फॉर्मिंग करता है । हमारे यहां छोटे फार्मर्स हैं । दो, तीन, पांच और दस एकड़ में डालने की वजह से वे उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए उसको एमएसपी देनी चाहिए । पहले से पॉम ऑयल का रेट काफी गिर गया है । इसमें ऑयल सीड्स और फार्मर्स के बारे में मेंशन किया गया है । पॉम ऑयल के किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए एमएसपी देनी चाहिए । इसके साथ ही यह बताया गया कि 2.5 परसेंट एमएसपी में पिछले दस साल में इंक्रीज़ हुआ है । यह सच बात है कि 2.5 परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, मगर उससे ज्यादा सभी चीजों की महंगाई बढ़ गयी है, जिसकी वजह से किसान का एमएसपी अब बहुत कम लगता है । उसको बढ़ाने का काम करना चाहिए । उसी के साथ-साथ रिवर लिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है । वाजपेयी जी के टाइम पर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था । पिछले 20 साल से कंट्री में एक तरफ बाढ़ होती है तो दूसरी तरफ सुखाड़ होता है, जिसकी वजह से कंट्री बहुत दिक्कत में है । इसलिए रिवर लिंकिंग के बारे में सोचना चाहिए । कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड बना है, जिसकी वजह से तेलंगाना को बहुत नुकसान हो रहा है । इसके बारे में भी सोचना चाहिए । आखिर में मैं यह बोलना चाहता हूं कि जो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वर्ष 2014 में पास हुआ था । दस साल में सब कुछ इम्प्लीमेंट करना था लेकिन दस साल होने के बाद

भी बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करना बाकी है । जिसमें काजीपेट की कोच फैक्ट्री नहीं बनी है, खम्मम की स्टील फैक्ट्री नहीं बनी है । मैंने मॉर्निंग में भी कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट को नवोदय विद्यालय दिया गया है, लेकिन हमें नहीं दिया गया है । इसलिए ये सब देखने की आवश्यकता है, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं । कुछ भी हो नैक्स्ट 25 ईयर्स में हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी, लेकिन हम सबको मिलकर काम करने की बहुत जरूरत है । वर्ष 2047 तक अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो काफी कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है । हम लोगों को मिल-जुलकर काम करना चाहिए । It may be a regional party, it may be a national party, it may be an opposition party, it may be the Government. सब पार्टी को मिल-जुलकर काम करना चाहिए । हर एक स्टेट जब डेवलप्ड होगा, तब कंट्री डेवल्पड होगी ।

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Thank you very much, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on Motion of Thanks on the President?s Address. On behalf of the people of Andhra Pradesh and our Chief Minister Jagan Mohan Reddy garu, I thank the hon. President for addressing the Parliament and listing out various achievements, priorities, and initiatives of the Government.

As regards economy and finance, as emphasised by the hon. President there has been a notable increase in the number of individuals paying GST and filing Income Tax Returns. Over the past ten years, the volume of ITR filings has notably surged, increasing from about 3.25 crore to about 8.25 crore. Additionally, the number of GST return filers witnessed a significant 65 per cent growth reaching 11.3 million in the five-year period until April, 2023.

Nonetheless, I wish to draw attention to certain challenges that are hindering our economic growth in this regard.

We should optimize tax policies for holistic economic development. The Central Government witnessed an impressive 303 per cent surge in tax revenue over 12 years, reaching Rs. 25.2 crore in the Financial Year 2022. The gross tax revenue to GDP ratio improved to 17.1 per cent in the Financial Year 2022. However, it is crucial to ensure that this historic upswing translates into tangible benefits for taxpayers such as direct tax refunds and increased spending in vital sectors like education and health.

The tax concerns of the middle-class should be addressed. The middle-class continues to bear a substantial tax burden despite recent adjustments in tax structure and exemptions. The decline in household savings and the expanding middle-class population underscores the need for the Government to explore avenues to gradually relieve the tax burden through increased exemptions, income tax relief, and reimbursements.

The tax base for inclusive growth should be expanded. Despite an increase in the workforce, the income tax base has not expanded correspondingly. To achieve inclusive growth, the Government should focus on broadening the tax net by reducing tax rates. This approach aims to encourage more individuals to file Income Tax Returns and contribute to payments, leading to a more even distribution of the tax burden and potential reductions in taxation.

As regards momentum of feminism, one-third reservation for women in the Lok Sabha and Legislative Assemblies is a welcome move. As a State which has already been implementing the same, Andhra Pradesh welcomes this move with open arms. However, a significant allocation of resources at the grassroots level is required to truly elevate the status of women in the political sphere. In Andhra Pradesh, for example 688 out of 1,356 politically nominated persons were women. I urge the Central Government to engage in community awareness programs and networking events exclusively for aspiring women politicians to help incentivize the same.

As regards PM Awas Yojana, over 70 per cent of houses under PM Awas Yojana in rural areas were given to women, which is commendable. However, continual investment in the scheme is important for the upliftment of women. The Andhra Pradesh Government had submitted a proposal for over Rs. 4,000 crore to be released under special assistance for capital investment, which would go on to benefit the women of our nation *via* schemes such as PM Awas Yojana and others. I urge the Government to release these funds to ensure the continued emancipation of women from oppression.

I have another submission regarding the Government of Andhra Pradesh. The Government in Andhra Pradesh had given 31 lakh houses only for women, out of which 25 lakh houses have been completed. Four Deputy CM posts were created for SC, ST, BC and minorities including one woman belonging to SC category who is a Home Minister.

In each Gram Panchayat, our Government has provided one pucca secretariat building, pucca Rythu Bharosa Kendra building, Anganwadi building and also one health centre. In all the Gram Panchayats, there are police posts and a secretariat of Revenue Record. Our CM, Jagan Mohan Reddy has provided all the facilities to the needy people in our State.

On behalf of YSR Congress Party, I support the motion. With these words, I am concluding my speech.

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापति जी, धन्यवाद । मैं अपनी शिवसेना पार्टी की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय, हमारे हिन्दू हृदय सम्राट स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे जी का सपना था कि दुनिया में हिन्दुओं की भी अपनी पहचान हो । सभापति महोदय, देश के प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र में एनडीए सरकार ने पूरे विश्व को अहसास दिलाया है कि भारत भी हिन्दुओं का देश है ।

सभापति महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बड़े-बड़े फैसलों के लिए जानी जाती है । जैसे कि नोटबंदी का फैसला हो, जीएसटी लागू करने का फैसला हो, तीन तलाक कानून लागू करने का फैसला हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो, 'उज्ज्वला योजना? हो या ?किसान सम्मान निधि योजना? हो, ?आयुष्मान भारत योजना? और अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण हो,

ये सभी फैसले अपने-आप में अभूतपूर्व फैसले हैं । हमारे एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे फैसले लिए हैं ।

सभापति महोदय, डीबीटी जैसा कानून लागू किया गया । कांग्रेस के राज में कहा जाता था कि हम दिल्ली से 100 रुपए भेज रहे हैं, तो नीचे आदमी के हाथ में 15 रुपए ही जा रहे हैं, बीच में 85 रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है । डीबीटी के माध्यम से सभी बिचौलिए खत्म हुए और भ्रष्टाचार भी लगभग खत्म हो गया ।

सभापति महोदय, नोटबंदी ने आतंकवाद, विशेषकर पाकिस्तान द्वारा फैलाये गये आतंकवाद की कमर तोड़ कर रख दी है । जीएसटी के लागू होने से टैक्स चोरी में कमी आई है । तीन तलाक कानून को लागू करने से मुस्लिम बहनों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है । सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन देश के हौसले पस्त हुए हैं । अनुच्छेद 370 को खत्म करने से जम्मू-कश्मीर की जनता को देश की मुख्यधारा से जोड़ा गया है ।

सभापति महोदय, देश में कुछ सालों पहले तक गांवों में सिर्फ चूल्हों पर ही खाना बनाया जाता था, जिसके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था । इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए केन्द्र सरकार ने ?प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? की शुरुआत की और यह योजना गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस उपलब्ध कराती है । आज ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रहने वाले लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों की बहनों को इसका फायदा मिला है ।

सभापति महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ?किसान सम्मान निधि योजना? 1 दिसम्बर, 2018 को लागू की । इस योजना के तहत खेती करने लायक जमीन रखने वाले किसानों को छः हजार रुपए हर साल दिये जाते हैं । यह राशि चार महीने में तीन किस्तों के रूप किसानों के बैक एकाउंट्स में डाली जाती है । इस योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय

जरूरतों को पूरा करना है । यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई है ।

सभापति महोदय, इसके अलावा एनडीए सरकार ने ?पीएम गरीब कल्याण योजना?, ?पीएम आवास योजना?, ?हर घर जल योजना?, ?डिजिटल इंडिया?, ?स्मार्ट सिटी? और ?नमामि गंगे? जैसी योजना की भी सौगात देशवासियों को दी है । प्रधान मंत्री जी ने ?स्वच्छ भारत मिशन? और ?आत्मनिर्भर भारत अभियान? को मजबूती दी । उन्होंने गरीबों को फ्री राशन देने का भी फैसला किया । इसके अलावा उन्होंने वन्दे भारत ट्रेन और नए संसद भवन की सौगात भी इस देश को दी है ।

महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ?मेक इन इंडिया? कार्यक्रम के तहत कई नीतिगत पहल की हैं ।? (व्यवधान) सभापति जी, मेरी पार्टी का समय 12 मिनट से ज्यादा है और मेरी पार्टी के पहले वाले वक्ता सिर्फ 2 मिनट ही बोले हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी समय की कमी है । इसलिए आप जरा जल्दी कनक्लूड कीजिए ।

श्री प्रतापराव जाधव : मैं सिर्फ दो-तीन मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं । रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार लाए हैं । आज देश में रक्षा उपकरणों का उत्पादन हो रहा है और भारत को निर्यात के लिए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं । हम पहले हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर होते थे लेकिन आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं ।

महोदय, आज विश्व की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई से जूझ रही हैं । लेकिन मोदी जी की नीतियों की वजह से भारत में औसत मुद्रास्फीति दर विश्व में सबसे कम है । महोदय, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने थे, तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपये के आस-पास थी । आज भारत की

जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपये यानी दुगुने से भी ज्यादा बढ़ी है । भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है । प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2025 तक भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है । मुझे आशा है कि मोदी जी के नेतृत्व में यह अवश्य पूरा हो जाएगा ।

महोदय, प्रधान मंत्री मोदी जी ?मेक इन इंडिया? का नारा लेकर आए थे और इसका मकसद था कि दुनिया में भारत की बनी चीजों को भेजना । बीते 10 सालों में एक्सपोर्ट करीब दुगुना हो गया है । वर्ष 2022-23 में भारत ने 36 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2014 में सिर्फ 19 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हुआ था । पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेजेज स्थापित किए गए हैं तथा 157 नर्सिंग कॉलेजेज स्थापित किए जा रहे हैं । सोलर एनर्जी क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है और हम विश्व में पांचवें नंबर पर है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री प्रतापराव जाधव : महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं ।? (व्यवधान) नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है । आज हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं । इन समूहों को आठ लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण और 40 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है । अब तक एक करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और आने वाले वर्ष में हमारे प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य तीन करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाना है । मैं यहां बताना चाहूंगा कि महिलाओं को दिक्कत यह है कि उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है । इसलिए सरकार की तरफ से मार्केटिंग की पहल होनी चाहिए । उनके लिए जगह-जगह पर तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर शॉप बननी चाहिए, जहां महिलाएं अपनी निर्मित वस्तुओं को हर दिन वहां बेच सकें और अपनी मार्केटिंग सही ढंग से वहां पर कर सके ।

माननीय सभापति : प्लीज अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री प्रतापराव जाधव : महोदय, मैं सिर्फ एक वाक्य बोलना चाहता हूं । मैं गरीब किसानों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की हृदय से सराहना करता हूं । मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में विशेषकर विदर्भ और मेरी बुलढाणा कॉन्स्टीट्यूएंसी में सोयाबीन और कपास के दाम बहुत ही नीचे आ गए हैं । कपास के निर्यात को उठाना चाहिए और सोयाबीन प्रोसेसिंग एसोसिएशन (SOPA) ने सरकार को पत्र लिखा है । एनसीईडीएस को खत्म किया गया था, जिसका फायदा प्रोसेसिंग यूनिट को हो रहा है और उसका नुकसान हमारे सोयाबीन उत्पादक किसानों को हो रहा है । इसलिए एनसीईडीएस को तुरंत चालू करना चाहिए और कपास पर जो निर्यात बंदी है, उसको भी हटाना चाहिए । धन्यवाद ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on Motion of Thanks on the President?s Address. By virtue of Article 87 of the Constitution of India, it is the responsibility of Her Excellency the President of India to address the Joint Session of the Parliament every calendar year before the first Session of the Parliament. The very purpose of the President?s Address to the Joint Session of the House before the Session begins is to state about the performance of the Government during the last years and also to state about the programmes and policies of the Government in the ensuing year. But it is deeply disappointing to note that the Presidential speech which is having pertinent paragraphs is wholly about the achievements of 10 years of the NDA Government. There is nothing else other than the

achievements of 10 years. It is absolutely a political statement of the Government regarding their achievements that too for the Parliament elections. It is a political speech made by Her Excellency the President of India. So, it is deeply disappointing as far as we are concerned.

I have gone through the entire speech, pertinent paras of the speech. It is very, very comprehensive detailing almost all sections of the society. But you may kindly see that Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and also economically weaker sections of the society have been addressed in the President?s Address. But it is quite unfortunate, quite disappointing to note that there is not even a single word mentioned about the minorities in the country. There is not even a mention in the President?s Speech regarding the affairs or regarding the things which the NDA Government has done in the last 10 years as far as the minorities are concerned. BJP is always expressing the slogan ?*Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas?*. What about the minorities? You are talking about an inclusive development. Where is the development of the minorities and what about the affairs of the minorities? It is quite unfortunate that not even a word is mentioned in the President?s speech. While mentioning about achievements of 10 years, there is not even a single word or a single sentence in the President?s Address regarding the minorities.

The second point is regarding the labour. It is another area where there is total omission of the word and the state of affairs of the labour. It is also a deliberate omission. It is a deliberate omission

because they have done nothing for the labour, the working class in the country during the last 10 years. If you go through the last 10 years of the Government, the President?s Address speaks about farmers, industrialists, youth, students, entrepreneurs and even the street vendors. Their mention is there. What about the labour? I would like to place it on record that NDA-led Government during the past 10 years is totally against the labour, the working class of this country. They are a part and parcel of the society. They are not only a part and parcel; they are an inevitable portion in the economic development of the country. In the nation-building process, they are playing a very good role. They are also wealth creators. The President?s speech is very, very vocal about wealth creation. But what about the role of the labour? Nothing has been mentioned about that. Also, if you critically examine, always you are praising about the ease of doing business. How the ease of doing business in all these ten years has happened? This ease of doing business is there at the cost of the labour. This is because the rights enjoyed or the benefits enjoyed by the labour are taken away. At the expense of the labour, there is this ease of doing business.

Take for example, the Employees? Pension Scheme, 1995. Immediately after the BJP Government came to power, on 01.09.2014 a circular was issued by which rights of 95 lakh employees, the EPF pensioners have been taken away. Now, you see the entitlement regarding PF and pension of the employees. Those who are having salary above Rs.15,000 are out of the pensionary benefit. The retirement benefit of the working class is taken away by an order of the Government. Secondly, the higher pension on the basis of actual

salary is taken away. The criteria regarding calculation of pension is changed thereby having a drastic reduction in the monthly pension. They are still getting less than Rs.1000 as minimum pension. A High Power Committee has been constituted. The Labour Ministry has recommended to the Government of India, the Finance Ministry to enhance the minimum pension from Rs.1000 to Rs.2000.

But nothing is done. The benefits of 95 lakh old-aged pensioners have been curtailed during the last ten years.

With regard to ESI benefits, most of the workers are now beyond the purview of the ESI medical benefit scheme. Why is it so? It is because the ceiling limit is Rs. 21,000. Most of the workers are above that ceiling limit. The Government and the Labour Minister has assured this House so many times that it will be considered. But so far nothing has been done as far as ESI is concerned. So, my point is that these two sections of the society -- minorities as well as labour -- are totally ignored. And it is quite unfortunate that nothing of that sort is mentioned in the Presidential Speech.

Hon. Chairperson, Sir, we want to say that we are going in for 2024 Elections. Wherever you go, you can see ?Modi?s Guarantees?. I would like to know from the Government as to what guarantees and promises were made during the 2014 election and also during the 2019 election? Will the Government bring back the black money which is stacked in foreign countries? Will every household be given Rs. 15 lakh in the account? Where is it? I would like to know where is the creation of two crore jobs every year? There is an exponential growth of unemployment rate in the country. They said that the prices

of petrol and diesel will be brought back to Rs. 50 per litre, and the price of cooking gas will be brought back to Rs. 320.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Hon. Chairperson, Sir, let me conclude with this point. ?Farmers? income will be doubled by 2022?, ?Housing for All?, and ?Drinking Water for All? -- these are all the promises but there is nothing in practice. Also, the secular and democratic fabric of the country is under a big threat. My point is that if you want to restore the constitutional values and protect the Constitution, the Government has to change in the coming election. And we appeal to the people of India to vote for the Indian National Developmental Inclusive Alliance so as to protect the constitutional values and safeguard the Constitution.

With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Thank you, hon. Chairperson. Sir, I will speak in my Tamil language.

At a time when I complete my tenure as MP for five full years, I sincerely express my gratitude to the Leader of my AIADMK Party Dr. Puratchithalaivar MGR, Puratchithalaivi Amma, the Coordinator and former Chief Minister of Tamil Nadu Shri O. Paneerselvam. I also thank the Hon. Speaker of Lok Sabha Shri Om Birla who has given so many opportunities for me to speak in this august House. I wholeheartedly thank our Hon Prime Minister of India Shri Narendra Modi for attending the election campaign in my Theni parliamentary constituency and ensuring my victory in the 2019 elections. Hon.

President?s Address in this new Parliament Building is an historic achievement. Hon. Prime Minister has given this great opportunity to our Hon. President who belongs to tribal community. In our free India, BJP has given three Hon. Presidents. Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Shri Ramnath Kovind and Smt. Droupadi Murmu are those three Presidents. One belongs to minority community, one belongs to a Scheduled Caste and another one belongs to tribal community. No other Government in our country has provided such an opportunity to these communities in the past.

When Hon. President came inside this new Parliament Building to deliver the Presidential Address, the procession was led by holding a Sengol - the sceptre received from Tamil Nadu. This is a pride-filled moment for the rich culture of Tamil Nadu. Similarly, Our Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi is the only Prime Minister who has spoken in Tamil at the UN General Assembly. He is an ambassador who carried forward the legacy of Tamil culture abroad to different countries. Hon. Narendra Modi ji has the unique distinction of being born in the independent India and becoming the Prime Minister of India. He led to Industrial revolution by way of Make in India. Opposition parties have placed so many accusations before this House.

I request for giving me more time to speak. If you see the history of Tamil Nadu, you can come to know different things. Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi has fulfilled the dreams of every citizen of India. After 500 years, the Ram temple has been

constructed in Ayodhya and consecration of Ram Lalla was completed by him.

Two days before the inauguration, Hon Prime Minister visited Tamil Nadu. He offered prayers at Srirangam temple and also the Ramanathaswamy temple in Rameswaram of Ramanathapuram district. Katchatheevu, where no people live, belonged to Ramanathapuram kingdom. During the 17th century Katchatheevu was a property of King Sethupathi of Ramanathapuram. A copper plaque released by King Sethupathi had the details of Katchatheevu and the land up to Thalaimannar in Sri Lanka belonging to King Sethupathi. The East India Company entered into an agreement with Ramanathapuram Kingdom in 1822. Britishers were allowed to use and utilize the land belonging to Ramanathapuram Kingdom including the Katchatheevu. If you look into history, Katchatheevu was very much a part of India and particularly of Tamil Nadu. When Smt. Indira Gandhi was the Prime Minister, she ceded this Katchatheevu to the then Prime Minister of Sri Lanka Smt. Bandaranayaka as a gift from India. This was not discussed in this House of Parliament. Without discussion, Katchatheevu was ceded to Sri Lanka. When we legislate a law for Jammu and Kashmir these opposition parties oppose those initiatives. But they have not held any agitation for retrieving Katchatheevu which was ceded by our former Prime Minister to Sri Lanka.

It is a matter of concern. But I request our Hon Prime Minister of India to retrieve Katchatheevu. Several welfare programmes of the Government led by Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi are

mentioned in our Hon. President?s Address. I appreciate them. While assuming power our Hon Prime Minister said in 2019 that new way has been paved for constructing a new vibrant India. During the last 10 years, from 2014 to 2019 and from 2019 to 2024, Shri Narendra Modi ji has paved new way and led our country to become a super power. The people of our country will vote and elect our Modi ji for the third consecutive term in the forthcoming elections to be held in 2024 and he will become our Prime Minister once again. Thank you for this opportunity.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक हमारे संयुक्त सदन को संबोधित किया । इसके बाद मैं सदन में बैठे सभी माननीय सांसदों को तथा देश के समस्त नागरिकों को हाथ जोड़ कर राम-राम करता हूँ ।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज़ गति से हो रहे विकास का एक प्रमाणित दस्तावेज़ यहां पर प्रस्तुत किया है । देश बदल रहा है, यह मैं नहीं पूरी दुनिया कहती है । लोगों की सोच भी बदल रही है, यह मैं नहीं कहता, आम आदमी कहता है ।

आज सबका साथ - सबका विकास हो रहा है । देश के समूचे भू-भाग में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हैं, जहां पर पिछले 10 वर्षों में विकास न हुआ हो । देश का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, जिस सेक्टर में रिफॉर्म न हुई हो । देश जिन गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था, अब धीरे-धीरे उनसे मुक्त होते जा रहा है । मैं कह सकता हूं कि एक समय था, जब देश में लंबे समय तक कांग्रेस का राज था । देश के सभी राजनीतिक दलों को सत्ता में रहने का मौका मिला है,

लेकिन सर्वाधिक समय कांग्रेस को मिला है । कांग्रेस के समय का जो नारा था- वह भय, भूख तथा भ्रष्टाचार था, लेकिन इसे कांग्रेस ने दिया । उनका नारा रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए था । पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल देने का भी उनका नारा था और गरीबी मिटाने के लिए भी नारा था । लेकिन, दुर्भाग्य है कि इस देश में न तो गरीबी मिटी, न ही लोगों को पेट भर भोजन मिला और न ही देश में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल तथा अस्पताल पहुंचा । वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बने । पुरानी सरकार का एक सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण था । वर्ष 2011 में मनमोहन सिंह जी ने एक सर्वेक्षण कराया था । वर्ष 2011 का सर्वेक्षण चुपचाप रखा हुआ था । जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको देश के अंदर गरीबी सबसे बड़ी चुनौती दिख रही थी । उन गरीबों को कैसे सुविधायुक्त बनाया जाए । तब उन्होंने वर्ष 2011 के उसी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को उठाया और वर्ष 2014 में उसे लागू किया । उसे लागू करके जब उन्होंने काम शुरू किया तो आज देखते-देखते देश के गरीबों की हर जरुरत पूरी हो रही है । जो गरीब वर्षों से इंतजार में था कि कभी मेरा घर बनेगा, कभी मेरे घर में बिजली का उजाला आएगा, कभी पीने का पानी मिलेगा, कभी मेरा भी खाना रसोई गैस से बनेगा, कभी मेरा भी चूल्हा दोनों टाइम जलेगा, कभी मेरे घर में भी माता-बहनों के सम्मान के लिए शौचालय बनेगा, कभी बीमारी के इलाज के लिए मुझे भी गारंटी का पत्र मिलेगा । यह इंतजार करते-करते उसको वर्षों बीत गए, लेकिन ये सारे सपनें वर्ष 2014 में मोदी जी के आने के बाद साकार हुए ।

अभी मोदी जी का विकसित भारत के लिए एक संकल्प है । अभी उस संकल्प की एक यात्रा पूरे देश में निकली है । यह यात्रा ढाई लाख पंचायतों में गई है । इस ढाई लाख संकल्प यात्रा में मैं भी अपने क्षेत्र में था ।

सभापति महोदय, मैंने अनुभव देखा, आम आदमी कहता था कि पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि कोई सरकार आकर गारंटी दे रही है । मोदी सरकार की गारंटी दी जा रही है कि हर गरीब की हर जरुरत पूरी

होगी । अभी हमने जो कुछ किया है, उसका लाभ गाँवों में रहने वाले 70 से 80 परसेंट लोगों को मिला है । यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि लोग कह रहे हैं । जो लोग बचे हुए हैं, उनको भी देने की मेरी गारंटी है । यह पहली बार भारत के लोकतंत्र के इतिहास में देखने को मिला है । यह पहचान है, यह कमिटमेंट है, यह वायदा है, जिसको पूरा किया गया है ।

इसीलिए मैं कहता हूं कि देश तेज गति से बदल रहा है । देश में रहने वाले लोगों का विश्वास सरकार के प्रति मजबूत हुआ है । हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि यह अमृतकाल है । इस अमृतकाल में सबसे बड़े विकास का यह इमारत है, जो हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है । आज इस संसद भवन के बनने के बाद हमें गर्व का अनुभव हो रहा है । कई ऐसे महत्वपूर्ण कानून बने हैं, जिनमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नव न्याय संहिता, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, जन विश्वास अधिनियम, जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम हैं । इन विभिन्न कानूनों के तहत 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया है । अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने सभी सांसदों का धन्यवाद भी किया । मैं सदन के माध्यम से उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । इन कानूनों को बनाने के लिए जिन सांसदों ने सहयोग किया, उनके प्रति भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

महोदय, इस अमृतकाल के दौरान कई ऐतिहासिक काम हुए है । कर्तव्य पथ पर सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना, जो कोई सोच नहीं सकता था, यह सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की है । अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम बना है । अब तक सर्वाधिक प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, लेकिन इसके बावजूद भी देश के विकास में जिन-जिन लोगों का इतिहास में योगदान था, वह आने वाली पीढ़ी को पता होनी चाहिए । इसलिए उन्होंने सभी प्रधान मंत्रियों का म्यूजियम बनाया । साहबजादों की याद में वीर बाल दिवस घोषित किया गया । भगवान बिरसा

मुंडा के जन्म दिवस को उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया । 14 अगस्त, जो हमारे देश के विभाजन की तारीख है, इसको विभीषिका दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ी जाने, उसकी भी घोषणा हुई । दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में आज 7.5 प्रतिशत से ऊपर हमारी विकास दर है । भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, आदित्य मिशन लांच हो गया, ऐतिहासिक जी-20 के सम्मेलन सफलतापूर्वक हुए, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है और भारत की वास्तविकता से पूरी दुनिया अवगत हुई है । पहली बार ऐसा देखने को मिला है ।

भारत ने पैरा-एशियाई खेलों में 100 मैडल लेकर खेल के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान कायम किया है । अटल सेतु की उपलब्धि हुई है । नमो भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, जो हमारे अपने देश में निर्मित हुई हैं, अब वे चल रही हैं । पुराने अनुपयोगी कानूनों की समाप्ति हुई है । यह एक बहुत बड़ी बात है । तीन तलाक को गैर-कानूनी बनाने का काम हुआ, धारा 370 की विदाई हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून बन गए, सीएए का कानून लागू हो गया, वन रैंक वन पेंशन लागू हो गई । मेरी सरकार का मानना है कि विकसित भारत की भव्य इमारत चार मजबूत स्तम्भों पर खड़ी है । पहला स्तम्भ युवा शक्ति है । दुनिया में सबसे युवा देश भारत है । दूसरी शक्ति हमारी नारी शक्ति है, जो देश की आधी आबादी है । तीसरी शक्ति, हमारे देश का किसान है, जो दिन-रात मेहनत करके अनाज पैदा करता है और पूरे देश को पेट भर भोजन दे रहा है । चौथी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वह है गरीबी कंट्रोल । कांग्रेस के जमाने में सुरसा की तरह गरीबी बढ़ गई, लेकिन उस पर कंट्रोल करने का कोई प्रयास नहीं हुआ ।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेन्द्र मोदी जी को, जिन्होंने गरीबी पर रोक लगाने का काम किया और आज उसके सार्थक परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं । इन चारों स्तम्भों को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से

कार्य प्रारम्भ किया था, जिसके परिणाम अब गांव-गांव में दिखाई देने लगे हैं । यह कार्य वर्ष 2047 तक पूरा होकर, विकसित भारत बनकर हम सबके सामने आएगा । 4 करोड, 10 लाख गरीबों के पक्के घर बन गए । कांग्रेस के जमाने में, वर्ष 2014 के पहले एक भी गरीब का पक्का घर देश में नहीं बना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं । ?(व्यवधान) एक भी गरीब का घर पक्का नहीं बना, एक भी गरीब के घर में शौचालय नहीं बना । यह सबसे छोटा काम था ।?(व्यवधान) वह भी काम करना पड़ा तो मोदी जी को करना पड़ा । ?(व्यवधान) यह कैसा देश है और कैसे सत्ता में बैठे हुए लोग थे? हमारे देश की नारी शक्ति लोटा लेकर बाहर शौच के लिए जाने को मजबूर थी ।?(व्यवधान) यह कभी इनको ध्यान नहीं आया । अगर उनकी इज्जत और सम्मान का ध्यान किया तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया ।

महोदय, 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच गया । 100 प्रतिशत घरों में इसे पहुंचाने की योजना चल रही है । आज हर एक संसदीय क्षेत्र में, चाहे वह कांग्रेस के मित्र हों या दूसरे दलों के मित्र हों, सबके क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना चल रही है । 10 करोड़ से ज्यादा घरों में उज्ज्वला गैस पहुंच गई । बेशरम पौधे की लकड़ियों से हमारी मातायें और बहनें रोटियां पकाती थीं । श्रीमान जी, यह सबको पता होना चाहिए कि वे बेशरम की लकड़ियों से जहरीला धुआं खाकर बीमार पड़ती थीं । आज 80 करोड़ घरों में मुफ्त में अनाज पहुंच रहा है । 5 साल के लिए उसको और बढ़ाने का काम हुआ । 19 करोड़ से ज्यादा लोग इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जुड़े हुए हैं । मैं प्रमाण दे रहा हूं, 19 करोड़ बड़ी संख्या होती है । विकसित भारत यात्रा का समर्थन करने लोग आए और उन्होंने प्रधान मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है । अब तक 10 करोड़ महिलायें स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं । इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपये के लोन तथा 40 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है । अब 2 करोड़ महिलाओं में लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प है । नमो ड्रोन दीदी योजना में 15 हजार स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : गणेश सिंह जी समाप्त कीजिए । मैं दूसरा नाम पुकारता हूं ।

श्री गणेश सिंह : मुद्रा बैंक योजना में 46 करोड़ से अधिक लोन दिए गए हैं । किसानों को अब तक 2.80 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि मिली है । पीएम फसल बीमा योजना में डेढ़ लाख करोड़ रुपये के क्लेम मिले हैं ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे कि दस सालों में क्या हुआ? दस सालों में यही तो हुआ है, जो सबसे बड़ा प्रमाण हमारे महामहिम राष्ट्रपति का दस्तावेज है । दस सालों में देश बदल गया, लोगों की तकलीफें दूर हो गईं । 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now. I am going to announce next speaker.

? (*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह : इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है ।? (व्यवधान) कांग्रेस की सरकार में आदमी गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल पाया । ? (व्यवधान) यह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ।?(व्यवधान)

<u>16.00 hrs</u>

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, on behalf of CPI (M) Party, I wish to register my strong disagreement on the Motion of Thanks to the hon. President?s Speech.

Sir, I feel very proud to see our hon. President being accorded a royal welcome given to her prior to her Address. Actually, I would like to appreciate the foresight of the framers of Constitution who

foresaw the situation where you all had to walk behind the hon. President, I repeat, behind her, but you deliberately excluded her during the inauguration of our New Parliament Building. She is the sole custodian of the Parliament, according to our Constitution. Again, I greatly admire the genius of the framers of the Constitution who could foresee that you might behave this way.

<u>16.01 hrs</u> (Shri A. Raja *in the Chair*)

Sir, I feel, destiny was taking sweet revenge to the disrespect the BJP Government has shown to the hon. President, by not inviting her to inaugurate this new building. I still want to know, why the hon. President, who is the full authority of this Parliament, was not invited to the opening ceremony of our Parliament. I hope, the hon. Prime Minister will reply in this regard in his speech.

Sir, it was pity that the hon. President, who was excluded from the consecration ceremony of Ram Temple, was forced to say that the construction of Ram Temple is one of the achievements of the Government. In the same way, you had invited all the celebrities and movie stars of different languages of the country to the consecration ceremony of Ram Temple. You gave invitation to all of them but you did not show the common courtesy to give an invitation to the President of India, who is the first person of our country.

People of this country could understand your ...* that the hon. President, who is a widow and who belongs to a Scheduled Tribe community, was out of all these functions. At the same time, you

claim to be doing a lot for women and also talk about Nari Shakti Vandan and upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Sir, we all know that the moment India gets transformed into a religious State, as our neighbours Pakistan and Afghanistan, for which the Sangh Parivar is channelising all its efforts, its *pran* will be freed forever. The *pran* of our Constitution will be taken away. I am sure that the soul of thousands of Indians, who sacrificed their lives for the freedom of their motherland will never ever allow that to happen.

Sir, coming to the 31-page speech of the hon. President, I am disappointed to state that it neither has any vision nor any direction to build an India to match the aspirations of the common people of this country. Instead, it contains only rhetoric and jargons to deceive the people of this country, as also mentioned by the earlier speakers.

Hon. President told us that this new Parliament is imbued with the fragrance of ?Ek Bharat, Shrestha Bharat?. This has been built on the remnants of our age-old tradition of ?Unity in Diversity?, which held this pluralistic country together for centuries. It includes religious minorities and linguistic minorities. But you are trying to exclude them from the ?Ek Bharat, Shrestha Bharat?.

The core of ?Ek Bharat, Shrestha Bharat?, as envisaged by the BJP Government is ?Hindi?, ?Hindu? and ?Hindustan?. This is the ideology of Savarkar.

Sir, in continuation of division of this country in the name of religion by the Britishers, the Government is trying to divide this

country in terms of language by imposing Hindi as a national language, against the aspirations of the non-Hindi States and the people of our country.

Sir, the hon. President made a claim in her speech that the Government gave jobs to lakhs of youth in mission mode last year. But unlike other claims before that, why was she not able to exactly state as to how many jobs her Government created all these years? The answer to the question lies in the promise given by the hon. Prime Minister, Narendra Modi ji, way back in 2013 in an election rally that his Government would create two crore jobs every year, if voted to power and her speech is nothing but an open admission of the fact that the BJP Government, after being voted to power for ten years has not been able to create even a part of one crore jobs.

Sir, in paragraph 6, our President has boasted that her Government brought in important legislations and enacted them with cooperation from all. But what happened in the last Session, Sir? The Government has not felt ashamed to ask the President to read such a false statement in this august House. The hon. President forgot that during the last Session, 10 important legislations were passed without proper discussion when 100 Members from this House as well as 49 Members from Rajya Sabha were suspended.

Sir, the hon. President seems to have forgotten that our Constitution envisages India as a secular country while she read the 7th paragraph regarding construction of Ram Mandir as a reality and fulfilment of our aspirations for centuries. You are trying to politicise

everything, which is Ram Temple construction and its inauguration is disrespect to Lord Rama.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

ADV. A.M. ARIFF: Sir, I am concluding in just one minute.

The hon. President presented the achievements of her Government one-by-one very proudly in her speech. But she failed to mention the failures of her Government, which are equally important as we have to overcome those failures in the years to come.

What about the Annadata? I have received a reply from the hon. Minister concerned that 58,000 farmers have committed suicide due to the flawed policies of the Government in agriculture sector.

Sir, she mentioned certain statistics in terms of Asian Games and Para Asian Games. What are the statistics in respect of Olympic Games where we could not get even a single gold medal? While the Governments world over are competing each other to create sports infrastructure, unfortunately, our Government is still interested in creating tall statues spending thousands of crores to achieve political gains.

Sir, I am concluding my speech with one last point with regard to AIIMS. Towards the end, we could see the tall claims of setting up of All India Institute of Medical Sciences (AIIMSs) in the country whose number rose from seven to 16 in the last decade. But even then, an AIIMS was not allotted to the State of Kerala though the State Government allotted the suitable land, only due to political

vendetta against the ruling LDF Government there. It is crystal clear that they are violating the federal principle of the Constitution.

With these words, I am concluding my speech.

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । वर्ष 2014 में लोकसभा इलैक्शन प्रचार के दौरान माननीय मोदी जी ने हमारे गांव में जाकर बोला था कि असम के कोकराझार के आदिवासियों और अन्य आदिवासियों को शैड्यूल ट्राइब्स में डालेंगे, लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ । सात साल पहले बेतिया-बोडो के साथ जो अकॉर्ड हुआ था, उसमें बाउंड्री कमीशन का पैराग्राफ था कि जहां बोडो या ट्राइबल लोग हैं, उनको इनकलूड करेंगे और जहां नहीं हैं, एक्सकलूड करेंगे । यह काम भी अभी तक इम्पलीमेंट नहीं हुआ ।

महोदय, एक नेता मारे गए थे जो लफीकुल इस्लाम थे । सीबीआई ने बोल दिया है कि किसने मारा है, लेकिन अभी तक वह पकड़ा नहीं गया है । मुझे उम्मीद है कि उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे ।

महोदय, हमारे यहां का एक मसला है, सरनीया कसारी, ठेंगाल कसारी और मुनाही कसारी, इनको सैंट्रल लिस्ट में लाना था लेकिन अभी तक नहीं ला पाए हैं । मैंने दो बार कहा, लेकिन दो बार हरा नहीं पाए लेकिन इस बार हमारे साथ कांस्पिरेसी हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि सरनीया कसारी की एसटी की सैंट्रल लिस्ट में लिस्टिंग करेंगे, क्योंकि ये बोडो से भी एसटी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन अभी भी काम कम्पलीट नहीं हुआ । मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह बात भी पूरी होगी ।

आदिवासी गौरव मना रहे हैं । यह हमारे लिए गौरव की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति जी महिला होने के साथ आदिवासी हैं और उन्हें 31 जनवरी को एड्रेस करने का मौका मिला । सभी आदिवासियों को इस बात का

दुख है कि अगर उनको संसद के उद्घाटन समारोह में बुलाया जाता और यह जिम्मेदारी दी जाती, तो हमें बहुत अच्छा लगता । इसके साथ ही साथ बहुत सारे आदिवासी भाई, जो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, जैसा कि गुजरात में भी है, उनको एसटी सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए 1950 का डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, लेकिन वहां के जो ओबीसी हैं, उनको 1975 का डॉक्यूमेंट देने से भी काम चल जाता है । यूपी के जो गोंड आदिवासी हैं, उनको अभी भी ठीक ढंग से सर्टिफिकेट नहीं मिला है । जमीन से लेकर सर्टिफिकेट तक को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं । मैं नंदूरबार गया, तो वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो पहाड़ों पर बसते हैं, लेकिन उनके पास जमीन के कोई कागज नहीं हैं । हमारे उधर भी ऐसा ही है । जहां-जहां भी आदिवासी हैं, जिनमें कोई फॉरेस्ट में है, कोई जंगल-पहाड़ों में हैं, हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां अच्छी तरह से बसाया, लेकिन जो आदिवासी जंगलों में हैं, उनको बीच-बीच में वहां से भगाया जाता है ।

महोदय, मैं जब गुजरात के पालनपुर गया, तो मुझे दुख हुआ, क्योंकि वहां भी ऐसा हादसा हुआ । हमारे देश में जगह की कमी नहीं है, विश्वास की कमी नहीं है, आदिवासी यदि कोई जंगल में बस गया, उसको हमें अच्छी तरह से सेटल करना चाहिए । इसके साथ-साथ मेरे सेक्टर में भी ऐसा ही एक इश्यू है ।

Sir, please give me only one minute. सर, मैं दो बार का सांसद हूं । बाकी लोगों को 10 मिनट बोलने के लिए मिलता है, मुझे तो केवल दो मिनट चाहिए ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude within one minute.

श्री नव कुमार सरनीया : सर, इन आदिवासियों को मान और इज्जत से जीने देना चाहिए । मैं जाते-जाते महामहिम जी को एक इन्विटेशन देना चाहूंगा । कासरगोड, महाराष्ट्र, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का संलग्न स्थल है, वहां हमारे

गोंडवाना समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन होता है । 22 से 26 तारीख तक उनको बुलाया गया है । यह मेरा आमंत्रण है, जिसको उन्हें स्वीकार करना है ।

अंत में, आदिवासियों के साथ जो होता है, वह केवल बोलने से नहीं होगा । यह भाषण तो टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो बात हम बोलते हैं, वह ग्राउंड पर भी होनी चाहिए ।

धन्यवाद ।

DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Motion of Thanks on the President?s Address on behalf of my party.

The hon. President has presented an elaborate account of the achievements of the Government. I take this opportunity to congratulate the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, and his Government for fulfilling the centuries-old desire of the people, and inaugurating and dedicating the Ram Temple to the people and the nation, a symbol that represents the nation?s faith in God. The temple reminds us of the very secular fabric on which our great democracy and nation was founded. I hope, with this, our faith in God will be strengthened, and various other religions will be able to perform the religious practices they have faith in, with freedom and without fear. However, unfortunately, attacks and atrocities on religious minorities have become rampant and the Government must stop this.

Among innumerable successes, I must make a special reference to the launching and historic landing of Chandrayaan-3 and hoisting of the tricolour on the southern pole of the Moon, the first among all nations of the world, historic success of the G20 Summit sealing India?s global standing, the fastest and the largest to introduce 5G connectivity and introduce 5G case-uses along with AI technologies to various other applications, including health and education. The much-needed solution to the ongoing Indo-Naga peace talks and various other political groups of the North-East, especially of the SoO groups of Manipur, unfortunately, do not find a mention in the Presidential Address. The Indo-Naga peace talks going on for the past 27 years must come to its logical conclusion and find a solution that is inclusive, agreeable, acceptable and honourable to all stakeholders as early as possible.

The violence that engulfed Manipur for the past more than nine months now between the Kukis, and the Kuki, Chin and Mizo groups must end. The Government must, in all seriousness, address the various issues of lawlessness leading to the loss of faith in the Constitution and the Government. Violence must stop; rule of law must return; and peace must return. Manipur needs peace. Make Manipur vibrant again. Thank you so much.

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): सभापति महोदय, देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । इस

नये सदन में मैं पहली बार बोल रहा हूं । महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं और मेरी पार्टी इसका समर्थन करते हैं ।

सभापति महोदय, आज 21 वीं सदी के नये भारत के लिए नई परम्परा के निर्माण संकल्प के साथ आजादी के 75 वर्ष पूरा करके हम लोगों ने अमृतकाल में प्रवेश किया है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन 10 वर्षों में भारत को एक नई ऊंचाई दी है तथा एक अभूतपूर्व कार्य किया है । हम लोग आज जिस संसद भवन में हैं, यह संसद भवन ससमय निर्मित हुआ और आज सभी माननीय सांसद यहां उपस्थित होकर, बैठकर बात करते हैं । मुझे वह दिन याद है, जब इस संसद भवन के निर्माण की बात चल रही थी । जब कार्य प्रारंभ हुआ था तो लोगों को इस बात की आशंका थी कि शायद यह संसद भवन ससमय पूरा नहीं होगा । लेकिन, हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि यह ससमय पूरा हुआ । उस दिन, जिस दिन संविधान की प्रति लेकर आदरणीय प्रधान मंत्री जी, लोक सभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति जी और संसदीय कार्य मंत्री जी उस संसद भवन से यहां आ रहे थे तो उस यात्रा में मैं भी साथ था । मुझे लगता है कि मेरे साथ-साथ सभी सांसद भी गौरवान्वित होंगे कि वर्ष 2019 के चुनाव में जीतने वाले सभी सांसद, उस संसद भवन में, जिसमें संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था, उसके बाद हम लोग एक नये संसद भवन में नई सदी का इतिहास गढ़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं और आज आपके सामने बात कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, बचपन से ही नारी सम्मान के प्रति हम लोगों के हृदय में, सभी सांसदों के मन में और पूरे देश के पुरूषों के मन में यह भाव रहता था । इसके लिए कई तरह के आंदोलन हुए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया । कोई सरकार नारी शक्ति के सम्मान को समझ नहीं सकी । लेकिन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर देश के आदरणीय प्रधान मंत्री

जी ने नारी समाज को सम्मान दिया और महिलाओं को जो विधान सभा और लोक सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया, आज वह देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है । इससे नारी शक्ति में वर्द्धन होगा और आने वाले दिनों में हमारी देश की माताएं-बहनें देश के साथ-साथ दुनिया में भी अपनी शक्ति दिखाने का काम करेंगी ।

सभापति महोदय, कुछ बातें दलगत होती हैं, कुछ बातें लोगों के मन की होती हैं, कुछ अपने विचार की होती हैं और कुछ अपने जीवन की होती हैं । हम जो बातें कहने जा रहे हैं, इससे हो सकता है कुछ माननीय सदस्यों के मन में यह बात आए कि एक सांसद इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? लेकिन, हम बोलने जा रहे हैं कि आज राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ है । हमें लगता है कि इसको लेकर पूरे देश में खुशी है, जन-जन के मन में खुशी है । 14 वर्षों तक प्रभु श्रीरामचंद्र जी पितृ आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए । लेकिन, भाई भरत और अयोध्या के नागरिकों ने उनके लौटने की प्रतीक्षा की । विदेशी आक्रांताओं के द्वारा प्रभु श्रीरामचंद्र जी के जन्मस्थली को क्षति किया गया । इस कृतज्ञ देश ने 500 वर्षों तक उसका इंतजार किया है । देश के शासकों ने उस पर गंभीरता से कोई काम नहीं किया । मैं आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की न्याय प्रणाली को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है । मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज अयोध्या में रामचन्द्र जी का भव्य मंदिर बना है । वहां 22 तारीख को रामलला विराजमान हुए हैं । अब देश में राम राज्य आ गया है, आने वाला नहीं है, आ गया है ।

मैं इस देश के लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं । हम लोगों को धारा 370 के बारे में बोलने का मौका नहीं मिला था । धारा 370 के बारे में लोगों ने कहा था कि धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, लेकिन उस समय भी हम लोगों का समर्थन था । आज धारा 370 हटाने से क्या फायदा हुआ है? मैं

आपको वे बातें बताना चाहता हूं । जब सन् 1992 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की एकता यात्रा निकली थी, वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे । नरेन्द्र भाई मोदी जी के कुशल संचालन में वह यात्रा श्रीनगर और जम्मू-कश्मीर गई थी । हां, मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं कि दुलाल चन्द्र गोस्वामी भी उस यात्रा में सहभागी था ।?(व्यवधान)

हम लोग वहां गए थे । अपना ही देश, अपना ही राष्ट्र, लेकिन उस समय श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए इस देश के लोगों को संघर्ष करना पड़ता था ।?(व्यवधान) धारा 370 समाप्त होने के बाद मैंने भी लाल चौक जाकर अपनी सेल्फी ली है । कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जब अपनी ?भारत जोड़ो यात्रा? कर रहे थे ।?(व्यवधान)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Sir. I rise to speak on the Motion of Thanks on the Presidential Address. ?(*Interruptions*)

Madam President made her comments immediately over the issue of mock Parliament performed by the suspended Opposition Members from both the Houses when we were suspended because of our demand from the hon. Home Minister to give his statement regarding the safety and security issue of the Parliament House. This is first time in the Indian history that 146 Opposition Members were suspended and the present Government has passed several important Bills without any discussion. This is a huge threat to our democracy.

But I am surprised by the shocking silence maintained by our hon. President over the heinous crime committed against two tribal women in Manipur. The situation in Manipur is still unstable even after eight months of the incidents. It is astonishing that there is no mention about the Manipur issue in her speech. Madam President did not say anything, not a single word when women wrestlers were being manhandled and inhumanly dragged by cops during their peaceful protest while the entire nation expected a remark from her. Where was our hon. President when the country?s sportspersons were returning their Padma Shri, Arjun Awards and medals?

The country witnessed the rapists and murderers of Bilkis Bano case being garlanded after their unjustified release much before the completion of their imprisonment term. Bilkis Bano deserves respect and justice for what she suffered and it is the opposite where instead of siding with the real victim we are silently watching as the criminals walk free. Thankfully, the Supreme Court ordered otherwise and overruled/overturned that ruling. But being a constitutional head, a woman and a mother, Madam President do you not think that you should have raised your voice for what is right and just? And on other critical issues of national importance, like rising unemployment and inflation, Madam President continues to remain silent.

Madam President mentioned women empowerment but I would like to mention here that the country?s one and only woman Chief Minister, our Chief Minister, Mamata Bandyopadhyay, made sure that there are one-third reserved seats for women in West Bengal

State Legislative Assembly and 50 per cent reserved seats are there for women at Panchayat level much before the Women Reservation Bill was passed in the Parliament House.

Now, coming to the report of Global Hunger Index of 2023, it gives India a rank of 111 out of 125 countries. This indicates an alarming level of hunger severity in the country that has been boasted by high GDP growth for past years.

Additionally, the NCRB report of 2023, which was released very recently, shows crimes against Scheduled Castes went up by 13 per cent and against Scheduled Tribes by 14.3 per cent. Reserved seats meant for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are lying vacant in different Government institutions and departments.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Appropriate action is not being taken to fill up these vacant posts. Child rape cases also witnessed a staggering 90 per cent increase from 2016 to 2022 as per analysis of NCRB data conducted by a child rights NGO. It is clear that in reality when it comes to the actual well-being, socio-economic development and empowerment of India?s people, there is really not much that has progressed, if not deteriorated as it was.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Sir, please give me one minute. But, somehow, Madam President chose to overlook these issues and remained silent and, in this context, I would like to quote the Father

of our Nation, Mahatma Gandhi, who said, ?Silence becomes cowardice when occasion demands speaking out the whole truth and acting accordingly?. Her silence on crucial matters of the country and on multiple incidents of blatant injustice indicates that she has sadly picked the wrong side and through these short interventions, it is my humble attempt to urge Madam President to open her eyes and speak up for what is right.

16.27 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to dwell on the Motion of Thanks on the Presidential Address which consists of 32 pages and 39 paras delivered according to article 87(1) of our Constitution.

I do not understand the few political jargons that have been enshrined in the Presidential Address. First of all, what is called ?*Vikasit Bharat?*? What does it mean by ?*Vikasit Bharat?*? I do not have any distinct idea of it. Why should we wait till 2047 to obtain ?*Vikasit Bharat?*? I also do not know that. I do not even know that till sighting ?*Vikasit Bharat?,* whether all of us will be alive or not. Naturally, I am little bit eager to know about the parameter or definition of what is called ?*Vikasit Bharat?*. In the milieu of highfalutin religious triumphalism, I thought it prudent to cite a few lines from no less than one of the greatest monks, a Hindu monk, of India, Shri Vivekananda ? Narendra Nath Dutta. He said, ?If the Parliament of Religions has shown anything to the world, it is this: it has proved to the world that holiness, purity and charity are not the exclusive possession of any church in the world, and that every system has produced men and women of

the most exalted character. In the face of this evidence, if any one dreams of the exclusive survival of his own religion and the destruction of others, I pity him from the bottom of my heart, and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written in spite of resistance: ?Help and not fight,? ?Assimilation and not Destruction,? ?Harmony and Peace and not dissension.?

Sir, Swami Vivekananda proudly said to the people of the world that ?I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. *We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.? That is the country that we have inherited.*

Sir, now the situation has been turning in such a rapid manner that it has created some sorts of apprehensions and fears among the minority population of our country. Swami Vivekananda *had warned us that ?Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilizations and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now.? Sir, we should not forget these homilies and this noble thought that was preached by Swami Vivekananda. He suggested that we are all Indians. He said that ?I am an Indian.* The ignorant, the poor and destitute, the Brahmin, the Pariah all are Indians. India's Gods and Goddesses are my God. India's society is the cradle of my infancy, the pleasure-garden of my youth, the sacred heaven, the Varanasi of my old age. The soil of

India is my highest heaven, the good of India is my good,". That is why, I thought it prudent to warn those hon. Members who are illuminating the discussion in this august House.

In the President?s speech, it has been referred that the new Parliament building, the magnificent building, has been constructed at the beginning of ?Azadi ka Amrit Kaal?. I am in agreement with my sister from West Bengal who has very distinctly stated and in a sorrowful manner also that hundreds of our MPs had been expelled from this august House for the reason best known to the Government. I would urge upon you that the august House should not be turned into a throttling chamber of democracy. The reason behind it is that Parliament means a panchayat of debate, discussion, disagreement and dissent. This is the laurels of the Parliamentary system of our country. That should not be sunk into oblivion.

सर, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ । राजनाथ सिंह जी को देखकर लगा कि एक बात कहना जरूरी है । हम सब यहां पर गरीबों, किसानों तथा बेरोजगारों के बारे में चर्चा करते हैं । चर्चा करना वाजिब भी है, लेकिन मैं एक दूसरी ओर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा । प्रेसिडेंशियल एड्रेस में सिक्योरिटी कन्सर्न के बारे में एक बात भी नहीं कही गई । मैं हमारे रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि लद्दाख का क्या हाल है? आपने कहा था कि वहां पर यथास्थिति को बहाल किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति कहां पर बहाल हुई है?

सर, दिन-ब-दिन लद्दाख की हालत बुरी होती जा रही है । वहां पर 2 हजार स्कायर किलोमीटर एरिया पर अतिक्रमण हो चुका है । वहां पर 20 राउंड मिलिट्री स्तर पर बातचीत हुई है और 28 राउंड डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हुई है । आज वहां पर चरवाहे नहीं जा पाते हैं । वे अपनी जमीन पर

चराई करवाने नहीं जा पाते हैं । आप लद्दाख के लोगों से पूछिए कि वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्यों चुप बैठे हैं? अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक के हाल दिन-ब-दिन बुरे होते जा रहे हैं । जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी, वहां पर हमारे 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी और आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि यहां पर कोई नहीं घुसा । यहां पर कोई घुसा हुआ नहीं है । इससे अगर किसी को हिम्मत मिली है तो वह चाइना को मिली है । आप देखिए कि वर्ष 2014 से लेकर आज तक एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेलियर होते जा रहे हैं । आप वर्ष 2014 में देख लीजिए, वर्ष 2017 में देख लीजिए, वर्ष 2019 में देख लीजिए या वर्ष 2022 में देख लीजिए, कभी डोकलाम, कभी लद्दाख तो कभी अरुणाचल प्रदेश का मामला सामने आता है । एक के बाद एक देखते जाइए, हमारी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रहे हैं । क्या आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं?

आज मालद्वीव में क्या हो रहा है? वहां पर ?इंडिया आउट? नारा लगाते हुए एक चुनाव होता है, उस समय आपके ? कहां पर थे?? (व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन चौधरी जी ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ है । इन्होंने चाइना के संबंध में और साथ ही साथ भारत और चीन एलएसी के संबंध में जो कुछ भी कहा है, उससे मैं पूरी तरह से असहमति व्यक्त करता हूँ । उसको मैं कंडेम करता हूँ । अगर आप कभी इस पर चर्चा की अनुमति देंगे तो मैं इस विषय पर अपनी बात रखूंगा ।? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, चीन पर चर्चा ही नहीं होती है । चीन पर सवाल ही नहीं लेते हैं ।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैंने आपसे इजाजत ली थी कि मैं सिर्फ पॉलिसी पर बात करूंगा । राजनाथ सिंह जी, पिछले कई सालों से हम लोग बार-बार

गुहार लगाते हुए आ रहे हैं कि चाइना के बारे में चर्चा होनी चाहिए । चाइना आज ?स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? के चलते हमारी घेराबंदी कर रहा है । क्या आप यह नहीं देख पाते हैं? मालद्वीव हमारे हाथ से निकल रहा है । मिनीकॉय से 70 नॉटिकल किलोमीटर दूर मालद्वीव है । क्या आपको 8 डिग्री चैनल के बारे में पता है? 8 डिग्री चैनल मिनीकॉय से मालद्वीव के बीच है । लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है और मिनीकॉय से मालद्वीव के बीच 8 डिग्री चैनल है तो आप भूगोल देख लीजिए । हमारे सी लाइन ऑफ कम्यूनिकेशन, जिसको ?स्लॉक? कहते हैं, एक तरफ होर्मुज एक तरफ मलक्का?(व्यवधान) गल्फ ऑफ एडेन?(व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा । भारत ताकतवर भारत बन गया है । भारत की तरफ कोई भी आंख उठा कर देखने की जुर्रत करेगा, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है । मैं इतना ही कहना चाहूंगा । अनावश्यक रूप से अपने देश को इस पार्लियामेंट के फोरम पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए । अधीर रंजन जी, कभी चर्चा करनी होगी, तो हम आप से चर्चा कर लेंगे ।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं कोई मनगढंत बात नहीं करता हूं । राजनाथ सिंह जी भरोसा रखिए । मैं इस सरकार और देश का एक स्टेक होल्डर हूं । जो कहे जाते हैं, अपोजिशन की तरफ से जो कहे जाते हैं, पेपर में कहिए, टीवी में कहिए, मैं उसी का जिक्र करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, रक्षा मंत्री जी ने आपको हर विषय पर स्पष्ट कर दिया कि हम कोई भी चीज पर समझौता नहीं करते हैं और न करेंगे ।

श्री राज नाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि यहां पर भले ही इनकी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, यदि देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न रहता, तो हमारी पार्टी पुरजोर

तरीके से इनके साथ खड़ी रही है और आगे भी वह खड़ी रहती । इस तरीके से इस पार्लियामेंट के फोरम पर अपने देश को बदनाम करना, इसका कोई औचित्य नहीं है । मैं इनकी इस एप्रोच को कंडेम करता हूं ।?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि मेरी नेत्री यहां मौजूद हैं । देश की रक्षा के लिए यह कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है । आप निश्चिंत रहिए । आप सभी लड़ते जाइए । आप नहीं लड़ते हैं, इसीलिए हम जिक्र करते हैं, आप लड़ते नहीं हैं । लगता है कि आप डरपोक होते जा रहे हैं । इसलिए हमें चिंता हो रही है कि आप लड़ते जाइए । मैं ही नहीं बल्कि सारा देश आपके साथ खड़ा होगा । आप इसे नकार नहीं सकते हैं । आज चाइना रिसर्च शिप मालदीव पहुंचा है । आप यह बताइए । वहां हाइड्रोग्राफिक सर्वे बंद हो चुका है । हमारी फौज के लिए हुक्म दिया गया है और ?इंडिया आउट? के नारे पर एक देश में चुनाव होता है, जो हमारे देश से सिर्फ 70 नॉटिकल मिल दूरी पर है । आप चुप क्यों बैठे थे? क्यों भूटान के साथ चीन का रिश्ता बढ़ रहा है? हमारी गलती कहां है, आप इसे देखिए ।

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप आगे बढ़िए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह मुद्दा है । यह बहुत बड़ा मुद्दा है ।?(व्यवधान) सर, वर्ष 1966 में मालदीव के साथ हमारा संपर्क बना था । हम आपको याद दिलाते हैं कि हम लोगों ने राजीव गांधी जी के जमाने में वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस मालदीव का उद्धार करने के लिए किया था । उस समय आतंकवादियों ने मालदीव पर कब्जा कर लिया था । राहुल गांधी जी के नेतृत्व में?(व्यवधान) सॉरी, दिवंगत नेता राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, हर वक्त राहुल गांधी का चलता है, इसलिए यह हो गया ।?(व्यवधान) बस ठीक है, मैंने अपनी गलती मान ली ।

दिवंगत नेता, हमारे डिपार्टमेंट लीडर स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था और हम लोगों ने वहां से गयूम को

उद्धार किया था । आप पता कर लीजिए । इसीलिए मैं कहता हूं । कांग्रेस ही नहीं बल्कि सारा देश हमारे जांबाज जवानों के साथ खड़ा है । आप यहां बड़े-बड़े दावा करते हैं । आज पाक ऑक्युपाइड का सिर चीर कर चाइना-पाकिस्तान कॉरिडोर काशगर से ग्वादर तक बन रहा है । आप इस सदन में खड़ा होकर कहते थे कि हम पीओके को कब्जे में लाएंगे । हिम्मत है तो पीओके के एक सेब के पेड़ से एक सेब तोड़ कर दिखाइए कि हां हम पीओके से एक सेब लाए हैं । आपको हिम्मत नहीं है ।?(व्यवधान) मैं इस लिए आपको चेताना चाहता हूं । यह और कुछ नहीं है, हम आपको चेताना चाहते हैं ।?(व्यवधान) एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, म्यांमार की हालत बुरी होती जा रही है । वहां कुकी और मैतेइ के बीच में झगड़ा के कारण म्यांमार की हालत बुरी होती जा रही है । म्यांमार में चीन अपना पोर्ट बना रहा है । श्रीलंका में हंबनटोटा पोर्ट बना रहा है । ईस्ट अफ्रीका में जिबूती पोर्ट बना रहा है । अगर अब मालदीव को कब्जा में लेगा तो जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन (SLOC) है, जहां से हमारी सारी एनर्जी आती है, सारा ट्रेड होता है, वह खतरे में आएगा । इसलिए हम चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं । देखिये, चारों तरफ पहाड़ है । हमारा निकलने का रास्ता सिर्फ समुद्र है । अगर वहां पाबंदी लग जाए, जो चाइना चाहता है, तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप आगे बढ़िये ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं इसलिए आपको चेताना चाहता हूं और कुछ नहीं । सर, देश की सुरक्षा सर्वोत्तम होनी चाहिए । मैं इसलिए कहता हूं कि चुशूल से लेकर देमचॉग हर जगह हम खतरे से गुजर रहे हैं । यहां पर बड़ी-बड़ी बात तो की जाती है, लेकिन आप एक बार खुले मन से सोचिये कि हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन बुरी होती जा रही है । चीन हमें एनसर्कल कर रहा है । हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बदले कहते हैं कि नेकलेस ऑफ डायमंड बनाना है, लेकिन असरदार नहीं होता है इसलिए आप और तेजी से काम कीजिए, सारा

विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा । ये बड़ी-बड़ी बात किए जाते हैं । उस दिन कहा था कि 7 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी बन चुकी है । आपके पास कहां से इतने ट्रिलियन डॉलर आते हैं, मुझे पता नहीं है । शायद इस सरकार के ऊपर हथिया बरस रही है । यह हो सकता है । शायद इस सरकार को कुछ अलग से तिलिस्म हासिल हुई है । ये कहां से 7 ट्रिलियन डॉलर की बात करते हैं, यह मुझे पता नहीं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोगों को गुमराह करने के लिए थर्ड इकोनॉमी बताई जाती है । लेकिन आप बताइये कि हमारे देश में पर कैपिटा जीडीपी क्या है? आप बताइये । हमारे देश में आज वर्ष 2023 में पर-कैपिटा जीडीपी 2600 डॉलर है । आप दो देशों जर्मनी और जापान को किनारे करके आगे बढ़ना चाहते हैं । जर्मनी की पर-कैपिटा जीडीपी कितनी है? क्या यह आप जानते हैं? जर्मनी की 52,800 डॉलर है और जापान की 33,950 डॉलर है । आप 2600 डॉलर लेकर बड़ा फुटानी कर रहे हैं कि मैंने क्या-क्या कर दिया । ऐसे नहीं होगा । अगर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो हम जरूर आप लोगों का विरोध करेंगे ।

देखिये, हमारे देश में सत्ता पक्ष बड़े जोर-शोर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं । इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के सारे लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में चुनाव हुआ था । उस समय लोगों को बरगलाने के लिए यह कहा गया था कि अच्छे दिन लाएंगे । हम बाहर से कालाधन लाकर हर व्यक्ति की जेब में 15 लाख रुपये देंगे । चुनाव खत्म हो गया । सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद आपके नेता कह रहे हैं कि यह चुनावी जुमला है । वर्ष 2019 में दूसरी बार आ गए । हमारे पुलवामा में 60 जवान शहीद हए । वहां के गवर्नर मालिक साहब कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुए थे । यह मैं नहीं, बल्कि मालिक साहब गवर्नर कहते थे । उसके बदले में आपने बालाकोट में हमला किया । सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारा देश बदला ले रहा है, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिली कि वहां क्या हुआ? हमें कोई जानकारी नहीं मिली । हमने चश्मदीद गवाह के साथ

यह पाया है कि मिग 21 को वहां क्रेश होते हुए देखा । हमने फ्रेंडली फायर में सी-17 हैलीकॉप्टर को तबाह होते हुए देखा । उसमें हमारे 6-7 एयर परसोनेल की शहादत हुई । कहा गया था कि हमने पाकिस्तान के एफ-16 मार गिराया, पता नहीं कहां गिराया? बालाकोट में असलियत में क्या हुआ, आज तक पता नहीं । क्योंकि आपने आज तक कुछ कहा नहीं । ? (व्यवधान) दूसरी तरफ सारी इंटरनेशनल एजेंसी कहती है कि बालाकोट में ऐसा कुछ सीरियस कंसीक्वेंसेज नहीं हुआ । मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं । Analysis of open source satellite imagery by the Atlantic Council?s Digital Forensic Laboratory, San Francisco based Planet Lab, European Space Imaging, and Australian Strategic Policy Institute have concluded that India did not hit any target of significant on the Jaba hilltop site in the vicinity of Balakot. यह मैं नहीं कहता हूं । बालाकोट की घटना का आज भी लोगों के सामने स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बालाकोट में क्या हुआ है? अगर हो सके तो आप बताइये । हमारे एक और कद्दावर मंत्री अमित शाह जी आ गए हैं । वह बता सकते हैं कि बालाकोट में असलियत में हुआ क्या था? आज तक इसकी जानकारी नहीं है । फिर नया चुनाव आ रहा है । जब चुनाव दरवाजा खटखटा रहा है तो आप प्रभु राम जी की शरण ले रहे हैं । यह आप अच्छा कर रहे हैं । प्रभु राम जी की शरण लेना कोई गुनाह नहीं है । आपने कहा था कि हम राम राज लाकर देंगे ।? (व्यवधान) जिस दिन नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति के द्वारा महात्मा गांधी को गोलियों से भून दिया गया था, उस दिन भी महात्मा गांधी जी ने देहांत के समय ?हे राम? कहा था । मतलब राम का अनुसरण सभी करते हैं ।? (व्यवधान)

एक राम दशरथ का बेटा,

एक राम घट घट में लेटा,

एक राम हैं जगत पसारा,

एक राम हैं जगत से न्यारा ।

इसलिए राम को हम सब मानते हैं । इसलिए आप राम को पेटेंट मत बनाइए । राम आपके चुनावी पेटेंट न हों, मैं यही चाहता हूँ । राम जी सबके हैं ।? (व्यवधान) हमारे देश हिन्दुस्तान में चार वेद हैं, हमारे देश में लाखों भगवान हैं, 18 उपनिषद हैं, दो महाकाव्य हैं । यह देश कोई छोटा-मोटा देश नहीं है । आप लोग राम जी को अपना पेटेंट बनाने की कोशिश न करें, तो लोग आपको धार्मिक कहेंगे ।? (व्यवधान) आप राम को पेटेंट मत बनाइए । राम को चुनावी उपकरण मत बनाइए । आप राम जी को राम की जगह पर ही रहने दीजिए ।? (व्यवधान)

वर्ष 1920 में महात्मा गांधी जी ने कहा था:

?By Ramarajya, I do not mean Hindu Raj. I mean by Ramarajya Divine Raj, the Kingdom of God. For me Rama and Rahim are one and the same deity.?

आज हमारे साथी, हसन साहब कह रहे थे, ठीक है, राम मन्दिर बन गया, अब ज्ञानवापी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, मथुरा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है ।? (व्यवधान) राजनाथ सिंह जी, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं । हमारे देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, आप उन लोगों के मन में डर पैदा न करें, तो बेहतर होगा । आरएसएस कहता है कि राम जन्मभूमि के बाद हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लोगों के अन्दर शंका है कि कोर्ट से उनके पक्ष में राय चली जाएगी । यह मैं नहीं कहता, बल्कि लोगों के मन में यह शंका है ।? (व्यवधान)

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप एक कानून लाइए, जिससे इस तरह का और कोई अतिक्रमण न हो, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा असर होने वाला है ।? (व्यवधान)

सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने इसको संज्ञान में लिया।? (व्यवधान) हमारे देश के अगल-बगल में जो देश हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि सभी देशों में केवल हिन्दु ही रहते हैं, वहाँ मुसलमान भी रहते हैं । उनके मन में पीड़ा हो, ऐसा काम न करें, तो देश के लिए बेहतर होगा ।

मैं सरकार को एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार को अच्छी सलाह देना हमारा फर्ज बनता है ।

सर, सरकार को मैं एक और बात कहना चाहता हूँ । ये कहते हैं कि हम बहुत ही तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर हम 111वें नम्बर पर आ गये हैं । दूसरी बात, यह भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली सरकार है, लेकिन वर्ष 2023 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कहा जाता है कि India ranks 93rd out of 180 countries in the Corruption Perception Index. जिस देश में सुख नहीं है, जिस देश में दुख ज्यादा है, उसे least happy nation कहते हैं । Out of 136 least happy nations in the world, India ranks 126th. आप यह मानकर चलिए । 197 देशों के अन्दर पर-कैपिटा इनकम में हमारी हालत क्या है, आप जानते हैं? इसमें हमारा स्थान 142 वें नम्बर पर है । आप लोगों से कहिए कि जेब में हाथ डालकर रखो और कहो कि मोदी ने तुमको क्या दिया, बीजेपी सरकार ने क्या दिया? जेब में हाथ रखकर कहो । आप तक पर-कैपिटा एक्सपेंडिचर का आँकड़ा पेश करने की आपकी हिम्मत नहीं हुई । वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार, Out of 180 countries, India stands at 161st. मतलब यह है कि हमारे देश में मीडिया वालों को आज़ादी नहीं है । दिन-पर-दिन वह आज़ादी खतरे में पड़ रही है । इसलिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मीडिया को आज़ादी चाहिए, लोगों को आज़ादी चाहिए । देश में हर समुदाय के बीच शांति का माहौल हो, एक अच्छा जीवन का माहौल बनाना चाहिए । अगर आप ऐसा माहौल नहीं बना पाते हैं तो देश आगे नहीं जा सकता है ।

सर, हमें बहुत कुछ करना है । राजीव जी कहते थे कि एक मॉर्डन इंडिया बनाने के लिए हमें हमारे देश में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति करनी चाहिए । आप वह करके दिखाइए । वे मेरा भारत महान कहते थे और मेरा भारत महान के चलते उन्होंने अपना रास्ता अपनाते हुए देशवासियों को भरोसा दिया था । मैं उनकी एक बात कोट करना चाहता हूँ: ?We cannot and will not rest until we have won true swaraj for the hungry and spiritually starving millions.? राजीव जी यह कहते थे । जवाहर लाल नेहरू जी कहते थे: ?Culture is the soul of a nation. It is what makes us who we are and gives us a sense of identity.?

यही हमारे देश की परम्परा है । इस परम्परा को हमें बचाकर रखना चाहिए । मैं मालदीव की बात कर रहा था तो आप चिल्लाने लगे, लेकिन मालदीव की हालत आप देखो । उसके साथ हमारे आजू-बाजू में देखिए ।

माननीय अध्यक्ष : ओके ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मुझे एक छोटी सी बात और कहनी है । मैं कहना चाहता हूँ कि आप अग्निवीर स्कीम के बारे में भी दोबारा सोचिए । इस अग्निवीर स्कीम के चलते नेपाल के साथ हमारा रिश्ता खराब होता जा रहा है । वर्ष 1947 में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के साथ हुआ था कि उनके देश के जवानों को हम अपनी फौज में रख सकते हैं, हम अपनी फौज में भर्ती करा सकते हैं, लेकिन इस अग्निवीर स्कीम के चलते वे लोग थोड़ा परेशानी में हैं । हमारा काला पानी को लेकर नेपाल से थोड़ा टकराव भी है । चीन नेपाल के अंदर घुसना चाहता है । आप सतर्क रहिए । मैं आपको सिर्फ चेताना चाहता हूँ । भूटान, नेपाल, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं । बांग्लादेश में सबमरीन डिप्लोमेसी हो रही है । म्यांमार में कलियापो में एक पोर्ट बना रहे हैं । श्रीलंका में हम्बनटोटा बन चुका है । पाकिस्तान में ग्वादर बन चुका है । हम कहाँ जाएँ? हम चारों तरफ घेरेबंदी में फँस रहे हैं । मैं मानता हूँ कि आप जरूर प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ठोस कदम उठाने से

हमें लाभ होगा। मैंने आपको यह सलाह देना जरूरी समझा और इसीलिए मैं यह सलाह आपको दे रहा हूँ।

मैं एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि समय काफी कम है। देखिए, बात यह है कि हमारे देश में सब धर्म के लोग मिलकर रहें, यही हमारा मकसद है। एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए। एक शायर ने कहा था:

?काबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की जात से है।,

तुम राम कहो या रहीम कहो, मकसद तो उसी की बात से है।।?

यह हम मानकर चलें।

मैं परशुराम शुक्ल जी की एक कविता का यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ:

धरती से सीखा है हमने सबका बोझ उठाना

और गगन से सीखा है हमने ऊपर उठते जाना

सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना

चंदा की किरणों से सीखा सबकी पीड़ा हरना

पर्वत से सीखा है हमने दृढ़ संकल्प बनाना

और नदी से सीखा हमने आगे बढ़ते रहना।

सागर की लहरों से सीखा सुख दु:ख को सह जाना

तूफानों ने यह सिखलाया आफत से टकराना।

हम आफत से टकराएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, देश को आगे ले जाएंगे और जहाँ-जहाँ खामियाँ देखेंगे, चाहे इस पार हो या उस पार हो, कोई कहीं रहे,

हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि अगली बार आप इधर रहोगे, हम उधर रहेंगे, यह मानकर आप चलिए । सर, धन्यवाद ।? (व्यवधान)

महोदय, यह राष्ट्रपति महोदया जी का अभिभाषण नहीं रहा, यह बीजेपी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो बन गया है । मैं इस इलेक्शन मैनिफेस्टो का विरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ । नमस्कार ।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अधीर जी, यह पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद, मैं आपको एक प्रपोजल देता हूँ, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बात करते-करते आपने ऐसी बातें कह दीं जो सत्य तो नहीं हैं, साथ ही साथ देश को नुकसान पहुँचाने वाली बात आपने कही है ।? (व्यवधान) आप सुनिए ।? (व्यवधान) आपने इतना भाषण दिया ।? (व्यवधान) यह बेसिक कर्टसी होती है ।? (व्यवधान) सर, इन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर, लद्दाख से लेकर अरूणाचल प्रदेश तक चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है ।? (व्यवधान) आप एक लीडर होकर इस तरह की बातें इस सदन में कर रहे हैं ।? (व्यवधान)

<u>17.00 hrs</u>

अध्यक्ष जी, चीन ने जितनी भी जमीन पर कब्जा किया है, वह कांग्रेस सरकार के समय कब्जा किया है ।? (व्यवधान) मोदी जी के आने के बाद एक इंच जमीन को भी चीन की फोर्स ने आक्यूपाई नहीं किया है ।? (व्यवधान) आपको मेरे साथ चलना होगा । आप गलत बात करके बच नहीं सकते हैं । पाकिस्तान की भाषा, चीन की भाषा और कांग्रेस पार्टी की भाषा एक हो गई है और ताल मेल में बात करते हैं ।? (व्यवधान) आपको शर्म आनी चाहिए ।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि अतिक्रमण करने की कोशिश हो रही है । लद्दाख से अरूणाचल, चाइना 3344 किलोमीटर बार्डर पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है ।

सतीश कुमार गौतम ।

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय । मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । डॉ. हिना गावीत और एसपी सिंह बघेल जी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष जी, गरीब की जिंदगी में तीन चीजों की आवश्यकता होती है ? रोटी, कपड़ा और मकान । ये तीनों चीजें देने का काम देश के प्रधान सेवक मोदी जी ने किया है । उधर के लोगों ने केवल कहा, लेकिन किया नहीं । इस काम को देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया ।

17.02 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

प्रधान मंत्री आवास ने आम जन के जीवन को बदलने का काम किया । कांग्रेस वालों को यह पता नहीं होगा कि छप्पर क्या होता है और झोंपड़ी क्या होती है । चौमासे में जब गरीब उस झोंपड़ी में रहता है और उसकी छत से जब पानी टपकता है, तो वह अपने बच्चों को सूखे में सुलाने का प्रयास करता है । इसके लिए देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने प्रधान मंत्री आवास देने का काम किया है । देश के प्रधान मंत्री की यह गरीबों के लिए सोच है ।

सभापति जी, मकान देने के बाद उसमें रोशनी देने की आवश्यकता पड़ती है । सौभाग्य योजना से देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने निशुल्क बिजली देने का काम किया । केबल फ्री, स्विच फ्री, बल्ब फ्री और मीटर भी फ्री । कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है । गरीब को रोशनी मिलनी चाहिए । पहले गरीब मिट्टी के तेल की शीशी लेकर ढक्कन में छेद करके बाती

लगाकर पढ़ाई करता था, आज उसके घर को रोशन करने का काम देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है । हर घर को स्वच्छ पानी मिले, उसके लिए ? हर घर नल? योजना से स्वच्छ पानी देने का काम किया है । रहने के लिए मकान मिल गया । शिक्षा के लिए रोशनी मिल गई । पीने के लिए पानी मिल गया और श्री अन्न योजना से उसे मुफ्त राशन देने का काम किया । मकान मिला, रोशनी मिली, पानी मिला और राशन मिल गया । उसके बाद प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना से रोटी बनाने के लिए गैस प्रदान की । यह मोदी जी की सरकार है, यह गरीबों की सरकार है ।

-

<u>17.04 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष जी, उज्ज्वला गैस मिलने के बाद उसने रोटी बना ली । सारे परिवार ने रोटी खा ली और सो गए । सुबह उसे शौचालय की आवश्यकता पड़ती है । उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय देने का काम किया, ये मोदी सरकार है । गरीब को मकान मिल गया, रोशनी मिल गई, पानी मिल गया, अन्न मिल गया, शौचालय मिल गया । अब आप देखिए कि यदि कोई गरीब बीमार हो जाता है, तो उसके लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत से पांच लाख रुपये इलाज के लिए देने हेतु आयुष्मान कार्ड देने का काम किया । वह कोई भी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सभी जगह वह अपना फ्री इलाज करा पाएगा । मैंने गरीबी में जिंदगी काटी है । मेरी माँ जब मेरे पिता से पैसे बचाकर रखती थी तो रजाई के कवर में, तकिए के कवर में पुड़िया बांध कर रख देती थी लेकिन देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने जन धन योजना के तहत बैंक में एकाउंट खोलने का काम किया । यह मोदी की सरकार है ।

अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि रेहड़ी-पटरी, नाई की दुकान, मोची की दुकान के लिए गरीब के पास पैसा नहीं होता । वे ब्याज पर पैसे

लेकर आते थे, लेकिन देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना से उन्हें लोन देकर रोजगार देने का काम किया । मोदी सरकार और कांग्रेस की सरकार में यह फर्क है ।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों को हमेशा गरीब ही बनाए रखा । देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर उन किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया ? यह है मोदी सरकार । इस सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना दी, ?बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? का नारा दिया और समाज में कन्या शिशु के प्रति सोच को बदलने का काम किया ।

इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना दी, सौभाग्य योजना के माध्यम से लोगों को रोशनी दी । गरीब को ये सब मिलने के बाद उसके बच्चे की पढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है । उसके लिए इस सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किया, जिसमें शिक्षा फ्री, किताब फ्री, ड्रेस फ्री, रहना-खाना फ्री दिया जाता है । इसे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने दिया, यह है मोदी जी की सरकार ।

आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गांव-गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, हमारी बहनें, जो गरीब हैं, जिनके पास व्यवसाय नहीं है और वे शिक्षित हैं, उनके लिए ?नमो ड्रोन दीदी? योजना लाकर उन्हें लखपति बनाने का काम देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया ? यह है मोदी जी की सरकार ।

अध्यक्ष महोदय, देश के माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने चार जाति घोषित कीं, जिनमें गरीब, किसान, नारी और युवा हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे यहां का खिलाड़ी रिंकू सिंह आज क्रिकेट खेल रहा है । किसी को उसकी जाति नहीं पता है । वह केवल युवा है । युवा, युवा होता है, किसान, किसान होता है । जब एक किसान किसी कलेक्टर के पास जाता है तो वह कहता है कि कलेक्टर साहब, मैं तो आपका किसान हूं, वह यह नहीं कहता

कि वह कितना बड़ा किसान है । वह केवल यह कहता है कि ?मैं तो किसान हूं ।? वैसे ही एक गरीब, गरीब होता है, एक नारी, नारी का रूप होती है । हमें ये चार जाति देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने दी हैं । यह देश बदल रहा है, यह भारत बदल रहा है ।

महोदय, जिस तरह से अनुच्छेद-370, धारा-35ए को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा समाप्त किया गया, उससे देश में लोगों द्वारा गर्व के साथ यह कहा गया कि वह भारत माता का बेटा है, वह भारत के लिए जीता है । यही भाव हमारी रगों में होने चाहिए । यह भारत का खून है । इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह करके दिखाया, अनुच्छेद-370 और धारा-35ए को हटाकर दिखाया ।

महोदय, जिस समय कोरोना बीमारी का दौर चल रहा था, उस समय कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता अपने-अपने घरों में छिपे पड़े थे, लोगों को लग रहा था कि कहीं हमारी जान न चली जाए । देश के प्रधान मंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा यह क्लियर आदेश था कि गरीब लोगों की सेवा कीजिए, रोड्स पर जाइए, उन्हें खाना दीजिए, जिनके पास चप्पलें नहीं हैं, उन्हें चप्पल पहनाइए, उन्हें राशन दीजिए । गरीबों के लिए वैक्सीन लाने का काम मोदी जी ने किया ? यह है मोदी सरकार ।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व में कांग्रेस के शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्ज़ा देने के लिए एक लेटर जारी कर दिया गया । वहां पर एस.सी., एस.टी. और ओबीसी के बच्चे नहीं पढ़ सकते । मैंने देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी से यह कहा कि माननीय मोदी जी, मेरे यहां एस.सी./एस.टी. के बच्चे नहीं पढ़ते, तो उन्होंने अलीगढ़ में ही जाट शिरोमणि राजा महेन्द्र प्रताप के नाम से एक अलग यूनिवर्सिटी देने का काम किया ? यह है मोदी की सरकार ।

आज अलीगढ़ के अन्दर डिफेंस कॉरिडोर देने का काम किया गया है । जब सीमा पर आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे अलीगढ़ के बच्चे सीमा पर गोला-बारूद चलाने का काम करेंगे । इससे उनका सीना चौड़ा होगा कि इस देश के प्रधान मंत्री, गरीब माँ के बेटे ने, इस प्रधान सेवक ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर देने का काम किया ? यह है मोदी सरकार ।

अध्यक्ष महोदय, पहले क्या था? पहले यह था कि मोदी से पहले राजा थे, मोदी के बाद सेवक हैं । मोदी से पहले राजपथ था, मोदी के बाद कर्त्तव्य पथ है । मोदी से पहले सत्ता थी, मोदी के बाद सेवा है । मोदी से पहले समस्या थी, मोदी के बाद समाधान है । मोदी से पहले आतंक था, मोदी के बाद शांति है । मोदी से पहले गरीबी थी, मोदी के बाद समृद्धि है । मोदी से पहले बेराजगारी थी, मोदी के बाद कौशल है । मोदी से पहले विभाजन था, मोदी के बाद एकता है । मोदी से पहले निराशा थी, मोदी के बाद आशा है । मोदी से पहले तुष्टीकरण था, मोदी के बाद विश्वास है । मोदी से पहले परिवारवाद था, मोदी के बाद लोकतंत्र है । मोदी से पहले भय था, मोदी के बाद धैर्य है । यह है राम राज्य, यह है राम राज्य, यह है राम राज्य । इसे कहते हैं राम राज्य ।

भारत माता की जय ।

धन्यवाद ।

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): I extend my sincere thanks to the hon. President for highlighting the visionary steps of this Government. Over the last decade, the transformative reforms introduced have yielded remarkable results that have not only propelled economic development but have also focused on inclusivity, ensuring that benefits reach every stratum of society.

Under the leadership of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we find ourselves at the juncture of an extraordinary era,

witnessing unparalleled achievements and monumental milestones as part of the ongoing Amrit Mahotsav.

Our nation, under this Government, has showcased remarkable economic resilience, emerging as the fastest-growing major economy with a sustained growth rate of over 7.5 per cent for two consecutive quarters amid challenging global conditions. This commendable feat has not only bolstered our economic standing but also reflects this Government's adept handling of complex financial landscapes.

The delineation of the 'Idea of Nation First' encapsulates the Government's focus on poverty alleviation and economic prosperity. Over the last decade, approximately 25 crore citizens have ascended from poverty which is a testament to the success of targeted interventions, economic reforms, and initiatives aimed at enhancing education and healthcare accessibility.

Guided by the principles of "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas," this Government remains unwavering in its dedication to ensuring equal opportunities for every segment of society. This commitment is evident through various measures, such as extending reservation benefits to economically weaker sections in the general category, introducing a 27 per cent reservation for OBCs in medical courses, and according Constitutional status to the National Commission for Backward Classes.

In the pursuit of inclusive growth, the Vishwakarma families, pivotal for skill transmission across generations, have found support through the PM Vishwakarma Yojana, impacting over 84 lakh

citizens. Similarly, the PM SVANidhi Yojana has addressed the challenges faced by street vendors, granting access to the banking system and disbursing collateral-free loans exceeding Rs. 10,000 Crore.

Embarking on a path of comprehensive development, the Government has extended its focus to long-neglected areas through initiatives like the Vibrant Village Programme, targeting villages adjacent to borders, and the Aspirational Districts Programme, aimed at bringing progress to historically lagging blocks.

In the realms of space exploration, sports, and diplomacy, India has truly excelled. From becoming the first country to plant its flag on the southern pole of the Moon to the successful launch of the Aditya Mission, India has solidified its position as a formidable player in the global space race. Diplomatically, the success of the historic G-20 Summit underscored India's influential role in shaping international dialogues and policies. Simultaneously, India's stellar performance in sports with winning over 100 medals in both the Asian Games and Para Asian Games, reflects our commitment to sporting excellence.

These achievements, coupled with monumental infrastructural developments like the completion of the largest sea-bridge Atal Setu, the introduction of Namo Bharat and Amrit Bharat trains, and India's fastest 5G rollout, collectively represent a transformative year under the government's visionary guidance, shaping the development of 'Viksit Bharat'.

Over the years, significant strides have been made by this Government in enhancing energy infrastructure and ensuring broader access to energy resources. From 2014 to 2023, my constituency witnessed impressive growth in key areas.

The number of petrol pumps increased from 132 to 206, demonstrating a notable 56.06% expansion. LPG distributors also saw commendable progress, rising from 28 to 43, reflecting a positive change of 53.57 per cent. The proactive establishment of 23 CNG stations, where none existed in 2014, underscores a commitment to alternative fuel options. Furthermore, LPG connections more than doubled, surging from 2.22 lakh in 2014 to 4.65 lakh in 2023, showcasing robust growth at 109.91% change. These endeavors align with the Government's dedication to advancing energy infrastructure in Jamnagar.

The Government's steadfast commitment to empowering MSMEs and small entrepreneurs is evident through a comprehensive set of measures. Notably, the definition of MSMEs has been broadened, now encompassing investment and turnover criteria, reflecting a nuanced approach to classification.

With approximately 3.5 crore MSMEs currently registered on the Udyam and Udyam Assist Portal, the Government has successfully streamlined the registration process, facilitating a more inclusive and accessible environment for businesses. Furthermore, the implementation of the Credit Guarantee Scheme for MSMEs has been instrumental, with guarantees totaling nearly Rs. 5 lakh crore sanctioned in recent years. This remarkable figure stands as a

testament to the Government's proactive stance, surpassing six times the amount provided in the decade preceding 2014 and fortifying the foundation for a thriving and resilient MSME sector.

The city of Jamnagar, renowned for its industrial prowess, is now reaping the benefits of these strategic government initiatives, experiencing a notable boost in its MSME sector as a result of these concerted efforts.

As I draw to a close, I would like to extend my heartfelt congratulations to the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for his unwavering commitment and guidance that has propelled our nation to unprecedented heights across various realms of development. His steadfast leadership, marked by economic reforms and the pursuit of global excellence, has played a pivotal role in our collective journey toward becoming a global powerhouse.

As I stand here, I urge my esteemed colleagues to rally behind the initiatives set forth by the Government in its endeavor to shape India into a developed nation, a nation that seamlessly blends a forward-looking vision with deep roots firmly anchored in its glorious past.

I support the Motion of Thanks on the President's Address in its entirety.

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का मौका मिला है । मैं हमारी पार्टी

की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और विश्वास जताया कि मैं गरीब मजलूम, दलित और पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों की आवाज इस सदन में रख सकूं ।

बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ों, गरीबों, किसानों, बेरोजगारों व समाज के अंतिम वंचित तबके के लिए विकास कार्यों का विवरण और उन कार्यों के लिए मद की व्यवस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

मैं जिस संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आया हूं, जिसके अंतर्गत दो जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर आते हैं, यह हर मायने में बहुत ही पिछड़ा है और उत्तर प्रदेश के कुल 8 अति पिछड़े जिलों में आता है । अभी भी यहां के लोग ज्यादातर कच्चे मकानों व झोपड़पट्टी में रहते हैं । यहां के लोगों को जीवन जीने के लिए मूलभूत बुनियादी सुविधाओं जैसे - स्वच्छ और पीने योग्य पानी, बिजली, सड़क, रेल, उच्च और गुणवत्तायुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है ।

यहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण कई हजार लोगों की जान और माल की क्षति होती है । इन पिछड़े जिलों का सर्वांगीण विकास हो सके, क्षेत्र के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है ।

सरकार किसानों की आय दोगुना करने का पिछले 10 सालों से दम भर रही है, लेकिन सरकार किसानों की आय अभी तक दोगुना नहीं हुई है ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो किसानों की फसलों को बेचने के लिए कुछ दिनों का क्रय केंद्र बनाया जाता है, उसमें किसान समय रहते अगर अपनी फसल को बेच नहीं पाता है, तो उसका लाभ बिचौलिए उठाते हैं और किसान अपनी फसलों को ओने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हो जाते

हैं । मैं चाहता हूं कि इस क्रय केंद्र को स्थाई किया जाए, ताकि किसान अपनी सुविधानुसार कभी भी निर्धारित मूल्य के तहत अपनी फसल को बेच सकें ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में महंगाई को कम करने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है । जबकि हमारे देश में 10 वर्षो में बेरोजगारी स्तर काफी बढ़ा है । इसे कैसे दूर किया जाएगा, इसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में आज भी कोई रेल लाइन नहीं है । बहराइच, खलीलाबाद, भिंगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, उतरौला, डुमरियागंज, मेहदावल और वासी रेल परियोजना की मंजूरी हो गई है, पर जमीनी स्तर पर इस परियोजना में अब तक कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें ।

हमारे देश के पिछड़े सुदूर क्षेत्रों में स्थित गांवों में स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने हेतु नए अस्पताल खोलने या मौजूदा अस्पतालों को आधुनिक स्वास्थ्य संसाधनों से युक्त बनाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है ।

SSB सीमा सुरक्षा बल के जवान जो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल कर दिन-रात देश की रखवाली करते हैं, उनके लिए नेपाल बॉर्डर के किनारे चौकियां बनी हुई हैं, लेकिन वहां जाने के लिए न तो कोई रास्ता है और न ही पीने के लिए स्वच्छ पानी है और न ही वहां बिजली और मोबाइल नेटवर्क की कोई व्यवस्था है । इस पर भी सरकार को कदम उठाने की जरूरत है ।

आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर बड़े ही दुःख के साथ कहना पड रहा है कि श्रावस्ती जिला आज भी शिक्षा के मामले में भारत में सबसे पिछड़ा हुआ है । पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के बच्चों को महंगाई के कारण उच्च

गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पा रही है । सरकार को वर्तमान में देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करने पर विशेष विचार करने की जरूरत है, जिसका महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

जातीय जनगणना के बारे में भी अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में भगवान बुद्ध जी ने अपने जीवन काल के करीब 24 से 25 साल व्यतीत किए हैं । यहां देश के कोने-कोने और विदेशों से भी हजारों अनुयायी और पर्यटक घूमने आते हैं । वाबजूद इसके अब तक कोई हवाई यात्रा शुरू नहीं की गई है, जिसका अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

आज सरकार को देश के जन-जन के सर्वांगीण विकास के लिए उपरोक्त बिंदुओं पर ध्यान देते हुए धरातल पर अमल में लाने की जरूरत है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में 2-3 माह पहले 7-8 बच्चों को चीता ने अपना निवाला बनाया था । भारत सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम 25 लाख रुपये दे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज) : मैं सरकार की योजनाओं और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं । महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण से मिशन मोड में युवाओं को रोजगार देने की बात कही है । मैं उनका समर्थन भी करती हूं, लेकिन जो रोजगार दिए गए हैं, वे स्थायी नहीं हैं । वे सीमित अवधि या आउटसोर्सिंग से हैं, जबकि केन्द्र और राज्यों में लाखों पद खाली हैं । सरकार एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए बैकलॉग निकालकर लाखों युवाओं को स्थायी रोजगार देने का काम करे । मैं यह अनुरोध करती हूं ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना की बात कही है, जिसमें जिन परिवारों के सदस्यों की संख्या 6 है, यह सिर्फ उन्हीं को मिल रही है । इस योजना से गरीब परिवार को काफी मदद मिलती है । मेरी सरकार से मांग है कि इसको सिर्फ 6 सदस्यों तक सीमित न रखा जाए, इसे 5 और 4 सदस्यों के लिए भी किया जाए । महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ?हर घर नल? से जल की योजना की बात कही है । यह काफी हितकारी योजना है । सरकार गरीब परिवारों तक जल पहुंचाने का काम कर रही है । यह सराहनीय कार्य है, लेकिन इस योजना में भी कार्य करने वाली संस्थायें हैं । गांवों में जाने वाली पक्की सड़कें, सीसी, इंटरलॉकिंग, खडंजा को तोड़कर पाइप डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन टूटी सड़कों को बनाने का काम नहीं कर रहे हैं । उनकी कई महीनों तक मरमत्त नहीं करते हैं, जिससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी मांग करती हूं कि ?हर घर नल? से जल योजना के साथ ?हर घर नाली? की भी योजना को जोड़ा जाए ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने का यह कार्य बताया, जो बहुत सराहनीय है, लेकिन मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज की तरफ ले जाना चाहूंगी, जहां पीएमजीएसवाई का फेस-1, फेस-2, फेस-3 का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है । सरकार कम से कम हर जिले से रिपोर्ट मंगवाकर इन कार्यों की समीक्षा करे और जो जिले पिछड़े हैं, उन पर कार्रवाई करने का काम करे ।

मैं सरकार को बधाई देती हूं कि अयोध्या में 500 साल से तिरपाल में रहने के बाद रामलला अपने घर में पुनः स्थापित हुए है । मेरी सरकार से मांग है कि अयोध्या और वाराणसी के बीच आजमगढ़ है, जहां कई धार्मिक स्थान हैं । विधान सभा निजामाबाद में तमसा नदी के तट पर स्थित दुर्वासा ऋषि धाम, दत्तात्रेय ऋषि धाम, चंद्रमा ऋषि धाम हैं, जो कि पौराणिक महत्व के तीर्थ

स्थल हैं । दीदारगंज के अंतर्गत अवंतिका पुरी धाम, जो महाभारत कालीन पौराणिक स्थल है । इसके साथ ही निजामाबाद में गुरु नानक देव जी की चरण पादुका स्थली तथा लालगंज का पल्हना धाम है, जो कि शक्तिपीठ है । ये सभी पौराणिक महत्व के स्थल हैं । इनका विकास करके अगर इन्हें अयोध्या सर्किट से जोड़ दिया जाए तो विदेश से आने वाले पर्यटक वाराणसी अयोध्या एवं गोरखनाथ मंदिर के साथ मध्य में स्थित आजमगढ़ में भी आएंगे और बेहतर पर्यटन क्षेत्र के विकास की संभावना है । यहां रोजगार के साथ साथ प्रदेश को भी आर्थिक लाभ मिलेगा ।

लालगंज क्षेत्र के पांचो विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध पहलवानों के अखाड़े रहे हैं, जहां से तमाम नामी-गिरामी पहलवानों ने राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है । सरकारी सुविधा के अभाव में यह खेल अब समाप्ति की ओर है । अतः यहां पर कुश्ती के लिए आधुनिक ऑडिटोरियम या मिनी स्टेडियम की आवश्यकता है । अगर ऐसा होता है तो यहां से भी हरियाणा की तरह कुश्ती के लिए विश्व स्तरीय पहलवान निकल सकते हैं तथा खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं । लालगंज के फूलपुर विधान सभा में पूर्व में लाल मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, जिसे लाल सोना भी कहा जाता था । यहां से लाल मिर्च का व्यापार अन्य जिलों एवं राज्यों में निर्यात के रूप में होता था । अगर यहां पर प्रशिक्षण एवं प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना हो सके तो लाल मिर्च की खेती को बढ़ाया जा सकता है । इसके साथ ही रोजगार के अवसर की अपार संभावनाएं हैं । ?वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट? के तहत मेरे क्षेत्र की ब्लैक पॉटरी के आयात निर्यात के साधन दिए जाएं और उसके लिए बाजार भी दिए जाएं ।

आजमगढ़ जिले के शाही पुल (जिसका निर्माण शेरशाह द्वारा कराया गया था) से 40 किलोमीटर दूर बेलवाई तक जर्जर सड़क जो तीन विधान सभाओं सदर, निजामाबाद, फूलपुर को जोड़ती है । यह आगामी लोक सभा चुनाव में ज्वलंत मुद्दा है । मऊ-शाहगंज के बीच फरिहा रेलवे स्टेशन पर मेल

ट्रेनों का ठहराव व गेट नंबर 40 पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण एवं समपार संख्या 41 का निर्माण हो । वाराणसी से लालगंज होते हुए आजमगढ़ से गोरखपुर तक की सीधी रेल लाइन की मांग मैंने कई बार की है । उस पर 2022-23 में बजट भी आवंटित हो गया है, लेकिन जो जनता की मांग थी कि लालगंज में स्टेशन बनाया जाए और लालगंज से होते हुए रेलवे लाइन जाए, इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में इस बात पर लोगों में बहुत आक्रोश है और जनता धरना प्रदर्शन कर रही है । मैंने भी कई बार मंत्री जी से लेकर शासन-प्रशाशन को भी अवगत कराया है । मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इस पर ध्यान दे और जनता की मांग को देखते हुए लालगंज से होते हुए रेलवे लाइन बनाई जाए तथा लालगंज में स्टेशन बनाने का कार्य किया जाए ।

माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार ने मिशन मोड में लाखों नौकरियां दी हैं । माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि लाखों बेरोजगारों को नौकरियां मिली हैं । मैं सरकार से सहमत हूं, लेकिन ज्यादातर नौकरियों को आउटसोर्सिंग से भरा गया है । विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली हैं, जिनको बैकलॉग के माध्यम से जल्द से जल्द भरने की मांग में करती हूं । एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के गरीब छात्रों ने टेक्निकल डिग्री जैसे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, बी.एड, बीटीसी, पैरामेडिकल कोर्सेज एवं तकनीकी डिग्रियों में बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन सरकार द्वारा एकमुश्त फीस जमा करने के कारण काफी बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं । सभी शिक्षण संस्थाओं के आधी से अधिक सीटें खाली पड़ी हैं । आपसे निवेदन है कि पूर्व में जिस तरह से शून्य बैलेंस पर एडमिशन होते थे, उसकी अनुमति प्रदान की जाए, जिससे लाखों बच्चे तकनीकी शिक्षा में एडमिशन ले सकें ।

पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास दिए हैं, लेकिन सिर्फ 1 लाख 20 हजार रुपये में आज की महंगाई में घर बनाना मुश्किल है ।

महंगाई को देखते हुए उसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाए, क्योंकि मिट्टी, बालू, ईंट, सीमेंट, सरिया की दर पिछले 5 वर्षों से दोगुनी हो गई है । केंद्र और राज्य सरकारों में लगभग लाखों कर्मचारी अपनी आधी से अधिक ज़िन्दगी सरकारों और आम जनमानस की सेवा में लगा देते है । वे न तो अपने परिवार न बच्चों को नौकरी के चलते अपना पूरा समय दे पाते हैं और जब पदमुक्त होते है तो सरकार से उम्मीद रखते है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में सरकार पेंशन के द्वारा उनकी सहायता करेगी, उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान में कमी नहीं आने देगी, लेकिन सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को हटाकर नई पेंशन लागू की है, जो उन कर्मचारियो पर आत्मघात है । पेंशन मिलने पर वह अपनी ज़िन्दगी अच्छे ढंग से जी सकते हैं । परिवारजन और बच्चे भी उनका सम्मान करते हैं और अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन नई पेंशन नीति में आज की महंगाई दर को देखते हुए उनकी मूल जरूरतों का भी खर्च नहीं निकल पायेगा । इसलिए मेरी सरकार से मांग है की कर्मचारियों की बेहतरी को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए ।

किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये मिल रहे हैं । क्या सरकार इसे बढ़ाकर 6000 रुपये करेगी? आयुष्मान योजना सरकार की बहुत लाभकारी योजना है । इससे सरकार परिवार के 6 संख्या वाले गरीबों को प्रत्येक व्यक्ति को पांच लाख रुपये को सीधा लाभ दे रही है । मेरी सरकार से मांग है इस योजना को सिर्फ 6 संख्या वाले परिवार तक न सीमित रखा जाये, बल्कि जिनके 5 और 4 संख्या वाले परिवार को भी यह लाभ दिया जाए ।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी ने नवनिर्मित संसद भवन में बजट सत्र के पहले भाषण को नये भारत के निर्माण का संकल्प बताते हुए वर्ष 2023-24 को ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला बताया ।

अभिभाषण में राम मंदिर, महिला आरक्षण, विभिन्न बिलों के पास होने से लेकर तीन तलाक, अनुच्छेद 370 और डिजिटल क्रान्ति की उपलब्धियों का जिक्र किया ।

अभिभाषण में विशेषत: सम्मिलित ?

?राम मंदिर को बताया सदियों की इच्छा पूरी होने जैसा ।

? देश के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका ।

? तीन दशक बाद महिला आरक्षण बिल पास होना अर्थात नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाना ।

? गणतंत्र दिवस की परेड में महिलाओं के शामिल होने से लेकर महिला शक्ति के विभिन्न आयामों को संजोने की कोशिश की गई ।

? खेती-बाड़ी को लाभकारी बनाने के लिए हर संभव प्रयास ।

? 10 करोड़ से अधिक किसानों को देश की कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी गई है ।

? भारत सबसे विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ा है । आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ।

? विश्व ने दो बड़े युध्द देखे और कोरोना जैसी महामारी का संकट देखा लेकिन महंगाई
को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया गया ।

? भारत को सबसे बड़ा समुद्र पुल अटल सेतु मिला ।

?सरकार ने मिशन मोड पर लाखों रोजगार दिये ।

? वन रैंक पन पेंशन का प्रावधान किया, साथ ही साथ चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई ।

? पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने को बड़ी उपलब्धि बताया ।

? खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में वृध्दि हुई ।

? इलेक्ट्रिक वाहनों की बिकी में वृध्दि ।

? भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम ।

? भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता ।

? भारत आज खिलौनों का निर्यात करने लगा है ।

? स्पेस सेक्टर को भारत के युवाओं के लिए खोल दिया गया है ।

? भारत में बिजनेस करना आसान हो इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं और लगातार इस हेतु काम किया जा रहा है ।

? आर्थिक नीतियां प्रशंसनीय है, आज एक लाख से ज्यादा स्टार्ट अप हैं ।

? एक करोड़ से ज्यादा लोग जी एस टी दे रहे हैं ।

? देश की तरक्की के लिए युवाओं की क्षमताओं का उपयोग देश के निर्माण में करने पर जोर दिया ।

? चार स्तंभों को मजबूत करने का कार्य- युवा शक्ति, किसान, नारी शक्ति और गरीबों का विकास ।

? सरकार की प्राथमिकताएं- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म ।

अभिभाषण में सुशासन और पारदर्शिता को अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बताते हुए विज्ञान से लेकर विरासत तक की बात की गई । मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को इस हेतु धन्यवाद प्रेषित करता हूं ।

***m102 SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR):** This year, while the President talked about India as one of the fastest growing economy, her speech did not have a word about unemployment.

- The Centre for Monitoring Indian Economy notes that the unemployment rate among youth in the age group 20-24 years was 45 per cent in the October-December 2023 quarter.
- Forty-two per cent of graduates under 25 years are unemployed in India.
- For the age-group 25-29 years, it was at a 14 month high of 14.33%.

- While India will need to create 7 crore jobs over the next 10 years, it is projected to only create 2.4 crore jobs.
- The fact becomes especially interesting in the light of Modi?s unfulfilled promise of creating 2 crores jobs annually/20 crore jobs in the last decade.

I. Rural Unemployment - Doubling Farmer Incomes

- The adversity of the job market is matched by the distress in rural India where the demand for MGNREGA has reached record highs. Yet, the President did not mention it contrary to the promise made back when the government came into power.
- Stagnant farmer income and falling rural wages at a time when stock markets are soaring, and billionaire wealth balloons, is an indictment of this government?s priorities.
- Far from seeing doubled incomes, farmers are caught in the pincer of low unfair prices for their produce and ever rising input costs.
- There are other structural issues that are endemic to rural populations. These range from high rates of unemployment and under-employment rates to higher malnutrition, and severe infrastructural gaps that hamper the growth and development of the rural economy vis-à-vis the urban landscape.

- The Modi government has tried to improve the welfare distribution system of public goods and services in rural areas through different centrally funded schemes, but the results have remained mixed at best.

II. Production-Linked Incentives

- Even the ardent supporters of trickle-down economics privately admit that this reliance on capital expenditure is not bearing fruits. The same sentiment is expressed regarding the Production Linked Incentive (PLI) scheme.
- Despite multiple revisions and handsome incentives, the manufacturing sector has not taken off.
- The manufacturing growth rate has averaged 5.9% since 2013-14, the share of manufacturing has remained stagnant and was at 16.4% in 2022-23, and manufacturing jobs halved between 2016 and 2021.
- The decade of Make in India saw the share of manufacturing in the workforce decline from 12.6% in 2011-12 to 11.6% in 2021-22.
- Make in India and now PLI have failed to enthuse MSMEs.

III. Manual Scavenging

- Further, in its manifesto, the BJP had said that it?s committed to eliminate manual scavenging. But in another long line of hollow promises, it appears to have not fulfilled this promise as well. However, year after

year - while budget allocations have supposedly ? increased?, its utilization reveals another picture.

- As many as 330 people have died due to ?hazardous cleaning of sewer and septic tanks? from 2017-2022. But, according to the government, none of those people died due to ?manual scavenging?.
- Manual Scavenging is banned under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. However, the practice remains prevalent in many parts of India.

- Between March 22 to April 26, 2023, as many as eight people died while cleaning sewers in various parts of Gujarat, the Hindu reported.
- Official data show that over 1,000 workers have died while cleaning sewers or septic tanks since 1993, but activists say the number is much higher as many are involved in manual scavenging.

IV. Hate crimes against Dalits have almost doubled in the last decade. Yet, there is no mention.

- According to NCRB data, there were 33,719 cases of crimes against Dalits in 2011, and this figure rose to 50,291 in 2020.
- The numbers point to a sharp rise in such cases over a decade, of which nearly 74 percent took place under the Hindu nationalist BJP?s tenure.

- Further, atrocities/crime against Scheduled Castes have increased by 1.2% in 2021 (50900) over 2020 (50,291 cases).

There has been a gross increase in caste-based gendered violence against Dalit women.

- As per the National Crime Records Bureau (NCRB) 2019, nearly ten Dalit women are raped every day in the country with Uttar Pradesh recording among the highest numbers.

V. Communal Violence and Hate Crimes

- The president also did not mention the vast increase in hate crimes over the years, including the Manipur violence which saw an internet shutdown of over 100 days and several casualties. Over 2,900 communal violence cases have been registered in India in the last 5 years.

***m103 श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच):**

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह नए संसद भवन में उनका पहला संबोधन है । उन्होंने "आजादी का अमृत काल" के प्रारंभ में निर्मित इस नए संसद भवन की भव्यता पर प्रकाश डाला गया । उन्होंने कहा

कि यह इमारत 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का सार रखती है और भारत की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में काम करती है।

राष्ट्रपति ने 21वीं सदी के भारत के लिए नई परंपराएं स्थापित करने के समर्पण को मूर्त रूप देते हुए लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के साथ इसकी प्रतिध्वनि पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विश्वास जताया कि नई इमारत आजादी के अमृत काल के दौरान 'विकसित भारत' के विकास को आकार देने वाली नीतियों पर रचनात्मक संवाद का गवाह बनेगी। राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र में उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा माननीय सदस्यों को सूचित किया गया कि इस वर्ष संविधान के लागू होने की 75वीं वर्षगांठ है, इसे आजादी के अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने इस अवधि के दौरान आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले उत्सव अमृत महोत्सव के समापन पर प्रकाश डाला। इसमें देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है। 75 वर्ष बाद युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण दौर को फिर से जीने का अवसर मिला।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि "अमृत कलश" नामक अभियान के दौरान, 'मेरी माटी, मेरा देश' पहल के हिस्से के रूप में देश के हर गांव से मिट्टी दिल्ली पहुंचाई गई थी। इसके अंतर्गत 2 लाख से ज्यादा शिला फलक स्थापित किए गए, जिसमें तीन करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने 'पंच प्राण' की शपथ ली थी। 70 हजार से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए, 2 लाख से अधिक अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ है। 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए और 16 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की है।

अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक

संग्रहालय की स्थापना की गई । शांति निकेतन और होयसल मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए । साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस घोषित हुआ है । भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया । सरकार ने विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभीषका दिवस के रूप में मनाया ।

माननीय सदस्यों को अपने संबोधन में, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पिछले वर्ष में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने राष्ट्र के गौरव में योगदान दिया । उन्होंने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत लगातार दो तिमाहियों सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना है तथा भारत की विकास दर 7.5% से अधिक रही है । एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि भारत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना । अंतरिक्ष संबंधी अध्ययन के लिए इसरो ने 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के साथ आदित्य मिशन के सफल प्रक्षेपण कर देश को गौरवान्वित किया ।

उन्होंने बताया कि भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति ऐतिहासिक जी-20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन में स्पष्ट रूप से देखी गयी । इसके अतिरिक्त, एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीते । पैरा एशियाई खेलों में भी भारत को 100 से अधिक पदक प्राप्त हुए ।

उन्होंने बताया कि आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास हो रहा है और इस क्रम में ही अटल सेतु का निर्माण हुआ । देश को वंदे भारत तथा अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेने मिली हैं । भारत ने विश्व में सबसे अधिक तेजी से 5जी नेटवर्क स्थापित किया है ।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में बताया कि गत वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है । भारतीय एयरलाइन कंपनी ने विश्व

की सबसे बड़ी एयरलाइन डील की है । सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है ।

माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पिछले 12 महीनों में महत्वपूर्ण कानून पेश करने, 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक मजबूत नींव रखने के सहयोगात्मक प्रयासों को स्वीकार किया ।

उन्होंने तीन दशक के इंतज़ार के बाद पारित हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए कहा कि इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है । रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्प को सरकार ने लगातार जारी रखा है ।

उन्होंने अपने सम्बोधन में बताया कि गुलामी के कालखंड की आपराधिक न्याय व्यवस्था को समाप्त करते हुए देश को नई न्याय संहिता मिली है । डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के द्वारा डिजीटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है । देश में अनुसंधान और नवाचार को बल देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम लाया गया है । जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून से वहां जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में युवाओं की चिंताओं के प्रति सरकार की जागरूकता को स्वीकार किया और इस तरह की गड़बड़ियों को सख्ती से संबोधित करने के लिए एक नया कानून बनाने के निर्णय की घोषणा की । यह सक्रिय कदम युवा पीढ़ी की चिंताओं को दूर करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून में भी संशोधन किया है जिससे तेलंगाना में ट्राइबल विश्वविद्यालय की स्थापना को बल मिलेगा । पिछले वर्ष 76 अन्य पुराने कानूनों को भी हटाया गया है । कोई

भी राष्ट्र, तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह पुरानी चुनौतियों को परास्त करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य-निर्माण में लगाए ।

माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, भारत ने राष्ट्र-हित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था । राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज यह सच हो चुका है । जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 इतिहास हो चुका है । तीन तलाक के विरूद्ध कड़ा कानून बनाया गया है । शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नया कानून बनाया गया है । वन रैक और वन पेंशन लागू की है जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी । सेना में सी डी एस. की नियुक्ति की है ।

राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये उपलब्धियां जो आज दिख रही हैं, वे बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार हैं । हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे थे । अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं । नीति आयोग के अनुसार, मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में, करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले है । यह प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है । जब 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है ।

उन्हेंने बताया कि आज की उपलब्धियां पिछले 10 वर्षों की साधना का विस्तार है । नीति आयोग के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं । देश सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है । भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 में पहुंचा है । भारत का निर्यात 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर हो चुका है । एफडीआई दोगुना हुआ है । खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना बढ़ोत्तरी हुई है । आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ हो चुकी है । स्टार्टअप्स बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए है । पिछले साल 1 लाख 60 हजार से अधिक कंपनिया रजिस्टर हुई है । जीएसटी देने वालों की

संख्या बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। 10 वर्षों में 21 करोड़ से अधिक वाहन बिके है। 2014-15 में लगभग 2 हजार इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे जबकि 2023-24 ने 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने है। इस दौरान देश को दिवाला और दिवालियापन संहिता मिली है। देश को जी.एस.टी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। सरकार ने मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में, कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड हो गया है। साथ ही, फिस्कल डेफिसिट भी नियंत्रण में है।

उन्होंने बताया कि आज हमारे फोरेक्स रिज़र्व 600 अरब डॉलर से ज्यादा हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था, वह आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है। बैंकों का NPA जो कभी डबल डिजिट में होता था, वह आज लगभग 4 प्रतिशत ही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुके हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है।

पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले भारत खिलौने आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन एक लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय, देश में बने एयक्राफ्ट करियर INS विक्रांत को देखकर, गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेन्स कॉरिडोर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्र

की भागीदारी सुनिश्चित की है । स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्ट-अप्स के लिए खोल दिया है ।

उन्होंने बताया कि यह सरकार वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करती है तथा निजी क्षेत्र के सामर्थ्य पर विश्वास करती है । भारत में व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए यह सरकार लगातार काम कर रही है । 40 हजार से अधिक प्रावधानों को सरल किया गया है । 63 प्रावधानों को अपराध की सूची से बाहर किया गया है । जन विश्वास अधिनियम द्वारा 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है । न्यायालय के बाहर विवादों के समाधान के लिए मध्यस्तता पर कानून बनाया गया है । वन और पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे, वहीं आज 75 दिन से भी कम समय लगता है । यह सरकार एम.एस.ई को सशक्त करने के लिए मजबूती से काम कर रही है ।

उन्होंने कहा की उनकी सरकार ने एम.एस.एम.ई का विस्तार किया है । आज उद्यम पोर्टल पर 3.5 करोड़ से अधिक एम.एस. एम.ई पंजीकृत हैं । इस क्षेत्र को क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत 5 लाख करोड़ की गारंटी स्वीकृत की गई है । 2014 से पहले के दशक की तुलना में 6 गुना अधिक है ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दशक में भौतिक बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक भारतीय के लिए बुनियादी ढांचे का सपना साकार हुआ । बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल है:

गांवों में लगभग 3.75 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण ; राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 90 हजार किलोमीटर से बढ़ाकर 1 लाख 46 हजार किलोमीटर ; चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 2.5 गुना वृद्धि ; हाई-स्पीड कॉरिडोर का 500 किलोमीटर से 4 हजार किलोमीटर तक विस्तार ; हवाई अड्डों की सख्या 74 से दोगुनी कर 149 करना ; प्रमुख बंदरगाहों पर

कार्गो प्रबंधन क्षमता को दोगुना करना ; ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या में 14 गुना वृद्धि ; लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना ;गांवों में 4 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना, रोजगार का अहम जरिया बन रहा है ;10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाना ; वन नेशन, वन पावर ग्रिड का कार्यान्वयन, देश में विद्युत पारेषण को बढ़ाना ; गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए वन नेशन, वन गैस ग्रिड का शुभारंभ ; 5 शहरों से 20 शहरों तक मेट्रो सुविधा का विस्तार ; 25 हजार किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक बिछाया गया, जो कई विकसित देशों में ट्रैक की कुल लंबाई से अधिक है ; रेलवे 100% विद्युतीकरण हासिल करने के करीब ; 'भारत में सेमी हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरूआत ; 39 से ज्यादा रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों का संचालन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का परिवर्तन ।

ये उपलब्धियाँ देश भर में व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने समाज के हर वर्ग को उचित अवसर प्रदान करते हुए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र द्वारा निर्देशित समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई । उन्होंने इस संबंध में प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला:

पहली बार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक आरक्षण का लाभ बढ़ाया गया ; स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ओबीसी के लिए केंद्रीय कोटा के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत ; राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना ; बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े पांच स्थानों का पंचतीर्थ के रूप में विकास और देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित दस संग्रहालयों का निर्माण ।

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार चार मजबूत स्तंभों: युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों पर 'विकसित भारत के निर्माण में विश्वास करती है । इन स्तंभों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास और संसाधन समर्पित किए गए हैं:

4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना, लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का व्यय; लगभग 4 लाख करोड़ रुपये की लागत से लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुँच रहा है ; करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च से 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन का वितरण और COVID-19 महामारी के दौरान, 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन प्रदान किया गया, इस सुविधा को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और 11 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

हर योजना के तहत त्वरित संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए, 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इस यात्रा में लगभग 19 करोड़ नागरिक भाग ले रहे हैं । सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे ।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला । दो प्रमुख युद्धों और कोविड-19 महामारी जैसे वैश्विक संकटों का सामना करने के बावजूद, सरकार ने मुद्रास्फीति को सफलतापूर्वक नियंत्रण में रखा है । औसत मुद्रास्फीति दर, जो 2014 से पहले के 10 वर्षों में 8 प्रतिशत से अधिक थी, पिछले दशक में 5 प्रतिशत पर बनी हुई है ।

आम नागरिकों के हाथों में बचत बढ़ाने के लिए, सरकार ने विभिन्न कर छूट और सुधार लागू किए है, जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं को महत्वपूर्ण बचत हुई है । आयकर सीमा बढ़ा दी गई है और इन उपायों के

कारण, भारतीय करदाताओं ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं ।

नागरिकों के लिए बचत में योगदान देने वाली अन्य पहलों में शामिल हैं:

आयुष्मान भारत योजना और विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त इलाज से लगभग रुपये की बचत । साढ़े तीन लाख करोड़ ; जन औषधि केंद्र, नागरिकों को दवाओं की खरीद पर लगभग 28 हजार करोड़ रुपये बचाने में मदद कर रहे हैं ; कोरोनरी स्टेंट, घुटने के प्रत्यारोपण और कैंसर की दवाओं की कीमतों में कमी से मरीजों को सालाना लगभग 27 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी ; किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम, 21 लाख से अधिक रोगियों को लाभ पहुंचा रहा है और उन्हें हर साल एक लाख रुपये की बचत हो रही है ; गरीबों के लिए रियायती राशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपये खर्च किये ; रेल यात्री यात्रा पर लगभग 50 प्रतिशत की छूट, जिससे गरीबों और मध्यम वर्ग को सालाना 60 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी ; उड़ान योजना के तहत हवाई टिकटों की कीमतें कम होने से गरीबों और मध्यम वर्ग को 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी ;एल.ई.डी. बल्ब योजना, बिजली बिल में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत में योगदान दे रही है और जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के तहत गरीब लोगों को 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का दावा वितरित किया गया ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने कौशल को आगे बढ़ाने में विश्वकर्मा परिवारों की अपरिहार्य भूमिका को स्वीकार किया । सरकारी सहायता की कमी के कारण इन परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने 84 लाख से अधिक लोगों को जोड़कर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की है ।

सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को भी संबोधित किया है, उन्हें बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच प्रदान की है । बिना किसी गारंटी के 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया है । दलितों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और महिलाओं सहित कई लाभार्थियों ने न केवल ऋण चुकाया है बल्कि योजना की सफलता और प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए अगली किस्त का लाभ भी उठाया है ।

11 करोड़ शौचालयों का निर्माण और खुले में शैच बंद होने से बीमारियों से रोकथाम हुआ है । इससे शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को चिकित्सा पर प्रति वर्ष 60 हजार रूपये तक की बचत हो रही है । नल से स्वच्छ जल मिलने से प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की जान बच रही है । पक्के मकानों की सुविधा मिलने से बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है और स्कूल छोड़ने के दर में गिरावट आई है । प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कारण शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहे हैं जिससे मृत्यु दर में भी गिरावट आई है ।

अब तक सिर्फ अधिकारों पर चर्चा होती थी, इस सरकार ने कर्तव्यों पर बल दिया है । यह सरकार मानव केंद्रित विकास पर बल दिया है । हजारों आदिवासी गांवों तक पहली बार बिजली और सड़क पहुंची, नल से पेयजल मिला, 90 से ज्यादा वन उपज पर एम.एस.पी देने से जनजातियों को लाभ हुआ है । जनजातीय गांवों तक 4 जी इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है । इस सरकार ने जनजातीय में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए 24 हजार करोड़ रूपये की प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई है । सिकल सेल अनिमिया के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है । इसके तहत 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है । दिव्यांग जनों के लिए सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराई गई है ।

इस सरकार ने दशकों से उपेक्षित क्षेत्रों को विकास से जोड़ा है । सीमा से सटे गांवों को जो कि पहले अंतिम गांव माने जाते थे उन्हें पहला गांव बनाया

है । इनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया है । अंडमान और लक्ष्यद्वीप जैसे सुदूर क्षेत्रों में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण हुआ है । लक्षद्वीप को अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है । आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक जिलों का विकास को प्राथमिकता दी गई थी, अब आकांक्षी प्रखंड योजना जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति को मजबूत करने और हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया । इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्रों में बेटियों की क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए महिला सशक्तिकरण को समर्पित थी ।

सरकार ने महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व को पहचानते हुए जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया है । इस संबंध में प्रमुख पहल और उपलब्धियाँ शामिल है:

स्व-सहायता समूहों से लगभग 10 करोड़ महिलाएँ जुड़ी हुई है ; इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण और 40 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का वितरण ; 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के अभियान का क्रियान्वयन ; नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत समूहों को 15 हजार ड्रोन का वितरण ; मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया, जिससे देश की लाखों महिलाओं को लाभ होगा ; पहली बार सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना ; पहली बार सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेटों को प्रवेश ; पहली बार लड़ाकू पायलट और नौसेना के जहाजों के कमांडर के रूप में महिलाओं की भागीदारी और मुद्रा योजना के तहत दिए गए 46 करोड़ से अधिक ऋणों में से 31 करोड़ से अधिक ऋण महिलाओं को दिए गए है, जिससे वे स्वरोजगार के लिए सशक्त हुई हैं ।

ये पहल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों को दर्शाती हैं ।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने लागत कम करके और मुनाफा बढ़ाकर खेती को अधिक लाभदायक बनाने पर सरकार के जोर पर प्रकाश डाला । कृषि क्षेत्र में प्रमुख पहल और उपलब्धियाँ शामिल है:

देश की कृषि नीतियों और योजनाओं में 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई ; प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वितरण ; पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बैंकों से आसान ऋण में तीन गुना वृद्धि ; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा, बदले में उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपये का क्लेम मिला ; पिछले दशक में किसानों को धान और गेहूं की फसल के लिए एम.एस.पी. (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के रूप में लगभग 18 लाख करोड़ रुपये मिले, जो 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में 25 गुना अधिक है ; पिछले दशक में तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रदान किए गए ; कृषि निर्यात नीति का निर्माण, जिससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेगा ; किसानों को सस्ती कीमत पर खाद उपलब्ध कराने के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च ; 1.75 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना ; लगभग 8,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन ; कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ; सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ ; गांवों में 2 लाख सहकारी समितियों की स्थापना ; मत्स्य पालन क्षेत्र में 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का क्रियान्वयन, पिछले दस वर्षों में मछली उत्पादन दोगुना कर 175 लाख मीट्रिक टन ; अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन को 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 131 लाख मीट्रिक टन करना ; मत्स्य पालन क्षेत्र में

निर्यात दोगुना कर 30 हजार करोड़ रुपये से 64 हजार करोड़ रुपये ; देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया ; पिछले दशक में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में 40 प्रतिशत की वृद्धि और जानवरों को खुरपका और मुंहपका रोगों से बचाने के लिए पहले मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत, चार चरणों में 50 करोड़ से अधिक खुराके दी गईं ।

मेड इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बना है, पूरे विश्व की कंपनियां मेक इन इंडिया को लेकर आकर्षित हो रही है । आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को समझ रही है । दुनिया भार की कंपनिया भारत में निवेश को लेकर उत्साहित है । सेमी-कंडक्टर में हो रहा निवेश इसका उदाहरण है । सेमी-कंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भी बहुत लाभ होगा ।

यह सरकार एक बड़े विजन पर काम कर रही है इसमें आनेवाले 25 साल का रोडमैप भी है । आज की पीढ़ी को ऐसा विरासत बनानी है जिसे सदियों तक याद किया जाए । विकसित भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक ताकत को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है । इसके बिना विकास और आर्थिक समृद्धि स्थाई नहीं रह सकती है ।

भारत के तेज विकास को लेकर विश्व की हर एजेंसी आश्वस्त है । राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसिया जो भी आकलन कर रही है उनका आधार भारत की नीतियां है । आज दुनिया को आज विश्वास हो रहा है कि भारत वैश्विक सप्लाई चैन को सशक्त कर सकता है । इसलिए भारत भी बड़े कदम उठा रहा है और देश में एम.एस.एम.ई का मजबूत नेटवर्क बनाया जा रहा है । पी.एल आई से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी लाभ हो रहा है । इस सरकार ने 3 चल्क इग पार्क भी बनाए है ।

यह सरकार सीमा पर आधुनिक आधारभूत संरचना बना रही है । सेनाओं के आधुनिकीकरण, जैसे को तैसा की नीति, के अनुसार काम कर

रही है । कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है, पूर्वोत्तर में शांति आई है । अनेक संगठनों ने शांति की ओर कदम बढाए है । नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घटे हैं और हिंसा में भी गिरावट आई है ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पहल के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डाला । उन्होंने पिछले दशक में हरित ऊर्जा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दियाः

गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावाट से बढ़कर 188 गीगावाट हो गई है ; सौर ऊर्जा क्षमता 26 गुना बढ़ गई है, और पवन ऊर्जा क्षमता दोगुनी हो गई है ; भारत नवीकरणीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमता दोनों के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है, और सौर ऊर्जा क्षमता में पांचवें स्थान पर है और देश ने 2030 तक अपनी विद्युत स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है ।

माननीय राष्ट्रपति ने पिछले दशक में 11 नए सौर पाकों की स्थापना का उल्लेख किया, नौ अन्य पर काम चल रहा है । एक करोड़ परिवारों की सहायता करने, बिजली बिल कम करने और अधिशेष बिजली को बिजली बाजार में बेचने के लिए हाल ही में सौर छत स्थापना की एक नई योजना शुरू की गई थी ।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, सरकार ने 10 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को मंजूरी दे दी है, जबकि हाइड्रोजन ऊर्जा में तेजी से प्रगति हो रही है, जिसमें लद्दाख और दमन-दीव में परियोजनाएं शुरू की गई है ।

राष्ट्रपति ने इथेनॉल क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य की भी सराहना की, 12 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य हासिल किया और 20 प्रतिशत सम्मिश्रण लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं । इस पहल से किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है, सरकारी कंपनियों ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का इथेनॉल खरीदा है ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल की खाड़ी में एक नए ब्लॉक में तेल उत्पादन की शुरुआत को देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मनाया, जिससे ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिली ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी पर महत्वपूर्ण खनिजों की सीमित मात्रा के कारण एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला । हाल ही में शुरू की गई 'वाहन स्क्रैपेज नीति इस लक्ष्य के अनुरूप है, जो टिकाऊ संसाधन उपयोग में योगदान देती है ।

खनिजों के लिए गहरे समुद्र में खनन की क्षमता को पहचानते हुए, सरकार ने गहरे महासागर मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य संभावनाओं का पता लगाना और समुद्री जीवन की समझ को बढ़ाना है । 'समुद्रयान' परियोजना इस क्षेत्र में अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल है ।

माननीय राष्ट्रपति ने न केवल मानव जीवन के सुधार के लिए बल्कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी भारत को विश्व स्तर पर एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों पर जोर दिया । देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिससे कई नए अंतरिक्ष स्टार्टअप का 10 निर्माण हुआ है । राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब भारत का गगनयान मिशन अंतरिक्ष तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत को दुनिया की अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित करने, लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की सफलता पर प्रकाश डाला । सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी बना रहे ।

माननीय राष्ट्रपति ने साझा किया कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, यह अनुमान लगाते हुए

कि यह भारतीय युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा, नए स्टार्टअप की स्थापना को बढ़ावा देगा और कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने एक और बड़ा रिफॉर्म डिजीटल इंडिया के निर्माण के रूप में किया है। डिजीटल इंडिया ने आम जनता के जीवन को आसान बना दिया है। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेनदेन का 46 प्रतिशत भारत में होता है। पिछले महीने यू.पी.आई. से रिकॉर्ड 1200 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है, जिसके तहत 18 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। जनघन आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। यह सरकार अब तक 34 लाख करोड़ डी.बी.टी से ट्रांसफर कर चुकी है। जनधन आधार मोबाइल के कारण 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी तंत्र से बाहर किए गए हैं। डिजी लॉकर भी जीवन को आसान बना रहा है। 53 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है।

इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी का उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि क्वांटम कंप्यूटिंग नए युग के डिजिटल बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त करेगी। चल रहे प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत तकनीकी प्रगति और नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए क्वोटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में सबसे आगे रहे।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दशक में पर्यटन क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में इसकी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों का उल्लेख किया, जिससे भारत आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। राष्ट्रपत्ति ने इस वृद्धि का श्रेय भारत के बढ़ते कद को दिया, क्योंकि दुनिया देश को खोजने और समझने में गहरी रुचि व्यक्त कर रही है। उन्होंने बतया कि उनकी सरकार ने

पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे ।

उन्होंने बताया कि तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर सरकार के ध्यान पर जोर देते हुए श्रीमती । मुर्मू ने बताया कि इससे भारत में तीर्थयात्रा आसान हो गई है । भारत में विरासत पर्यटन भी वैश्विक रुचि प्राप्त कर रहा है । राष्ट्रपति ने काशी, महाकाल और केदारधाम जैसे तीर्थ स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की महत्वपूर्ण संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराए, जिसमे पिछले एक वर्ष में 8.5 करोड़ काशी गए, 5 करोड़ से अधिक लोग महाकाल, 19 लाख से अधिक केदारनाथ के दर्शन किए, जो देश भर में इन स्थानों पर सुविधाओं के अभूतपूर्व विस्तार का संकेत देते हैं ।

माननीय राष्ट्रपति ने भारत के इतिहास में ऐसे मोड़ों के महत्व पर जोर देते हुए, सभ्यताओं के भविष्य को आकार देने वाले ऐतिहासिक क्षणों पर विचार किया । उन्होंने बताया कि इस साल 22 जनवरी को देश ने एक यादगार पल देखा जब रामलला को आखिरकार अयोध्या में उनके भव्य मंदिर में स्थापित किया गया । करोड़ों देशवासियों की इस आकांक्षा की पूर्ति सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई । उन्होंने बताया कि अयोध्या में 5 दिन में 13 लाख श्रद्धालु ने दर्शन प्राप्त किये ।

इसके अलावा, राष्ट्रपति ने भारत को बैठकों और प्रदर्शनियों के लिए एक अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित करने की सरकार की महत्वाकांक्षा व्यक्त की । इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसी पहल लागू की गई हैं । राष्ट्रपति ने भविष्यवाणी की कि पर्यटन निकट भविष्य में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बन जाएगा ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तेजी से कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत के युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास के लिए सरकार की निरंतर पहल की रूपरेखा तैयार की ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है । एक उल्लेखनीय विकास इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कानून जैसे विषयों को भारतीय भाषाओं में पढ़ाना शुरू करना है ।

स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार 14,000 से अधिक 'पीएम श्री विद्यालयों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिनमें से 6,000 से अधिक स्कूल पहले से ही चालू हैं ।

माननीय राष्ट्रपति ने देश भर में ड्रॉपआउट दर को कम करने में सरकारी प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला । इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

अटल इनोवेशन मिशन के तहत, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक छात्र शामिल है । राष्ट्रपति ने पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ-साथ 157 नर्सिंग कॉलेजों के विकास के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का भी उल्लेख किया । इस अवधि के दौरान एमबीबीएस सीटों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो देश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश के युवाओं को शामिल करने, उनके कौशल को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के साधन के रूप में खेल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला । खेल और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व समर्थन दिया गया है, जिससे भारत एक मजबूत खेल शक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है ।

उन्होंने बताया कि उनकी सरकार का ध्यान एथलीटों से आगे बढ़कर खेल के अन्य पहलुओं को भी शामिल करने पर है । राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना और देश भर में कई उत्कृष्टता केंद्रों का विकास युवाओं को खेल को एक पेशे के रूप में चुनने का अवसर प्रदान करता है । खेल सामग्री उद्योग को भी व्यापक समर्थन दिया जाता है ।

पिछले दशक में, भारत ने विभिन्न विषयों में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिससे वैश्विक खेल क्षेत्र में

देश की बढ़ती पहचान में योगदान मिला है ।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 'मेरा युवा भारत' संगठन की शुरुआत की गयी, जिसका उद्देश्य युवाओं को 'विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना और उनमें कर्तव्य और सेवा की भावना पैदा करना है । लगभग 1 करोड़ युवा पहले ही इस पहल में शामिल हो चुके हैं, जो कार्यक्रम की सफलता और प्रतिध्वनि को दर्शाता है ।

माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पिछले तीन वर्षों में दुनिया भर में कई संघर्षों के साथ अनुभव की गई वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए उथल-पुथल के समय में एक मजबूत सरकार होने के लाभ को रेखांकित किया । उन्होंने गर्व से कहा कि उनकी सरकार के नेतृत्व में भारत विश्व-मित्र के रूप में उभरा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है ।

पिछले दशक में, राजनयिक व्यस्तताओं में एक आदर्श बदलाव आया है । परंपरागत रूप से दिल्ली के गलियारों तक ही सीमित, कूटनीति से संबंधित घटनाओं में अब प्रत्यक्ष सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है, जो उनकी सरकार द्वारा लाया गया एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है । यह समावेशिता भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान स्पष्ट थी, जहां जनता सक्रिय रूप से शामिल थी, और देश भर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन कर रही थी । विशेष रूप से, जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहली बार महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ देखी गईं ।

भारत द्वारा आयोजित ऐतिहासिक जी-20 शिखर सम्मेलन को वैश्विक सराहना मिली, साथ ही दिल्ली घोषणापत्र को सर्वसम्मति से अपनाए जाने को टूटे हुए माहौल में ऐतिहासिक माना गया । 'महिला नेतृत्व वाले विकास' से लेकर पर्यावरणीय मुद्दों तक भारत के दूरदर्शी दृष्टिकोण ने घोषणा का आधार बनाया ।

श्रीमती मुर्मू ने जी-20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता हासिल करने के भारत द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक स्वागत पर प्रकाश डाला । इसके अलावा, सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करना है । वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ एक और महत्वपूर्ण घटना थी, जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करती है ।

माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक विवादों और संघर्षों के वर्तमान युग में भी, उनकी सरकार ने विश्व मंच पर भारत के हितों को दृढ़ता से प्राथमिकता दी है । भारत की विदेश नीति का दायरा ऐतिहासिक बाधाओं को पार करते हुए काफी विस्तारित हो गया है । भारत विभिन्न वैश्विक संगठनों के एक सम्मानित सदस्य के रूप में उभरा है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अग्रणी आवाज रखता है ।

माननीय राष्ट्रपति ने दुनिया भर में मानवीय संकटों के प्रति भारत की सक्रिय प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला, जहाँ भी चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं, उनका तेजी से समाधान करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई । ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी और वंदे भारत जैसी सरकार की पहलों ने संकट के दौरान प्रत्येक भारतीय की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की है ।

राष्ट्रपति ने विश्व स्तर पर भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार के प्रयासों की सराहना की, विशेष रूप से योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का उल्लेख किया । उन्होंने गर्व से बताया कि 135 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामूहिक योग सत्र में भाग लिया और एक रिकॉर्ड बनाया । इसके अतिरिक्त, आयुष के विकास के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की शुरुआत को महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में रेखांकित किया गया ।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सभ्यताओं के भविष्य को आकार देने वाले ऐतिहासिक क्षणों पर विचार किया और भारत के इतिहास में ऐसे मोड़ों के महत्व पर जोर दिया । उन्होंने बताया कि इस साल 22 जनवरी को देश ने एक यादगार पल देखा जब रामलला को आखिरकार अयोध्या में उनके भव्य मंदिर में स्थापित किया गया । करोड़ों देशवासियों की इस आकांक्षा की पूर्ति सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई ।

माननीय राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि संयुक्त रात्र में मौजूद प्रतिनिधि लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं की आवाज है । उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं के विकसित हो रहे सपनों पर प्रकाश डाला और अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ने की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया । राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत (विकसित भारत) इस पीढ़ी की आकांक्षाओं को साकार करने में सहायक होगा और इस प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए एकजुट प्रयासों का आह्वान किया ।

मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं ।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह परिलक्षित होता है कि केन्द्र सरकार "सबका साथ - सबका विकास" के अपने वायदे के अनुरूप देश को तेजी से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है । देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा सरकार के इस समावेशी आर्थिक विकास के केन्द्र में है ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में अमृत काल के 25 वर्षों के कालखंड में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का खाका पेश किया है,

जो सराहनीय है ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने लगभग 74 मिनट के संबोधन में केन्द्र सरकार के विजन और देश में बीते 10 साल की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया है और अपने संयुक्त अधिवेशन में बताया कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी जो अब पूरी हुई है ।

अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने, औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों के स्थान पर नए कानून बनाए जाने, नारी वंदन अधिनियम और सरकार के कईअन्य कदमों का भी उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और लगातार पिछली दो तिमाही में देश की विकास दर साढ़े सात प्रतिशत रही ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डाला है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण कार्यों को दर्शाता है ।

1. ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा साल 2023 ।

2. नई संसद भवन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक ।

3. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत ।

4. मिशन मोड में सरकारी नौकरियां देना बड़ी उपलब्धि ।

5. नारी शक्ति वंदन कानून से महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई ।

6. भारत में जी-20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन ।

7. राम मंदिर के निर्माण का सदियों पूरा सपना सच हुआ ।

8. देश के करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर निकले ।

9. भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ।

10. देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर एक लाख के आंकड़े से भी आगे निकली ।

11. देश में मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में पांच गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई ।

12. डिजिटल इंडिया से बड़ा बदलाव, यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लेन-देन ।

13. खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने पर जोर ।

14. पहली बार कृषि निर्यात की नीति बनाई गई ।

15. देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है । स्थानीय सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी ।

16. सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की गई ।

17. सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए कटिबद्ध ।

18. 22 जनवरी को लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए ।

19. हमारी विरासत ऐसी हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें ।

20. नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को ऊर्जा देता रहेगा (यहां नई और स्वस्थ परंपराओं की शुरुआत का भरोसा ।

राष्ट्रपति महोदया अपने अभिभाषण में इन महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा इस बात का भी उल्लेख किया है कि भारत ने बीते एक दशक के दौरान वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौर में भी, अपने हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है । उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ को देखने के लिए अनेक साथी इस सदन में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसी होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद करे ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि स्टार्टअप आज कुछ सौ से बढ़कर चार लाख से भी अधिक हो गए हैं औरा भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है । इसने पहले की तरह खिलौनों का आयात करने के बजाय उनका निर्यात करना भी शुरू कर दिया है तथा व्यापार करने में आसानी के लिए 40,000 से अधिक अनुपालन हटा दिए गए हैं या सरल बना दिए गए हैं ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में यह भी उल्लेख किया है कि वन एवं पर्यावरण मंजूरी में 75 दिन से भी कम समय लगता है, जबकि पहले 600 दिन लगते थे तथा उद्यम और उद्यम सहायता पोर्टल पर लगभग 3.5 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं । करीब पांच लाख करोड़ रुपये के एमएसएमई लोन पर सरकारी गारंटी दी गई है । यह 2014 से पहले प्रदान की गई राशि से छह गुना अधिक है एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएं शुरू की गई हैं । यह भी सरकार की उपलब्धि को दर्शाता है ।

राष्ट्रपति महोदया ने यह भी जिक किया है कि पिछले दशक में लगभग 21 करोड़ वाहन बेचे गए हैं, जबकि इससे पहले के दशक में यह आंकड़ा 13 करोड़ था और जीएसटी भरने और आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा दिवाला और दिवालियापन संहिता अधिनियमित की गई एवं बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां पहले दोहरे अंक में रहने के

बाद घटकर लगभग 4 प्रतिशत पर आ गई हैं । यह सरकार की उलब्धियों का दर्शाता है, जो प्रशंसनीय है ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में इस प्रकार से जहां विगत वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश के सर्वांगीण विकास हेतु किए गए कार्यों को उद्धरित किया है, वहीं सरकार के दूसरे कार्यकाल में केन्द्रीय प्राथमिकताओं और इस दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का भी उल्लेख किया है, जिसमें हमारी लोकप्रिय सरकार की आत्म छवि का एक अंदाजा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ।

अंत में, मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का हृदय से समर्थन करता हूं ।

धन्यवाद ।

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ । संसद के इस नए भवन में जब आदरणीया राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित करने के लिए आई थीं, और जिस गौरव और सम्मान के साथ सेंगोल पूरे प्रोसेशन का नेतृत्व कर रहा था और हम सब उसके पीछे-पीछे चल रहे थे, नए सदन में यह नई परंपरा भारत के आजादी के उस पवित्र पल का प्रतिबिंब, जब साक्षी बनता है, तो लोकतंत्र की गरिमा कई गुणा ऊपर चली जाती है ।

यह 75वां गणतंत्र दिवस, इसके बाद संसद का नया भवन, सेंगोल की अगुवाई, यह सारा दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था । मैं जब वहां से पूरे कार्यक्रम की भागीदारी कर रहा था, यहां से तो हमें उतनी भव्यता नज़र नहीं आती है, लेकिन जब वहां से मैंने देख तो वाकई इस नए सदन में इस गरिमामयी उपस्थिति में ? राष्ट्रपति जी, उप-राष्ट्रपति जी और आप, हम सबके मन को प्रभावित करने वाला वह दृश्य हमेशा-हमेशा याद रहेगा ।

करीब 60 से ज्यादा जिन माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के आभार प्रस्ताव पर अपने-अपने विचार रखे हैं, मैं विनम्रता के साथ उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ । मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है, उसकी सराहना करता हूँ । उनके भाषण की एक-एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया है । आप कई दशक तक, जैसे यहां बैठे थे, वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प है अब जनता-जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है । आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता-जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी । आप जिस ऊंचाई पर हैं, उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक-दीर्घा में दिखेंगे ।? (व्यवधान)

अधीर रंजन जी, इस बार क्या आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है? ? (व्यवधान) आपने इन्हीं चीजों को पचाया है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं । मैंने सुना है कि बहुत लोगों ने पिछली बार भी सीट बदलीं, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं । मैंने सुना है कि बहुत लोग अब लोक सभा के बजाय राज्य सभा में जाना चाहते हैं । स्थितियों का आकलन करके वे अपना-अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर, हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, जो देश के सामने राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है । अगर आप इस पूरे दस्तावेज को देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है, जिससे देश किस स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस स्केल के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा-जोखा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है ।

आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए चार मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है । उनका सही-सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा । उन्होंने इन चार स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई-बहन और देश के हमारे किसान, मछुआरे, पशुपालक की चर्चा की है । इनके सशक्तीकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो राह है, उसके स्पष्ट दिशा-निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा हैं ।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : इसमें माइनोरिटीज़ नहीं है ।?(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : हो सकता है आपके यहां फिशरमैन माइनोरिटी के न हों, हो सकता है आपके यहां पशुपालक माइनोरिटी के न हों, हो सकता है किसान आपके यहां माइनोरिटी के न हों, हो सकता है महिलाएं आपके यहां माइनोरिटी में न हों, हो सकता है कि आपके यहां युवा माइनोरिटी में न हों, क्या हो गया है दादा? क्या इस देश के युवा वर्ग की बात होती है, समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? देश की नारी की बात होती है, तो क्या देश की सभी नारी नहीं होती हैं? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे, कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब छीना करो, छीना करो, बहुत तोड़ा देश को ।?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता कि जाते-जाते तो कम से कम इस चर्चा के दरम्यान कुछ सकारात्मक बातें होतीं, कुछ सकारात्मक सुझाव आते । लेकिन, हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया । आपकी सोच की मर्यादा देश समझता है । उसको बार-बार दर्द होता है कि यह दशा है इनकी, इनके सोचने की मर्यादा इतनी है । आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता तो बदल गए, लेकिन टेपरिकार्डर वही बज रहा है । वही बातें, कोई नई बात आती नहीं, पुरानी ढपली, पुराना राग, वही चलता रहता है आपका । चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता

को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल हो गए आप । चलिए, यह भी मैं सिखाता हूं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत है, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है । कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला । दस साल कम नहीं होते हैं । लेकिन दस सालों में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल रहे । जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए, इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्ष के जो तेजस्वी लोग हैं, उनको दबा दिया जाए । हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उनमें उत्साह भी है, उमंग भी है । लेकिन, अगर वे बोलें, उनकी छवि उभर जाए, तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए, उस चिंता में इस यंग जेनरेशन को मौका न मिले, हाउस को चलने नहीं दिया गया । एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी । मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ, अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : प्रधान मंत्री जी, प्रेसीडेंशियल एड्रेस पर बात करिए न ।?(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है । अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना यह समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी ही पड़ती है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए । हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए । ? (व्यवधान) गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए । ये सब परिवारवाद की भेंट चढ़ गए ।

एक ही प्रोडक्ट को बार-बार लांच करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है । दुकान हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग ही कहते हैं कि दुकान खोलिए, सब जगह बोलते हैं । दुकान पर ताला लगने की बात आई है । ? (व्यवधान) यहां दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं । परिवारवाद पर बैठे-बैठे कमेंट कर रहे हैं । मैं जरा समझा देता हूं । अध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा समय ले रहा हूं कि हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं । अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है । हम उस परिवारवाद की चर्चा करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देता है । पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, यह परिवारवाद है । न राजनाथ सिंह जी की कोई पोलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलीटिकल पार्टी है । जहां एक परिवार की पार्टी लिखी जाती है वह लोकतंत्र में उचित नहीं है । एक परिवार के दस लोग राजनीति में आएं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है । हम चाहते हैं कि नौजवान लोग राजनीति में आएं, हम भी चाहते हैं कि इसकी चर्चा कीजिए । हमारा और आपका विषय नहीं है ।

देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, यह हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए । यदि किसी परिवार के दो लोग राजनीति में प्रगति करते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंग । दस लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा, देश में नई पीढ़ी और अच्छे लोग राजनीति में आएं, यह स्वागतयोग्य है । सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती हैं, यह पक्का है कि अगर यह अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा । ये नहीं तो उसका बेटा होगा, यह लोकतंत्र का खतरा है । दादा आपको थैंक्यू, यह अच्छा हुआ, मैं इस विषय पर कभी बोलता नहीं था ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार-बार लांच करने का प्रयास हो रहा है । कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई । देश के करोड़ों परिवार

की अकांक्षाएं और उपलब्धियां देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं सकते हैं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है । कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है, कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल । एक ऐसे कैंसिल कल्चर में फंस गई है, अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं संसद की नयी इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल । यह मोदी की उपलब्धियां नहीं हैं, यह देश की उपलब्धियां हैं । इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे, इसके कारण देश की सफलताएं, देश के एचीवमेंट्स, उसको भी आप कैंसिल करके बैठ गए हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा की, आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की । उन्होंने अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार पर बारीकी से चर्चा की है । भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है । जब विश्व संकट से गुजर रहा तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है । जी-20 सम्मिट के अंदर सारे देशों ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोचता है और क्या कहता है । इन 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, इसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा और यह मोदी की गारंटी है । ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): बेरोजगारी की गारंटी है, पेट्रोल और डीजल की गारंटी है । ? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : बेरोजगारी की गारंटी है । ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, क्या इनको पहले बोलने का मौका नहीं दिया था? आपने तो सबको मौका दिया है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेंगे तो विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्क देते हैं । ? (व्यवधान) इसमें क्या है? यह तो अपने आप हो जाएगा । क्या कमाल है आप लोगों का? मोदी का क्या है? यह तो अपने आप हो जाएगा । सरकार की भूमिका क्या होती है? मैं ज़रा इस सदन के माध्यम से देश को विशेषकर देश के युवा मन को बताना चाहता हूं, देश की युवा शक्ति को बताना चाहता हूं कि यह होता कैसे है और सरकार की भूमिका क्या होती है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले 2014 में फरवरी महीने में इंटरिम बजट आया था, उस समय कौन लोग बैठे थे, आपको तो मालूम ही है और देश को भी मालूम है । दस साल पहले जो इंटरिम बजट आया था, उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा, मैं उसे क्वोट कर रहा हूं । इसका एक-एक शब्द बड़ा मूल्यवान है । जब आप लोग कहते हैं कि यह तो अपने आप तीसरे नंबर पर चला ही जाएगा, ऐसा जो कहते हैं उनको ज़रा समझना चाहिए । उन्होंने कहा था ? ?I now wish to look forward and outline a vision for the future.? विज़न फॉर द फ्यूचर, पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे । ?I now wish to look forward and outline a vision for the future.? आगे कहते हैं - ?I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world.?

यानी वर्ष 2014 में 11 नंबर पर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था । आज पांच पर पहुंच गए और आप यह कह रहे हैं?

श्री गौरव गोगोई : इसके आगे क्या बोला वह भी बोल दीजिए । इसी स्पीच में लिखा है कि आने वाले समय में थर्ड लार्जेस्ट होंगे । ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आगे पढ़ रहा हूं । गोगोई जी, थैंक्यू, आपने अच्छा कहा । ध्यान से सुनिए । साथियों, ध्यान से सुनिए । उन्होंने कहा था कि ??is the 11th largest in the world.? बड़े गौरव का वाक्य था । ? There are great things in store.? फिर वह आगे कहते हैं कि ?There is a well-argued view that in the next three decades India?s nominal GDP will take the country to the third rank after the US and China.?

आदरणीय अध्यक्ष जी, उस समय के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे । 30 साल, और फिर कहा था कि यह मेरा विजन है, ? (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): मनमोहन सिंह जी, उस समय नहीं थे । आप बैठ जाइए । ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : बहुत लोग हैं, जो ख्यालों में रहते हैं, वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं । ये लोग वर्ष 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं ? वर्ष 2044, यानी वर्ष 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की ये बात करते हैं । यह इनकी सोच, इनकी मर्यादा है । ये सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे, संकल्प तो दूर की बात थी । 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को ये कहकर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे । यह मोदी की गारंटी है । मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा । ? (व्यवधान) ये कैसे लक्ष्य रखते थे? इनकी सोच कहां तक जाती थी? दया आती है । आप लोग ग्यारह नंबर पर बड़ा गर्व कर रहे थे, जबकि हमने पांचवे नंबर पर पहुंचा दिया । अगर ग्यारह पर पहुंचने से आपको खुशी होती थी, तो पांच नंबर पर पहुंचने पर भी खुशी होनी चाहिए कि देश पांचवें नंबर पर पहुंच गया । आपको खुशी होनी चाहिए । आप किस बीमारी में फंसे पड़े हैं?

आदरणीय अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार की काम करने की स्पीड, हमारे लक्ष्य कितने बड़े होते हैं, हमारा हौसला कितना बड़ा होता है, वह आज पूरी दुनिया देख रही है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है । एक कहावत कही जाती है- ?नौ दिन चले अढ़ाई कोस ।? मुझे लगता है कि यह कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित करती है । कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान बने ।? (व्यवधान) अगर कांग्रेस की रफ्तार से ये घर बने होते तो क्या हुआ होता? ? (व्यवधान) मैं इसका हिसाब लगाता हूं । अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी, उस प्रकार से चला होता तो इतना काम करने में 100 साल लगते ।? (व्यवधान) पांच पीढ़ियां गुजर जातीं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 वर्ष में 40 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ । अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता तो इस काम को करने में 80 साल लग जाते । एक प्रकार से चार पीढ़ियां गुजर जातीं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 17 करोड़ अधिक गैस कनेक्शन दिए । यह मैं 10 साल का हिसाब दे रहा हूं । अगर कांग्रेस की चाल से चलते तो ये कनेक्शन देने में और 60 साल लग जाते । तीन पीढ़ियां धुएं में खाना पकाते-पकाते गुजर जातीं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने सैनिटेशन कवरेज को 40 परसेंट से 100 परसेंट तक पहुंचाई है । अगर कांग्रेस की रफ्तार होती तो यह काम होते-होते 60-70 साल और लगते और कम से कम तीन पीढ़ियां गुजर जातीं, लेकिन गारंटी नहीं होता कि यह काम होता या नहीं होता ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ है । ? (व्यवधान) कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया । वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता-जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे? मैं जानता हूं कि नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त को लाल किले से प्रधान मंत्री नेहरू ने जो कहा था, वह मैं जरा पढ़ता हूं । लाल किले से भारत के प्रथम प्रधान मंत्री नेहरू जी ने जो कहा था, वह पढ़ रहा हूं । उन्होंने कहा था ? ?हिन्दुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है । हम इतना काम नहीं करते हैं, जितना कि यूरोप वाले, जापान वाले, चीन वाले, रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं ।? यह नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं । ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : महोदय, प्रधानमंत्री जी ने राज्य सभा में एक महिला सांसद के लिए क्या कहा है ।?(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : यह न समझिए कि वे कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गईं, वे मेहनत से हुई हैं और अक्ल से हुई हैं । ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं ।?(व्यवधान) यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी हैं, नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं ।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह आपको शोभा नहीं देता है ।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की भी सोच उससे ज्यादा अलग नहीं थी ।?(व्यवधान) इंदिरा जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि ?दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है, तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और

जब कोई कठिनाई आ जाती है, तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं । कभी-कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है? ।?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको ?आयरन लेडी? कहा था ।?(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : आज कांग्रेस के लोगों को देखकर लगता है कि इंदिरा जी भले ही देश के लोगों का आकलन सही न कर पाईं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन किया था । कांग्रेस से इस शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे । उनके विषय में ऐसा ही सोचते थे ।?(व्यवधान) आज भी वही सोच देखने को मिलती है ।?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : वे भी प्रधानमंत्री थे । दुनिया में कभी आप भी नहीं रहेंगे ।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक ही परिवार पर रहा है । एक परिवार के आगे वे न कुछ सोच सकते हैं, न ही कुछ देख सकते हैं । कुछ दिन पहले ?भानुमति का कुनबा जोड़ा?, लेकिन फिर ?एकला चलो रे? करने लग गए । कांग्रेस के लोगों ने मोटर मैकेनिक का नया-नया काम सीखा है । इसीलिए एलाइनमेंट क्या होता है, उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अलायंस का ही एलाइनमेंट बिगड़ गया है ।?(व्यवधान) अगर इनको अपने इस कुनबे में एक-दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे?...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : महोदय, प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे?...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के इस सामर्थ्य पर भरोसा है । हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश की जनता ने हमें पहली बार सेवा करने का अवसर दिया, तो हमारे पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे, उन गड्ढों को भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी । हम पहले कार्यकाल में वे गड्ढे भरते रहे ।

हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत के निर्माण को नई गति देंगे । हमने पहले कार्यकाल में ?स्वच्छ भारत?, ?उज्ज्वला?, ?आयुष्मान भारत?, ?बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ?, उसी प्रकार से ?सुगम्य भारत?, ?डिजिटल इंडिया? ऐसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप देकर आगे बढ़ाया । ? (व्यवधान) टैक्स व्यवस्था आसान हो, इसके लिए जीएसटी जैसे निर्णय लिए और हमारे इन कामों को देखकर जनता ने भरपूर समर्थन दिया, जनता ने बहुत आशीर्वाद दिए, पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद दिए और हमारा दूसरा कार्यकाल प्रारम्भ हुआ । दूसरा कार्यकाल संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा । जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वे सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे । ? (व्यवधान) हम सबने अनुच्छेद 370 खत्म होते हुए देखा । इन्हीं माननीय सांसदों की आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से अनुच्छेद 370 गया । ?नारी शक्ति वंदन अधिनियम? दूसरे कार्यकाल में कानून बना ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, अंतरिक्ष से लेकर ओलम्पिक तक, सशस्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज उठ गई । ? (व्यवधान) नारी शक्ति के सशक्तिकरण को आज देश ने देखा है । उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक लोगों ने दशकों से अटकी, भटकी, लटकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा होते हुए देखा । अंग्रेजी शासन के पुराने दण्ड प्रधान कानूनों से हम ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के नेता बोल रहे हैं । प्लीज, आप समझाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन के नेता बोल रहे हैं । मैंने आप सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था । यह तरीका गलत है । हमें मर्यादा बनाकर रखनी पड़ेगी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, बैठे-बैठे कोई टिप्पणी नहीं करेगा ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, नो । यह गलत तरीका है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या यह आपका तरीका है?

? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजी शासन के पुराने कानून जो दंड प्रधान थे, उन दंड प्रधान कानूनों से हटकर के हमने न्याय संहिता तक प्रगति की है । हमारी सरकार ने सैंकड़ों ऐसे कानूनों को समाप्त किया, जो अप्रसांगिक हो गए थे । सरकार ने 40,000 से ज्यादा कम्प्लायेंसेस खत्म कर दिए ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत ने अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों से भविष्य की उन्नति के सपने देखे हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के गांव-गांव ने, देश के कोटि-कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है और सेच्युरेशन के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, उसके हक की चीज उसको मिले, उसके दरवाजे दस्तक देकर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ, जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नयी ऊर्जा देता रहेगा । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है । ज्यादा से ज्यादा सौ-सवा सौ दिन बाकी हैं और ?अब की बार?-

अनेक माननीय सदस्य : ?400 पार ।?

***m130 श्री नरेन्द्र मोदी :** पूरा देश कह रहा है, ?अब की बार? **?**

***m131 अनेक माननीय सदस्य :** ?400 पार ।?

***m132 श्री नरेन्द्र मोदी :** खड़गे जी भी कह रहे हैं ।

***m133 अनेक माननीय सदस्य :** ?400 पार ।?

***m134 श्री नरेन्द्र मोदी :** अध्यक्ष जी, मैं आम तौर पर आंकड़ों-वांकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं । लेकिन मैं देश का मिजाज देख रहा हूं कि एनडीए को तो 400 पार करवा के ही रहेगा । लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा । ? (व्यवधान) बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा की कार्यवाही इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा । मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था ।

<u>18.00 hrs</u>

मैंने कहा था कि मैं देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहता हूँ । तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं भारतवासियों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही विश्वास से भरा हुआ हूँ । मेरा देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर अपार भरोसा है । मेरा बहुत विश्वास है । 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं । यह सामर्थ्य दिखाता है ।? (व्यवधान) मैंने हमेशा कहा है कि गरीब को अगर साधन मिले, गरीब को अगर संसाधन मिले, गरीब को अगर स्वाभिमान मिले तो हमारा गरीब गरीबी को परास्त करने का सामर्थ्य रखता है और हमने वह रास्ता चुना और मेरे गरीब भाइयों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया है ।

इसी सोच के साथ हमने गरीब को साधन दिए, संसाधन दिए, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया । आज 50 करोड़ गरीबों के पास बैंक खाता है । वे पहले कभी बैंक से गुजर नहीं पाते थे । आज 4 करोड़ गरीबों के पास पक्का घर है । घर उसके स्वाभिमान को एक नया सामर्थ्य देता है । 11 करोड़ से अधिक परिवारों को पीने का शुद्ध जल नल से मिल रहा है । 55 करोड़ से अधिक गरीबों को ?आयुष्मान भारत? कार्ड मिला है । घर में कोई भी बीमारी

आ जाए और उस बीमारी के कारण वह फिर से गरीबी की तरफ न चला जाए, उसको भरोसा है कि कितनी भी बीमारी क्यों न आ जाए, उसके लिए मोदी बैठा है । 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा दी गई है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी ने उनको पूछा, जिनको पहले कोई पूछता तक नहीं था ।? (व्यवधान) देश में पहली बार रेहड़ी-पटरी वाले साथियों के बारे में सोचा गया । ?पीएम स्वनिधि योजना? से आज वे ब्याज के चक्कर से बाहर निकले और बैंक से पैसे लेकर अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं । देश में पहली बार जिनका सामर्थ्य हाथ का हुनर है, जो राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं, ऐसे मेरे विश्वकर्मा साथियों के बारे में सोचा गया । उनको आधुनिक टूल्स, आधुनिक ट्रेनिंग, पैसों की मदद तथा उनके लिए वैश्विक मार्केट खुल जाए, यह मेरे विश्वकर्मा भाइयों के लिए हमने किया है । देश में पहली बार पी.वी.टी.जी., यानी जनजातियों में भी अति पिछड़े हमारे जो भाई-बहन हैं, चूँकि उनकी संख्या बहुत कम है । उन पर वोट के हिसाब से किसी की नजर नहीं जाती है, लेकिन हम वोट से परे हैं । हम दिलों से जुड़े हुए हैं । इसलिए पी.वी.टी.जी. जातियों के लिए ?पीएम जनमन योजना? बनाकर उनके कल्याण का मिशन मोड में काम उठाया है । इतना ही नहीं, सरहद के जो गांव थे, जिनको आखिरी गांव करके छोड़ दिया गया था, हमने उन आखिरी गांवों को पहला गांव बनाकर विकास की पूरी दिशा बदल दी है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बार-बार मिलेट्स की वकालत करता हूं । दुनिया के अंदर जाकर मिलेट्स की चर्चा करता हूं । जी-20 देशों के लोगों के सामने गर्व के साथ मिलेट्स परोसता हूं, इसके पीछे मेरे दिल में तीन करोड़ से ज्यादा मेरे छोटे किसान हैं, जो मिलेट्स की खेती करते हैं । उनके कल्याण से हम जुड़े हुए हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं, जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं, तब मैं करोड़ों गृह उद्योग, लघु उद्योग,

कुटीर उद्योग, उससे जुड़े हुए मेरे लाखों परिवारों के साथ, उनके कल्याण के लिए सोचता हूं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, खादी, कांग्रेस पार्टी ने उसको भुला दिया, सरकारों ने भुला दिया, आज मैं खादी को ताकत देने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा हूं, क्योंकि खादी के साथ, हैंडलूम के साथ करोड़ों बुनकरों की जिंदगी लगी हुई है, मैं उनके कल्याण को देखता हूं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार हर कोने में गरीबी को निकालने के लिए, गरीब को समृद्ध बनाने के लिए अनेक विविध प्रयासों को कर रही है । जिनके लिए वोट बैंक ही था, उनके लिए उनका कल्याण संभव नहीं था । हमारे लिए उनका कल्याण राष्ट्र का कल्याण है और इसलिए हम उसी रास्ते पर चल पड़े ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया है, अन्याय किया है ।?(व्यवधान) इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है । कुछ दिनों पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वह सम्मान दिया, लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर जी, अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था? किस प्रकार से उनके साथ जुल्म किया? वर्ष 1970 में, वे बिहार के मुख्यमंत्री बने । उनको पद से हटाने के लिए कैसे-कैसे खेल खेले गए थे? उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था?

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था । वर्ष 1987 में जब कांग्रेस के पास, पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और कारण क्या दिया कि वे संविधान का सम्मान नहीं कर सकते ।?(व्यवधान) जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन

लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथी आज कल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी के कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां हैं, उसका हिसाब-किताब करते रहते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि उनको इतना, सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है ।?(व्यवधान) कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं?? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दुनिया भर की चीजें करते हैं ।?(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं ।? (व्यवधान) यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉंस्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी, जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी । नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ? जरा कोई निकाल कर देखें कि उसमें क्या कोई ओबीसी था? जरा निकाल कर देखिये । इतनी बड़ी पावरफुल बॉडी बनाई थी और उसे अपॉइंट कर रहे थे ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में नारी शक्ति के सशक्तीकरण को लेकर अनेक विध कदम उठाए गए हैं ।? (व्यवधान) नारी के नेतृत्व में समाज के सशक्तीकरण पर काम किया गया है । अब देश की बेटी के लिए हिंदुस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, जहां देश की बेटियों के लिए दरवाजे बंद हो । आज हमारे देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं आर हमारे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रख रही हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी है । विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं और आर्थिक गतिविधि करती हैं । ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वे नई ताकत दे रही हैं और मुझे आज खुशी है कि इन प्रयासों का परिणाम है कि करीब-करीब एक करोड़ लखपति दीदी आज देश में बनी हैं । जब मेरी उनसे बातें होती हैं, उनका जो आत्मविश्वास देखता हूं, मेरा पक्का विश्वास है कि हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले हमारे

कार्यकाल में 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश के अंदर देखेंगे । आप कल्पना कर सकते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में बेटियों के संबंध में जो पहले सोच थी, समाज के घर में घुस गई थी, दिमाग में भी घुस गई थी, आज वह सोच कितनी तेजी से बदल रही है । थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा सुखद बदलाव आ रहा है । पहले अगर बेटी का जन्म होता था तो चर्चा होती थी कि अरे, खर्चा कैसे उठाएंगे? उसको कैसे पढ़ाएंगे? उसकी आगे की जिंदगी एक प्रकार से कोई बोझ है, ऐसी चर्चाएं हुआ करती थीं । आज बेटी पैदा होती है तो पूछा जाता है कि अरे, सुकन्या समृद्धि एकाउंट खुला कि नहीं खुला? यह बदलाव आया है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले सवाल होता था कि प्रेग्नेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगी । पहले यह बात होती थी कि प्रेग्नेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगी । आज कहा जाता है कि 26 हफ्ते की पेड लीव और बाद में भी अगर छुट्टी चाहिए तो मिलेगी । यह बदलाव होता है । पहले समाज में सवाल होते थे कि महिला होकर नौकरी क्यों करना चाहती हो? क्या पति की सैलरी कम पड़ रही है? ऐसे सवाल होते थे । आज लोग पूछ रहे हैं कि मैडम आपका जो स्टार्ट-अप है न, बहुत प्रगति कर रहा है । क्या मुझे नौकरी मिलेगी? यह बदलाव आया है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक समय था, जब सवाल पूछा जाता था कि बेटी की उम्र बढ़ रही है, शादी कब करोगी? बेटी की उम्र बढ़ रही है, शादी कब करोगी? आज पूछा जाता है कि बेटी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों को संतुलित कितना बढ़िया करती हो, कैसे करती हो?

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक समय था, घर में कहा जाता था कि घर के मालिक घर पर है कि नहीं है? ऐसा पूछा जाता था । घर के मुखिया को

बुलाइये । ऐसा कहते थे । आज किसी के घर जाते हैं, तो घर महिला के नाम पर, बिजली का बिल उसके नाम पर आता है, पानी, गैस सब उसके नाम पर है, तो परिवार के मुखिया की जगह आज मेरी माताएं एवं बहनों के नाम हैं । यह बदलाव है ।

अमृतकाल में विकसित भारत का हमारा जो संकल्प है, उसमें यह बदलाव एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाला है और मैं उस शक्ति के दर्शन कर पा रहा हूँ ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए आँसू बहाने की आदत मैंने बहुत देखी है । किसानों के साथ कैसा-कैसा विश्वासघात किया गया है, उसे इस देश ने देखा है । कांग्रेस के समय कृषि के लिए कुल वार्षिक बजट 25 हजार करोड़ रुपए होता था । हमारी सरकार का बजट है सवा लाख करोड़ रुपए का । कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसानों से 7 लाख करोड़ रुपए के धान और गेहूँ खरीदे थे । हमने 10 वर्ष में करीब 18 लाख करोड़ रुपए के धान और गेहूँ की खरीद की है । कांग्रेस सरकार ने नाम मात्र की दलहन और तिलहन की खरीदी कभी की हो, तो की हो, लेकिन हमने सवा लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के दलहन और तिलहन खरीदे हैं ।

हमारे कांग्रेस के साथियों ने पीएम किसान सम्मान निधि का मजाक उड़ाया । जब मैंने मेरी पहली टर्म में यह योजना शुरू की थी, तो मुझे याद है, झूठे नरेटिव की जो फैशन चल पड़ी है, गांवों में जाकर कहा जाता था, देखिए मोदी के पैसे मत लेना, ये एक बार चुनाव जीत गया, तो सारे पैसे ब्याज समेत तुमसे वापस मांगेगा । ऐसा झूठ फैलाया गया था । किसानों को इतना मूर्ख बनाने की कोशिश की गई थी ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, पीएम किसान सम्मान निधि में हमने 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपए भेजे हैं । पीएम फसल बीमा योजना के तहत 30 हजार

रुपए का प्रिमियम और उसके सामने डेढ़ लाख करोड़ रुपए मेरे किसान भाई-बहनों के लिए दिए गए हैं ।

कांग्रेस ने शासन काल में, उनके काम में तो मछुआरे और पशुपालकों का नामो-निशान नहीं था । पहली बार, इस देश में मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बना और पशुपालन के लिए अलग मंत्रालय बना । पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया ताकि कम ब्याज पर उनको बैंक से पैसे मिल सकें और वे अपना कारोबार बढ़ा सकें । किसानों और मछुआरों की भी चिंता है, सिर्फ जानवरों की नहीं होती है । ये जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं । आर्थिक चक्र को चलाने में इन पशुओं की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है ।

हमने फुट एंड माउथ डिजीज जैसे रोगों से पशुओं को बचाने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा टीके लगवाए हैं । पहले यह कभी सोचा नहीं गया था ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज भारत में युवाओं के लिए जितने भी नये अवसर बने हैं, ये पहले कभी नहीं बने । आज पूरी वोकैबलरी बदल गयी है । शब्द हैं, जो पहले कभी सुनने को नहीं मिलते थे । ऐसे शब्द बोलचाल की सहज दुनिया में आ चुके हैं ।

आज चारों तरफ स्टार्ट-अप्स की गूंज है । आज नि-कॉम्स चर्चा में हैं । आज डिजिटल क्रिएटर्स का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है । आज गिग इकोनॉमी की चर्चा हो रही है । युवाओं की जुबान पर नये भारत की नयी वोकैबलरी है । यह नये आर्थिक साम्राज्य का नया परिवेश है, नई पहचान है ।

ये सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बना रहे हैं । वर्ष 2014 से पहले डिजिटल इकोनॉमी की साइज न के बराबर थी, बहुत ज्यादा उसकी चर्चा भी नहीं थी । आज भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी है । लाखों युवा इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में यह डिजिटल इंडिया

मूवमेंट जो है, वह देश के नौजवानों के लिए अनेक-अनेक अवसर, अनेक-अनेक रोजगार, अनेक-अनेक प्रोफेशंस के लिए अवसर लेकर आने वाला है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत, मेड इन इंडिया फोन दुनिया में पहुँच रहे हैं । दुनिया में हम नंबर दो बन गए हैं और एक तरफ सस्ता मोबाइल प्राप्त हुआ है और दूसरी तरफ सस्ता डेटा । इन दोनों ने देश में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है और दुनिया में हम जिस कीमत पर इसे प्राप्त करवा रहे हैं, हम सबसे कम कीमत पर करवा रहे हैं । वह इसका एक कारण बना है । आज मेड इन इंडिया अभियान, रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट देश देख रहा है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सारे काम हमारे नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा रोजगार लाने वाले काम हैं, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने वाले काम हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 10 वर्ष में टूरिज्म सेक्टर में अभूतपूर्व उछाल आया है । हमारे देश में यह ग्रोथ हुई है और टूरिज्म सेक्टर ऐसा है, जिसमें कम से कम पूँजी निवेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का अवसर है । सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी यह रोजगार देने वाला अवसर है । स्वरोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला टूरिज्म क्षेत्र है । 10 वर्ष में दोगुने एयरपोर्ट्स बने हैं । सिर्फ एयरपोर्ट्स बने हैं, ऐसा नहीं है । भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर बन चुका है । हम सबको खुशी होनी चाहिए । भारत की जो एयरलाइंस कंपनियाँ हैं, उन्होंने एक हजार नए एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर दिए हैं । देश में एक हजार नए एयरक्राफ्ट्स होंगे ।? (व्यवधान) जब इतने सारे हवाई जहाज ऑपरेट होंगे, सारे एयरपोर्ट कितने दमखम पर होंगे, कितने पायलेट्स की जरूरत पड़ेगी, कितने हमें क्रू मेंबर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने ग्राउंड सर्विस के लिए लोग चाहिए यानी रोजगारी के नये-नये क्षेत्र खुलते जा रहे हैं । एविएशन सेक्टर भारत के लिए एक बहुत बड़ा नया अवसर बनकर आया है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी कोशिश रही है कि इकोनॉमी को हम फॉर्मलाइज करने की दिशा में मजबूती से कदम उठाएं । युवाओं को नौकरी भी मिले, सोशल सिक्योरिटी भी मिले । इन दोनों को लेकर और जिन बातों के आधार पर हम निर्णय करते हैं और देश में भी माना जाता है, वह ईपीएफओ का डाटा होता है । ईपीएफओ में जो रजिस्ट्रेशन होता है, 10 साल में करीब 18 करोड़ नए सब्सक्राइबर आए हैं । वह तो सीधा पैसों से जुड़ा खेल होता है, उसमें फर्जी नाम नहीं होते हैं । मुद्रा लोन पाने वालों में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने जीवन में पहली बार अपना कारोबार शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है । जब वह मुद्रा लोन लेता है तो खुद तो रोजगारी पाता ही है, एक या दो और लोगों को भी रोजगारी देता है, क्योंकि उसका काम ऐसा होता है । हमने लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया है । 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी से जुड़ीं, जैसा मैंने कहा है कि एक करोड़ लखपति दीदी, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ।

मैंने जैसे कहा कि हमने तीन करोड़ का टार्गेट रखा है । कुछ आंकड़े हैं, जो केवल अर्थशास्त्री ही नहीं समझ सकते, बल्कि सामान्य आदमी भी समझ सकते हैं । वर्ष 2014 के पहले दस वर्षों में इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में करीब-करीब 12 लाख करोड़ रुपये का बजट था । दस साल में 12 लाख करोड़ रुपये का बजट था । बीते दस वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के अंदर बजट 44 लाख करोड़ रुपये का है । रोजगार कैसे बढ़ते हैं, यह इससे समझ आता है ।

अध्यक्ष जी, इस राशि से जितनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है, उसके कारण बहुत लोगों को रोजी-रोटी मिली है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं । हम भारत को मैनुफैक्चरिंग का, रिसर्च का, इनोवेशन का हब बनाने की दिशा में देश की युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं, आर्थिक मदद की योजनाएं बना रहे हैं ।

अध्यक्ष जी, एनर्जी के क्षेत्र में हम हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं । एनर्जी के सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और हमारी कोशिश ग्रीन एनर्जी की तरफ है । हाईड्रोजन को लेकर हम बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं । इसमें अभूतपूर्व निवेश हो रहा है । उसी प्रकार से दूसरा क्षेत्र है, जिसमें भारत को लीड लेनी होगी और वह सेमी कंडक्टर का क्षेत्र है । पिछली सरकारों ने प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली । अब हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, मैं विश्वास से कहता हूं कि भले ही हमारे तीन दशक खराब हो गए हैं, लेकिन आने वाला समय हमारा है । मैं सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश देख रहा हूं और भारत दुनिया में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा । इन सारे कारणों से क्वालिटी जॉब की संभावनाएं बहुत बढ़ने वाली हैं । हमने समाज में अलग स्किल मिनिस्ट्री बनाई । इसके पीछे हित यह है कि देश के नौजवानों को हुनर तथा ऐसे अवसर मिलें कि हम इंडस्ट्री 4.0 के लिए मैनपॉवर को तैयार करते हुए आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां महंगाई को लेकर काफी बातें कही गई हैं । मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए । इतिहास गवाह है कि जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है । मैं कुछ वक्तव्य आज सदन में कहना चाहता हूं । मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझ नहीं पाते हैं, वे अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे । कभी कहा गया था और किसने कहा था, वह मैं बाद में कहूंगा ? ?हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है ।? यह स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हमारे पंडित नेहरू जी का है और लाल किले से उस समय कहा था । ? हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है? ? यह उस समय की बात है । उन्होंने लाल किले से माना था । चारों तरफ महंगाई बढ़ी थी । इस वक्तव्य के दस साल बाद के दूसरे वक्तव्य का कोट आपके सामने रखता हूं ? ?आप लोग आज कल भी कुछ दिक्कतों में

हैं, परेशानियों में हैं महंगाई की वजह से । कुछ तो लाचारी है, पूरे तौर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में, हालांकि वह काबू में आएगी ।? दस साल बाद भी महंगाई के यही गीत कहे गए थे और यह किसने कहा था? फिर से यह नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में ही कहा था, तब देश का पीएम रहते हुए उन्हें ।12 साल हो चुके थे । लेकिन हर बार महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, महंगाई के कारण आपको मुसीबत हो रही है, इसी के गीत गाते रहे ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, अब मैं एक और भाषण का हिस्सा पढ़ रहा हूं - ?जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक कीमतें भी बढ़ती हैं । हमको यह भी देखना है कि जो भी आवश्यक वस्तु हैं, उनकी कीमत को कैसे थामें?? यह किसने कहा था? इसे इन्दिरा गाँधी जी ने कहा था । वर्ष 1974 में, जब उन्होंने देश में सारे दरवाजों पर ताले लगा दिए थे, लोगों को जेल में बंद कर दिया था, उस समय 30 प्रतिशत महंगाई थी ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, उनके भाषण में यहां तक कहा गया था, क्या कहा गया था, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, उन्होंने कहा था - ?अगर जमीन न हो, यानी कुछ पैदावार के लिए जमीन न हो तो अपने गमले और कनस्तर में सब्जी उगा लें ।? ऐसी सलाहें उच्च पद पर बैठे हुए लोग दिया करते थे । हमारे देश में महंगाई को लेकर दो गाने सुपरहिट हुए थे, घर-घर गाए जाते थे । एक, ?महंगाई मार गई?, और दूसरा, ?महंगाई डायन खाए जात है ।? ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यूपीए के शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी, इसको नकार नहीं सकते हैं । यूपीए की सरकार का तर्क क्या था? असंवेदनशीलता में कहा गया था कि ?महंगी आइस्क्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो ।? जब भी कांग्रेस आई है, उसने महंगाई को ही मजबूत किया है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा है ।? (व्यवधान) दो-दो युद्ध के बावजूद और 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंत्रण में है और हम यह कर पाए हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया है । जितना हो सका, उतने कठोर शब्दों में गुस्सा व्यक्त किया गया है । उनका दर्द मैं समझता हूं । उनकी मुसीबत और यह गुस्सा, मैं समझता हूं, क्योंकि ? तीर निशाने पर लगा है ।? भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं । उसको लेकर भी इतना गुस्सा! क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है?

आदरणीय अध्यक्ष जी, दस साल पहले हमारे पार्लियामेंट में, सदन में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी । सदन यही मांग करता रहता था कि ?एक्शन लो?, ?एक्शन लो?, ?एक्शन लो ।? देश ने वह कालखंड देखा है । उस समय रोजाना चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें थीं, और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनके समर्थन में हंगामा करते हैं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई और काम नहीं करने दिया जाता था । अब आप देखिए कि उनके कालखंड में क्या हुआ? पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले दोगुने से अधिक केस दर्ज किए । कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी । हमारे कार्यकाल में ईडी ने एक लाख करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की है । देश का यह लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा । जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हों, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, उन्होंने तो नोटों के ढेर देखे हैं, किस-किस के घर में से पकड़े जाते हैं, किस-किस के राज्य में पकड़े जाते हैं । यह देश इन नोटों के ढेरों को देख-देख कर चौंक गया है । लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं । जनता

देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टचार की बातें होती थीं, उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ रुपये का रहा है, उसकी चर्चा होती थी । हमने लाखों-करोड़ों के घोटाले तो पकड़े ही और उन सारे पैसों को गरीबों के काम में लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए लगा दिया । अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है । डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जन-धन अकाउंट, आधार, मोबाइल आदि की ताकत हमने पहचानी है । तीस लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम हमने लोगों के खाते में सीधी पहुंचाई है । कांग्रेस के एक प्रधान मंत्री ने कहा था कि वे एक रुपया भेजते हैं और लोगों के पास 15 पैसे पहुंचते हैं, अगर उस हिसाब से मैं देखूं, तो हमने जो तीस लाख रुपये भेजे हैं, अगर उनका ज़माना होता तो कितना रुपया कहां चला जाता? इसका हिसाब लगाइए । मुश्किल से 15 पर्सेंट लोगों के पास पहुंचता, बाकी सब कहां चला जाता?

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने दस करोड़ फर्ज़ी नाम हटाए हैं । अभी लोग पूछते हैं न कि पहले इतना आंकड़ा था, अब कम क्यों हो गया । आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, उसको आपके यहां से विधवा पेंशन जाती थी । इस प्रकार से सरकारी योजनाओं को मारने के जो रास्ते थे, उनको बंद कर के दस करोड़ फर्ज़ी नाम हटाए हैं । यह जो परेशानी है न, वह इन चीजों की हैं, क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की कमाई बंद हो गई है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने इन फर्ज़ी नामों को हटा कर करीब-करीब तीन लाख करोड़ रुपये फर्ज़ी हाथों में जाने से बचाए हैं, गलत हाथों में जाने से बचाए हैं । देश के टैक्सपेयर का पाई- पाई बचाना और सही काम में लगाना, इसके लिए हमने जीवन खपा रखे हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे हैं, उनको देखने की जरूरत है । आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वह भी दस दिन तक अपना मुंह किसी को

दिखाता नहीं था । आज जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय काट कर के पैरोल पर आए हैं, आज वाशिंग मशीन से भी बड़ा, उनको कंधे पर बिठा कर, ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में महिमामंडन कर रहे हैं । आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? जिनकी सजा हो चुकी है, मैं यही तो समझता हूं कि जो आरोप है, उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जिनका गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का आप महिमामंडन करते हैं ।? (व्यवधान) कौन-सा कल्चर है, देश की भावी पीढ़ी को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो? ऐसी कौन-सी आपकी मजबूरी है? ऐसे लोगों का महिमामंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है ।

माननीय अध्यक्ष जी जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं । ये लोग लिख कर के रखें । उनके महिमामंडन का जो काम चल रहा है, वे अपने ही खात्मे की चिट्ठी पर सिग्नेचर कर रहे हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना एजेंसियों का काम है । एजेंसियाँ स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है ।? (व्यवधान) जज करने का काम न्यायाधीश का है और वे अपना काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष जी, इस पवित्र सदन में मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है, कर लें, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई चलती रहेगी । जिसने देश को लूटा हैं, उनको लौटाना पड़ेगा । जिन्होंने देश को लूटा है, उनको लौटाना पड़ेगा । यह मैं देश के इस पवित्र सदन से वादा करता हूं । जिसको जो आरोप लगाना है, लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जिसने लूटा है, उसे लौटाना पड़ेगा ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश सुरक्षा और शांति का अहसास कर रहा है । पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश वाकई सशक्त हुआ है । आतंकवाद, नक्सलवाद अब एक छोटे दायरे में सिमटा हुआ है । लेकिन,

भारत की टेररिज्म के प्रति जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा है ।

भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर समुद्र तक अपने सामर्थ्य को लेकर आज भी उनकी धाक है ।? (व्यवधान) हमें अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए । हम कितना ही उनकी मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है । मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है । कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के-फुल्के शब्द बोलते हैं कि इससे हमारे देश की सेना डिमोरलाइज होगी, ऐसा कोई सपनों में भी रहता है तो वह निकल जाए । वे देश के मनोबल को खत्म नहीं कर सकते हैं । किसी के एजेंट बन कर के इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है तो देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है । जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके भी आपके मन का समाधान नहीं हुआ है? आप देश के इतने टुकड़े कर चुके हैं, क्या और टुकड़े करना चाहते हैं, कब तक करते रहोगे?

आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी, तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छींटाकशी होती थी, आरोप-प्रत्यारोप होते थे । आज जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है ।

पर्यटन लगातार बढ़ रहा है । जी-20 समिट वहां होती है । पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है । आर्टिकल 370 को लेकर कैसा हौवा बना के रखा था? कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, आखिर यह समस्या किसकी देन थी, किसने देश के माथे पर मढ़ा था, किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी?

आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है । लेकिन कश्मीर को जो समस्यायें झेलनी पड़ीं, उसके मूल में उनकी यह सोच थी और उसी का परिणाम इस देश को भुगतना पड़ रहा है । जम्मू-कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी । ? (व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, वह भले गलतियां करके गए, लेकिन हम मुसीबतें झेलकर भी गलतियां सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखेंगे । हम रुकने वाले नहीं हैं । हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग हैं । हमारे लिए नेशन फर्स्ट है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा । भारत के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया है, वैश्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा अवसर आया है, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर आया है । राजनीति अपनी जगह पर होती है, आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है । इसलिए, आइए, मैं निमंत्रण देता हूं आपको, कंधे से कंधा मिलाकर हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ें । राजनीति में किसी भी जगह पर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती । हम इस राह को मत छोड़ें । मैं आपका साथ मांग रहा हूं, मां भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूं, विश्व के अंदर जो अवसर आया है, उस अवसर को भुनाने के लिए आपका साथ मांग रहा हूं । मैं आपका सहयोग चाहता हूं, 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए, और सुखी बनाने के लिए । लेकिन, अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है, तो आप लिखकर रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लगा दूंगा । आपके हर पत्थर को, मैं विकसित भारत के जिन सपनों को लेकर हम चले हैं, उसकी नींव मजबूत करने के लिए लगा दूंगा और देश को हम उस समृद्धि की ओर लेकर जाएंगे । जितने पत्थर उछालने हैं, उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर समृद्ध भारत के, विकसित भारत के

सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा । यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं साथियों की तकलीफें जानता हूं । लेकिन, वे जो कुछ भी बोलते हैं, मैं दु:खी नहीं होता और दु:खी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये नामदार हैं, हम कामदार हैं । हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही पड़ता है । नामदार कुछ भी कहते रहें, कुछ भी कहने के उनको तो जन्मजात अधिकार मिले हुए हैं और हम कामदारों को सुनना होता है । हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहेजते भी रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस पवित्र सदन में आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को समर्थन करने के लिए बोलने का अवसर दिया । मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के इस उद्बोधन को समर्थन देते हुए, धन्यवाद प्रस्ताव पर आभार व्यक्त करते हुए, मेरी वाणी को विराम देता हूं ।?(व्यवधान)

***m135 माननीय अध्यक्ष :** धन्यवाद प्रस्ताव पर श्रीमती अपरूपा पोद्दार और श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन ने अपने-अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं । अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

? कि माननीय राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

?कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके हम अत्यंत आभारी हैं ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही मंगलवार, 6 फरवरी, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

<u>18.52 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday, February 6, 2024/Magha 17, 1945 (Saka).

-

<u>INTERNET</u>

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

www.sansad.in/ls

<u>LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA</u>

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

-

-

-

-